[2012] 9 एस. सी. आर. *311*

आरईः *2012* का विशेष संदर्भ संख्या *1*

[भारत के संविधान के अनुच्छेद *143 (1)* के तहत*]*

27 सितंबर*, 2012*

[एस. एच. कपाडिया, सीजेआई, डी. के. जैन, जगदीश सिंह

खेहर, दीपक मिश्रा और रंजन गोगोई, जे. जे.*]*

भारत का संविधान*, 1950:*

अनुच्छेद *143 (1)*-उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति का दायरा-यह आवश्यक नहीं है कि वह प्रश्न जिस पर उच्चतम न्यायालय की राय मांगी गई है जो वास्तव में उत्पन्न हुई होगी राष्ट्रपति पूर्वकाल में भी संदर्भ दे सकते हैं। स्तर, अर्थात्, उस स्तर पर जब राष्ट्रपति संतुष्ट होता है कि सवाल उठने की संभावना है-संतुष्टि क्या राष्ट्रपति को निर्णय लेने के लिए मामला-एक संदर्भ प्राप्त होने परकला के तहत। *143 (1)* , सर्वोच्च न्यायालय के पास एकमात्र विवेकाधिकार है या तो संदर्भ का जवाब देने के लिए या सम्मानपूर्वक भेजने से इनकार करने के लिए राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट-तत्काल संदर्भ में, प्रश्न नहीं। *1* एक संवैधानिक सिद्धांत की व्याख्या शामिल है कला के अंतर्गत निहित। *14* संविधान और यह महान है सार्वजनिक महत्व क्योंकि यह आवंटन/अलगाव/से संबंधित है प्राकृतिक संसाधनों का निपटान/वितरण।

कला. *137* और *143 (1)*-समीक्षा और संदर्भ-अंतर के बीच-समझाया-आयोजितः केवल इसलिए कि एक समीक्षा एक मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय दायर किया गया था और वापस ले लिया गया और संदर्भ के पाठ में, वर्णन संबंधित है उक्त मामले में, यह प्रतिबंध नहीं होगा यासंदर्भ का उत्तर देने के लिए विवेक के प्रयोग के लिए बाधा।

कला. *143 (1)* - राष्ट्रपति का संदर्भ सूचना-अभ्यास और प्रक्रिया।

कला. *143 (1)* - बाद में राष्ट्रपति का संदर्भ *"2* जी मामले*"* में उच्चतम न्यायालय का निर्णय-रखरखाव आयोजित किया गयाः संदर्भ बनाए रखने योग्य है, इसके बावजूद *2* जी मामले के अनुपात पर प्रभाव, जब तक कि उस मामले में निर्णय अंतर-पक्षीय मामलों को अप्रभावित छोड़ दिया गया है-संदर्भ द्वारा, अनुमति के सीमित बिंदु पर अदालत की राय मांगी जाती है। प्राकृतिक विलयन के लिए नीलामी के अलावा अन्य विधियों का स्पेक्ट्रम के अलावा अन्य संसाधन। - इसकी ओर से कहा गया है भारत सरकार का कहना है कि वह सवाल नहीं उठा रही हैजहां तक आवंटन की बात है, *2* जी मामले में निर्देशों की शुद्धता स्पेक्ट्रम का संबंध है और वास्तव में, सरकार में है उसी को अक्षर और भावना में लागू करने की प्रक्रिया-जब तक स्पेक्ट्रम लाइसेंस के आवंटन के संबंध में निर्णय के रूप में अछूत है, न्यायालय मूल्यांकन करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में है और *2* जी मामले में निर्णय के अनुपात को स्पष्ट करें।

कला. *141* - उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून-आयोजितः एक निर्णय में घोषित *'*कानून*'*, जो अदालतों पर बाध्यकारी है, है

निर्णय का अनुपात तय करता है-यह सिद्धांत लिया गया हैके प्रकाश में एक समग्र रूप से एक निर्णय के पढ़ने पर बाहर

जिन प्रश्नों पर मामले का फैसला किया जाता है-"*2* जी मामले" में

न्यायालय सामान्य रूप से नीलामी के मामले पर विचार नहीं कर रहा था,

लेकिन विशेष रूप से विधियों की वैधता का मूल्यांकन कर रहा था संबंधित अवधि के दौरान स्पेक्ट्रम के वितरण में अपनाया गया

अवधि-के अलगाव के लिए नीलामी की सिफारिश

प्राकृतिक संसाधनों को कभी भी एक के रूप में लेने का इरादा नहीं थानिरपेक्ष या कंबल कथन सभी प्राकृतिक क्षेत्रों में लागू होता है।

संसाधन-'शायद' शब्द का चुनाव बताता है कि

न्यायालय ने उन स्थितियों पर विचार किया जिनमें इसके अलावा किसी अन्य विधि की आवश्यकता होती है।

नीलामी जैसा कि कल्पना की जा सकती है और वांछनीय-*2* जी में अवलोकन मामला स्पेक्ट्रम के विशिष्ट मामले से परे लागू नहीं हो सकता था,

जिसे *2* जी मामले में घोषित कानून के अनुसार, केवल नीलामी द्वारा अलग किया जाना है और कोई अन्य तरीका नहीं है-पूर्ववर्ती।

कला. *14* - राज्य द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का निपटान-नीलामी

आयोजित किया गयाः सभी क्षेत्रों और सभी क्षेत्रों में सभी प्राकृतिक संसाधनों के निपटान के लिए नीलामी ही एकमात्र अनुमत तरीका नहीं है।परिस्थितियाँ-नीलामी, प्राकृतिक के निपटान की एक विधि के रूप में

313 के तहत संसाधनों को संवैधानिक जनादेश घोषित नहीं किया जा सकता है।

आरईः *2012* का विशेष संदर्भ संख्या *1*

Art.14-नीलामी एक अधिक बेहतर तरीका होने के बावजूदप्राकृतिक संसाधनों के अलगाव/आवंटन को संवैधानिक आवश्यकता या अलगाव के लिए सीमा नहीं माना जा सकता है।

सभी प्राकृतिक संसाधन और, इसलिए, इसके अलावा हर विधि

नीलामी को रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि यह संविधान के अधिकार से बाहर है

बाजार मूल्य, अर्थशास्त्र में, उस मूल्य का सूचकांक है जो

बाजार एक वस्तु को निर्धारित करता है-हालाँकि, यह मूल्यांकन एक है

कई गतिशील चरों का कार्य; यह एक विज्ञान है और नहीं

एक कानून-नीलामी कई मूल्य खोजों में से एक है।

मूल्यांकन, नीलामी या प्रतिस्पर्धी बोली का कोई अन्य रूप,एक आर्थिक जनादेश का गठन भी नहीं कर सकता, बहुत कम

संवैधानिक जनादेश-इसलिए, नीलामी, एक आर्थिक के रूप में

प्राकृतिक संसाधनों के निपटान का चुनाव संवैधानिक नहीं है।

जनादेश-प्राकृतिक संसाधनों का अलगाव एक नीतिगत निर्णय है, और इसके लिए अपनाए गए साधन इस प्रकार हैं, कार्यकारी

विशेषाधिकार-हालाँकि, जब ऐसा नीतिगत निर्णय नहीं होता है

एक सामाजिक या कल्याणकारी उद्देश्य द्वारा समर्थित, और बहुमूल्य और

दुर्लभ प्राकृतिक संसाधनों को निजी क्षेत्र से अलग कर दिया गया है। अधिकतम लाभ के वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए उद्यमी,

प्रतिस्पर्धी साधनों के अलावा अन्य साधनों को अपनाना और

अधिकतम राजस्व मनमाना हो सकता है और कला के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है।

14 संविधान से।

कला. *14 Art.299* के साथ पढ़ें-सरकारी अनुबंध-आयोजितः

राज्य की कार्रवाई का कला की कसौटी पर परीक्षण किया जाना चाहिए। *14* - कार्रवाई निष्पक्ष, उचित, गैर-भेदभावपूर्ण होनी चाहिए।

पारदर्शी, गैर-मनमौजी, निष्पक्ष, पक्षपात के बिना या

भाई-भतीजावाद, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए और

न्यायसंगत व्यवहार-यह उन मानदंडों के अनुरूप होना चाहिए जो तर्कसंगत हों, कारणों से सूचित हों और जनहित द्वारा निर्देशित हों।

आदि-ये सभी सिद्धांत मूल सिद्धांत में निहित हैं।

कला की अवधारणा। *14* - यह कला का अधिदेश है। *14* .

कलाएँ। *14* और। *39 (ख)* प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन में समानता

संसाधन और "सामान्य भलाई" कारक-आयोजितः नीलामी राजस्व को अधिकतम करने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है लेकिन राजस्व *314* सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट *[2012] 9* एस. सी. आर.

अधिकतमकरण हमेशा सबसे अच्छा तरीका नहीं हो सकता है

सार्वजनिक भलाई-"आम भलाई" एकमात्र मार्गदर्शक कारक है और

कला के तहत एक मानक। *39 (ख)* प्राकृतिक संसाधनों के वितरण के लिए-जहां राजस्व को अधिकतम करना एक नीति का उद्देश्य है,

उस समय उस संसाधन को माना जाता है

आम भलाई को कम करने का सबसे अच्छा तरीका होगा नीलामी बेहतर विधियों में से, हालांकि एकमात्र विधि नहीं

जहाँ राजस्व अधिकतमकरण की नीति का उद्देश्य नहीं है

वितरण, नीलामी का सवाल ही नहीं उठेगा-राजस्वविचार विकासात्मक विचारों को मार्ग दे सकते हैं।

- जनहित याचिका-न्यायिक सूचना।

कलाएँ। *298* और *299* को *Art.14*-राज्य की शक्ति के साथ पढ़ा जाता है

अनुबंधों का व्यापार और निष्पादन-चर्चा की गई।

प्रशासनिक कानूनः

राज्य नीति-न्यायिक समीक्षा-आयोजितः अदालत ऐसा नहीं कर सकती।

विभिन्न विधियों का तुलनात्मक अध्ययन करना

प्राकृतिक संसाधनों का वितरण और सबसे अधिक सुझाव

प्रभावी विधि-निपटान से संबंधित कार्यप्रणाली

प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण स्पष्ट रूप से एक आर्थिक नीति है-ऐसा नहीं हो सकता।

और न्यायालय का मूल्यांकन करने का प्रयास नहीं होगा

निपटान के अन्य तरीकों की तुलना में नीलामी की प्रभावशीलता प्राकृतिक संसाधन-जब पूछताछ की जाती है, तो अदालतें वितरण के विभिन्न साधनों की कानूनी वैधता का विश्लेषण करने की हकदार होती हैं और

संवैधानिक उत्तर दें कि कौन से तरीके अतिप्रभावी हैं

यदि कोई नीति या कानून स्पष्ट रूप से इस हद तक अनुचित है कि यह संविधान के प्रावधानों के अधिकार और अधिकार के भीतर आता है। कला की निष्पक्षता की आवश्यकता। *14* , न्यायालय इसे निरस्त करने में संकोच नहीं करेगा-राज्य नीति की वैधता और संवैधानिकता और उसके कार्यान्वयन-चर्चा-संविधान

भारत का, *1950-Art.14*।

मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद

सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन *& Ors.*[1], *(2G* केस*)*

कला के खंड *(1)* के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राष्ट्रपति द्वारा तत्काल संदर्भ दिया गया था।

143 2012 का विशेष संदर्भ सं. *1,315* भारत के बारे में, विचार और रिपोर्ट के लिए

निम्नलिखित प्रश्नों पर न्यायालयः

*"*क्या एकमात्र अनुमेय विधि है

सभी प्राकृतिक संसाधनों का निपटान

क्षेत्रों और सभी परिस्थितियों में द्वारा है नीलामियों का संचालन*?*

क्या कानून का एक व्यापक प्रस्ताव है कि केवल

नीलामियों के मार्ग का सहारा लिया जा सकता है

प्राकृतिक संसाधनों का निपटान नहीं चलता है

सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णयों के विपरीत

बड़ी पीठों सहित न्यायालय*?*

क्या एक व्यापक सिद्धांत का उच्चारण,

यद्यपि एक विषय के रूप में व्यक्त किया गया

संवैधानिक कानून, वास्तव में नहीं है

एक नीति का निर्माण और तैयार किए गए अस्थिर नीतिगत निर्णयों का प्रभाव है और

विभिन्न क्रमिक द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण वर्षों से वैध के लिए सरकारें

संसाधन और विकास के लिए नवीन और विभिन्न दृष्टिकोणों का सहारा लेने की आवश्यकताअर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में?

हस्तक्षेप की अनुमेय गुंजाइश क्या है?

नीति निर्माण के साथ अदालतों द्वारा

निपटान के तरीकों सहित सरकार

प्राकृतिक संसाधन?

क्या, यदि न्यायालय मानता है, के भीतर

न्यायिक समीक्षा का अनुमेय दायरा, कि

नीति त्रुटिपूर्ण है, क्या अदालत इसके लिए बाध्य नहीं है

के तहत किए गए निवेशों को ध्यान में रखें

बहुपक्षीय/द्विपक्षीय के तहत विदेशी निवेशकों द्वारा किए गए निवेश सहित उक्त नीति

समझौते?

यदि उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर नेतृत्व करते हैं

दिनांकित निर्णय की पुष्टि करने के लिए

02.02.2012 तब निम्नलिखित प्रश्न हो सकते हैं -

उठें, अर्थात।

क्या निर्णय की आवश्यकता है

((i)

पूर्वव्यापी प्रभाव दिया जाए ताकि जारी किए गए सभी लाइसेंसों और *2* जी को अस्थिर करें

स्पेक्ट्रम *(800,900* और *1800* मेगाहर्ट्ज़*)*

बैंड*) 1994* में और उसके बाद आवंटित किए गए और

10.01.2008 से पहले*?*

क्या *2* जी का आवंटन

*((*ख*)*

सभी परिस्थितियों में और सभी में स्पेक्ट्रम

विभिन्न नीतियों के लिए विशिष्ट मामले

फिर भी विचार होंगे

दूर करने के लिए*?*

विशेष रूप से

(iii) क्या दूरसंचार लाइसेंस दिए गए हैं

1994 क्या यह प्रभावित होगा*?*

((iv) क्या दूरसंचार लाइसेंस दिए गए हैं।

2001 में बुनियादी लाइसेंसों के माध्यम से और

अवधि के बीच दिए गए लाइसेंस *2003-2007* क्या यह प्रभावित होगा*?*

क्या यह सरकार के लिए खुला है

(v)

भारत शर्तों में बदलाव के लिए कोई भी कार्रवाई करेगा समान स्तर का खेल सुनिश्चित करने के लिए किसी भी लाइसेंस का

सभी मौजूदा लाइसेंसधारियों के बीच क्षेत्र*?*

(vi) क्या दोहरे प्रौद्योगिकी लाइसेंस

2007 और *2008* में दिया गया

प्रभावित*?*

(vii) चाहे वह आवश्यक हो या अनिवार्य

317 को वापस लेने के लिए भारत सरकार

2012 का विशेष संदर्भ संख्या *1*

सभी मौजूदा लोगों को आवंटित स्पेक्ट्रमअनुज्ञप्तिधारी या उसी के लिए शुल्क लेने के लिए

पूर्वव्यापी प्रभाव और यदि ऐसा है तो किस पर आधार और किस तारीख से*?*

चाहे, संचालन के लिए कार्रवाई करते समय

के आदेशों के अनुसार नीलामी

सुप्रीम कोर्ट, यह अनुमेय रहेगा

सरकार के लिए:

स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए प्रावधान करें

((i)

समय-समय पर नीलामी में

ज्ञात मूल्य और अवधि के दौरान निर्धारित मानदंडों के अनुसार

नीलामी द्वारा निर्धारित मूल्य की वैधता*?*

((ii) अधिग्रहण पर एक सीमा लागू करें।

बाजार में प्रभुत्व के उदय से बचने के उद्देश्य से स्पेक्ट्रम विधिवत लेने वाले किसी भी लाइसेंसधारी/आवेदक द्वारा

टी. आर. ए. आई. पर विचार

इस संबंध में सिफारिशें*?*

((iii) आवंटन के लिए प्रावधान करें।

नीलामी से संबंधित कीमतों पर स्पेक्ट्रम बैंड में निर्धारित मानदंडों के अनुसार जहां अपर्याप्त हो सकता है

या कोई प्रतिस्पर्धा नहीं (जैसे कि वहाँ है

निम्न स्तर की प्रतिस्पर्धा होने की उम्मीद है सी. डी. एम. ए. के लिए *800* मेगाहर्ट्ज बैंड और टी. आर. ए. आई.

एक समतुल्यता अनुपात की सिफारिश की गई *1.5* या *800* मेगाहर्ट्ज और *900* मेगाहर्ट्ज बैंड के लिए *1.3X 1.5* की मात्रा के आधार पर

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा धारित स्पेक्ट्रम जो कर सकता है

एक विशिष्ट मूल्य के अभाव में *1800* मेगाहर्ट्ज बैंड में नीलामी मूल्य पर लागू किया जाएगा।

इन गुटों के लिए*)?*

318

[2012] 9 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्र. *8 3* जी पर फैसले का क्या प्रभाव पड़ता है*?*

नीलामी द्वारा संस्थाओं द्वारा अधिग्रहित स्पेक्ट्रम

जिनके लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं

फैसला कहा*? "*

भारत के महान्यायवादी को नोटिस जारी किया गया था,

और उन्हें सुनने के बाद, यह निर्देश दिया गया कि सभी राज्यों को उनके स्थायी वकील के माध्यम से नोटिस जारी किया जाए।

2 जी मामले में याचिकाकर्ता, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और

भारतीय उद्योग परिसंघ।

आंशिक रूप से संदर्भ का उत्तर देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः प्रति डी. के. जैन, जे. *(*सीजेआई के लिए, खुद दीपक मिश्रा*)*

और रंजन गोगोई, जे. जे*)*

संदर्भ की मुख्यताः

1.1 कला. *143* भारत के संविधान को लागू किया गया है

व्यापक रूप से*;* और इसकी भाषा से, यह स्पष्ट है कि यह है

आवश्यक नहीं है कि वह प्रश्न जिस पर राय

उच्चतम न्यायालय की मांग वास्तव में उत्पन्न हुई होगी।राष्ट्रपति उक्त के तहत एक संदर्भ दे सकते हैं

अनुच्छेद पूर्ववर्ती अवस्था में भी, अर्थात् उस अवस्था में जब राष्ट्रपति संतुष्ट होते हैं कि प्रश्न संभावित है।

उठने के लिए। इस बात की संतुष्टि कि क्या प्रश्न पूरा होता हैकला की पूर्व-आवश्यकताएँ। *143 (1)* अनिवार्य रूप से एक मामला है

राष्ट्रपति तय करें। एक संदर्भ प्राप्त होने पर

कला. *143 (1)* , इस न्यायालय का कार्य उस संदर्भ, उस प्रश्न *(*प्रश्नों*)* पर विचार करना है जिस पर राष्ट्रपति के पास है।

में बताए गए तथ्यों पर संदर्भ दिया गया

प्रत्येक संदर्भ में सलाहकार राय दें और हो सकता है मजबूत, सम्मोहक के लिए अपनी राय व्यक्त करने से इनकार करना और

अच्छे कारण। *[* पैरा *23-24] [373-E-F, G-H; 374-B-C] 319*

आरईः *2012* का विशेष संदर्भ संख्या *1*

1964 का विशेष संदर्भ संख्या *1 ("*केशव सिंह*") [1965]*

1 एस. सी. आर. *413* और पुनः: केरल शिक्षा विधेयक, *1957* भारत के संविधान के अनुच्छेद *143 (1)* के तहत संदर्भ

[1959] एस. सी. आर. *995*-पर निर्भर था।

पुनः में - भूमि और भवनों का आवंटन एक प्रमुख में स्थित होता है

आयुक्त का प्रांत और द्वारा संदर्भ के मामले में

गवर्नर-जनरल धारा *212* के तहत*;* भारत सरकार अधिनियम,

1935 ए. आई. आर. *(30) 1943* एफ. सी. *13;* और डॉ. एम. इस्माइल फारूकी और

ओआरएस। बनाम भारत संघ और अन्य। *1994 (5)* पूरक। एससीआर *1 = (1994)*

6 एस. सी. सी. *360*-संदर्भित।

1.3 जहाँ तक दुर्भावनापूर्ण आरोप का संबंध है, यह सामान्य बात है कि इस न्यायालय को न तो इस मामले में जाने की आवश्यकता है।

पाठ के तथ्यों की सच्चाई या अन्यथा न तो यह जा सकता है

सत्यनिष्ठा या अन्यथा के प्रश्न में एक संदर्भ बनाने वाला प्राधिकारी। संवैधानिक शक्ति

इस न्यायालय की राय लेना राष्ट्रपति के पास है। द.

इस न्यायालय के पास केवल विवेकाधिकार है कि वह या तो जवाब दे संदर्भ या सम्मानपूर्वक रिपोर्ट भेजने से इनकार करना

राष्ट्रपति। इसलिए, दुर्भावनापूर्ण आधार पर चुनौती, जैसा कि उठाया गया है, अस्थिर है। *[पैरा 34] [379-ए-सी]*

रीः राष्ट्रपति चुनाव *1975 (1)* एससीआर *504 = (1974) 2* एससीसी

33 - संदर्भित किया गया।

1.4 विशेष न्यायालय विधेयक के निर्णय से,

1978 , तीन व्यापक सिद्धांत उभरते हैंः *((i)* एक संदर्भ अस्पष्ट, सामान्य और अव्याख्यायित नहीं होना चाहिए, *(ii)* यह न्यायालय

लिखित संक्षिप्त विवरण और तर्कों के माध्यम से जा सकते हैं

कानूनी विवादों को कम करना, और *(iii)* जब

प्रश्न अनिर्दिष्ट और समझ से बाहर हो जाता है,

अनुत्तरित संदर्भ को वापस करने का जोखिम पैदा होता है। *[* पैरा

30] [377 - डी-ई*]*

रीः विशेष न्यायालय विधेयक, *1978 (2)* एस. सी. आर. *476 =*

(1979) 1 एस. सी. सी. *380; 1964* का विशेष संदर्भ संख्या *1*

*("*केशव सिंह*), [1965] 1* एस. सी. आर. *413 320* सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्टों को संदर्भित करता है।

[2012] 9 एस सी आर।

1.5 इस तथ्य से कोई इनकार नहीं है कि समग्र रूप से

संदर्भ 'संदेह' शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। ऐसा भी नहीं है

संविधान की किसी भी अनुसूची में प्रावधान किया गया हैसंदर्भ कैसे तैयार किया जाना है। शब्द का प्रयोग

'किसी संदर्भ में 'संदेह' भी संवैधानिक नहीं है।

आदेश या आदेश। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि 'संदेह' शब्द का उपयोग एक आवश्यक शर्त है

कला के तहत बनाए रखने योग्य संदर्भ। *143 (1) .* इसके अलावा,

तत्काल संदर्भ का प्रश्न संख्या *1* न तो अस्पष्ट है।

न ही सामान्य और न ही अनिर्दिष्ट, लेकिन के दायरे में है

समझ जो कानून के प्रश्न से संबंधित है। यह एक 'संदेह' व्यक्त करता है और न्यायालय की राय मांगता है

उस सवाल पर, दूसरों के अलावा। *[* पैरा *27* और *32] [374]*

जी-एच*; 375-*ए*; 378-*बी*]*

पी. रामनाथ अय्यर, द मेजर लॉ लेक्सिकन, चौथा संस्करण। *;*

संक्षिप्त ऑक्सफोर्ड शब्दकोश *(*दसवां संस्करण*);* और काले का कानून

शब्दकोश-संदर्भित।

1.6 जहाँ तक फाइलिंग और निकासी का प्रभाव है

2 जी मामले में निर्णय के खिलाफ भारत संघ द्वारा समीक्षा आवेदन *

तत्काल संदर्भ का संबंध है, एक अंतर है

समीक्षा में इस न्यायालय द्वारा प्रयोग की गई अधिकारिता और उत्तर देने में प्रयोग किए गए विवेकाधिकार के बीच

कला के तहत संदर्भ। *143 (1)* संविधान से। एक समीक्षा

मूल रूप से अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है

किसी निर्णय की समीक्षा और बीच-बीच में पारित डिक्री या आदेश

वे पार्टियाँ। लेकिन, जब कार्यपालिका द्वारा इस न्यायालय की राय मांगी जाती है, तो वह संवैधानिक व्यवस्था का सहारा लेती है।

शक्ति, वही पूरी तरह से एक अलग पायदान पर खड़ा है। एक समीक्षा विशिष्ट है और विवाद के लिए पक्षों के अधिकारों को उसमें निपटाया जाता है; जबकि एक संदर्भ

संदर्भ की शर्तों को ध्यान में रखते हुए जवाब दिया जाता है

और जांच करना कि क्या वही संतुष्ट करता है

के तहत नियोजित भाषा में निहित आवश्यकताएँ

कला. *143 (1)* संविधान से। इसलिए, केवल इसलिए कि *321*

आरई: *2012* का विशेष संदर्भ संख्या *1*

एक समीक्षा दायर की गई थी और वापस ले ली गई थी और पाठ में

कथन उक्त मामले से संबंधित है, वही होगा

के अभ्यास के लिए प्रतिबंध या बाधा नहीं होना

संदर्भ का उत्तर देने का विवेकाधिकार। *[* पैरा *33] [378*-सी-एच*]*

*** जनहित याचिका और अन्य के लिए केंद्र। बनाम यूनियन ऑफ

भारत और ओआरएस। *(2012) 3* एससीआर *147 = (2012) 3* एससीसी *1*-संदर्भित

को।

1.7 रखरखाव पर आपत्ति के संबंध में

यह संदर्भ कि यह अस्थिर करने का एक अप्रत्यक्ष प्रयास है

और *2* जी मामले में फैसले को पलट दें, शुरुआत में यह ध्यान दिया जा सकता है कि यह *2* जी मामले की ओर से कहा गया है।

भारत सरकार ने कहा कि वह सवाल नहीं उठा रही है *2* जी मामले में निर्देशों की शुद्धता, जहाँ तक

स्पेक्ट्रम के आवंटन का संबंध है और वास्तव में,

सरकार इसे लागू करने की प्रक्रिया में है,

अक्षर और आत्मा में। *[* पैरा *35-36] [379*-सी-डी; ई-एफ*]*

1.8 जहाँ तक किसी निर्णय पर पुनर्विचार करने का संबंध है, वहाँ हैं

दो सीमाएँ-एक अधिकार क्षेत्र और दूसरा स्वयं

थोपा गया। पहली सीमा यह है कि इस न्यायालय का निर्णय केवल कला के तहत समीक्षा की जा सकती है। *137* या एक उपचारात्मक याचिका

और किसी अन्य तरीके से नहीं। एक बार पार्टियों के बीच एक समझौता हो जाता हैतय किया, ऑपरेटिव डिक्री केवल में खोला जा सकता है

समीक्षा करें। एक पूर्ववर्ती के रूप में निर्णय को रद्द करना-करता है डिक्री को फिर से न खोलें। दूसरी सीमा, एक स्वयं

न्यायिक अनुशासन का अधिरोपित नियम, यह था कि

किसी कानूनी मुद्दे पर न्यायालय की राय अपील में बैठने का गठन नहीं करती है, बल्कि केवल अपवादात्मक मामलों में की जाती है।

सार्वजनिक शरारत पैदा करना। वास्तव में, ए का ओवररुलिंगकानून का सिद्धांत अपीलीय अधिकार क्षेत्र का परिणाम नहीं है, बल्कि इसकी अंतर्निहित शक्ति का परिणाम है। यह स्वाभाविक है

शक्ति का प्रयोग तब तक किया जा सकता है जब तक कि पिछली डिक्री बनाम यह अंतर-पक्षीय रूप से प्रभावित नहीं होता है।

[पैरा *45-47] [386-*डी *322* सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट *[2012] 9* एस. सी. आर.

एच*; 387-*ए-सी*]*

बंगाल इम्युनिटी कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य *(1955) 2* एस. सी. आर. *603;* कावेरी जल विवाद

न्यायाधिकरण *1991 (2)* पूरक। एससीआर *497 = 1993* सप्लीमेंट *(1)* एससीसी

*96 (II) ("*कावेरी*-II");* तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु राज्य

कर्नाटक और ओआरएस। *1991 (2)* एस. सी. आर. *501 = 1991* पूरक *(1)* एस. सी. सी.

240 (" कावेरी *1 ")* और रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा औरएन. आर. *2002 (2)* एससीआर *1006 = (2002) 4* एससीसी *388-*संदर्भित

1.9 इस न्यायालय के निर्णयों से, यह है

यह प्रदर्शित किया जा सकता है कि संदर्भ का मनोरंजन करते हुए कला. *143 (1)* , यह न्यायालय पहले के किसी निर्णय पर विचार कर सकता है।

पूर्व निर्णय पर ध्यान देना अनुज्ञेय है। कि इसके अलावा, कोई इस तथ्य से अनजान नहीं हो सकता है कि दायरा

दूसरे न्यायाधीशों के मामले में सीमित न्यायिक समीक्षा, जो अन्यथा काफी प्रतिबंधित है, थोड़ी सी थी।

न्यायालय की राय में राष्ट्रपति के संदर्भ का विस्तार किया गया। *[पैरा 58] [395-डी-ई]*

पुनः में - विशेष न्यायालय विधेयक, *1978 (2)* एस. सी. आर. *476*

(1979) 1 एस. सी. सी. *380,* पुनः दिल्ली विधि अधिनियम, *1912,* अजमेर-मेरवाड़ा *(*विधियों का विस्तार*)* अधिनियम, *1947* और

सी राज्य *(*कानून*)* अधिनियम, *1950 [1951]* एस. सी. आर. *747,* जतिंद्र नाथ

गुप्ता बनाम। बिहार और ओआरएस का प्रांत। *[1949-50]* एफ. सी. आर. *595 1964 [1965]* का विशेष संदर्भ सं. *1* एस. सी. आर.

*41 ("*केशव सिंह *"),* गुणपति केशवरम रेड्डी बनाम।

एम एस एम शर्मा बनाम श्री श्री कृष्ण सिन्हा और अन्य। *[1959]* सप. *1* एस. सी. आर. *806 ("*शर्मा*"),* उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता

ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन और ओआरएस। बनाम भारत संघ *(1993) 4* एस. सी. सी. *441,1998* का विशेष संदर्भ सं. *1* री. *1998 (2)*

पूरक। एस. सी. आर. *400 = (1998) 7* एस. सी. सी. *739 ("*द्वितीय न्यायाधीश मामला*"),* और डॉ. एम. इस्माइल फारूकी और अन्य। बनाम भारत संघ और

ओआरएस। *(1994) 6* एस. सी. सी. *360-*संदर्भित।

1.10 इस न्यायालय के निर्णयों के विश्लेषण से, *323*

आरई: *2012* का विशेष संदर्भ संख्या *1*

यह बहुत स्पष्ट है कि यह न्यायालय सम्मानपूर्वक अस्वीकार कर देगा

एक संदर्भ का जवाब देने के लिए यदि यह अनुचित, अस्वीकार्य है और

अवांछनीय*;* या तैयार किए गए प्रश्नों में विशुद्ध रूप से

सामाजिक-आर्थिक या राजनीतिक कारण, जिनके पास कोई कारण नहीं है

के किसी भी प्रावधान के साथ जो भी संबंध

संविधान या अन्यथा कोई संवैधानिक नहीं है।

महत्व; या जवाब देने में असमर्थ हैं; याकिसी भी उद्देश्य को पूरा नहीं करेगा; या वहाँ आधिकारिक है

इस न्यायालय की घोषणा जो पहले ही निर्णय ले चुकी है

प्रश्न का उल्लेख किया गया। *[पैरा 60] [395-एच; 396-ए-बी]*

1.11 हाथ में मामले में, संदर्भ बताता है कि

नीलामी के संचालन के संबंध में दूरगामी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निहितार्थ उत्पन्न हुए हैं औरमें दूरसंचार उद्योग का विनियमन

निर्णय *(2* जी मामला*)* के अनुसार जो प्रभावित कर सकता है

दूरसंचार उद्योग में और अन्यथा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह

इस देश में अन्य क्षेत्र। संदर्भ में यह भी कहा गया है

कि कानून के जो सवाल उठे हैं वे बहुत बड़े हैं

सार्वजनिक महत्व और देश के विकास के लिए दूरगामी परिणाम हैं और इसलिए, यह हैइस न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन समझा गया। संदर्भ के प्रश्न संख्या *1* में व्याख्या शामिल है।

कला के तहत निहित एक संवैधानिक सिद्धांत। *14* संविधान और यह बहुत सार्वजनिक महत्व का है क्योंकि यह

आबंटन/अलगाव/निपटान/वितरण से संबंधित

प्राकृतिक संसाधन। *[पैरा 28* और *61] [375-एच; 376-ए-सी]*

1.12 इसलिए, इस न्यायालय का विचार है कि जब तक

स्पेक्ट्रम के आवंटन के संबंध में निर्णय के रूप में

लाइसेंस अछूते हैं, यह न्यायालय इसके अधिकार क्षेत्र में है

2 जी मामले में निर्णय के अनुपात का मूल्यांकन और स्पष्टीकरण करना। इसलिए, तथ्य यह है कि संदर्भ की आवश्यकता हो सकती हैअदालत ने जो कुछ कहा है उससे कुछ अलग कहा है

2 जी मामले में कानून के प्रस्ताव के रूप में वर्णित, नहीं कर सकते

संदर्भ की रखरखाव की जड़ पर प्रहार करें। नतीजतन, यह न्यायालय मानता है कि संदर्भ *324* सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट *[2012] 9* एस. सी. आर. है।

के अनुपात पर इसके प्रभाव के बावजूद बनाए रखने योग्य

2 जी मामला, जब तक उस मामले में निर्णय अंतर है

भागों को अप्रभावित छोड़ दिया जाता है। *[* पैरा *62] [396*-ई-जी*]*ऑन मेरिट्स

2.1 कला. *141* संविधान में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित 'कानून' सभी के लिए बाध्यकारी है

भारत के क्षेत्र के भीतर की अदालतें। 'घोषित कानून'

इसे कानून के एक सिद्धांत के रूप में समझा जाना चाहिए जो उत्पन्न होता है

किसी निर्णय से, या किसी कानून या निर्णय की व्याख्या से

उच्चतम न्यायालय द्वारा, जिसके आधार पर मामले का निर्णय लिया जाता है।

इसलिए, 'घोषित कानून' वह सिद्धांत है जिस पर विचार किया गया है।के प्रकाश में समग्र रूप से एक निर्णय का पढ़ना

उठाए गए प्रश्न जिन पर मामले का निर्णय लिया जाता है। इस प्रकार, एक निर्णय में घोषित 'कानून', जो बाध्यकारी है

न्यायालय, निर्णय का अनुपात निर्णय होता है। यह वह है

मामला तय हो जाता है, जिसके संबंध में पता लगाया जाना हैविषय-निर्णय का विषय। *[* पैरा *66] [397*-ई-एच*;*

398 - ए*]*

फिदा हुसैन और ओआरएस। बनाम मुरादाबाद विकास

प्राधिकरण और ए. एन. आर. *2011 (9)* एससीआर *290 = (2011) 12* एससीसी *615;*

अम्बिका क्वारी वर्क्स बनाम गुजरात राज्य और अन्य। *1987 (1)* एस. सी. आर. *562 = (1987) 1* एस. सी. सी. *212* और आय आयुक्त

कर बनाम सन इंजीनियरिंग वर्क्स *(*पी*)* लिमिटेड *1992 (1)* पूरक। एससीआर

732 = 1992 (4) एस. सी. सी. *363;* इस्लामी शिक्षा अकादमी और

एन. आर. बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य। *(2003) 6* एससीसी *697*-आश्रित

पर

भारत संघ बनाम अमृत लाल मनचंदा और अन्न। *(2004) 3*

एस. सी. सी. *75;* उड़ीसा राज्य और अन्य। बनाम मो. इलियास *2005 (5)* पूरक।

एस. सी. आर. *395 = 2006 (1)* एस. सी. सी. *275*-संदर्भित।

"न्यायमूर्ति बेंजामिन द्वारा न्यायिक प्रक्रिया की प्रकृति

कार्डोजो-संदर्भित।

2.2 325 के पैराग्राफ *85* और *89* को पढ़ने पर

आरईः *2012* का विशेष संदर्भ संख्या *1*

2 जी मामले में निर्णय, यह देखा जा सकता है कि संदर्भ देते समय

'सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत' की अवधारणा पर जोर दिया गया था

समानता, व्यापक सार्वजनिक भलाई के सिद्धांत पर आधारित,

एक पारदर्शी और निष्पक्ष पद्धति को अपनाना, अवसर प्रतिस्पर्धा; और किसी भी अवसर से बचने के लिए

समान रूप से स्थित आवेदकों का दावा। सौदा करते समय

स्पेक्ट्रम जैसे प्राकृतिक संसाधनों के अलगाव के साथ, यह था

कहा कि यह सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य है कि वितरण के लिए एक गैर-भेदभावपूर्ण तरीका अपनाया जाए और अलगाव जिसका परिणाम अनिवार्य रूप से होगा

राष्ट्रीय/लोक हित का संरक्षण। पैराग्राफ *94* और

95 सुझाव है कि न्यायालय मामले पर विचार नहीं कर रहा थासामान्य रूप से नीलामी का, लेकिन विशेष रूप से वितरण में अपनाई गई उन विधियों की वैधता का मूल्यांकन करना

सितंबर *2007* से मार्च *2008* तक स्पेक्ट्रम। यह भी है

यह ध्यान देने योग्य है कि नीलामी का संदर्भ में किया गया है

बाद के पैराग्राफ *(96)* में सवार के साथ 'शायद'। इसमें है। यह देखा गया है कि "निष्पक्ष और निष्पक्ष रूप से आयोजित एक विधिवत प्रचारित नीलामी शायद सबसे अच्छा तरीका है

इस बोझ का निर्वहन करना "। यह सच है कि कोई निर्णय नहीं है

एक कानून के रूप में पढ़ा जाना है, लेकिन साथ ही, जब यह है

महत्व प्राप्त करते हैं। यह बताता है कि प्राकृतिक विलयन के लिए नीलामी की सिफारिश

या ब्लैंकेट स्टेटमेंट सभी प्राकृतिक में लागू होता है संसाधन, लेकिन बस पहली बार में किया गया एक निष्कर्ष

प्राकृतिक संसाधनों के निपटान में नीलामी जैसी विधि के आकर्षण पर। *'शायद'* शब्द के चयन से पता चलता है कि न्यायालय ने स्थितियों पर विचार किया

नीलामी के अलावा किसी अन्य विधि की आवश्यकता है जिसकी कल्पना की जा सकती है

और वांछनीय। इसके अलावा, अंतिम निष्कर्षों का सारांश दिया गया

फैसले *(*एस. सी. सी.*)* के पैराग्राफ *102* में नीलामी के एकमात्र अनुमेय और अधिकार के भीतर होने का कोई उल्लेख नहीं है।

प्राकृतिक संसाधनों के निपटान के लिए विधि*;* निष्कर्ष हैं

स्पेक्ट्रम के मामले तक सीमित। मामले में न्यायालय ने *326*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2012] 9 एस सी आर।

अलगाव के लिए एकमात्र अनुमेय विधि या तरीका है */* प्राकृतिक संसाधनों का आवंटन, वही होगा

सारांश के अंत में एक उल्लेख मिला

निर्णय। *[* पैरा *75,76,78* और *79] [402-G; 403-A-B; 404-G*

एच*; 405-*ए*-*ई*]*

एम. सी मेहता बनाम कमल नाथ और अन्य। *1996 (10)* पूरक।

एस. सी. आर*. 12 = 1997 (1)* एस. सी. सी*. 388;* जमशेद होर्मुसजी वाडिया बनाम।

न्यासी मंडल, मुंबई बंदरगाह और ए. एन. आर*. 2004 (1)* एससीआर *483 = 2004 (3)* एससीसी *214;* बौद्धिक मंच, तिरुपति बनाम राज्य

फोमेंटो रिसॉर्ट्स एंड होटल्स लिमिटेड एंड एन. आर. बनाम मिंगुएल मार्टिन्स और ओआरएस। *2009 (3)* एससीआर *1 = (2009) 3* एससीसी *571* और

रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड बनाम रिलायंस इंडस्ट्रीज

सीमित *2010 (5)* एससीआर *704 = 2010 (7)* एससीसी *1;* अखिल भारतीय

उपभोक्ता कांग्रेस बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य।

2011 (5) एससीआर *77 = (2011) 5* एससीसी *29,* सच्चिदानंद पांडे

& एन. आर. बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य। *1987 (2)* एस. सी. आर. *223 = (1987) 2* एस. सी. सी. *295*-संदर्भित।

इलिनोइस सेंट्रल रेलरोड कं। बनाम। के लोग

इलिनोइस राज्य *36* एल ईडी *1018: 146* अमेरिका *387 (1892)*-संदर्भित

को

2.3 2 जी मामला अन्य कानूनों पर भी विचार नहीं करता है

और निर्णय जो विधियों को निर्धारित करते हैं, इसके अलावाप्राकृतिक संसाधनों के वितरण के लिए नीलामी; कुछ

कि यह किया होगा, मामले में, यह एक बनाने का इरादा सभी प्राकृतिक संसाधनों पर नीलामी लागू करने के रूप में व्यापक दावा। इसलिए, पैरास *94* से *96* में टिप्पणियाँ

स्पेक्ट्रम के विशिष्ट मामले से परे लागू नहीं हो सका,

जिसे *2* जी मामले में घोषित कानून के अनुसार, केवल नीलामी द्वारा अलग किया जाना है और कोई अन्य तरीका नहीं है। इस प्रकार, *2* जी मामला आवंटन के तरीकों से संबंधित नहीं है।

प्राकृतिक संसाधनों के लिए, स्पेक्ट्रम के अलावा। *[* पैरा *80-81]*

[405 - एच*; 406*-ए-सी*]* आरईः

2012 का विशेष संदर्भ संख्या *1*

327

3.1 संदर्भ द्वारा इस न्यायालय की राय मांगी जाती है।

अन्य विधियों की अनुमति के सीमित बिंदु पर

प्राकृतिक संसाधनों के अलगाव के लिए नीलामी से अधिक, अन्य स्पेक्ट्रम से अधिक। *[पैरा 82] [406-डी-ई]*

3.2 संबंधित आपत्ति के संबंध में

दुर्लभ प्राकृतिक संसाधनों के लिए विशेष मामला केवलव्यावसायिक दोहन। हालाँकि, इस न्यायालय ने

किसी संदर्भ की विषय वस्तु को वर्गीकृत करने की अधिकारिता,

यदि इसके लिए कोई वास्तविक मामला मौजूद है। *[पैरा 83] [406-जी-एच; 407-ए*

बी-डी*]*

3.3 2 जी मामले में, दो अवधारणाएँ हैं, "सार्वजनिक विश्वास"।

बौद्धिक मंच ने माना है कि जब सकारात्मककर्तव्यों को एक निरर्थक कोण से निर्धारित किया गया है, सिद्धांत वास्तव में आयोजित संपत्ति के अलगाव को प्रतिबंधित नहीं करता है।

एक सार्वजनिक न्यास के रूप में, लेकिन उच्च स्तर की न्यायिक जांच को अनिवार्य करता है। *[पैरा 85* और *87] [407-जी-एच; 409-ई; 410-बी]*

एम. सी मेहता बनाम कमल नाथ और अन्य। *1996 (10)* पूरक।

एससीआर *12 = (1997) 1* एससीसी *388*, बौद्धिक मंच, तिरुपति

बनाम। ए. पी. और अन्य का राज्य। *(2006) 3* एससीसी *549*-संदर्भित

इलिनोइस सेंट्रल रेलरोड कं। बनाम। के लोग

इलिनोइस राज्य *36* एल ईडी *1018: 146* अमेरिका *387 (1892)*-संदर्भित

3.4 सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत एक विशेष क्षेत्र के साथ एक विशिष्ट सिद्धांत है और इसे सावधानीपूर्वक लागू किया जाना चाहिए।*[पैरा 90] [411-सी]*

" प्राकृतिक संसाधन कानून में सार्वजनिक न्यास सिद्धांतः जोसेफ द्वारा प्रभावी न्यायिक हस्तक्षेप। एल. सैक्स;

और संपत्ति की अवधारणाओं को बदलना औरप्राकृतिक संसाधनों में संप्रभुताः

328 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्टों पर सवाल उठाना

[2012] 9 एस सी आर।

सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत "रिचर्ड जे. लाज़र द्वारा,संदर्भित किया गया है

3.5 विधायिका और कार्यपालिका संविधान के प्रति जवाबदेह हैं और यही वह जगह है जहाँ न्यायपालिका,संविधान के संरक्षक को इसकी रूपरेखा खोजना चाहिए

प्राकृतिक संसाधनों, विशेष रूप से कला के निपटान की शक्तियाँ। *14* और कला। *39 (* बी*)*। *[* पैरा *92] [413-*ए-बी*]*

दिल्ली नगर निगम बनाम बिड़ला कपास, कताई

और वीविंग मिल्स, दिल्ली और अन्न। *[1968] 3* एससीआर *251* पर भरोसा किया गया

पर।

राजा राम पाल बनाम माननीय अध्यक्ष, लोकसभा और अन्य।

(2007) 3 एस. सी. सी. *184*-संदर्भित।

रे मेंः दिल्ली विधि अधिनियम, *1912*-निर्दिष्ट

मैनडेट ऑफ आर्ट। *14 : 4.1* कला का अंतर्निहित उद्देश्य। *14* भारत के संविधान का प्रावधान सभी व्यक्तियों, नागरिकों या गैर-नागरिकों के लिए सुरक्षित है।

संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित स्थिति और अवसर की समानता। समानता का अधिकार

इससे पहले कि कानून सभी विधायी और कार्यपालिका से सुरक्षित हो

भाषा के बाद से भेदभाव के माध्यम से अत्याचार

*Art.14 "*राज्य*"* शब्द का उपयोग करता है जिसमें *Art.12* के अनुसार, शामिल हैं

कार्यकारी अंग। इसके अलावा, *Art.14* को व्यक्त किया जाता है

पूर्ण शर्तें और इसका प्रभाव कला द्वारा *Art.19 (1)* पर लगाए गए प्रतिबंधों से कम नहीं होता है। *19 (2)*

(6) . हालाँकि, इस तरह की अनुपस्थिति के बावजूद

प्रतिबंध, कुछ परीक्षण, जैसे वर्गीकरण परीक्षण, *'* मनमानेपन का सिद्धांत इसके माध्यम से तैयार किया गया है

जाँचने के लिए न्यायिक निर्णय कि *Art.14* का उल्लंघन किया गया है या नहीं। अभिव्यक्तियाँ *'*मनमानी*'* और *'*अनुचितता*'*

एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया गया है और वास्तव में, एक है दूसरे के संदर्भ में परिभाषित किया गया है। *[* पैरा *94* और *101] [413]*

डी-एफ*; 414-*ए*; 418-*बी-सी*] 329*

आरईः *2012* का विशेष संदर्भ संख्या *1*

बशेशर नाथ बनाम। आयकर आयुक्त,

दिल्ली और राजस्थान और अन्न. *1959* पूरक *(1)* एससीआर *528;* बुधन

चौधरी और ओआरएस। बनाम बिहार राज्य ए. आई. आर. *1955* एस. सी. *191;* श्री

राम कृष्ण डालमिया बनाम। श्री न्यायमूर्ति एस. आर. तेंदुलकर और

ओआरएस। *[1959] 1* एस. सी. आर. *279;* ई. पी. रोयप्पा बनाम तमिल राज्य

नाडू और अन्न। *1974 (2)* एस. सी. आर. *328 = (1974) 4* एस. सी. सी. *3;* मेनका

गांधी बनाम भारत संघ और ए. एन. आर. *1978 (2)* एससीआर *621 = (1978)*

1 एस. सी. सी. *248* शर्मा ट्रांसपोर्ट बनाम। ए. पी. और अन्य की सरकार

2001 (5) पूरक। एससीआर *390 = (2002) 2* एससीसी *188;* ओम कुमार

& ओआरएस। बनाम भारत संघ *2000 (4)* पूरक। एससीआर *693 = (2001)*

2 एस. सी. सी. *386;* एयर इंडिया बनाम नरगेश मिर्जा *1982 (1)* एस. सी. आर. *438*

(1981) 4 एस. सी. सी. *335;* अजय हसिया और अन्य। बनाम खालिद मुजीब

सेहरावर्दी और ओआरएस। *1981 (2)* एससीआर *79 = (1981) 1* एससीसी *722;* और

भारत और ओआरएस। *1979 (3)* एससीआर *1014 = (1979) 3* एससीसी *489:* एयर *1979* एस. सी. *1628*-निर्दिष्ट।

4.2 निर्णयों की प्रवृत्ति की जांच से यह है

स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि राज्य की कार्रवाई, चाहे वह

उदारता के वितरण, अनुबंधों के अनुदान या

भूमि के आवंटन का परीक्षण टचस्टोन पर किया जाना है

Art.14। किसी कानून को मनमाना होने के कारण निरस्त नहीं किया जा सकता है।

संवैधानिक दुर्बलता की ओर इशारा किए बिना। इसलिए,

संवैधानिक दुर्बलताओं के लिए राज्य की कार्रवाई का परीक्षण किया जाना चाहिए *qa Art.14*। कार्रवाई निष्पक्ष, उचित, गैर-उचित होनी चाहिए।

पदोन्नति के लिए भेदभावपूर्ण, पारदर्शी, गैर-मनमौजी, निष्पक्ष, पक्षपात या भाई-भतीजावाद के बिना

स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और न्यायसंगत उपचार। इसे होना चाहिए।

उन मानदंडों के अनुरूप जो तर्कसंगत हैं, जिनके साथ सूचित किया गया हैकारण और जनहित आदि द्वारा निर्देशित। ये सभी सिद्धांत *Art.14* की मौलिक अवधारणा में निहित हैं। यह *Art.14* का आदेश है। *[* पैरा *105] [421*-बी-ई*]*

ए. पी. और अन्य का राज्य। बनाम मैकडॉवेल एंड कंपनी और अन्य। *1996 (3)*

एस. सी. आर. *721 = (1996) 3* एस. सी. सी. *709*-संदर्भित।

'नीलामी*'* एक संवैधानिक आदेशः

4.3 प्राकृतिक *330* सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट *[2012] 9* एस. सी. आर. के निपटान की एक विधि के रूप में नीलामी।

संसाधनों को संवैधानिक जनादेश घोषित नहीं किया जा सकता है।

भारत के संविधान के *Art.14* के तहत। सबसे पहले, *Art.14* किसी व्यक्ति के लिए सकारात्मक और नकारात्मक अधिकार हो सकते हैं,

लेकिन राज्य के संबंध में, यह केवल नकारात्मक है

शर्तें*;* राज्य के खिलाफ एक चेतावनी की तरह जो

राज्य को ऐसी कार्रवाई करने से रोकता है जो हो सकती है

मनमाना, अनुचित, मनमौजी या भेदभावपूर्ण। कला*. 14 ,* इसलिए, लेने के खिलाफ राज्य के लिए एक निषेधाज्ञा है

इसे विशेष कदम उठाने के लिए आदेश देने के बजाय कुछ प्रकार के कार्य। नीलामी के आदेश को इसमें पढ़ें

इस प्रकार, योजना पूरी तरह से इरादे के विपरीत होगी।

अपनी सादा भाषा से स्पष्ट लेख का। दूसरा,

एक संवैधानिक जनादेश एक पूर्ण सिद्धांत है जो

सभी स्थितियों में लागू किया जा सकता है; इसमें लागू नहीं किया जा सकता है कुछ और दूसरों में परीक्षण नहीं किया गया। निरपेक्ष सिद्धांत है

फिर मामला दर मामला आधार पर यह देखने के लिए आवेदन किया गया कि कौन सा

कार्रवाई संवैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करती है

सिद्धांत और जो नहीं करते हैं। *[* पैरा *106-107] [421-F-H; 422*

ए-सी*]*

" न्यायमूर्ति के. सुब्बा राव द्वारा कुछ संवैधानिक समस्याएं; न्यायमूर्ति के. के. द्वारा "लोकतंत्र, समानता और स्वतंत्रता"।

मैथ्यू-संदर्भित

4.4 समानता केवल नीलामी तक सीमित नहीं हो सकती है।

हर परिदृश्य में इसका परीक्षण किए बिना। कोई परीक्षण नहीं कर सकता है

आवश्यक तत्वों के संदर्भ में किसी कानून की वैधता

आदर्श लोकतंत्र, वास्तव में में शामिल

संविधान। *[* पैरा *110] [423*-डी-ई*]*

परम पूज्य केशवानंद भारती श्रीपदगलवरु बनाम।

केरल राज्य और अन्र। *1973* पूरक। एस. सी. आर. *1 = (1973) 4* एस. सी. सी. *225;* पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार *1952*

एससीआर *284;* इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण *1976* एससीआर *347 = 1975 (* एस. सी. सी. *1*-संदर्भित

कोटच बनाम। पायलट कमांडर *330* यू. एस. *552*-संदर्भित।

331

आरईः *2012* का विशेष संदर्भ संख्या *1*

4.5 न्यायालयों को किसी क़ानून को अमान्य घोषित करने की स्वतंत्रता नहीं है।

क्योंकि उनकी राय में यह भावना के खिलाफ है

संविधान। न्यायालय सीमा घोषित नहीं कर सकते हैं या होने की धारणा के तहत संवैधानिक आवश्यकता

कुछ आदर्श मानक की खोज की। इसके अलावा, एक संवैधानिक

सिद्धांत एक सटीक सूत्र तक सीमित नहीं होना चाहिए लेकिन

सटीक पर लागू एक अमूर्त सिद्धांत होना चाहिए परिस्थितियाँ। *[पैरा 110] [423-एफ]*

4.6 एक के रूप में नीलामी आयोजित करने का परिणाम

संवैधानिक जनादेश प्रत्येक को रद्द करना होगा सामाजिक प्रयासों सहित इससे विचलित होने वाली कार्रवाई,

कल्याणकारी योजनाएं और प्रचार नीतियाँ। यह होगा

केवल एक संवैधानिक सिद्धांत के रूप में नीलामी प्राप्त करने के लिए अजीब

व्यापक और सामान्य से स्थितियों के एक सीमित समूह के लिए

Art.14 की घोषणा। संवैधानिक शक्ति

न्यायनिर्णयन मामला न्यायनिर्णयन के मामले में निहित है और इसलिए, नीलामी को संवैधानिक स्तर पर नहीं बढ़ाया जा सकता है।

आदेश दिया। *[पैरा 110] [423-एफ-जी; 424-ए-बी]*

4.7 अंत में, नीलामी को संवैधानिक रूप से पढ़ना

आदेश अस्वीकार्य होगा क्योंकि इस तरह के

दृष्टिकोण एक अन्य संवैधानिक सिद्धांत को विकृत कर सकता है

Art.39 (b) में सन्निहित, जो अनिवार्य करता है कि

प्राकृतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण ऐसा होना चाहिए

सामान्य भलाई के लिए सर्वोत्तम रूप से वितरित किया जाता है। *Art.37*

यह प्रावधान करता है कि भाग *IV* के प्रावधान नहीं होंगे

किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय, लेकिन उसमें निर्धारित सिद्धांत फिर भी शासन में मौलिक हैं।

राज्य का यह कर्तव्य होगा कि - कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करें। *[पैरा 111] [424-सी*

जी]

वस्तु पर थोपा जाता है न कि साधन पर। द. 'वितरण' को नियंत्रित करने वाला व्यापक और अंतर्निहित सिद्धांत आम भलाई को आगे बढ़ाना है।

लेकिन *332* सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट *[2012] 9* एस. सी. आर. के लिए।

उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, संविधान का उपयोग करता है

सामान्य शब्द 'वितरण'। वितरण की व्यापक रूपरेखा होती है और यह केवल एक अर्थ तक सीमित नहीं हो सकता है।

विधि अर्थात नीलामी। इसमें ऐसे सभी तरीकों की परिकल्पना की गई है।प्राकृतिक संसाधनों के वितरण/आवंटन के लिए उपलब्ध

जो अंततः "आम भलाई" को कम करता है। *[* पैरा

112] [424 - एच*; 425-*ए-बी*]*

4.9 "वितरण" शब्द निस्संदेह व्यापक है।

आयाम और सभी शिष्टाचार और विधियों को शामिल करता है वितरण, जिसमें वर्ग, उद्योग शामिल होंगे,

क्षेत्र, निजी और सार्वजनिक अनुभाग आदि। *Art.39 (b)* की मूल प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, एक संकीर्ण अवधारणा

Art.14 के तहत समानता व्यापक अवधारणा को विफल कर सकती है

वितरण की, जैसा कि कला में कल्पना की गई है। *39 (* बी*)*। वहाँ नहीं हो सकता है,

इसलिए, एक ऐसी गुहा बनें जो "सामान्य भलाई" और "बड़ी" हो।

जनहित को संवैधानिक माना जाना चाहिए।

यथार्थ के योग्य वास्तविकता। *[* पैरा *115] [425-*एच*; 426-*ए

सी*]*

तमिलनाडु राज्य और अन्य। बनाम एल. अबू कावुर बाई और अन्य।

1984 (1) एससीआर *725 = (1984) 1* एससीसी *515-*संदर्भित

4.10 नीलामी अधिकतम करने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है।

राजस्व लेकिन राजस्व अधिकतमकरण हमेशा नहीं हो सकता है

सार्वजनिक भलाई के लिए सबसे अच्छा तरीका "। आम भलाई "

कला के तहत एकमात्र मार्गदर्शक कारक और एक मानक है। *39 (ख)* इसके लिए

प्राकृतिक संसाधनों का वितरण। यह स्पर्शशिला है

यह जाँचने के लिए कि क्या कोई नीति "सामान्य" के अधीन है

अच्छा "और यदि ऐसा होता है, चाहे कोई भी साधन अपनाया गया हो, यह स्पष्ट रूप से निहित सिद्धांत के अनुसार है

कला. *39 (बी)*। "सामान्य भलाई" के मानदंड को समग्र तरीके से समझना और सराहना करनी होगी। यह है।

स्पष्ट है कि जिस तरीके से आम भलाई है

सबसे अच्छा अधीन एक ऐसा मामला नहीं है जिसे किसी भी संवैधानिक मानदंड से मापा जा सकता है-यह इस बात पर निर्भर करेगा कि

सरकार का आर्थिक और राजनीतिक दर्शन।

राजस्व अधिकतमकरण एकमात्र तरीका नहीं है जिसमें *333*

आम भलाई को कम किया जा सकता है। राजस्व कहाँ है*?*

अधिकतमकरण एक नीति का उद्देश्य है, जिस पर विचार किया जा रहा है

क्या उस समय उस संसाधन को सबसे अच्छा तरीका होना चाहिए

आम भलाई के लिए, नीलामी एक होगी

बेहतर तरीके, हालांकि एकमात्र तरीका नहीं है।

जहाँ राजस्व अधिकतमकरण किसी नीति का उद्देश्य नहीं है।

वितरण के लिए नीलामी का सवाल ही नहीं उठेगा। राजस्व संबंधी विचार गौण स्थिति ग्रहण कर सकते हैं।

विकासात्मक विचारों के लिए। *[पैरा 116 और 119]*

[426 - डी-एफ; 427-एफ-एच; 428-ए]

कर्नाटक राज्य और अन्न। बनाम श्री रंगनाथ

रेड्डी और अन्न। *1978 (1)* एससीआर *641 = (1977) 4* एससीसी *471;*

बेनेट कोलमैन एंड कंपनी और ओआरएस। बनाम भारत संघ और अन्य।

1973 (2) एस. सी. आर. *757 = (1972) 2* एस. सी. सी. *788*-संदर्भित।

4.11 इसमें कोई संवैधानिक अनिवार्यता नहीं है

आर्थिक नीतियों का मामला। कला. *14* पूर्व-परिभाषित नहीं करता है संवैधानिक अधिदेश के रूप में कोई भी आर्थिक नीति। यहां तक कि

*39 (*बी*)* का जनादेश इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है

इसका अर्थ है सार्वजनिक भलाई के लिए अपनाया गया और व्यापक शब्द *'*वितरण*'* का उपयोग करता है, यह सुझाव देते हुए कि

वितरण की पद्धति निश्चित नहीं है। आर्थिक तर्क यह स्थापित करता है कि प्राकृतिक संसाधनों का अलगाव/आवंटन

सबसे अधिक बोली लगाने वाले के लिए जरूरी नहीं कि यह एकमात्र तरीका होआम भलाई को कम करने के लिए, और कभी-कभी, चल सकता है

सार्वजनिक भलाई के खिलाफ। इसलिए, इस पर बहुत कम जोर देने की आवश्यकता है

स्पष्ट रूप से एक संवैधानिक जनादेश नहीं है। *[* पैरा *120] [430*-बी-डी*] 4.12* अंत में, बाजार मूल्य, अर्थशास्त्र में, उस मूल्य का एक सूचकांक है जो एक बाजार किसी वस्तु के लिए निर्धारित करता है। हालांकि,

यह मूल्यांकन कई गतिशील चरों का एक कार्य है*;*

यह एक विज्ञान है, कानून नहीं। नीलामी सिर्फ एक है

ऐसे मूल्यांकन, नीलामी या किसी भी कार्य में चर शामिल होते हैं। प्रतिस्पर्धी बोली का अन्य रूप, एक आर्थिक जनादेश का गठन भी नहीं कर सकता है, एक संवैधानिक *334* सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट से बहुत कम

[2012] 9 एस सी आर।

आदेश। *[* पैरा *147] [444*-जी-एच*]*

4.13 अधिक बेहतर तरीका होने के बावजूद नीलामी

प्राकृतिक संसाधनों के अलगाव/आवंटन का, नहीं हो सकता है

सभी प्राकृतिक संसाधनों के अलगाव के लिए एक संवैधानिक आवश्यकता या सीमा माना जाता है और इसलिए, प्रत्येक

नीलामी के अलावा अन्य विधि को रद्द नहीं किया जा सकता है क्योंकिसंवैधानिक जनादेश को अधिकार से बाहर कर देता है। *[* पैरा *148] [445-*ए

बी*]*

नीलामी से कानूनी प्रावधानः

5.1 सरकार बार-बार भटकती रही है

नीलामी की प्रक्रिया और इस न्यायालय ने बार-बार

मनमानेपन और निष्पक्षता के सीमित दायरे पर *Art.14* और इसकी भूमिका उस हद तक सीमित है। अनिवार्य रूप से

जब भी नीति का उद्देश्य राजस्व के अलावा कुछ भी हो

अधिकतमकरण, कार्यपालिका को नीलामी के अलावा अन्य तरीकों को अपनाते हुए देखा जाता है। *[129] [434 -* ई-एफ*]*

सच्चिदानंद पांडे और अन्र। बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य। *(1987) 2* एससीसी *295;* एम. पी. ऑयल एक्सट्रैक्शन एंड ए. एन. आर. बनाम।

एम. पी. और अन्य का राज्य। *(1997) 7* एस. सी. सी. *592;* नेताई बैग और अन्य। बनाम।

डब्ल्यू. बी. और ओ. आर. एस. की स्थिति *(2000) 8* एस. सी. सी. *262;* एम. एंड टी. सलाहकार,

सिकंदराबाद बनाम एस. वाई. नवाब *(2003) 8* एससीसी *100;* हाजी टी. एम.

हसन रॉथर बनाम केरल वित्तीय निगम। *1988 (1)* एससीआर *1079 = (1988) 1* एस. सी. सी. *166;* विलियनूर लियार्काई पडुकप्पु

मैयम बनाम भारत संघ और अन्य। *1997 (1)* पूरक। एससीआर *671*

= (2009) 7 एस. सी. सी. *561-*पैरा *128* में संदर्भित।

5.2 कानूनी तर्क के अलावा अनिवार्य नीलामी भी आर्थिक तर्क के विपरीत हो सकती है। अलग-अलग

संसाधनों को अलग-अलग उपचार की आवश्यकता हो सकती है। बहुत बार, अन्वेषण और दोहन अनुबंध एक साथ किए जाते हैं।प्राकृतिक संसाधनों की खोज में भारी पूंजी की आवश्यकता के कारण। एक चिंता जोखिम उठाती है

इस तरह के अन्वेषण करने और भारी लागत केवल *335* खर्च होती है

आरईः *2012* का विशेष संदर्भ संख्या *1*

यदि यह खोजे गए संसाधन के उपयोग का आश्वासन दिया गया था;

एक विवेकपूर्ण व्यावसायिक उद्यम, खर्च नहीं करना चाहेगाअन्वेषण गतिविधियों में शामिल उच्च लागत और फिर

एक खुली नीलामी में उस संसाधन के लिए प्रतिस्पर्धा करें। इसका तर्क

यह पेटेंट में लागू होने के समान है। फर्मों को दिया जाता है

एक विशिष्ट उद्योग में। नीलामी से इसी तरह का विचलन इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि राज्य नीति का उद्देश्य क्या है

किसी उद्योग के घरेलू विकास को बढ़ावा देना। इस प्रकार,

नीलामी सभी के अलगाव का एकमात्र मानदंड नहीं हो सकता है।

प्राकृतिक संसाधन। *[* पैरा *130-131] [434-G-H; 435-A-D]*

मेसर्स कस्तूरी लाल लक्ष्मी रेड्डी बनाम जम्मू राज्य और

कश्मीर और अन्र। *1980 (3)* एससीआर *1338 = (1980) 4* एससीसी *1 -*

संदर्भित किया गया हैसंभावित दुर्व्यवहार की कृपाः

5.3 दुरुपयोग की संभावना आधार नहीं हो सकती है

एक विधि को निरस्त करना क्योंकि यह संविधान के अधिकार से बाहर है। यह वास्तविक दुरुपयोग ही है जिसे सामने लाया जाना चाहिएसंवैधानिक आधार पर परीक्षण किए जाने के लिए न्यायालय

प्रावधान। वास्तव में, यह कहा जा सकता है कि नीलामी में भी

दुरुपयोग की संभावना, आवंटन के किसी भी अन्य तरीके की तरह, लेकिन यह इसे घोषित करने का आधार नहीं हो सकता है

असंवैधानिक कार्यप्रणाली भी। *[* पैरा *135] [437-*डी

ई*]*

आर. के. गर्ग बनाम भारत संघ और अन्य। *1982 (1)* एससीआर *947 =*

(1981) 4 एस. सी. सी. 675; डी. के. त्रिवेदी और सन्स और अन्य। बनाम राज्य

गुजरात और ओआरएस। 1986 एस. सी. आर. 479 = (1986) पूरक एस. सी. सी. 20 संदर्भित।

[2012] 9 एस सी आर।

336 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नीति निर्णयों की न्यायिक समीक्षाः

6.1 नीतियों की समझदारी और सलाह ये हैं -

आम तौर पर न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी नहीं है जब तक कि

प्रावधान या मनमाना या तर्कहीन या शक्ति का दुरुपयोग।न्यायालय द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय को रद्द नहीं किया जा सकता है

सरकार केवल इसलिए कि उसे लगता है कि एक और निर्णय निष्पक्ष, या अधिक वैज्ञानिक या तार्किक होता, या

बुद्धिमान। इसके अलावा, यह एक कानून की वैधता है न कि इसकी प्रभावकारिता।

इसे चुनौती दी जा सकती है। उस क्षण के संदर्भ में

संदर्भ में, इस बात पर जोर देने की आवश्यकता है कि यह न्यायालय

विभिन्न का तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर सकते हैं प्राकृतिक संसाधनों के वितरण के तरीके और सुझाव

सबसे प्रभावी मोड, अगर पहली जगह में एक सार्वभौमिक प्रभावी विधि है। यह सम्मान करता है

ऐसे मामलों के लिए कार्यपालिका का अधिदेश और विवेक।

प्राकृतिक संसाधनों के निपटान से संबंधित कार्यप्रणाली स्पष्ट रूप से एक आर्थिक नीति है। यह जटिल है

आर्थिक विकल्प और अदालत में आवश्यक सुविधाओं का अभाव है।उन्हें बनाने के लिए विशेषज्ञता। जैसा कि बार-बार कहा गया है, इस न्यायालय का यह प्रयास नहीं हो सकता और न ही होगा कि

प्राकृतिक संसाधनों के निपटान के अन्य तरीकों की तुलना में नीलामी की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें। अदालत आदेश नहीं दे सकती

सभी तथ्यों और परिस्थितियों में पालन की जाने वाली एक विधि।

इसलिए, नीलामी, प्राकृतिक संसाधनों के निपटान का एक आर्थिक विकल्प, एक संवैधानिक जनादेश नहीं है। *[* पैरा

139 , 144 और *146] [440*-एफ*; 443*-डी*; 444*-बी-डी*]*

रुस्तम कावासजी कूपर बनाम भारत संघ *1970 (3)* एससीआर *530 = (1970) 1* एससीसी *248;* आर. के. गर्ग बनाम भारत संघ

& ओआरएस। *1982 (1)* एससीआर *947 = (1981) 4* एससीसी *675;* दिल्ली विज्ञान

फोरम और ओआरएस। बनाम भारत संघ और एएनआर। *1996 (2)* एससीआर *767 = (1996) 2* एससीसी *405;* पीयरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट

कं. लिमिटेड और ए. एन. आर. बनाम भारतीय रिजर्व बैंक *1992 (1)* एससीआर *406*

= (1992) 2 एस. सी. सी. *343;* प्रीमियम ग्रेनाइट और ए. एन. आर. बनाम राज्य

टी. एन. और ओआरएस. *1994 (1)* एससीआर *579 = (1994) 2* एससीसी *691* दिल्ली

विज्ञान मंच और अन्य। बनाम भारत संघ और एएनआर। *1996 (2)* एससीआर *337*

आरईः *2012* का विशेष संदर्भ संख्या *1*

767 = (1996) 2 एस. सी. सी. *405;* बाल्को कर्मचारी संघ *(*विनियमित*)* बनाम भारत संघ और अन्य। *2001 (5)* पूरक। एससीआर *511 = (2002)*

2 एस. सी. सी. *333;* मेसर्स प्राग आइस एंड ऑयल मिल्स एंड एन. आर. बनाम भारत संघ *[1978] 3* एस. सी. सी. *459;* और मध्य प्रदेश राज्य बनाम।नर्मदा बचाओ आंदोलन और अन्न। *2011 (6)* एससीआर *443 = (2011)*

7 एस. सी. सी. *639*-संदर्भित

6.2 हालांकि, अदालतें वैधता का परीक्षण कर सकती हैं और

इन विधियों की संवैधानिकता। जब उनसे पूछताछ की गई तो

न्यायालयों को विभिन्न न्यायालयों की कानूनी वैधता का विश्लेषण करने का अधिकार है।

वितरण का साधन और एक संवैधानिक उत्तर दें

किन विधियों के लिए अल्ट्रा वायर्स और इंट्रा वायर्स हैं

संविधान के प्रावधान। फिर भी, यह नहीं हो सकता है

और तुलना नहीं करेंगे कि कौन सी नीति दूसरी की तुलना में बेहतर है, लेकिन, यदि कोई नीति या कानून स्पष्ट रूप से इस हद तक अनुचित है कि

यह *Art.14* की निष्पक्षता आवश्यकता का उल्लंघन करता है

संविधान, न्यायालय इसे निरस्त करने में संकोच नहीं करेगा।

[पैरा *146] [444*-डी-एफ*]*

6.3 प्राकृतिक संसाधनों का अलगाव एक नीति है

इस प्रकार निर्णय और उसके लिए अपनाए गए साधन कार्यकारी विशेषाधिकार हैं। हालांकि, जब इस तरह का नीतिगत निर्णय किसी सामाजिक या कल्याणकारी उद्देश्य से समर्थित नहीं है,

और बहुमूल्य और दुर्लभ प्राकृतिक संसाधनों को अधिकतम निजी लाभ के वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए अलग किया जाता है।

उद्यमियों के अलावा अन्य साधनों को अपनाना

प्रतिस्पर्धी हैं और अधिकतम राजस्व मनमाना हो सकता है

और कला के प्रकोप का सामना करें। *14* संविधान से। इसलिए, एक निर्धारित करने या प्रतिबंधित करने के बजाय

विधि, निपटान के तरीकों की न्यायिक जांच

प्राकृतिक संसाधनों को प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर होना चाहिए,

तत्काल राय में सिद्धांत निकाले गए। ऐसा न कर पाने पर,

न्यायालय, न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग करते हुए, कार्यकारी कार्रवाई को मनमाना, अनुचित बताएगा।

कला के साथ अपनी दुश्मनी के कारण अनुचित और मनमौजी। *14* संविधान से। *[* पैरा *149] [445-* सी-ई*] 338* सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

[2012] 9 एस सी आर।

7.1 अंत में, पहले समूह के लिए इस न्यायालय का जवाब

पाँच प्रश्नों में से यह है कि नीलामी ही एकमात्र नहीं है।

सभी क्षेत्रों में और सभी परिस्थितियों में सभी प्राकृतिक संसाधनों के निपटान के लिए अनुमेय विधि। *[पैरा 150]*

[445 - एफ]

7.2 शेष प्रश्नों के संबंध में, उत्तर

उसी का मोड पर सीधा असर होगा

सरकार की ओर से दिया गया बयान कि यह नहीं है*2* जी मामले में निर्णय की शुद्धता पर सवाल उठाते हुए,

यह न्यायालय सम्मानपूर्वक उक्त का उत्तर देने से इनकार करता है।

सवाल करते हैं। *[पैरा 151] [445-जी-एच]*

पर जगदीश सिंह खेहर, जे *(सहमति):*

1.1 यह स्पष्ट है कि सरकार इस तथ्य के प्रति सचेत है कि कुछ प्राकृतिक संसाधनों का निपटान किया जाना चाहिए।

केवल नीलामी द्वारा किया गया। इसलिए, पहले प्रश्न में

इसे प्राप्त करने के लिए राष्ट्रपति के संदर्भ को समझना चाहिए।इस पर अदालत की राय कि क्या परिस्थितियाँ हैं

किन प्राकृतिक संसाधनों का केवल द्वारा निपटान किया जाना चाहिए

नीलामी। *[पैरा 2] [447-सी-डी]*

*1.2 "*नीलामी*"* शब्द तत्काल व्यक्त किया गया

राय को *"*राजस्व को अधिकतम करने*"* के साधन के रूप में देखा जा सकता है

*"*लौटाता है*"*, चाहे कोई भी साधन अपनाया गया हो

तकनीकी और सही ढंग से निविदा के रूप में वर्णित किया जाना चाहिए,

निविदा-सह-नीलामी या नीलामी। *[पैरा 3] [448-*ए-बी*]*

1.3 कानून के समक्ष समानता की अवधारणा और

कानूनों का समान संरक्षण, संविधान के *Art.14* में व्यक्त मौलिक अधिकार से उभरता है

भारत से। *Art.14* का वास्तविक प्रभाव समानता प्रदान करना है।

यह सुनिश्चित करना कि इसके नागरिक संतुलन के दूसरी तरफ हैं इसी तरह समानता के अपने अधिकार से वंचित नहीं हैं

कानून के समक्ष, और आरई के समान संरक्षण का उनका अधिकारः

2012 का विशेष संदर्भ संख्या *1*

339

राष्ट्र के प्राकृतिक संसाधनों पर स्वामित्व अधिकार, निहित देश के नागरिकों में। *[* पैरा *4] [448*-बी-सी-जी-एच*; 449*

ए-बी*]*

1.4 प्राकृतिक संसाधन राष्ट्र के सामूहिक संसाधन हैं।

धन-सम्पत्ति। न्यायशास्त्र के रूप में जनहित याचिका

अवधारणा बहुलता के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करती है *(*जैसेव्यक्ति के अधिकार के विरुद्ध*)* विशेष रूप से जब बहुलता है*,*

एक या दूसरे कारण से, अपनी शिकायतों का निवारण करने की स्थिति में नहीं। *[* पैरा *5] [449*-ई-एफ*; 449*-डी*]*

2.1 इस न्यायालय के निर्णयों का विश्लेषण किया जाएगा

इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि राज्य को व्यापार करने का अधिकार है।

गतिविधि, राज्य को प्रासंगिक सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए, और बाहरी या अप्रासंगिक विचार से नहीं। वही तर्कसंगतता और तर्कसंगतता पर आधारित होना चाहिए क्योंकि

साथ ही गैर-मनमानी। राज्य में प्रवेश करते समय

संविदात्मक संबंध बनाए रखने के लिए बाध्य है

मानक या सिद्धांत जो परीक्षण को पूरा करता है

जब तक कि यह अच्छे कारणों से समर्थित न हो। *[* पैरा *6 (*बी*)* और *(*सी*)] [456*-ई-एफ*; 459*-ए-सी*]*

रमण दयराम शेट्टी बनाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा

भारतीय प्राधिकरण और अन्य। *, 1979 (3)* एससीआर *1014 = (1979) 3* एससीसी

489 ; रासबिहारी पांडा आदि। बनाम उड़ीसा राज्य *1969 (3)* एससीआर *374 = (1969) 1* एस. सी. सी. *414;* एस. जी. जयसिंघानी बनाम भारत संघ

& ओआरएस। , *1967* एस. सी. आर. *703 =* ए. आई. आर. *1967* एस. सी. *1427;* कस्तूरी लाल

लक्ष्मी रेड्डी बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य और अन्न।

1980 340 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट *[2012] 9* एस. सी. आर.

(3) एस. सी. आर. *1338 = (1980) 4* एस. सी. सी. *1;* द्वारकादास मरफतिया एंड संस बनाम बॉम्बे बंदरगाह का न्यासी मंडल, *1989 (2)*एस. सी. आर. *751 = (1989) 3* एस. सी. सी. *293;* महाबीर ऑटो स्टोर और अन्य।

बनाम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और अन्य। *(1990) 3* एससीसी *752;* कुमारी

श्रीलेखा विद्यार्थी और अन्य। बनाम। यू. पी. और अन्य का राज्य। *1990 (1)*

पूरक। एससीआर *625 = (1991) 1* एससीसी *212;* लखनऊ विकास प्राधिकरण बनाम। एम. के. गुप्ता, *1993 (3)* पूरक। एससीआर *615 = (1994)*

1 एस. सी. सी. *243;* कॉमन कॉज, ए रजिस्टर्ड सोसाइटी बनाम यूनियनभारत और ओआरएस। , *1996 (6)* पूरक। एससीआर *719 = (1996) 6* एससीसी

530 ; मेरठ विकास प्राधिकरण बनाम एसोसिएशन ऑफ

प्रबंधन अध्ययन और ए. एन. आर. आदि। *2009 (6)* एससीआर *663 = (2009)6* एस. सी. सी. *171,* रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड। बनाम रिलायंस

इंडस्ट्रीज लिमिटेड आदि। *2010 (5)* एससीआर *704 = (2010) 7* एससीसी *1;* अखिल

भारतीय उपभोक्ता कांग्रेस बनाम मध्य प्रदेश राज्य*&* ओआरएस। , *2011 (5)* एससीआर *77 = (2011) 5* एससीसी *29*-संदर्भित

सिविल सेवा संघ परिषद बनाम सिविल सेवा मंत्री, *(1984) 3* सभी ई. आर. *935,950*

वेडः प्रशासनिक कानून *(*छठा संस्करण*)*-संदर्भित

2.2 सभी शक्तियाँ एक सार्वजनिक पद में निहित हैं, यहां तक कि

अनुबंध के क्षेत्रों का उपयोग सार्वजनिक भलाई और जनहित को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है*;* और कला। *14* में से

सरकार की कार्रवाई परीक्षण को संतुष्ट करने में विफल रही तर्कसंगतता, वही असंवैधानिक होगा।

[पैरा 6 (जी)] [476-सी-डी*]*

कुमारी श्रीलेखा विद्यार्थी और अन्य। बनाम। यू. पी. और अन्य का राज्य। *1990 (1)* पूरक। एस. सी. आर. *625 = (1991) 1* एस. सी. सी. *212*-संदर्भित।

2.3 सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में, यह पुष्टि की गई थी कि राज्य इसे अपनाने के लिए कर्तव्यबद्ध थाप्राकृतिक संसाधनों को अलग करते हुए व्यापक प्रकाशन देकर नीलामी की विधि, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी

पात्र व्यक्ति इस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। *[* पैरा *6]*

[501 - जी*]* आरईः

2012 का विशेष संदर्भ संख्या *1*

341

जनहित याचिका और अन्य के लिए केंद्र। बनाम यूनियन ऑफ

भारत और ओआरएस। *(2012) 3* एस. सी. सी. *1*-संदर्भित।

2.4 इस न्यायालय ने अपने निर्णयों में कहा है कि

Art.14 की प्रयोज्यता के दायरे के संबंध में मापदंड

संविधान के उन मामलों में जहां राज्य अपने वाद्ययंत्र, और उनके कार्यकर्ता, इसमें लगे हुए हैं

संविदात्मक दायित्व। *Art.14* के परीक्षण का सामना करने में सक्षम होने के लिए, यह पहले ही व्यक्त किया जा चुका है।

*"*मुख्य राय*"* में कि यह निष्पक्ष, उचित, गैर-भेदभावपूर्ण, पारदर्शी, गैर-मज़बूत होना चाहिए, निष्पक्ष, पक्षपात या भाई-भतीजावाद के बिना, की खोज में

स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और न्यायसंगतता को बढ़ावा देना

उपचार। इस न्यायालय के निर्णय उन सभी का समर्थन करते हैं।

आवश्यकताएँ जहाँ राज्य, उसके साधन, और

उनके पदाधिकारी संविदात्मक कार्यों में लगे हुए हैं

लेन-देन। इसलिए, सभी *"*सरकारी नीति*"* तैयार की गई हैं।

संविदात्मक मामलों के संदर्भ में, यह अभिनिर्धारित किया गया है,

उक्त मापदंडों के अनुरूप होना चाहिए। जबकि *Art.14* एक तर्कसंगत वर्गीकरण की अनुमति देता है

प्राप्त करने की मांग की गई वस्तु के साथ संबंध, यह नहीं है

चुनने और मनमाने ढंग से चुनने की शक्ति की अनुमति दें

एक ही श्रेणी में आने वाले कई व्यक्ति। इसलिए,एक मानदंड या प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए ताकि

समान श्रेणी में आने वालों के बीच चयन तर्क, निष्पक्षता और गैर-मनमानेपन पर आधारित होता है। भले ही वहाँ

केवल दो दावेदार हैं जो क्षेत्र में आते हैंविचार करने पर, यह इंगित करने के लिए एक स्पष्ट, पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ मानदंड या प्रक्रिया होनी चाहिए कि इनमें से कौन सा

दो को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यही वह है जो पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा। *[पैरा 7] [501-एच; 502-ए-ई]*

2.5 एक अन्य पहलू जो सामने आता है

इस न्यायालय के निर्णय यह हैं कि राज्य, इसके साधन और उनके पदाधिकारी प्रयोग करते समय

व्यापार या व्यवसाय आदि के मामलों में उनकी कार्यकारी शक्ति, जिसमें अनुबंध बनाना भी शामिल है, का ध्यान रखा जाना चाहिए

जनहित, सार्वजनिक उद्देश्य और सार्वजनिक भलाई।

यह *342* सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट *[2012] 9* एस. सी. आर. है।

इसलिए, क्योंकि सार्वजनिक पद के प्रत्येक धारक के आधार पर

जो वह राज्य की ओर से कार्य करता है, या

उपकरण, अंततः लोगों के प्रति जवाबदेह है जिसमें संप्रभुता निहित है। इस प्रकार, सभी शक्तियाँ निहित हैं

राज्य में सार्वजनिक भलाई के लिए प्रयोग किया जाता है

और जनहित में। अतः प्रश्न यह है कि

एक कार्यकारी प्राधिकरण में निरंकुश विवेक, बस करता है

उठती नहीं है। विवेकाधिकार पर बंधन स्पष्ट हैं,

पारदर्शी और उद्देश्यपूर्ण मानदंड या प्रक्रिया जो

जनहित, सार्वजनिक उद्देश्य और सार्वजनिक उद्देश्य को बढ़ावा देना।

अच्छा है। इसलिए, एक सार्वजनिक प्राधिकरण को कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

उचित रूप से और अच्छे विश्वास के साथ और वैध और

लोक हित के प्रासंगिक आधार। *[पैरा 8] [502-एफ-एच; 503*

ए-बी*]*

2.6 इस न्यायालय द्वारा अभिलिखित टिप्पणियाँ

राजस्व वापसी का विषय, अवधि के दौरान

वाणिज्यिक उद्यमों में राज्य की भागीदारी की जा रही हैसंक्षेप मेंः यह आयोजित किया गया है, जहां राज्य केवल एक उत्पाद बेच रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि राज्य

उच्चतम मूल्य प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, बशर्ते कि

किसी भी अन्य प्रमुख सार्वजनिक विचार के लिए पाठ्यक्रम। द.

द्वारा निष्पादित एक व्यापारिक समझौते की वैधता

सरकार को परीक्षण द्वारा आंका जाना चाहिए, कि पूरे

इनसे राज्य को होने वाला लाभ, और नहीं है

एक पर निजी लाभ प्रदान करने के लिए एक लबादा के रूप में उपयोग किया जाता हैव्यक्तियों का सीमित वर्ग। रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज में

लिमिटेड के मामले में, भारत संघ ने स्थिति को अपनाया है,

कि प्राकृतिक संसाधन राज्य में निहित हैं

देश के नागरिकों के लिए और उनकी ओर से विश्वास का होना और उनकी रक्षा करना राज्य का गंभीर कर्तव्य है।

प्राकृतिक संसाधन। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह स्वीकार की गई कि

प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हमेशा देश के नागरिकों के सामान्य हित में किया जाना चाहिए, न कि निजी हित में।

ब्याज। *[पैरा 9] [503-सी-एच; 504-ए]*

3.1 जब प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं

वाणिज्यिक दोहन के लिए राज्य से निजी व्यक्ति आरईः

2012 का विशेष संदर्भ संख्या *1*

343

विशेष रूप से अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, राज्य के

लौटते हैं। यह केवल यह सुनिश्चित करेगा कि मौलिक *Art.14* में निहित अधिकार *(*कानून के समक्ष समानता का आश्वासन*)*

और कानूनों का समान संरक्षण*),* और निर्देश *Art.39 (b)* में निहित सिद्धांत *(*वह भौतिक संसाधन*)*

समुदाय का इस तरह से वितरण किया जाता है कि सबसे अच्छा निर्वाह किया जा सके

आम भलाई*),* नागरिकों तक विस्तारित की गई है

देश से। अनुच्छेद *14* राज्य को कई व्यक्तियों में से मनमाने ढंग से चुनने और चुनने की अनुमति नहीं देता है।

एक ही श्रेणी। एक पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ मानदंड */*

प्रक्रिया को विकसित करना होगा ताकि दोनों के बीच चयन किया जा सके।

एक ही वर्ग या श्रेणी से संबंधित लोग तर्क, निष्पक्षता और गैर-मनमानेपन पर आधारित होते हैं। अगर

निजी व्यक्तियों की भागीदारी वाणिज्यिक के लिए है।

विशेष रूप से अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए शोषण, फिर

अकेले राजस्व को अधिकतम करने के लिए राज्य का प्रयास,कला में निहित संवैधानिक अधिदेश को पूरा करना। *14*

और संविधान के *39 (*बी*)*। *[* पैरा *10-12] [504-E-G; 505 B-D]*

कॉमन कॉज, ए रजिस्टर्ड सोसाइटी बनाम भारत संघ

& ओआरएस। *1996 (6)* पूरक। एससीआर *719 = (1996) 6* एससीसी *530 -*

संदर्भित किया गया।

3.2 नीलामी निश्चित रूप से एक संवैधानिक जनादेश नहीं है

व्यक्त किए गए तरीके से, *"*मुख्य राय*"* में, लेकिन यह कर सकता है

निश्चित रूप से कुछ स्थितियों में राजस्व को अधिकतम करने के लिए लागू किया जाएगा।

कानूनी और संवैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वापसी।

इसलिए, यह तत्काल राय है कि"राजस्व का अधिकतमकरण" शब्दों का उपयोग करके प्राकृतिक संसाधनों के निपटान के तरीके को व्यक्त करने के लिए चुना गया

"नीलामी" शब्द के स्थान पर। इसके अलावा, प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से नीलामी निश्चित रूप से एक निर्विवाद साधन है। जिसके द्वारा राजस्व रिटर्न का अधिकतमकरण सुनिश्चित किया जाता है। यह दोहराया जाता है कि निविदा की प्रक्रिया द्वारा परिसंपत्तियों का निपटान,

निविदा-सह-नीलामी और नीलामी सुनिश्चित कर सकती है।

राजस्व लाभ को अधिकतम करना। इस प्रकार, यदि राज्य *344* सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट प्राप्त करता है

[2012] 9 एस सी आर।

निष्कर्ष पर, किसी दी गई स्थिति में, कि अधिकतम

प्राकृतिक की नीलामी से राजस्व अर्जित किया जाएगा

प्रश्न में संसाधन, तो अकेले वह होगा

प्रक्रिया जिसे उसे अपनाना होगा। *[* पैरा *3* और *12]*

[447 - जी-एच*; 505*-एफ-एच*; 506*-ए-बी*]*

3.3 इस तथ्य का न्यायिक संज्ञान लेने के लिए मजबूर किया जाता है,

कि प्राकृतिक संसाधनों का आवंटन एक मुद्दा है

प्रत्येक अवसर पर जब प्राकृतिक के आवंटन का मुद्दा संसाधनों के परिणामस्वरूप राजस्व का कथित नुकसान होता है, यह है

राष्ट्र के लिए नुकसान के रूप में चित्रित किया गया। राष्ट्रपति

संदर्भ का उद्देश्य इस न्यायालय की सलाह को लागू करना है।

क्रीज को इस्त्री करने का अधिकार क्षेत्र, ताकि कानूनी और

संवैधानिक मापदंडों को सही ढंग से समझा जाता है। यह

भविष्य में इस तरह के विवादों से बचें। अतः एक

चौथे प्रश्न पर भी राय दी जा रही है।*Art.39 (b)* में निहित जनादेश में परिकल्पना की गई है कि सभी

भौतिक संसाधनों को इस तरह से वितरित किया जाना चाहिए जो "आम भलाई के लिए सबसे अच्छा" हो। यह है,

इसलिए, स्पष्ट है कि सरकारी नीति के लिए

ऐसे संसाधनों का वितरण तैयार किया जाना चाहिए

समुदाय की "आम भलाई" को ध्यान में रखते हुए अर्थात, इस देश के नागरिक। में व्यक्त किया गया है

"मुख्य राय" कि नीति के मामले इसके अंतर्गत आते हैं

विधायिका या कार्यपालिका का क्षेत्र, और नहीं हो सकता है

हस्तक्षेप किया जाता है, जब तक कि नीति का उल्लंघन न हो

वैधानिक कानून, या इसके प्रावधान *(ओं)* के अधिकार से बाहर है

संविधान। यह एक अदालत के लिए एक वैकल्पिक नीति का सुझाव देने के लिए न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं है, जो

न्यायालय का ज्ञान बेहतर हो सकता है एक मामले की परिस्थितियाँ। अब तक, स्थिति स्पष्ट है

असंदिग्ध। *[पैरा 13] [506-सी-डी; 507-ए-बी-एच; 508-ए-सी]*

3.4 नीति की वैधता और संवैधानिकता एक है।

मामला, और इसके कार्यान्वयन का तरीका काफी आरई:

2012 का विशेष संदर्भ संख्या *1*

345

एक और। कार्यान्वयन के चरण में भी एक स्पष्ट और वैध नीति, एक अवैध नीति का रूप ले सकती है।

रणनीति। सार्वजनिक भलाई के लिए प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन की नीति को विधायिका द्वारा परिभाषित किया जा सकता है।

इसी तरह, प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन के लिए नीति

कार्यपालिका द्वारा भी निर्धारित किया जाएगा। मानकों के लिए

दोनों की वैधता और संवैधानिकता का निर्धारण करना।

वे बिल्कुल एक ही हैं। अतः इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि

"मुख्य राय" में दर्ज निष्कर्ष कि नीलामी जो कई मूल्य वसूली में से एक है

तंत्र, के अलगाव के लिए एकमात्र संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त विधि नहीं माना जा सकता है

प्राकृतिक संसाधन। यह नहीं समझना चाहिए कि मतलब, कि यह कभी भी निपटान के लिए एक वैध तरीका नहीं हो सकता है

प्राकृतिक संसाधन। *[पैरा 13] [514-सी-ई; 508-डी]*

3.5 इसलिए, प्राकृतिक संसाधन का कोई भी हिस्सा नहीं हो सकता है

उदारता, दान, दान या दान के रूप में विघटित निजी शोषण के लिए दान। हर एक प्राकृतिक

खर्च किए गए संसाधन को पारस्परिक रूप से वापस लाना चाहिए।

विचार करें। विचार राजस्व अर्जित करने की प्रकृति में हो सकता है या "सर्वोत्तम उप-सेवा" के लिए हो सकता है।

आम भलाई "। यह दोनों का मिश्रण हो सकता है। मुक्त रूप से भौतिक संसाधनों का अपव्यय नहीं हो सकता है

लागत या उनके वास्तविक मूल्य से कम पर।

नागरिकों का एक समूह दूसरे की कीमत पर समृद्ध नहीं हो सकता है

नागरिकों का समूह, इसके लिए उचित या उचित नहीं होगा।*[पैरा 13] [514-ई-जी]*

मामला कानून संदर्भः

डी. के. जैन के अनुसार, जे.

(2012) 3 एससीसी *1*

संदर्भित किया गया है

पैरा *2*

[1951] एस. सी. आर *747*

संदर्भित किया गया है

पैरा *5*

[1960] 3 एस. सी. आर. *250*

संदर्भित किया गया है

पैरा *5*

[1959] एस. सी. आर. *995*

संदर्भित किया गया है

पैरा *5 46* सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2012] 9 एस.

[1965] 1 एस. सी. आर. *413*

संदर्भित किया गया है

पैरा

1975 (1) एससीआर *504*

संदर्भित किया गया है

पैरा

1979 (2) एससीआर *476*

संदर्भित किया गया है

पैरा

1991 (2) पूरक। एससीआर *497*

संदर्भित किया गया है

पैरा

1998 (2) पूरक। एससीआर *400*

संदर्भित किया गया है

पैरा

पैरा

संदर्भित किया गया है

1994 (5) पूरक। एससीआर *1*

[1934] ए. सी. *586*

संदर्भित किया गया है

पैरा

संदर्भित किया गया है

[1959] सप. *1* एस. सी. आर *806*

पैरा

संदर्भित किया गया है

ए. आई. आर. *(30) 1943* एफ. सी. *13*

पैरा

1991 (2) एससीआर *501*

संदर्भित किया गया है

पैरा

2002 (2) एससीआर *1006*

पैरा

संदर्भित किया गया है

(1955) 2 एससीआर *603*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1949-50] एफ. सी. आर. *595*

संदर्भित किया गया है

पैरा

आकाशवाणी *1954* एससी *636*

संदर्भित किया गया है

पैरा

(1993) 4 एस. सी. सी. *441*

संदर्भित किया गया है

पैरा

उस पर भरोसा करें

2011 (9) एससीआर *290*

पैरा

उस पर भरोसा करें

1987 (1) एससीआर *562*

पैरा

उस पर भरोसा करें

1992 (1) पूरक। एससीआर *732*

पैरा

2005 (5) पूरक। एससीआर *395*

संदर्भित किया गया है

पैरा

(2004) 3 एससीसी *75*

संदर्भित किया गया है

पैरा

(2003) 6 एस. सी. सी. *697*

उस पर भरोसा करें

पैरा

संदर्भित किया गया है

36 एलईडी *1018: 146*

पैरा

अमेरिका *387 (1892)*

1996 (10) पूरक। एससीआर *12*

संदर्भित किया गया है

2012 का पैरा नंबर *1*

347

पैरा *74*

संदर्भित किया गया है

पैरा *74*

संदर्भित किया गया है

संदर्भित किया गया है

पैरा *74*

पैरा *74*

संदर्भित किया गया है

पैरा *74*

संदर्भित किया गया है संदर्भित किया गया है

पैरा *74*

पैरा *91*

संदर्भित किया गया है

उस पर भरोसा करें

पैरा *92*

संदर्भित किया गया है

पैरा *94*

528

संदर्भित किया गया है

पैरा *95* पैरा *95*

संदर्भित किया गया है

पैरा *96*

संदर्भित किया गया है

पैरा *97*

संदर्भित किया गया है

संदर्भित किया गया है

पैरा *98*

संदर्भित किया गया है

पैरा *99*

390

संदर्भित किया गया है

पैरा *101*

693

संदर्भित किया गया है

पैरा *102*

पैरा *103*

संदर्भित किया गया हैसंदर्भित किया गया है

पैरा *104*

पैरा *109*

1

संदर्भित किया गया हैसंदर्भित किया गया है

पैरा *110*

पैरा *110*

संदर्भित किया गया है

संदर्भित

पैरा *11*

48 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्टों के लिए

[2012] 9 एस.

1984 (1) एससीआर *725*

संदर्भित किया गया है

पैरा

1978 (1) एससीआर *641*

संदर्भित किया गया है

पैरा

1973 (2) एससीआर *757*

संदर्भित किया गया है

पैरा

1980 (3) एससीआर *1338*

संदर्भित किया गया है

पैरा

1988 (1) एससीआर *1079*

संदर्भित किया गया है

पैरा

संदर्भित किया गया है

1988 (1) एससीआर *1079*

पैरा

1997 (1) पूरक। एससीआर *671*

संदर्भित किया गया है

पैरा

(2000) 8 एससीसी *262*

संदर्भित किया गया है

पैरा

(2003) 8 एससीसी *100*

संदर्भित किया गया है

पैरा

1997 (1) पूरक। एस. सी. आर. *671* संदर्भित

पैरा

1982 (1) एससीआर *947*

संदर्भित किया गया है

पैरा

संदर्भित किया गया है

1986 एससीआर *479*

पैरा

1970 (3) एससीआर *530*

संदर्भित किया गया है

पैरा

1994 (1) एससीआर *579*

संदर्भित किया गया है

पैरा

संदर्भित किया गया है

1996 (2) एससीआर *767*

पैरा

2001 (5) पूरक। एस. सी. आर. *511* संदर्भित

पैरा

1992 (1) एससीआर *406*

संदर्भित किया गया है

पैरा

1978] 3 एससीसी *459*

संदर्भित किया गया है

पैरा

2011 (6) एससीआर *443*

संदर्भित किया गया है

पैरा

खेहर के अनुसार, जे।

संदर्भित किया गया है

1967 एससीआर *703*

पैरा

1969 (3) एससीआर *374*

संदर्भित किया गया है

पैरा

संदर्भित किया गया है

1979 (3) एससीआर *1014*

पैरा

संदर्भित किया गया है

1980 (3) एससीआर *1338*

पैरा आरईः

2012 का विशेष संदर्भ संख्या *1*

349

पैरा *6 (*ई*)*

1989 (2) एससीआर *751*

संदर्भित किया गया है

(1984) 3 सभी ई. आर. *935,950*

संदर्भित किया गया है

पैरा *6 (*ई*)*

(1990) 3 एस. सी. सी. *752*

पैरा *6 (*एफ*)*

संदर्भित किया गया है

पैरा *6 (*जी*)*

1990 (1) पूरक। एससीआर *625*

संदर्भित किया गया है

1993 (3) पूरक। एससीआर *615*

संदर्भित किया गया है

पैरा *6 (*एच*)*

1996 (6) पूरक। एससीआर *719*

संदर्भित किया गया है

पैरा *6 (i)*

पैरा *6 (*जे*)*

संदर्भित किया गया है

2009 (6) एससीआर *663*

पैरा *6 (*के*)*

संदर्भित किया गया है

2010 (5) एससीआर *704*

(2012) 3 एससीसी *1*

संदर्भित किया गया है

पैरा *6 (1)*

(2012) 3 एससीसी *1*

संदर्भित किया गया है

पैरा *13*

सलाहकार न्यायनिर्णयः विशेष संदर्भ संख्या *1*

2012 .

[भारत के संविधान के अनुच्छेद *143 (1)* के तहत*] [2* जी स्पेक्ट्रम के बारे में*]*

गुलाम ई. वाहनवती, डी. जे. खंबाटा, ए. मरियारपुथम,

एजी, इंदिरा जयसिंह, ए. एस. जी., शांति भूषण, सोली जे. सोराबजी,

विश्वजीत देब, विवेक के. तन्खा, रवींद्र श्रीवास्तव, सी. ए.सुंदरम, हरीश एन. साल्वे, टी. आर. अंधारुजिना, श्याम दीवान,

एम. एन. कृष्णमणि, विकास सिंह, डॉ. मनीष सिंघवी, मंजीत

सिंह, गुरु कृष्ण कुमार, एएजीएस। , देवदत्त कामत, अनूपम

एन. प्रसाद, रोहित शर्मा, निशांत पाटिल, आनंद कन्नन, टी. ए. खान, डी. एस. माहरा, सुप्रिया जैन, सोनम आनंद, झूमा सेन,

निजाम पाशा, प्रशांत भूषण, प्रणव सचदेवा, शकील

अहमद, गौरव ढींगरा, ए. सुभाशिनी, जी. एन. रेड्डी, एम.

रामबाबू, एस. नागराजन, अशोक ठाकुर, अनिल के. चोपड़ा, ख्वैरकपम नोबिन सिंह, सपम विश्वजीत मेइतेई, नवनीत

कुमार, दीपिका घाटोवार *(*कॉर्पोरेट लॉ ग्रुप के लिए*)*,

प्रज्ञान शर्मा, रुपेश गुप्ता, मंदाकिनी शर्मा, गौतम धमीजा, हेशु कायना, बी. एस. बंथिया, विकास उपाध्याय, *350* सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट *[2012] 9* एस. सी. आर.

समीर सोधी, अविजीत सिंह, रचना श्रीवास्तव, उत्कर्ष

शर्मा, गोपाल सिंह, मनीष कुमार, चंदन कुमार, राधा श्याम जेना, इरशाद अहमद, मिलिंद कुमार, रमेश बाबू एम. आर.,

सुश्रुत जिंदल, माधवी दीवान, संजय खारडे, आशा जी. नायर, सुनील फर्नांडीस, वर्निका तोमर, वी. एन. रघुपति, पी. वी.

योगेश्वरन, सी. डी. सिंह, डॉ. इंद्र प्रताप सिंह, सनी

चौधरी, हिमिंदर लाल, अनिल श्रीवास्तव, ऋतुराज विश्वास, एडवर्ड बेल्हो, के. एनाटोली सेमा, निमशिम वाशुम, जगजीत सिंह

छाबड़ा, अरुणा माथुर, यूसुफ खान, कमल मोहन गुप्ता, बी।बालाजी, ए. प्रसन्ना वेंकट, हेमंतिका वाही, जायेश गौरव, एस. चंद्र शेखर, पल्लवी एस. श्रॉफ, मनु नायर, कीरत सिंह।

नागरा, रोहिणी मूसा, सांझ एन. पुरोहित, मोनिका सिंघल, मोहित

औलक, ए. पी. मेध *(*सुरेश ए. श्रॉफ एंड कंपनी के लिए*)*, रोहित कुमार

सिंह, अनुपम भारती, रुचि ए. महाजन, बिन्सी सुसान, अन्न्या घोष, समरिका सिंह *(*सुरेश ए. श्रॉफ एंड कंपनी के लिए*)*,

सुनील डोगरा, किरण सूरी, एस. जे. अमित, जयना कोठारी, श्रुति

रामकृष्ण, वासुमन खंडेलवाल, मोहित कुमार शाह, डॉ.

सुब्रमण्यम स्वामी *(*इन-पेसन*)*, दीपक कुमार जेना, मीनाक्षी घोष जेना, राजेश सिंह, गौतम नारायण, टी. जी. एन. नायर

दिखाई देने वाली पार्टियाँ।

न्यायालय की राय दी गई थी

[एस. एच. कपाडिया, सी. जे., स्वयं के लिए,

डी. के. जैन, जे.

दीपक मिश्रा और रंजन गोगोई, जे. जे.*]*

अनुच्छेद *143 (1)* के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

भारत का संविधान, भारत के राष्ट्रपति ने *12* अप्रैल को,

2012 , वर्तमान संदर्भ दिया। का पूरा पाठ

संदर्भ *(*अनुलग्नकों के बिना*)* इस प्रकार हैः

" जहाँ *1994* में, विभाग

दूरसंचार, भारत सरकार *("*जीओआई*")*, जारी किया गया*8* सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सेवा लाइसेंस *("*सीएमटीएस*")*

लाइसेंस*)*, दिल्ली के चार मेट्रो शहरों में से प्रत्येक में *2*,

मुंबई, कोलकाता और चेन्नई *10* साल की अवधि के लिए *(*

" 1994 लाइसेंस *")*। *1994* के लाइसेंसधारियों का चयन किया गया था।

तकनीकी और *351* पर उनके द्वारा प्राप्त रैंकिंग के आधार पर

आरईः *2012* का विशेष संदर्भ संख्या *1*

[डी. के. जैन, जे.*]*

द्वारा निर्धारित मापदंडों के आधार पर वित्तीय मूल्यांकन

निविदा में लक्ष्य और प्रारंभिक तीन वर्षों के लिए एक निश्चित लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता थी और बाद में इसके आधार पर

न्यूनतम प्रतिबद्धता के अधीन ग्राहकों की संख्या

निविदा दस्तावेज और लाइसेंस समझौते में उल्लिखित।

गोल द्वारा जारी *1994* के लाइसेंसों में उल्लेख किया गया है किउपयुक्त आधार पर *900* मेगाहर्ट्ज बैंड में अधिकतम *4.5* मेगाहर्ट्ज तक की अनुमति दी जाएगी।

औचित्य। इसके लिए कोई अलग अग्रिम शुल्क नहीं था

लाइसेंसधारियों को स्पेक्ट्रम का आवंटन, जिन्होंने केवल भुगतान किया था

वार्षिक स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क, जो इसके अधीन होगा

समय-समय पर संशोधन और जिसकी शर्तों के तहत

लाइसेंस का नाम "लाइसेंस शुल्क और रॉयल्टी" था। *1994* के लाइसेंस की एक प्रति, एक टेबल सेटिंग के साथ

डी. ओ. टी. द्वारा निर्धारित पूर्व निर्धारित लाइसेंस शुल्क का भुगतान करें।

निविदा में, यहाँ अनुलग्नक *I* (कोली) के रूप में संलग्न किया गया है।

दिसंबर *1995* में *34* सी. एम. टी. एस. लाइसेंस

18 दूरसंचार के लिए नीलामी के आधार पर मंजूरी दी गई थी

10 साल की अवधि के लिए वृत्त ("*1995* लाइसेंस")। द.

1995 अनुज्ञप्ति में उल्लेख किया गया है कि संचयी अधिकतम

उचित औचित्य के आधार पर लाइसेंसधारियों को *900* मेगाहट्र्ज बैंड में *4.4* मेगाहट्र्ज तक की अनुमति दी जाएगी। वहाँ। लाइसेंसधारियों को स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए कोई अलग अग्रिम शुल्क नहीं था, जिन्हें वार्षिक भुगतान करने की भी आवश्यकता थी

स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क, जो की शर्तों के तहत

लाइसेंस का नाम था "लाइसेंस शुल्क और रॉयल्टी"।

जो समय-समय पर संशोधन के अधीन होगा। *1995* के लाइसेंसों की एक प्रति, एक तालिका के साथ

उच्चतम बोलीदाता द्वारा देय शुल्क, यहाँ अनुलग्नक *II* (कोली) के रूप में संलग्न किया गया है।

जबकि *1995* में, बुनियादी के लिए बोलियां भी आमंत्रित थीं

टेलीफोन सेवा लाइसेंस ("बीटीएस लाइसेंस")

15 साल की अवधि के लिए देय लाइसेंस शुल्क। शर्तों के तहत बीटीएस लाइसेंसों में से, एक लाइसेंसधारी निश्चित लाइन प्रदान कर सकता है

बुनियादी टेलीफोन सेवाओं के साथ-साथ वायरलेस बुनियादी *[2012] 9* एस. सी. आर.

?

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

टेलीफोन सेवाएँ। वर्ष में छह लाइसेंस दिए गए थे।

1997-98 देने के लिए निविदा के माध्यम से नीलामी के माध्यम से

बुनियादी दूरसंचार सेवाएं *("1997* बीटीएस लाइसेंस*")*। द.

अनुज्ञप्ति की शर्तें, अन्य बातों के साथ-साथ, बशर्ते कि

स्थानीय लूप में वायरलेस के लिए उपकरणों की उपलब्धता

(डब्ल्यू. एल. एल.*)*, विश्व बाजार में, बैंड में स्पेक्ट्रम

स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए अलग से अग्रिम शुल्क औरबुनियादी वायरलेस टेलीफोन सेवा प्रदान करने वाले लाइसेंसधारी

वार्षिक स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क का भुगतान करना आवश्यक था,

जिनका लाइसेंस की शर्तों के तहत नामकरण किया गया था

" लाइसेंस शुल्क और रॉयल्टी *"*। *1997* बीटीएस की एक नमूना प्रति

अनुज्ञप्ति शुल्क निर्धारित करने वाली तालिका वाले अनुज्ञप्तिउच्चतम बोलीदाता द्वारा भुगतान यहाँ अनुलग्नक के रूप में संलग्न किया गया है

*III (*कोली*)*।

जबकि *1997* में, दूरसंचार नियामक

भारतीय प्राधिकरण अधिनियम, *1997* अधिनियमित किया गया और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण *("*ट्राई*")* की स्थापना की गई। *1* अप्रैल, *1999* को नई दूरसंचार नीति

1999 (" एन. टी. पी. *1999 ")* को लागू किया गया था

दूरसंचार पर एक समूह *("*जीओटी*")* की सिफारिश जो

यहाँ अनुलग्नक *IV* के रूप में संलग्न किया गया है। एन. टी. पी. *1999* ने प्रावधान किया किसेल्युलर मोबाइल सेवा प्रदाता *("*सीएमएसपी*")* होंगे

भुगतान पर *20* साल की अवधि के लिए लाइसेंस दिया गया

एक बार के प्रवेश शुल्क और लाइसेंस शुल्क के रूप में

आय का हिस्सा। एन. टी. पी. *1999* ने यह भी प्रदान किया कि बीटीएस *(*निश्चित*)*

सेवा प्रदाता या एफ. एस. पी.*)* दोनों निश्चित प्रदान करने के लिए लाइसेंस

और वायरलेस *(*डब्ल्यू. एल. एल.*)* सेवाएं भी एक बार के प्रवेश शुल्क के भुगतान पर *20* साल की अवधि के लिए जारी की जाएंगी और

स्पेक्ट्रम उपयोग के लिए राजस्व हिस्सेदारी और निर्धारित शुल्क के रूप में लाइसेंस शुल्क, जिसका उपयुक्त स्तर

ट्राई द्वारा इसकी सिफारिश की जानी थी। दोनों लाइसेंसधारी

सेलुलर और बेसिक को भी वार्षिक भुगतान करना पड़ता था।

स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क।

आरईः *2012* का विशेष संदर्भ संख्या *1*

353

[डी. के. जैन, जे.*]*

जबकि एन. टी. पी. *1999* पर आधारित, एक प्रवास

निर्धारित लाइसेंस शुल्क से एक बार के लिए स्थानांतरण के लिए पैकेज राजस्व हिस्सेदारी व्यवस्था के आधार पर प्रवेश शुल्क और लाइसेंस शुल्क

22 जुलाई, *1999* को सभी मौजूदा लाइसेंसों की पेशकश की गई थी।यह *1* अगस्त *1999* को लागू हुआ। माइग्रेशन पैकेज के तहत, सभी सीएमटीएस के लिए लाइसेंस अवधि

और एफ. एस. पी. लाइसेंसधारियों को *20* साल तक बढ़ा दिया गया था

लाइसेंस जारी करने की तिथि।

1997 और *2000* में सी. एम. टी. एस. लाइसेंस

2 और *21* वृत्तों में भी महानगर को अनुदान दिया गया था।

टेलीफोन निगम लिमिटेड *(*एम. टी. एन. एल.*)* और भारत संचार निगम लिमिटेड *("*बीएसएनएल*")* क्रमशः *("*पीएसयू*")*

लाइसेंस *")*। हालांकि, इसके लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं लिया गया था।

पीएसयू लाइसेंस। बी. एस. एन. एल. को जारी किए गए सी. एम. टी. एस. लाइसेंस और

एम. टी. एन. एल. ने उल्लेख किया कि उन्हें जी. एस. एम. दिया जाएगा

900 मेगाहर्ट्ज बैंड में *4.4 + 4.4* मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम। पीएसयू

लाइसेंसधारियों को वार्षिक स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क का भी भुगतान करना पड़ता था। पीएसयू लाइसेंस की एक प्रति संलग्न की गई है

यहाँ अनुलग्नक वी *(कोली)* के रूप में।

जबकि जनवरी *2001* में, ट्राई के आधार पर

*"*मल्टीस्टेज इन्फॉर्म्ड आरोही*"* के रूप में संरचित प्रक्रियाबोली प्रक्रिया *"*। एक निविदा के आधार पर, *4* वर्षों में *20* वर्षों की अवधि के लिए *17* नए सीएमटीएस लाइसेंस जारी किए गए।

मेट्रो शहर और *13* दूरसंचार मंडल *(2001* सेल्युलर*)*

लाइसेंस *")*। *2001* के लाइसेंसों के लिए आवश्यक था कि लाइसेंसधारक निर्धारित किए गए एक बार के गैर-वापसी योग्य प्रवेश शुल्क का भुगतान करें।

उपरोक्त नीलामी के माध्यम से और वार्षिक लाइसेंस शुल्क भी और

वार्षिक स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क और कोई नहीं थास्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए अलग से अग्रिम शुल्क। में।

निविदा दस्तावेज की शर्तों के अनुसार, लाइसेंस की शर्तों में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान किया गया है कि संचयी अधिकतम *4. 1* मेगाहर्ट्ज *+ 4.4* मेगाहर्ट्ज तक की अनुमति दी जाएगी और आगे उपयोग, औचित्य और उपलब्धता के आधार पर, अतिरिक्त।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2012] 9 एस सी आर।

1.8 मेगाहर्ट्ज *+ 1.8* मेगाहर्ट्ज तक का स्पेक्ट्रम कुल *6.2* मेगाहर्ट्ज बनाता है।

MHz + 6.2 MHz, पर असाइनमेंट के लिए विचार किया जा सकता है

मामला दर मामला आधार पर, अतिरिक्त लाइसेंस शुल्क के भुगतान पर।इंगित अधिकतम बैंडविड्थ अर्थात *4.4* मेगाहर्ट्ज

&6.2 मेगाहर्ट्ज, जैसा भी मामला हो, प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं के आधार पर आवंटित किया जाएगा *(*जैसे सी. डी. एम. ए. *@1.25* मेगाहर्ट्ज,

जी. एस. एम. *@200* किलोहर्ट्ज़ आदि*)*। निर्धारित आवृत्तियाँ नहीं हो सकती हैं

सन्निहित हो और सभी मामलों में समान नहीं हो सकता है, जबकि बड़े हिस्से उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाएंगे

संभव हद तक। *2001* के सेल्युलर लाइसेंस की एक प्रति,

उच्चतम बोलीदाता द्वारा देय शुल्क निर्धारित करने वाली एक तालिका के साथ, यहाँ अनुलग्नक *VI* के रूप में संलग्न किया गया है।

जबकि *2001* में, बीटीएस लाइसेंस भी थे

फिक्स्ड लाइन और वायरलेस बेसिक दोनों प्रदान करने के लिए जारी किया गया

निरंतर आधार पर टेलीफोन सेवाएं *(2001* बेसिक*)*

टेलीफोन लाइसेंस*)*। सेवा क्षेत्रवार एकमुश्त प्रवेश शुल्क और समायोजित राशि के प्रतिशत के रूप में वार्षिक लाइसेंस शुल्क

स्थानीय क्षेत्र में बेतार अभिगम प्रणाली, *5 +* से अधिक नहीं *5 869-889 MHz* बैंड के साथ जोड़ी गई *824-844 MHz* में *MHz* किसी भी बुनियादी सेवा ऑपरेटर को आवंटित किया जाएगा, जिसमें शामिल हैं -

एफ. सी. एफ. एस. आधार पर मौजूदा। एक विस्तृत प्रक्रियाएफ. सी. एफ. एस. आधार पर स्पेक्ट्रम का आवंटन किया गया था

2001 बीटीएस लाइसेंस का अनुलग्नक-*IX*। वहाँ कोई नहीं था।

स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए अलग से अग्रिम शुल्क और

लाइसेंसधारियों को राजस्व के *2* प्रतिशत हिस्से का भुगतान करना आवश्यक था।

स्थानीय लूप ग्राहकों में वायरलेस से अर्जित एजीआर

एक बार के प्रवेश शुल्क के अलावा स्पेक्ट्रम शुल्क के रूप में

और वार्षिक लाइसेंस शुल्क। *2001* बेसिक की एक नमूना प्रति

प्रविष्टि निर्धारित करने वाली मेज के साथ टेलीफोन लाइसेंस

शुल्क यहाँ अनुलग्नक *VII* के रूप में संलग्न है।

जबकि *27* अक्टूबर, *2003* को ट्राई ने एक एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस की सिफारिश की थी*("*यू. ए. एस. एल.*)* व्यवस्था। ट्राई की सिफारिश की एक प्रति है -

यहाँ अनुलग्नक *VIII* के रूप में संलग्न किया गया है।

[डी. के. जैन, जे.]

जबकि *11.11.2003* पर दिशा-निर्देश जारी किए गए थे,

मौजूदा प्रचालक के स्थानांतरण के लिए प्रक्रिया निर्दिष्ट करना

नई यू. ए. एस. एल. व्यवस्था। दिशानिर्देशों के अनुसार, नए अभिगम सेवा लाइसेंस के लिए सभी आवेदन इस प्रकार होंगे -

एकीकृत अभिगम सेवा अनुज्ञप्ति की श्रेणी। बाद में,

टी. आर. ए. आई. के दिनांक *14.11.2003* के स्पष्टीकरण के आधार पर, प्रवेश शुल्क

नए एकीकृत लाइसेंसधारी के लिए प्रवेश शुल्क के समान ही निर्धारित किया गया था

चौथा सेलुलर ऑपरेटर। टी. आर. ए. आई. की दिनांक *19.11.2003* की आगे की सिफारिशों के आधार पर, स्पेक्ट्रम को

नए लाइसेंसधारियों को मौजूदा नियमों के अनुसार दिया जाना था।

संबंधित लाइसेंस समझौतों में स्पेक्ट्रम से संबंधित नियम और शर्तें। दिनांकित दिशानिर्देशों की एक प्रति

11.11.2003 इसे यहाँ अनुलग्नक *IX* के रूप में संलग्न किया गया है।

जबकि एफ. डी. आई. सीमा में वृद्धि के परिणामस्वरूप

दूरसंचार क्षेत्र में *49* प्रतिशत से *74* प्रतिशत, संशोधित दिशानिर्देश

समायोजित सकल राजस्व *(*ए. जी. आर.*)* और स्पेक्ट्रम शुल्कराजस्व हिस्सेदारी आधार। स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए कोई अलग अग्रिम शुल्क निर्धारित नहीं किया गया था। प्रारंभिक स्पेक्ट्रम

सेवा को यू. ए. एस. लाइसेंस शर्तों के अनुसार आवंटित किया गया था

विभिन्न आवृत्ति बैंडों में प्रदाता, के अधीन

उपलब्धता। प्रारंभ में टी. डी. एम. ए. आधारित प्रणालियों के लिए संचयी अधिकतम *4.4* मेगाहर्ट्ज *+ 4.4* मेगाहर्ट्ज या *2.5* मेगाहर्ट्ज तक का आवंटन।

सी. डी. एम. ए. आधारित प्रणालियों के लिए मेगाहर्ट्ज *+ 2.5* मेगाहर्ट्ज

उपलब्धता होनी थी। स्पेक्ट्रम *5* से अधिक नहींसी. डी. एम. ए. प्रणाली के संबंध में मेगाहर्ट्ज *+ 5* मेगाहर्ट्ज या *6.2* मेगाहर्ट्ज *+*

6.2 टी. डी. एम. ए. आधारित प्रणाली के संबंध में मेगाहर्ट्ज किसी भी नए यू. ए. एस. लाइसेंसधारी को आवंटित किया जाना था। यूएएसएल की एक प्रति

दिनांकित *14.12.2005* दिशानिर्देश यहाँ इस प्रकार संलग्न किए गए हैं

अनुलग्नक *X.*

[2012] 9 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

6

जहाँ यू. ए. एस. एल. की शुरुआत के बाद

2003 और मार्च *2007* तक, *51* नए यूएएसएल लाइसेंस थे

पहले आओ पहले पाओ की नीति के आधार पर जारी किया गया

उसी प्रवेश शुल्क का भुगतान जैसा कि *2001* के लिए भुगतान किया गया था

सेलुलर लाइसेंस *("2003-2007* लाइसेंस*")* औरएफ. सी. एफ. एस. के आधार पर स्पेक्ट्रम भी आवंटित किया गया था

मामला-दर-मामला आधार पर अलग वायरलेस संचालन लाइसेंस

और उपलब्धता के अधीन। लाइसेंसधारियों को एजीआर के प्रतिशत के रूप में वार्षिक स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क का भुगतान करना पड़ता था।

स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए कोई अग्रिम शुल्क नहीं है। ए.टेबल सेटिंग के साथ *2003-2007* लाइसेंस की प्रति

देय शुल्क को यहाँ अनुलग्नक *XI* के रूप में संलग्न किया गया है

(कोली*)*।

जबकि *28* अगस्त *2007* को ट्राई ने समीक्षा की

नए लाइसेंस जारी करना, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम का आवंटनशुल्क, प्रवेश शुल्क और इसकी सिफारिशें जारी की, ए

16.07.2008 दिनांकित और सिफारिशें कीं जो इसे यहाँ अनुलग्नक *XIII* के रूप में संलग्न किया गया है।

जबकि *2007* और *2008* में, गोल ने दोहरी जारी की।

साथ ही दोनों के माध्यम से सेवा प्रदान करने के लिए स्पेक्ट्रम जी. एस. एम. और सी. डी. एम. ए. नेटवर्क। पहला संशोधन दिसंबर, *2007* में जारी किया गया था। सभी लाइसेंसधारी जिन्होंने दोहरी का विकल्प चुना

प्रौद्योगिकी लाइसेंसों ने समान प्रवेश शुल्क का भुगतान किया, जो था

प्रवेश शुल्क के रूप में निर्धारित राशि के बराबर राशि

उसी सेवा क्षेत्र में नया यू. ए. एस. लाइसेंस प्राप्त करना। द.

अन्य बातों के साथ-साथ लाइसेंस में संशोधन में उल्लेख किया गया है कि शुरू में

टी. डी. एम. ए. आधारित प्रणालियों के मामले में *4,4* मेगाहर्ट्ज *+ 4,4* मेगाहर्ट्ज तक की संचयी अधिकतम राशि आवंटित की जानी थी।

किलोहर्ट्ज़ प्रति वाहक या *30* किलोहर्ट्ज़ प्रति वाहक*)* और अधिकतम

2.5 मेगाहर्ट्ज *+ 2.5* मेगाहर्ट्ज के मामले में आवंटित किया जाना था

सी. डी. एम. ए. आधारित प्रणालियाँ *(@1.25* मेगाहर्ट्ज प्रति वाहक*)*, मामले में

उपलब्धता के अधीन मामले के आधार पर। यह भी, अन्य बातों के साथ, आरई थाः

2012 का विशेष संदर्भ संख्या *1*

357

[डी. के. जैन, जे.*]*

उल्लेख किया कि उपरोक्त से परे अतिरिक्त स्पेक्ट्रम

बाद में आवंटन के लिए शर्त पर भी विचार किया जा सकता है।

पहले से ही इष्टतम और कुशल उपयोग सुनिश्चित करना

सभी प्रकार के यातायात को ध्यान में रखते हुए आवंटित स्पेक्ट्रम

और समय-समय पर निर्धारित दिशा-निर्देश/मानदंड।

तथापि, स्पेक्ट्रम *5 + 5* मेगाहर्ट्ज से अधिक नहीं

सी. डी. एम. एस. प्रणाली और टी. डी. एम. ए. के संबंध में *6.2 + 6.2* मेगाहर्ट्ज लाइसेंसधारी को आधारित प्रणाली आवंटित की जानी थी। वहाँ

स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए कोई अलग अग्रिम शुल्क नहीं था।

हालांकि, दोहरी प्रौद्योगिकी लाइसेंसधारियों को भुगतान करने की आवश्यकता थी

पर लाइसेंस शुल्क के अलावा स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क ए. जी. आर. के प्रतिशत के रूप में राजस्व हिस्सेदारी आधार। स्पेक्ट्रम

इन लाइसेंसधारियों को *10.01.2008* आवंटित किया गया था।

सी. एम. टी. एस. के लिए अभिदाता आधारित मानदंड

वर्ष *2002* में अतिरिक्त राशि के आवंटन के लिए निर्धारित किया गया था

1.8 + 1.8 मेगाहट्र्ज का स्पेक्ट्रम *6.2 + 6.2* मेगाहट्र्ज से अधिक

ए. जी. आर. का *1* प्रतिशत अतिरिक्त स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क लगाना।

आवंटन मानदंडों को समय-समय पर संशोधित किया गया था। ए.

इस संबंध में डीओटी के दिनांकित *01.02.2002* पत्र की प्रति है यहाँ अनुलग्नक *XIV* के रूप में संलग्न किया गया है।

जहाँ *6.2* से अधिक आवंटित स्पेक्ट्रम के लिए

मेगाहट्र्ज, डीओटी मे द्वारा जारी आवृत्ति आवंटन पत्रों में

2008 इसके बाद, यह उल्लेख किया गया कि स्पेक्ट्रम का आवंटन भविष्य में निर्धारित मूल्य निर्धारण के अधीन है

6. 2 मेगाहट्र्ज *+ 6.2* मेगाहट्र्ज से अधिक के स्पेक्ट्रम के लिए लक्ष्य द्वारा और

न्यायालय के आदेशों का परिणाम। हालांकि, वार्षिक स्पेक्ट्रम

उपयोग शुल्क ए. जी. आर. के आधार पर लगाया गया था।

निर्दिष्ट स्पेक्ट्रम की मात्रा। आवृत्ति आवंटन पत्र की एक नमूना प्रति यहाँ अनुलग्नक के रूप में संलग्न की गई है।

XV.

3 जी बैंड के लिए स्पेक्ट्रम *(यानी 2100)*

लाइसेंस समझौता किया जाएगा और मौजूदा के लिएनीलामी में सफल होने वाले लाइसेंसधारक, लाइसेंस *3* सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट *[2012] 9* एस. सी. आर.

3 जी बैंड में स्पेक्ट्रम के उपयोग के लिए समझौते में संशोधन किया जाएगा। आवेदन आमंत्रित करने वाले नोटिस की एक प्रति औरइनके स्पष्टीकरण यहाँ संलग्न किए गए हैं और इस प्रकार चिह्नित किए गए हैं

अनुलग्नक *XVI (*कोली*)*। संशोधन पत्र की शर्तें बशर्ते कि *3* जी स्पेक्ट्रम वापस ले लिया जाएगा यदि लाइसेंस किसी भी कारण से समाप्त कर दिया जाता है।

संशोधन पत्र के मानक प्रपत्र की एक प्रति है

यहाँ संलग्न किया गया और अनुलग्नक *XVII* के रूप में चिह्नित किया गया।

जहाँ *122* के लिए आशय पत्र जारी किए गए थे

10 जनवरी को या उसके बाद *2* जी सेवाएँ प्रदान करने के लिए लाइसेंस

2008 , जिनके खिलाफ लाइसेंस *("2008* लाइसेंस*")* थे

बाद में जारी किया गया। हालांकि, फैसले के अनुसार

इस माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक *2* फरवरी, *2012* को लिखित रूप में

2010 की याचिका *(*सिविल*) No.423 ("*निर्णय*"), 2008* के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। फैसले की एक प्रति है

यहाँ संलग्न किया गया और अनुलग्नक *XVIII* को चिह्नित किया गया।

जबकि गोल ने एक मध्यस्थ भी दायर किया है

निर्णय के स्पष्टीकरण के लिए आवेदन, जिसमें

गोल ने नीलामी के तरीके को रिकॉर्ड में रखा है।

निर्णय के अनुसार आयोजित करने का प्रस्ताव है औरसे उचित स्पष्टीकरण आदेश/निर्देश मांगे गए

माननीय न्यायालय। अंतर्वर्ती आवेदन की एक प्रति है

यहाँ संलग्न किया गया और अनुलग्नक *XIX* के रूप में चिह्नित किया गया।

जबकि गोल लागू कर रहा है

पैराग्राफ *81* पर निर्णय में दिए गए निर्देश और लाइसेंसों के नए अनुदान और आवंटन के साथ आगे बढ़ना

नीलामी द्वारा स्पेक्ट्रम, गोल एक सीमित समीक्षा की मांग कर रहा है

निर्णय की इस सीमा तक कि यह आम तौर पर राज्य द्वारा राष्ट्रीय संसाधनों के आवंटन की विधि को प्रभावित करता है। पुनरीक्षण याचिका की एक प्रति यहाँ संलग्न की गई है और

जबकि निर्णय द्वारा, इस माननीय न्यायालय ने ट्राई को अनुदान के लिए नई सिफारिशें करने का निर्देश दिया *359* तक *2* जी बैंड में स्पेक्ट्रम के लाइसेंस और आवंटन

आरईः *2012* का विशेष संदर्भ संख्या *1*

[डी. के. जैन, जे.*]*

नीलामी आयोजित करना, जैसा कि आवंटन के लिए किया गया था *3* जी लाइसेंसों के लिए स्पेक्ट्रम।

जबकि, इस माननीय के निर्देशों के संदर्भ में

कोर्ट, गोल अब संबंधित में स्पेक्ट्रम आवंटित करेगा

2 नीलामी के माध्यम से खोजे गए मूल्यों पर जी बैंड।

जबकि ट्राई की सिफारिशों पर आधारित

दिनांकित *11.05.2010* के बाद और स्पष्टीकरण और

सिफारिशें, जी. ओ. एल. ने फरवरी में निर्धारित की हैं

2012 , मेट्रो में स्पेक्ट्रम असाइनमेंट की सीमा

जीएसएम *(900* मेगाहर्ट्ज*)* के लिए *2x8* मेगाहर्ट्ज*/2x5* मेगाहर्ट्ज के रूप में सेवा क्षेत्र, *1800* मेगाहर्ट्ज बैंड*)/*सीडीएमए *(800* एमएचजेड बैंड*),* क्रमशः

इस शर्त के अधीन कि लाइसेंसधारी खुले में निर्धारित सीमा से अधिक अतिरिक्त स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकता है।

बाजार में स्पेक्ट्रम की नीलामी होनी चाहिए

आगे की शर्त यह है कि इसके पास कुल स्पेक्ट्रम नहीं हैअनुज्ञप्ति के विलय के लिए निर्धारित सीमा से अधिक अर्थात

25 % उस सेवा क्षेत्र में सौंपे गए कुल स्पेक्ट्रम का

नीलामी के माध्यम से या अन्यथा। सी. डी. एम. एस. स्पेक्ट्रम के लिए यह सीमा *10* मेगाहर्ट्ज है।

जबकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि स्पेक्ट्रम हो सकता है

समय-समय पर अलग-अलग संस्थाओं को आवंटित करने की आवश्यकता होती है लक्ष्य द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार, जैसे कि ग्राहक आधार, किसी विशेष क्षेत्र में स्पेक्ट्रम की उपलब्धता

वृत्त, अंतर-से प्राथमिकता इस बात पर निर्भर करती है कि क्या स्पेक्ट्रम

इसमें प्रारंभिक आवंटन या अतिरिक्त आवंटन आदि शामिल हैं, इसके लिए नीलामी आयोजित करना हमेशा संभव नहीं हो सकता है।

स्पेक्ट्रम का आवंटन।

और जहाँ उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए,

2 जी बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी के परिणामस्वरूप हो सकता है

ऐसी स्थिति जहाँ कोई भी लाइसेंसधारी 2 जी बैंड का उपयोग नहीं कर रहा हो

800 मेगाहर्ट्ज। , 900 मेगाहर्ट्ज और 1800 मेगाहर्ट्ज ने कोई भी भुगतान किया होगा

स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए अलग से अग्रिम शुल्क।

[2012] 9 एस सी आर।

/ सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

और जहाँ भारत सरकार ने

अन्य में स्थित कंपनियों से विभिन्न नोटिस प्राप्त किए

द्वीपक्षीय निवेश समझौतों का आह्वान करने वाले देश औरके कारण भारत संघ के खिलाफ हर्जाने की मांग करना

लाइसेंस रद्द करने/रद्द करने की धमकी।

और जहाँ परिस्थितियों में निश्चित

दूरगामी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रश्न

प्रभाव उत्पन्न हुए हैं, जिनमें शामिल हैं

नीलामी का संचालन और विनियमन

दूरसंचार उद्योग के अनुसार

दूरसंचार उद्योग में इस देश में निर्णय और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

और अन्यथा अन्य क्षेत्रों में।

यह देखते हुए कि जो मुद्दे उत्पन्न हुए हैं वे बहुत बड़े हैं

माननीय सर्वोच्च की राय प्राप्त करने के लिए समीचीन उस पर भारत का न्यायालय।

अब वहाँ, शक्तियों के प्रयोग में

अनुच्छेद *143* के खंड *(1)* द्वारा मुझे प्रदत्त

भारत का संविधान, *I*, प्रतिभा देवीसिंह पाटिल, राष्ट्रपति

भारत सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित प्रश्नों को संदर्भित करती है -

विचार और रिपोर्ट के लिए भारत का सर्वोच्च न्यायालय

उस पर, अर्थात्ः

प्र. *1* क्या एकमात्र अनुमेय विधि है

सभी प्राकृतिक संसाधनों का निपटान क्षेत्रों और सभी परिस्थितियों में द्वारा है

नीलामियों का संचालन*?*

प्र. *2* क्या कानून का एक व्यापक प्रस्ताव है कि केवल

नीलामियों के मार्ग का सहारा लिया जा सकता है

प्राकृतिक संसाधनों का निपटान सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णयों के विपरीत नहीं है।

बड़ी पीठों सहित न्यायालय*?*

361

2012 का सभी संदर्भ संख्या *1*

[डी. के. जैन, जे.*]*

क्या एक व्यापक सिद्धांत का उच्चारण,

यद्यपि एक विषय के रूप में व्यक्त किया गया

संवैधानिक कानून, वास्तव में नहीं है

एक नीति का निर्माण और इसका प्रभाव है

अस्थिर करने वाले नीतिगत निर्णय तैयार किए गए और

विभिन्न क्रमिक द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण

वर्षों से वैध के लिए सरकारें

जनता की कमी सहित विचार

संसाधन और सहारा लेने की आवश्यकतानवीन और विभिन्न दृष्टिकोण

विभिन्न क्षेत्रों का विकास

अर्थव्यवस्था? किसके लिए अनुमेय दायरा है

नीति निर्माण में न्यायालयों का हस्तक्षेप

सरकार के लिए तरीकों सहित

प्राकृतिक संसाधनों का निपटान?

क्या, यदि न्यायालय मानता है, के भीतर

न्यायिक समीक्षा का अनुमेय दायरा, कि

नीति त्रुटिपूर्ण है, क्या अदालत इसके लिए बाध्य नहीं है

किए गए निवेशों सहित उक्त नीतिबहुपक्षीय के तहत विदेशी निवेशकों द्वारा /

द्वैपाक्षिक समझौते?

यदि उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर

दिनांकित निर्णय की पुष्टि के लिए नेतृत्व करें *02.02.2012* तब निम्नलिखित प्रश्न हो सकते हैं -

उठें, अर्थात।

क्या निर्णय देने की आवश्यकता है

सभी को अस्थिर करने के लिए पूर्वव्यापी प्रभाव

लाइसेंस जारी किए गए और *2* जी स्पेक्ट्रम *(800,900,*

और *1800* मेगाहर्ट्ज बैंड*)* में और उसके बाद आवंटित किए गए

1994 और *10.01.2008* से पहले?

क्या सभी यू. पी. आर. ई. एम. ई. कोर्ट रिपोर्टों में *2* जी स्पेक्ट्रम का आवंटन

[2012] 9 एस सी आर।

अलग-अलग नीतिगत विचार होंगे फिर भी क्या इसे वापस लेना होगा?

विशेष रूप से

(iii) क्या दूरसंचार लाइसेंस दिए गए हैं

1994 क्या यह प्रभावित होगा?

((iv) क्या दूरसंचार लाइसेंस द्वारा दिए गए हैं।

2001 में बुनियादी लाइसेंसों और लाइसेंसों का तरीका

अवधि *2003-2007* के बीच दिया गया

क्या यह प्रभावित होगा?

(v)

क्या यह भारत सरकार के लिए खुला है

समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए किसी भी लाइसेंस की शर्तों में बदलाव करने के लिए कोई भी कार्रवाई करना।

सभी मौजूदा लाइसेंसधारी?

(vi) क्या दोहरे प्रौद्योगिकी लाइसेंस दिए गए हैं

2007 और *2008* प्रभावित होगा?

(vii) चाहे वह आवश्यक हो या अनिवार्य

वापस लेने के लिए भारत सरकार

सभी मौजूदा लाइसेंसधारियों को आवंटित स्पेक्ट्रम या पूर्वव्यापी के साथ उसी के लिए शुल्क लेना

प्रभाव और यदि ऐसा है तो किस आधार पर और किस आधार से

तारीख?

क्या नीलामी के संचालन के लिए कार्रवाई करते समय

न्यायालय, यह अनुमेय रहेगासरकार कोः

स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए प्रावधान करें

(1)

समय-समय पर नीलामी में ज्ञात मूल्य और निर्धारित मूल्य के अनुसार

वैधता की अवधि के दौरान मानदंडनीलामी निर्धारित मूल्य*?*

आरईः *2012* का विशेष संदर्भ संख्या *1*

363

[डी. के. जैन*,* जे.*]*

के अधिग्रहण पर एक सीमा लागू करें

*((*ख*)*

बचने के उद्देश्य से स्पेक्ट्रम

द्वारा बाजार में प्रभुत्व का उदय

कोई भी लाइसेंसधारी/आवेदक जो विधिवत रूप से प्रवेश ले रहा हो

इसमें ट्राई की सिफारिशों पर विचार करें।

ध्यान दें*?*

(iii) स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए प्रावधान करें

बैन्डों में निर्धारित मानदंड जहां हो सकता हैअपर्याप्त या कोई प्रतिस्पर्धा नहीं *(*उदाहरण के लिए।

निम्न स्तर होने की उम्मीद है

800 मेगाहट्र्ज बैंड में सी. डी. एम. ए. के लिए प्रतिस्पर्धा और

ट्राई ने समतुल्यता अनुपात की सिफारिश की है।

800 मेगाहट्र्ज और *900* मेगाहट्र्ज के लिए *1.5* या *1.3X 1.5*

मात्रा के आधार पर बैंड

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा धारित स्पेक्ट्रम जो हो सकता है

1800 मेगाहट्र्ज बैंड में नीलामी मूल्य पर लागू किया गया

इनके लिए एक विशिष्ट मूल्य के अभाव में

बैंड*)?*

प्र. *8 3* जी स्पेक्ट्रम पर निर्णय का क्या प्रभाव पड़ता है*?*

नीलामी द्वारा उन संस्थाओं द्वारा अधिग्रहित जिनके लाइसेंस हैंउक्त निर्णय द्वारा रद्द कर दिया गया*?*

नई दिल्ली*;* तारीखः *12* अप्रैल *2012* भारत के राष्ट्रपति *"*

2. संदर्भ के एक नंगे पढ़ने से पता चलता है कि यह है

2 फरवरी*, 2012* को केंद्र में दो विद्वान न्यायाधीशों के लिएजनहित याचिका और अन्य। बनाम भारत संघ और *Ors.*[1] *("2G* केस*"* के लिए*)*।

3. संदर्भ की प्राप्ति पर*, 9* मई के आदेश के माध्यम से*,*

2012 , भारत के महान्यायवादी को नोटिस जारी किया गया था। उस परविद्वान महान्यायवादी को सुनकर*,* आदेश के माध्यम से निर्देश दिया गया

1. (2012) 3 एससीसी *1.*

[2012] 9 एस सी आर।

364 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दिनांक *11* मई*, 2012* को सभी राज्यों को उनके स्थायी वकील के माध्यम से संदर्भ की सूचना जारी की जाएगी।सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन *(*सीपीआईएल*)* और डॉ*.*

सुब्रमण्यम स्वामी *(2* जी मामले में याचिकाकर्ता*);* साथ ही

भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल संघ

(फिक्की*)* और भारतीय उद्योग परिसंघ *(*सी*.* आई*.* आई*.),*

भारतीय उद्योग के प्रतिनिधि। के सुझाव पर

विद्वान महान्यायवादी*,* यह भी निर्देशित किया गया था *(*हालांकि नहीं

आदेश में अभिलिखित*),* कि संदर्भ के साथ व्यवहार किया जाएगा

दो भाग अर्थात। पहली बार में केवल प्रश्न संख्या *1* से *5* पर विचार किया जाएगा और शेष प्रश्न

पहले पाँच प्रश्नों के हमारे उत्तरों के आलोक में प्रश्नों को बाद में लिया जाएगा।

4. संदर्भ की सुनवाई की शुरुआत में

10 जुलाई*, 2012* को*,* रखरखाव के लिए एक मजबूत आपत्ति

2 जी मामले में रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा संदर्भ उठाया गया था। तदनुसार, पहले विद्वान वकील को सुनने का निर्णय लिया गया

संदर्भ की वैधता के प्रश्न पर।

रखरखाव पर निवेदनः

5. श्री सोली सोराबजी, विद्वान वरिष्ठ वकील, उपस्थित हुए

सी. पी. आई. एल. के लिए, दृढ़ता से आग्रह किया गया कि प्रभाव और सार में,

संदर्भ निर्णय की शुद्धता पर सवाल उठाना चाहता है।

2 जी मामले में, जो इस न्यायालय के पास होने के बाद अनुज्ञेय नहीं है

अब कानून के सवाल पर अपनी आधिकारिक राय घोषित की

उठाने की कोशिश की। विद्वान वकील ने तर्क दिया कि संदर्भ

संविधान के अनुच्छेद *143 (1)* के तहत अपील की आवश्यकता नहीं है।या क्षेत्राधिकार की समीक्षा, विशेष रूप से एक निर्णय के संबंध में जो

तथ्य के प्रश्न के संबंध में कोई 'संदेह' व्यक्त करें या सुझाव दें। या सभी प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन से संबंधित कानून, एक वैध संदर्भ के लिए अनिवार्य है। प्रस्ताव के समर्थन में, विद्वान वकील ने पहले के संदर्भों में टिप्पणियों पर भरोसा रखा

इन रेः दिल्ली विधि अधिनियम, *1912*, अजमेर-मेरवाड़ा

(विधियों का विस्तार*)* अधिनियम, *1947* और भाग सी राज्यों *(*विधियों*)*

आरईः *2012* का विशेष संदर्भ संख्या *1*

365

[डी. के. जैन, जे.*]*

अधिनियम, *1950 2*, पुनःः बेरूबरी संघ और विनिमय

संविधान के अनुच्छेद *143 (1)* के तहत संदर्भ संलग्न करता है

भारत का *3*, पुनःः केरल शिक्षा विधेयक, *1,95,7* में

भारत के संविधान के अनुच्छेद *143 (1)* के तहत संदर्भ, *19645* का विशेष संदर्भ संख्या *1 (*आमतौर पर के रूप में संदर्भित*)*

"केशव सिंह "), पुनः: राष्ट्रपति चुनाव, पुनः: द स्पेशल

न्यायालय विधेयक, 19787, निम्नलिखित मामलों में - कावेरी जल विवाद

न्यायाधिकरण (इसके बाद "कावेरी-II" के रूप में संदर्भित) और विशेष

1998 का संदर्भ सं. 1 अनु. 9

6. इसके बाद, विद्वान वरिष्ठ वकील ने इसका प्रतिवाद किया

कि यदि किसी कारण से, कार्यपालिका को लगता है कि 2 जी मामला ऐसा करता है

कानून का एक सही प्रस्ताव निर्धारित नहीं करता है, यह इसके लिए खुला है

एक अन्य पीठ, जिसके समक्ष उक्त निर्णय पर भरोसा किया जाता है, को इस मुद्दे को एक बड़ी पीठ के पास भेजने के लिए राजी करें।

पुनर्विचार। संक्षेप में, निवेदन यह था कि एकआधिकारिक घोषणा, 2 जी मामले की तरह,

अनुच्छेद 143 (1) का सहारा लेकर शॉर्ट सर्किट नहीं किया जा सकता है।

7. विद्वान वकील ने यह भी तर्क दिया कि संदर्भ के रूप में

फ्रेम्ड सर्वव्यापी प्रकृति का होता है, जिस पर जवाब की तलाश होती है

काल्पनिक और अस्पष्ट प्रश्न, और इसलिए, नहीं होने चाहिए जवाब दिया। हमें पुनः बधाईः विशेष न्यायालय विधेयक,

1978 (ऊपर) और कई अन्य निर्णय, विद्वान सलाहकार

आग्रह किया कि संविधान के अनुच्छेद 143 (1) के तहत एक संदर्भ

राय किसी विशिष्ट प्रश्न या प्रश्न पर होनी चाहिए। यह था।

दावा किया कि शर्तों के निर्माण के कारण

संदर्भ, जिस तरह से प्रश्न किए गए हैं

2. [1951] एससीआर 747।

3. [1960] 3 एस. सी. आर 2504 . [1959] एससीआर 995। 5. [1965] 1 एस सी आर 413. 6. (1974) 2 एससीसी 33. 7. (1979) 1 एससीसी 380। 8. 1993 पूरक (1) एस. सी. सी. 96 (II)।

9. (1998) 7 एससीसी 739।

तैयार किए गए और प्रस्तावित उत्तरों की प्रकृति, यह न्यायालय

द्वारा अनुत्तरित संदर्भ को वापस करने का हकदार होगा

यह उत्साहपूर्वक अनुरोध किया गया था कि यदि वर्तमान संदर्भ हैमनोरंजन, यह कार्यपालिका के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा

असुविधाजनक निर्णयों के प्रभाव को दरकिनार या नकारें, जैसे

2 जी मामले में निर्णय, जो न केवल एक निर्धारित करेगा

खतरनाक और अस्वास्थ्यकर मिसाल, लेकिन यह भी स्पष्ट रूप से होगा

कावेरी द्वितीय में निर्णय के अनुपात के विपरीत।

8. श्री प्रशांत भूषण, विद्वान वरिष्ठ वकील, जबकि

श्री सोली सोराबजी द्वारा दिए गए तर्कों को स्वीकार करते हुए,दोहराया कि प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के प्रारूप से भी

2 जी में सरकार द्वारा दायर समीक्षा याचिका से मामला, यह स्पष्ट है कि वर्तमान संदर्भ को रद्द करना चाहता है

2 जी मामले में इस दिशा को पढ़कर निर्णय लिया गया कि

आवंटन के लिए अनुमेय साधन के रूप में केवल 'नीलामी' की अनुमति है। 2 जी मामले के पैराग्राफ 94 से 96 में सभी प्राकृतिक संसाधनों का,

स्पेक्ट्रम के विशिष्ट मामले में। यह विद्वान द्वारा तर्क दिया गया था

सलाह दें कि यह समीक्षा में आग्रह किए गए आधारों से स्पष्ट है सरकार द्वारा दायर याचिका कि वह अनुपात को समझती है

2 जी मामला, संबंधित बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों को अलग करते हुए उन्हें प्रक्रिया के रूप में पालन करने के लिए बाध्य करता है

लोगों के लिए, और फिर भी यह सलाह का उपयोग करना चाहता है अपने पूर्व निर्णय पर अपील के रूप में इस न्यायालय की अधिकारिता।

यह तर्क दिया गया था कि भले ही यह माना जाए कि एक संदेह संबंधित है

सभी प्राकृतिक संसाधनों के निपटान के लिए कारण उत्पन्न हुआ है

इस बिंदु पर निर्णयों के टकराव का, इस तरह का टकराव नहीं हो सकता है

राष्ट्रपति के संदर्भ के माध्यम से हल किया गया; वह राशि होगी

यह अभिनिर्धारित करना कि एक या दूसरे निर्णय गलत हैं

निर्णय लिया गया, जो विद्वान वकील के अनुसार, अनुच्छेद *143 (1)* के दायरे से बाहर है। विद्वान वकील ने आरोप लगाया कि

भाषा जिसमें संदर्भ जोड़ा जाता है, माला प्रदर्शित करता है

कार्यपालिका की ओर से विश्वास करता है। इस प्रकार उन्होंने आग्रह किया कि हमें

राय देने से बचें।

9. डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर *367* पर कड़ी आपत्ति जताई

आरईः *2012* का विशेष संदर्भ संख्या *1*

[डी. के. जैन, जे.*]*

समान आधारों पर संदर्भ की रखरखाव के लिए,

उन्होंने कहा कि वर्तमान संदर्भ की भावना के खिलाफ है

अनुच्छेद *143 (1)*, जो संविधान सभा के अनुसार

बहस, मामले के विपरीत, संयम से लागू किया जाना था

यहाँ। यह अनुरोध किया गया कि संदर्भ *2* जी मामले में निर्देशों के कार्यान्वयन में देरी करने का एक और प्रयास है।

डॉ. एम. इस्माइल फारूकी मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए *&* ओआरएस। बनाम भारत संघ और *Ors.10*, डॉ. स्वामी ने प्रस्तुत किया कि

हमें अच्छी तरह से सलाह दी जाएगी कि हम बिना उत्तर दिए संदर्भ को वापस कर दें।

10. श्री जी. ई. वाहनवती, विद्वान महान्यायवादी

भारत ने संदर्भ का बचाव करते हुए कहा कि याचिका जमीनी स्तर पर संदर्भ की गैर-रखरखाव के संबंध में

कि यह एक 'संदेह' की वर्तनी नहीं करता है, एक मैदान पर गलत है

उसमें तैयार किए गए प्रश्नों को पढ़ें। उनके अनुसार,

अनुच्छेद *143 (1)* में 'प्रश्न' शब्द का उपयोग किया गया है जो तभी उत्पन्न होता है जब

एक 'संदेह' है और यही तथ्य है कि राष्ट्रपति ने मांग की है

पूछे गए प्रश्नों पर इस न्यायालय की राय से पता चलता है कि

उन मुद्दों पर कार्यपालिका के मन में संदेह है।

इस बात पर जोर दिया गया कि केवल इसलिए कि संदर्भ नहीं है अन्य उद्धृत मामलों की तरह, गायन में 'संदेह' शब्द का उपयोग करें,

इसका मतलब यह नहीं है कि सभी प्राकृतिक संसाधनों के अलगाव के तरीके के संबंध में कोई संदेह नहीं है, अन्य

स्पेक्ट्रम की तुलना में, अधिक तब जब राय के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं

इसके दूरगामी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निहितार्थ हैं। यह था।

आग्रह किया कि संदर्भ की सामग्री की उचित परिप्रेक्ष्य में सराहना की जानी चाहिए, न कि संदर्भ को ध्यान में रखते हुए

रूप में।

11. यह आग्रह किया गया था कि रखरखाव और विवेक

किसी संदर्भ का उत्तर देने से इनकार करना दो पूरी तरह से अलग चीजें हैं।

रखरखाव का सवाल तब पैदा होता है जब पूर्व-दृष्टि से,

राष्ट्रपति का संदर्भ बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है।

अनुच्छेद *143 (1)*, विवेकाधिकार के प्रश्न के विपरीत, जो

न्यायालय की किसी संदर्भ का उत्तर देने से इनकार करने की शक्ति है, क्योंकि

अच्छे कारण, एक बार जब संदर्भ बनाए रखने योग्य हो। समर्थन में

10. (1994) 6 एससीसी *360*।

368 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट *[2012] 9* एस. सी. आर.

प्रस्ताव के अनुसार, इन रे पर निर्भरता रखी गई थीः केरल

शिक्षा विधेयक, *1957 (ऊपर)*, केशव सिंह और पुनः: द. विशेष न्यायालय विधेयक, *1978 (ऊपर)*। विद्वानों के अनुसार

परामर्श, सवाल यह है कि क्या संदर्भ का जवाब दिया जाना है या नहीं, रखरखाव का एक पहलू नहीं है, और है

गुण-दोष पर निर्देश सुनने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा।

12. विद्वान महान्यायवादी, याचिका का विरोध करते हुए

कि अनुच्छेद *143 (1)* के तहत एक संदर्भ में, शुद्धता या

अन्यथा पहले के निर्णयों को कभी भी नहीं लिया जा सकता है, प्रस्तुत किया जा सकता है

कि राष्ट्रपति के संदर्भ में, पहले के निर्णयों के संदर्भ के खिलाफ कोई संवैधानिक प्रतिबंध नहीं है ताकि

स्पष्ट करना, दोहराना या यहाँ तक कि एक सिद्धांत पर एक नई राय बनाना

कानून, जब तक कि एक अंतर-पक्षीय निर्णय अप्रभावित रहता है। में।इस तर्क का समर्थन कि अतीत में, निर्णयों की शुद्धता के संबंध में प्रश्नों पर संदर्भ दिए गए हैं,

विद्वान वकील ने इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा रखा

1998 का सं. *1 (*ऊपर*)*, केशव सिंह *(*ऊपर*)* और प्रिवी काउंसिल इन री पाइरेसी ज्यूर जेंटियम *1 1*। यह दावा किया गया है किकार्यपालिका की ओर से बार-बार स्पष्ट किया गया है कि *2* जी मामले में निर्णय स्वीकार कर लिया गया है और नहीं किया जा रहा है

चुनौती दी। संदर्भ निश्चित रूप से आवश्यक था उक्त निर्णय में कानून के बयान के रूप में की गई टिप्पणियाँ

जिसे स्पष्ट करने की आवश्यकता है। कुछ टिप्पणियों का उल्लेख करते हुए

रे में: बेरूबरी संघ और एन्क्लेव्स का आदान-प्रदान *(*ऊपर*)*,

विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय ने स्वीकार किया था कि ए लंबी मुकदमेबाजी से बचने के लिए संदर्भ का जवाब दिया जा सकता है।

13. विद्वान महान्यायवादी ने यह भी तर्क दिया कि

सरकार द्वारा समीक्षा याचिका को वापस लेने का कोई मतलब नहीं है

परिणाम*;* इसकी वापसी का मतलब यह नहीं है कि प्रश्न

अन्य प्राकृतिक संसाधनों के निपटान के अनुमेय तरीके और पर्यावरण से संबंधित मुद्दों के बारे मेंदेश में निवेश तय हो गया। इसका पुरजोर खंडन करते हुए

विद्वान वकील ने आरोप लगाया कि संदर्भ दुर्भावनापूर्ण है

11. [1934] ए. सी. *586*

आरई: *2012* का विशेष संदर्भ संख्या *1*

369

[डी. के. जैन, जे.*]*

यह निर्धारित किया गया कि न्यायालय की ईमानदारी पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है राष्ट्रपति संदर्भ दे रहे हैं।

14. विद्वान वरिष्ठ वकील श्री टी. आर. अंधारुजिना ने आवाज उठाई।

प्रावधानों के बीच एक स्पष्ट संघर्ष से उत्पन्न होने वाली चिंताएँ

2 जी मामले में विधियों और दिए गए निर्णय का*;*

विशेष रूप से खानों की धारा *10* और *11* के संदर्भ में

और खनिज *(*विनियमन और विकास*)* अधिनियम, *1957 (*संक्षेप में, *"*एम. एम. आर. डी. अधिनियम*"),* जो तरजीही नीति निर्धारित करता है।

उपचार और पहले आओ पहले पाओ, *2* जी मामले के विपरीत, जो

विद्वान वकील के अनुसार केवल सभी के लिए नीलामी अनिवार्य है प्राकृतिक संसाधन। इस प्रकार उन्होंने इस न्यायालय से सभी को हटाने का आग्रह किया

के बाद कानून की वास्तविक स्थिति के बारे में अनिश्चितताएँ

2 जी मामले में निर्णय, इसे प्रकाश में इनक्यूरियम के अनुसार आयोजित करके

एम. एम. आर. डी. अधिनियम और अन्य कानूनों के प्रावधान।

15. श्री हरीश साल्वे, विद्वान वरिष्ठ वकील, उपस्थित हुए

सीआईआई की ओर से, संदर्भ का समर्थन करते हुए, उत्साहपूर्वक आग्रह किया गया

कि यह तर्क कि संदर्भ वापस करने योग्य है

संदर्भ के पाठ में *'*संदेह*'* शब्द के उपयोग के अभाव के कारण अनुत्तरित, असमर्थनीय है। इसके अनुसार

विद्वान वकील, अनुच्छेद *143 (1)* के तहत, राष्ट्रपति मांग कर सकते हैं

कानून या तथ्य के किसी भी प्रश्न पर एक राय जो उत्पन्न हुई है, या है उत्पन्न होने की संभावना है, जो ऐसी प्रकृति का है और ऐसा सार्वजनिक है

कानून या तथ्य के कुछ प्रश्नों को निश्चितता प्रदान करने के लिए उत्पन्न होता है जोऐसी प्रकृति और ऐसे क्षण के हैं जो मांग करने के लिए वारंट करते हैं

इस न्यायालय की राय। यह आग्रह किया गया था कि एक पांडित्यपूर्ण व्याख्या,

जिसके द्वारा राष्ट्रपति के संदर्भ को अस्वीकार कर दिया जाएगा

शब्दार्थ संबंधी विचार, जैसे कि शब्द का उपयोग करने में विफलता

'संदर्भ में 'संदेह'को छोड़ दिया जाना चाहिए।

16. विद्वान वकील ने तर्क दिया कि बनाने के चरण में

एक संदर्भ में, यह *370* सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट *[2012] 9* एस. सी. आर. के संबंध में राष्ट्रपति की संतुष्टि है।

प्रश्न की प्रकृति और उसका महत्व जो प्रासंगिक है।संस्थाओं के समुदाय के मामले के रूप में, इस न्यायालय ने हमेशा उन कारणों के पीछे जाने से इनकार किया है जो इस पर प्रबल थे

राष्ट्रपति एक संदर्भ और उसके प्रामाणिक होने के लिए।

फिर भी, इस न्यायालय के पास हमेशा जवाब नहीं देने का विवेकाधिकार हैऐसा कोई संदर्भ या उसमें अच्छे के लिए उठाए गए प्रश्न

कारणों से। इस बात पर जोर दिया गया कि चूंकि यह न्यायालय इसमें नहीं बैठता है

राष्ट्रपति की संतुष्टि पर समीक्षा, का प्रश्न

अधिकारिता और रखरखाव की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है।

17. विद्वान वकील ने यह भी तर्क दिया कि आधार यह है कि

इस न्यायालय के पूर्व निर्णय संदर्भ में बाध्यकारी हैं।

अधिकारिता, और इस प्रकार कोई भी संदर्भ, जो एक पर निहित है

पहले के फैसले को बिना जवाब दिए वापस किया जाना चाहिए, समान रूप से है

भ्रामक। यह तर्क दिया गया था कि टकटकी निर्णय का सिद्धांत और पूर्ववर्ती के सिद्धांत को आम तौर पर स्वीकार किया जाता है और उनका पालन किया जाता है

न्यायिक अनुशासन के नियमों के रूप में और न कि अधिकार क्षेत्र की बाधाओं के रूप में और,

इसलिए, इस न्यायालय को पुनः जाँच करने से नहीं रोका गया है

पिछली पूर्ववर्तियों की शुद्धता। विद्वानों के अनुसार वकील, केशव सिंह में, इस न्यायालय ने जांच की

पंडित एम. एस. एम. शर्मा बनाम में निर्णय की शुद्धता। श्री. श्री कृष्ण सिन्हा और अन्य। *12 (* इसके बाद के रूप में संदर्भित

" शर्मा *")*। कावेरी-*11* में निर्णय के अनुपात की व्याख्या करते हुए,

विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि यह किसी भी सीमा से परे स्पष्ट है

संदेह है कि उक्त घोषणा, कानून के एक अमूर्त प्रस्ताव के रूप में, यह नहीं बताती है कि अनुच्छेद *143 (1)* के तहत, यह न्यायालय किसी भी पूर्ववर्ती की शुद्धता पर विचार नहीं कर सकते। यह जो बताता है वह यह है कि एक बार जब पक्षों के बीच समझौता तय हो जाता है, तो

ऑपरेटिव डिक्री केवल समीक्षा के माध्यम से खोली जा सकती है।

विद्वान वकील के अनुसार, एक फैसले को ओवररूल करना-एक मिसाल के रूप में-डिक्री को फिर से खोलने के समान नहीं है।

18. इसी तर्ज पर बहस करते हुए श्री सी. ए. सुंदरम ने सीखा

12. [1959] सप. *1* एससीआर *806*।

[डी. के. जैन, जे.*]*

फिक्की की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि यदि

2 जी मामले में टिप्पणियों को सभी पर लागू होने के रूप में पढ़ा जाता है

प्राकृतिक संसाधन और स्पेक्ट्रम तक सीमित नहीं, यह होगा

न्यायालय द्वारा वास्तविक नीति निर्माण के समान, जो न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर है। उन्होंने एक बारीकियों को भी लिया

इस पर पुनर्विचार करने की इस न्यायालय की शक्ति पर रुख

कानून की स्थिति का सम्मान; पूर्व इस से परे है एक बार इस न्यायालय की पिछली पीठ की समीक्षा की अदालत की शक्तियाँ

इस पर एक आधिकारिक राय घोषित की है, लेकिन बाद वाली नहीं।

इस प्रकार उन्होंने आग्रह किया कि इस न्यायालय के पास यह शक्ति है कि अपने पूर्ववर्ती में निर्धारित कानून के सिद्धांतों पर पुनर्विचार करें।

अनुच्छेद *141* के तहत भी घोषणाएँ।

19. श्री डेरियस खंबाटा, विद्वान महाधिवक्ता

महाराष्ट्र ने प्रस्तुत किया कि *2* जी मामले में टिप्पणियां थीं

इस प्रकार केवल स्पेक्ट्रम के संबंध में बनाया गया, इसे इसके लिए खुला छोड़ दिया गया

न्यायालय अन्य लोगों के अलगाव के संबंध में मुद्दे की जांच करेगा

प्राकृतिक संसाधन। यह आग्रह किया गया था कि भले ही व्यापक हो

सभी प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में टिप्पणियां की गई थीं, फिर भी यह कहना इस न्यायालय के लिए अनुच्छेद *143 (1)* के तहत खुला होगा

अन्यथा। उन्होंने कुछ राज्य कानूनों की ओर भी इशारा किया कि

नीलामी के अलावा अन्य तरीके निर्धारित करें और इस प्रकार, इस न्यायालय से आग्रह किया

पहले प्रश्न का उत्तर नकारात्मक में देना ताकि उन सभी विधानों को असंवैधानिक न समझा जाए।

20. श्री सुनील गुप्ता, विद्वान वरिष्ठ वकील, पेश हुए

यू. पी. राज्य की ओर से जोड़ा गया कि जब अनुच्छेद *143 (1)*

संविधान एक उच्च संवैधानिक विशेषाधिकार को उजागर करता है

प्राधिकारी, अर्थात् राष्ट्रपति, प्रश्न पर इस न्यायालय से परामर्श करने के लिए

कानून या तथ्य के मामले में, इसमें इस न्यायालय का कम उच्च विशेषाधिकार नहीं है कि वह राष्ट्रपति को निर्दिष्ट प्रश्न पर अपनी राय रिपोर्ट करे,

या तो सवाल का जवाब देकर या देने से इनकार करके। दूसरे शब्दों में, विद्वान वकील के अनुसार, राष्ट्रपति के कहने पर एक संदर्भ बनाए रखने योग्य होने का मुद्दा इस न्यायालय की न्यायिक शक्ति से *372* सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट से अलग है।

संदर्भ में पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें या न दें।

21. श्री रवीन्द्र श्रीवास्तव, विद्वान वरिष्ठ वकील

छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से पेश हुए, तर्क दिया

कि न तो इतिहास समर्थन करता है और न ही वास्तविकता नीलामी का समर्थन करती है

सभी स्थितियों में सभी प्राकृतिक संसाधनों के निपटान का नियम। उन्होंने इस न्यायालय के निर्णयों का उल्लेख किया जो स्पष्ट रूप से एक

राज्य की शक्ति के विचारों के बीच संतुलन और

सार्वजनिक भलाई के प्रति कर्तव्य, प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन के तरीके का विकल्प राज्य पर छोड़ कर, जब तक कि

यह अनुच्छेद *14* की आवश्यकताओं के अनुरूप है। यह अनुरोध किया गया कि राज्य को आवंटन की कार्यप्रणाली चुनने की अनुमति दी जाए।

विशेष रूप से उन मामलों में जहां यह निवेश को प्रोत्साहित करने का इरादा रखता है

और पिछड़े क्षेत्रों में रोजगार सृजन जो अन्यथा निजी खिलाड़ियों द्वारा अछूते छोड़ दिए जाते यदि संसाधन दिए जाते

बाजार मूल्यों पर।

22. संक्षेप में, रखरखाव से संबंधित आपत्तियाँ

संदर्भ मुख्य रूप से निम्नलिखित बिंदुओं पर अभिसरण करते हैंः *((i)*

अनुच्छेद *143 (1)* के तहत संदर्भ के लिए मूलभूत आवश्यकता।

तथ्य या कानून के प्रश्नों के बारे में एक वास्तविक *'*संदेह*'* कि

कार्यकारी श्रमिक अनुपस्थित हैं*; (ii)* फाइलिंग और निकासी

एक समीक्षा याचिका जिसका पाठ *2* जी मामले से संबंधित है

अनुच्छेद *143 (1)* के तहत विवेकाधिकार के प्रयोग में एक बाधा होगी*; (iii)* वह भाषा जिसमें संदर्भ दिया गया है।

कार्यपालिका की ओर से दुर्भावना प्रदर्शित करता है*; (iv)* के आलोक में

कावेरी द्वितीय में मुद्दे पर कानून का उच्चारण, एक मनोरंजक

एक विषय पर राष्ट्रपति का संदर्भ, जो किया गया है

प्रत्यक्ष रूप से और अंतिमता के साथ निर्णय लिया जाता है, वर्जित है; *(v)* वर्तमान संदर्भ *2* जी मामले में इस न्यायालय के फैसले को पलटने का प्रयास है, जो संविधान के अनुच्छेद *143 (1)* की भावना के खिलाफ है।

संविधान और *(vi)* कार्यपालिका *2* जी मामले में निर्देशों से बाहर निकलने के लिए इस संदर्भ के मार्ग को अपना रही है क्योंकि उनका पालन करना उनके लिए असुविधाजनक है।

परिचर्चाः

23. इससे पहले कि हम *373* पर प्रतिद्वंद्वी स्टैंड का मूल्यांकन करें

आरईः *2012* का विशेष संदर्भ संख्या *1*

[डी. के. जैन, जे.*]*

संदर्भ की रखरखाव, यह आवश्यक होगा कि

अनुच्छेद *143* के दायरे और विस्तार की जांच करें

संविधान, जो इस प्रकार पढ़ता हैः

" 143. उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। *(1)* यदि किसी भी समय राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि एक प्रश्न

कानून या तथ्य का उत्पन्न हुआ है, या उत्पन्न होने की संभावना है, जो है

ऐसी प्रकृति और इस तरह के सार्वजनिक महत्व का है कि

सर्वोच्च न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीनयदि, वह प्रश्न को विचार के लिए उस न्यायालय को भेज सकता है

और न्यायालय ऐसी सुनवाई के बाद, जो वह उचित समझे, रिपोर्ट कर सकता है।

राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय दें।

(2) राष्ट्रपति, किसी बात के होते हुए भी,

अनुच्छेद *131* का परंतुक, उल्लिखित प्रकार के विवाद को संदर्भित करता है

राय के लिए उच्चतम न्यायालय को उक्त परंतुक में और

उच्चतम न्यायालय ऐसी सुनवाई के बाद, जो वह उचित समझे,

राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय दें।

लेख को नंगे पढ़ने से पता चलता है कि यह अंतर्वर्धित है।

व्यापक शब्द। अनुच्छेद *143 (1)* की भाषा से यह स्पष्ट है कि

यह आवश्यक नहीं है कि जिस प्रश्न पर राय

उच्चतम न्यायालय की मांग वास्तव में उत्पन्न हुई होगी। द.

राष्ट्रपति उक्त अनुच्छेद के तहत संदर्भ भी दे सकते हैं।

एक पूर्ववर्ती अवस्था, अर्थात्, उस अवस्था में जब राष्ट्रपति

संतुष्ट हैं कि सवाल उठने की संभावना है। संतुष्टि

क्या प्रश्न अनुच्छेद *143 (1)* की पूर्व अपेक्षाओं को पूरा करता है

यह अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति को तय करने का मामला है। रसीद मिलने पर

अनुच्छेद *143 (1)* के तहत एक संदर्भ का, इस न्यायालय का कार्य है -

संदर्भ पर विचार करने के लिए; प्रश्न *(ओं)* जिस पर

राष्ट्रपति ने संदर्भ दिया है, तथ्यों पर जैसा कि में कहा गया है

राष्ट्रपति को अपनी राय भेजें और उसे रिपोर्ट करें।

24. फिर भी, बाद वाले में "मई" शब्द का उपयोग

अनुच्छेद *143 (1)* के भाग का तात्पर्य है कि यह न्यायालय बाध्य नहीं है -

प्रत्येक संदर्भ में सलाहकार राय दें और इनकार कर सकते हैंमजबूत, सम्मोहक और अच्छे कारणों से अपनी राय व्यक्त करें।

केशव सिंह में, वाक्यांश *374* सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट में अंतर को उजागर करते हुए

[2012] 9 एस सी आर।

अनुच्छेद *143* के खंड *(1)* और *(2)* में प्रयुक्त, पी. बी. गजेंद्रगडकर, सी. जे., बहुमत के लिए बोलते हुए, निम्नानुसार आयोजित किया गयाः

"...... जबकि अनुच्छेद के तहत किए गए संदर्भ के मामले में

143 (2) यह इस न्यायालय का संवैधानिक दायित्व है किउस संदर्भ पर उसकी सलाह को शामिल करते हुए एक रिपोर्ट बनाएँ

राय, अनुच्छेद *143 (1)* के तहत दिए गए एक संदर्भ में

ऐसा कोई दायित्व नहीं है। इस बाद के वर्ग से निपटने में

संदर्भ में, इस न्यायालय के लिए यह विचार करने के लिए खुला है कि क्या यह राष्ट्रपति को अपनी सलाह देते हुए एक रिपोर्ट देनी चाहिए

संदर्भ के तहत प्रश्नों पर राय।*25.* इसके अलावा, यहां तक कि पहले के एक फैसले में भीः आवंटन

मुख्य आयुक्त के कार्यालय में स्थित भूमि और भवनों की संख्याप्रांत और राज्यपाल द्वारा संदर्भ के मामले में

धारा*213*, भारत सरकार अधिनियम, *1935* के तहत सामान्य

संघीय न्यायालय ने कहा था कि भले ही न्यायालय अपने दायरे में हो।

किसी संदर्भ पर किसी प्रश्न का उत्तर देने से इनकार करने का अधिकार, उसे इनकार करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए सिवाय अच्छे के

कारण "। इसी तरह के एक वाक्यांश का उपयोग इन रे में किया गया थाः केरल

शिक्षा विधेयक, *1957 (ऊपर)* जब इस न्यायालय ने कहा कि

अनुच्छेद *143 (1)* के तहत किसी संदर्भ पर राय को "उचित मामले" और "अच्छे कारणों से" अस्वीकार किया जा सकता है। डॉ. एम. इस्माइल में

फारूकी और ओआरएस। *(ऊपर)*, यह जोड़ा गया था कि एक संदर्भ नहीं हो सकता है

जब न्यायालय निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं हो तो जवाब दिया जाए

ऐसा प्रश्न जो विशेषज्ञ साक्ष्य पर आधारित हो या राजनीतिक हो।

26. के अनुच्छेद *143 (1)* की प्रासंगिक रूपरेखाओं को ध्यान में रखते हुए

संविधान, अब हम आपत्तियों से निपट सकते हैं

संदर्भ की रखरखाव क्षमता।

27. इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पूरे संदर्भ में

'संदेह' शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। यह भी सच है कि पैरा *5 (उपर्युक्त)* में उल्लिखित पिछले सभी संदर्भों में यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि विभिन्न संदर्भों के बारे में संदेह उत्पन्न हुए थे।

मुद्दे। फिर भी, तथ्य यह है कि अनुच्छेद *143 (1)* ऐसा करता है।

13. ए. आई. आर. *(30) 1943* एफ. सी. *13.*

'संदेह' शब्द का प्रयोग न करें। कोई विशिष्ट प्रारूप प्रदान नहीं किया गया है।

संविधान की किसी भी अनुसूची में कि कैसे एक संदर्भखींचा जाना है। एक संदर्भ में 'संदेह' शब्द का उपयोग है

अनिश्चितता, किसी तथ्य या सिद्धांत के संबंध में हो सकती है। पी में। रामनाथ अय्यर, द मेजर लॉ लेक्सिकन, चौथा संस्करण,

निम्नलिखित में 'संदेह' और 'प्रश्न' शब्दों का वर्णन किया गया है।

तरीका -

अपने निर्णय पर टिके रहना। संदेह पूरी तरह से मन में निहित है। सवाल की तुलना में कम सक्रिय भावना है*;* पूर्व से हम

केवल निर्णय को निलंबित करें*;* बाद वाले द्वारा हम वास्तव में मांग करते हैं

निर्णय लेने में हमारी सहायता करने के लिए प्रमाण। हम संदेह कर सकते हैं

मौन रहें। हम इसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्त किए बिना सवाल नहीं कर सकते। जो संदेह का सुझाव देता है वह इसे सावधानी के साथ करता हैः

जो कोई सवाल करता है वह कठिनाइयों में डाल देता है आत्मविश्वास की डिग्री। हम एक स्थिति की सच्चाई पर संदेह करते हैं*;* हम

एक लेखक की सच्चाई पर सवाल उठाते हैं। *(* क्रेब*.) "*

संक्षिप्त ऑक्सफोर्ड शब्दकोश *(*दसवें संस्करण*)* के अनुसार, 'प्रश्न'

मतलबः *"* एक संदेह*;* एक संदेह या आपत्ति को उठाना*;* एक समस्या जिसके समाधान की आवश्यकता होती है।

ब्लैक लॉ डिक्शनरी में 'संदेह' को एक क्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है।

इस प्रकार हैः

"सवाल पूछना या संदिग्ध ठहराना। "

एक संज्ञा के रूप में 'संदेह' शब्द का वर्णन इस प्रकार किया गया हैः

"मन की अनिश्चितता; एक स्थिर राय की अनुपस्थिति या

विश्वास; की स्वीकृति के प्रति मन का दृष्टिकोण

या किसी प्रस्ताव, सिद्धांत या कथन में विश्वास, जिसमें निर्णय स्थिर नहीं है, लेकिन दोनों पक्षों के लिए बारी-बारी से झुका हुआ है।

28. तत्काल संदर्भ के पूर्व-निकाले गए पाठ

बता दें कि वर्तमान परिस्थितियों में, कानून के कुछ प्रश्न *376* सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

[2012] 9 एस सी आर।

दूरगामी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों के साथ

उत्पन्न हुआ, नीलामी के संचालन के संबंध में और दूरसंचार उद्योग का विनियमन

निर्णय *(2* जी मामला*)* के साथ जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रवाह को प्रभावित कर सकता है

दूरसंचार उद्योग और अन्यथा अन्य क्षेत्रों में

देश। इसके बाद, यह भी कहा जाता है कि कानून के प्रश्नउत्पन्न हुए हैं जो बहुत सार्वजनिक महत्व के हैं और दूर के हैं

इसलिए, इस न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन माना जाता है। संदर्भ का प्रश्न संख्या *1* इस प्रकार हैः

"क्या सभी के निपटान के लिए एकमात्र अनुमेय विधि है

सभी क्षेत्रों में और सभी में प्राकृतिक संसाधनपरिस्थितियाँ नीलामी के संचालन से होती हैं*?*

29. इस मोड़ पर, लाभप्रद रूप से संदर्भ दिया जा सकता है -

इन रे में निर्णयः विशेष न्यायालय विधेयक*, 1978 (*ऊपर*),*

सात विद्वान न्यायाधीशों की पीठ द्वारा एक राय, जिसमें यह था

निम्नलिखित रूप में देखा गयाः

"27. हम, तर्क के एक चरण में, इतना था

संदर्भ की अनिर्धारित चौड़ाई पर प्रयोग किया गया कि

हम गंभीरता से विचार कर रहे थे कि क्या

परिस्थितियों में संदर्भ वापस करने की सलाह नहीं दी गई थी

अनुत्तरित। लेकिन पक्षों द्वारा दायर लिखित विवरण और

हमारे सामने मौखिक तर्क हैं, उनके द्वारापूर्णता और क्षमता, कानूनी को कम करने में मदद की

विधेयक के आसपास के विवादों और हमारे विचार के लिए उत्पन्न होने वाले मुद्दों को स्पष्ट करने के लिए। हम प्रस्ताव करते हैं किहमारी राय को विशेष रूप से हमारे सामने उठाए गए बिंदुओं तक सीमित रखें।

इस स्तर पर यह इंगित करना सुविधाजनक होगा कि वे क्या हैं।

अंक हैं "।

यह आशा व्यक्त करते हुए कि भविष्य में इस न्यायालय की राय के लिए विशिष्ट प्रश्न तैयार किए जाएंगे, वाई. वी. चंद्रचूड़ *(* जैसा कि उनके अधिपति तब थे*)*, बहुमत के लिए बोलते हुए कहाः

"30. हम आशा करते हैं कि भविष्य में जब भी कोई संदर्भ दिया जाएगा

संविधान के अनुच्छेद *143* के तहत इस न्यायालय को देखभाल *377* होगी।

आरईः *2012* का विशेष संदर्भ संख्या *1*

[डी. के. जैन, जे.*]*

न्यायालय की राय के लिए विशिष्ट प्रश्न तैयार करने के लिए लिया जाए। सौभाग्य से, यह पल में संभव हो गया है

संदर्भ की शर्तों के भीतर समझा गया लेकिनजोखिम है कि एक अस्पष्ट और सामान्य संदर्भ वापस किया जा सकता है

अनुत्तरित वास्तविक है और इसका ध्यान आकर्षित करना चाहिए

जिनका कर्तव्य संदर्भ तैयार करना है। क्या थे*?*

संदर्भ में दोनों बिंदुओं की समझ ऊपर हमारे द्वारा उल्लिखित और जिसे हम तय करने का प्रस्ताव करते हैं।

एक लंबा विधेयक विशिष्ट बिंदुओं पर संदर्भ के अभाव में हमारे सामने एक उलझन भरा कार्य प्रस्तुत करता, जिससे यह हो जाता

विधेयक के प्रावधानों को संवैधानिक चुनौती। *30.* उपरोक्त निकाले गए अनुच्छेदों में से तीन व्यापक हैं।

सिद्धांत उभरते हैं: *((i)* संदर्भ अस्पष्ट, सामान्य नहीं होना चाहिए।

और अव्याख्यायित, *(ii)* यह न्यायालय कानूनी विवादों को कम करने के लिए लिखित संक्षिप्त विवरण और तर्कों को देख सकता है, और *(iii)*

जब प्रश्न अनिर्दिष्ट और समझ से बाहर हो जाता है,

अनुत्तरित संदर्भ को वापस करने का जोखिम उत्पन्न होता है। केशव में

सिंह, इस न्यायालय ने संदर्भ की वैधता पर विचार करते हुए,

-पहले के निर्णयों का उल्लेख किया और निम्नलिखित रूप में राय दी:

"...... इस प्रकार यह देखा जाएगा कि अब तक के प्रश्न संदर्भित किए गए हैं। राष्ट्रपति द्वारा इस न्यायालय की सलाहकार राय के लिए

अनुच्छेद *143 (1)* के तहत एक समान पैटर्न का खुलासा नहीं करते हैं और

यह स्पष्ट रूप से अनुच्छेद *143 (1)* में उपयोग किए गए व्यापक और व्यापक शब्दों के अनुरूप है।

31. पूर्व-उल्लिखित मामलों का विश्लेषण इंगित करता है कि न तो कोई विशेष प्रारूप निर्धारित किया गया है और न ही कोई विशिष्ट प्रारूप निर्धारित किया गया है।

संदर्भों को तैयार करने में पैटर्न का पालन किया गया है। पहला सिद्धांत

*'*रूप*'* से संबंधित है और दूसरा *'*के पैटर्न*'* से संबंधित है

अकेले पैटर्न में, एक संदर्भ को बिना उत्तर दिए वापस नहीं किया जाना है। यह.उचित विश्लेषण, समझ और प्रशंसा की आवश्यकता है

378 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट *[2012] 9* एस. सी. आर.

संवैधानिक उत्तरदायित्व, न्यायिक औचित्य और न्यायिक विवेक की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए।

32. इस प्रकार, हमें इस स्थिति को स्वीकार करना मुश्किल लगता है कि

अनुच्छेद *143 (1)* के तहत किसी संदर्भ को बनाए रखने योग्य बनाने के लिए 'संदेह' शब्द एक आवश्यक शर्त है। इसके अलावा, हमारे विचार में,ऊपर उद्धृत प्रश्न संख्या *1* न तो अस्पष्ट है और न ही सामान्य या

अनिर्दिष्ट, लेकिन समझ के दायरे में है जो है

कानून के किसी प्रश्न से संबंधित। यह एक 'संदेह' व्यक्त करता है और चाहता है

उस प्रश्न पर न्यायालय की राय, अन्य के अलावा।

33. जहाँ तक दाखिल करने और वापस लेने के प्रभाव का संबंध है

तत्काल संदर्भ की रखरखाव पर *2* जी मामले में संबंधित है, यह अभिलेख का विषय है कि पुनरीक्षण याचिका में,

समीक्षा के लिए आधारों के कुछ पहलू जो

संदर्भ के पाठों के साथ-साथ कुछ प्रश्नों में बताए गए प्रश्नों पर प्रकाश डाला गया। हालांकि, एक खाड़ी है

इस न्यायालय द्वारा प्रयोग की गई अधिकारिता के बीच अंतर

समीक्षा और संदर्भ का उत्तर देने में प्रयोग किया गया विवेकाधिकार

संविधान के अनुच्छेद *143 (1)* के तहत। मूल रूप से एक समीक्षा

निर्णय की समीक्षा के लिए सुव्यवस्थित सिद्धांतों द्वारा निर्देशित

और एक डिक्री या आदेश दोनों पक्षों के बीच पारित किया गया। न्यायालय में

समीक्षा की शक्ति का प्रयोग इसके तहत समीक्षा का मनोरंजन कर सकता है

स्वीकार्य और व्यवस्थित मापदंड। लेकिन, जब इस बारे में कोई राय

कार्यपालिका द्वारा अदालत की मांग की जाती है जो एक

संवैधानिक शक्ति, कहने की आवश्यकता नहीं है, वही एक पर खड़ा है

पूरी तरह से अलग पैर। एक समीक्षा विशिष्ट है और अधिकार विवाद के पक्षकारों से उसमें निपटा जाता है, जबकि

एक संदर्भ का उत्तर शर्तों को ध्यान में रखते हुए दिया जाता है

संदर्भ और जांच करना कि क्या वही संतुष्ट करता हैअनुच्छेद के तहत नियोजित भाषा में निहित आवश्यकताएँ

143 (1) संविधान से। हमारी राय में, केवल

क्योंकि एक समीक्षा दायर की गई थी और वापस ले ली गई थी औरकथन का पाठ उक्त मामले से संबंधित है, यह विवेकाधिकार के प्रयोग के लिए कोई प्रतिबंध या बाधा नहीं होगी

संदर्भ का उत्तर दें।

आरईः *2012* का विशेष संदर्भ संख्या *1*

379

[डी. के. जैन, जे.*]*

34. जहाँ तक दुर्भावनापूर्ण आरोप का संबंध है, यह है

मान लीजिए कि इस न्यायालय को न तो सच्चाई में जाने की आवश्यकता है और न ही अन्यथा पाठ के तथ्यों के बारे में और न ही यह प्रामाणिक होने के सवाल में जा सकता है या अन्यथा प्राधिकरण के बारे में

संदर्भ। *[* देखिएः इन रेः राष्ट्रपति चुनाव *(*ऊपर*)]*। इसे रखने के लिए

अलग तरह से, इस न्यायालय की राय लेने की संवैधानिक शक्ति

राष्ट्रपति के साथ आराम करें। इस न्यायालय का एकमात्र विवेकाधिकार हैया तो संदर्भ का जवाब देने के लिए या सम्मानपूर्वक भेजने से इनकार करने के लिए

राष्ट्रपति को रिपोर्ट करें। इसलिए जमीनी स्तर पर चुनौती

दुर्भावना, जैसा कि उठाया गया है, अस्थिर है।

35. रखरखाव के लिए प्रमुख आपत्ति

अस्वीकार्य। विरोध करने वालों का रुख यह है कि *2* जी मामला सिद्धांत के संबंध में एक आधिकारिक मिसाल है याकानून का प्रस्ताव कि सभी प्राकृतिक संसाधनों का निपटान किया जाना है

सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से और इसलिए, संदर्भ को बनाए रखने योग्य नहीं माना जाना चाहिए। इस ओर से जोर दिया गया था

उक्त निर्णय के पैराग्राफ *85* और *94* से *96*। प्रस्ताव के समर्थन में, कावेरी द्वितीय पर भारी निर्भरता रखी गई थी।

36. शुरुआत में, हम ध्यान दे सकते हैं कि विद्वान वकील

जनरल ने एक से अधिक बार कहा है कि भारत सरकार *2* जी में निर्देशों की शुद्धता पर सवाल नहीं उठा रहा है

मामला, जहाँ तक स्पेक्ट्रम के आवंटन का संबंध है, और वास्तव में सरकार इसे लागू करने की प्रक्रिया में हैसमान रूप से, अक्षर और आत्मा में। इसलिए, उक्त के प्रकाश में

बयान, हम महसूस करते हैं कि इस प्रस्तुति पर टिप्पणी करना अनावश्यक होगा कि संदर्भ प्राप्त करने का एक प्रयास है

इस न्यायालय के निर्णय और निर्देशों को अस्थिर करने के लिए राय

2 जी मामला। फिर भी, उपरोक्त के समर्थन में

प्रस्तुत करते हुए, कावेरी द्वितीय में इस न्यायालय की राय दी गई है

संदर्भित और विस्तार से निर्भर, यह उचित होगा

कावेरी द्वितीय के वास्तविक अनुपात को समझने के लिए, जो वर्तमान संदर्भ की स्थिरता के लिए विपक्ष का लिंचपिन है।

37. कावेरी द्वितीय से पहले तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु राज्य था।

कर्नाटक राज्य और *Ors.14* (इसके बाद *"*कावेरी*"* के रूप में संदर्भित)

I "), जो इस मुद्दे पर केंद्रित था कि क्या कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण (संक्षेप में *"*न्यायाधिकरण*")* के पास यह शक्ति थी कि

अंतरिम राहत प्रदान करें। उस मामले में, राज्य द्वारा दायर आवेदन तत्काल अंतरिम राहत के लिए तमिलनाडु को खारिज कर दिया गया था

न्यायाधिकरण ने इस आधार पर कि वे बनाए रखने योग्य नहीं थे। यह

आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसके परिणामस्वरूप *26* अप्रैल के फैसले में,

1991 इस न्यायालय द्वारा, जहाँ यह निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित किया गया थाः

" 15. इस प्रकार, हम मानते हैं कि यह न्यायालय अंतिम दुभाषिया है अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम के प्रावधानों का,

1956 और सीमाएँ, शक्तियाँ और निर्णय लेने का अधिकार है

अधिनियम के तहत गठित न्यायाधिकरण की अधिकारिता।

इस न्यायालय के पास न केवल निर्णय लेने की शक्ति है बल्कि दायित्व भी हैइस बारे में कि क्या न्यायाधिकरण का कोई अधिकार क्षेत्र है या नहीं

अधिनियम, किसी भी अंतरिम आवेदन को अंतिम रूप से स्वीकार करने के लिए

इसे संदर्भित विवाद का फैसला करता है।

38. न्यायाधिकरण ने फैसला सुनाया था कि चूंकि यह अन्य की तरह नहीं था

अंतरिम राहत देने की अंतर्निहित शक्तियों वाले न्यायालय, केवल उस स्थिति में जब केंद्र सरकार ने किसी मामले को अंतरिम राहत के लिए भेजा हो,क्या उसे यह देने का अधिकार क्षेत्र होगा। अन्य बातों के अलावा,

न्यायालय ने कहा कि न्यायाधिकरण यह अभिनिर्धारित करने में गलत था कि

केंद्र सरकार ने अनुदान देने के लिए कोई संदर्भ नहीं दिया था

कोई भी अंतरिम राहत, और यह निष्कर्ष निकाला कि अंतरिम राहतों ने प्रार्थना की

स्पष्ट रूप से द्वारा निर्दिष्ट विवाद के दायरे में आता है

केंद्र सरकार। तदनुसार, द्वारा पसंद की गई अपीलें

तमिलनाडु राज्य को अनुमति दी गई और न्यायाधिकरण को निर्देश दिया गया

अंतरिम राहत के लिए आवेदनों पर निर्णय लेना। हालांकि, अदालत ने

इस बड़े सवाल का फैसला नहीं किया कि क्या अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम, *1956* के तहत गठित एक न्यायाधिकरण के पास अंतरिम राहत देने की शक्ति थी, हालांकि इसका जवाब

अंतिम दिशा से भी यही अनुमान लगाया जा सकता है।

39. इन निर्देशों के अनुसरण में, न्यायाधिकरण ने निर्णय लिया

आवेदन और *25* जून, *1991* के अपने आदेश के माध्यम से,*14. 1991* पूरक *(1)* एस. सी. सी. *240*।

381

आरईः *2012* का विशेष संदर्भ संख्या *1*

[डी. के. जैन, जे.*]*

कर्नाटक राज्य को कुछ निर्देश जारी करने के लिए आगे बढ़े।

इसके बाद *25* जुलाई *1991* को कर्नाटक के राज्यपाल ने

कर्नाटक कावेरी बेसिन नामक एक अध्यादेश जारी किया।

सिंचाई संरक्षण अध्यादेश, *1991* "। ऊँची एड़ी पर गर्मअध्यादेश, कर्नाटक राज्य ने भी इसके तहत एक मुकदमा दायर किया

तमिलनाडु राज्य के खिलाफ संविधान का अनुच्छेद *131*

एक घोषणा के लिए कि न्यायाधिकरण का आदेश अंतरिम राहत प्रदान करता है

अधिकारिता के बिना था और इसलिए, शून्य और शून्य, आदि। द.

अध्यादेश का स्थान *1991* के अधिनियम *27* ने ले लिया। के संदर्भ में

इन घटनाक्रमों का राष्ट्रपति ने इस संदर्भ में उल्लेख किया

संविधान के अनुच्छेद *143 (1)* के तहत न्यायालय, तीन

राय के लिए प्रश्न। संदर्भ का तीसरा प्रश्न,

वर्तमान संदर्भ के लिए प्रासंगिक थाः

" 3. क्या जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया गया है

अधिनियम पक्षों को कोई भी अंतरिम राहत देने के लिए सक्षम है। विवाद के लिए "।

हालाँकि, कावेरी द्वितीय में संदर्भ पर विचार करते हुए,

न्यायालय ने प्रश्न को विभाजित किया, अर्थात। , क्या जल विवाद न्यायाधिकरण है

अधिनियम के तहत गठित कोई भी अंतरिम राहत देने के लिए सक्षम है

दो भागों में: *(i)* जब अंतरिम राहत देने के लिए एक संदर्भ है

न्यायाधिकरण को दिया गया, और *(ii)* जब ऐसा कोई संदर्भ नहीं दिया जाता है

इसके लिए। कर्नाटक और केरल राज्यों ने इसका विरोध किया था। कि यदि न्यायाधिकरण के पास अंतरिम राहत देने की शक्ति नहीं थी, तो

केंद्र सरकार ऐसा करने में अक्षम होगी

उद्देश्य के लिए पहला संदर्भ और न्यायाधिकरण में

इस तरह के संदर्भ पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा, यदि

बनाया गया। उक्त प्रस्तुति से निपटना, एक करने के बाद पहले के आदेश के संदर्भ में, इस न्यायालय ने कहा कि एक बार केंद्र सरकार ने न्यायाधिकरण के लिए एक संदर्भ दिया था

अंतरिम राहत के लिए दावे पर विचार, द्वारा प्रार्थना की गईतमिलनाडु राज्य, न्यायाधिकरण के पास विचार करने का अधिकार क्षेत्र था

उक्त अनुरोध स्वयं संदर्भ का एक हिस्सा है। में निहित है

उक्त निर्णय यह निष्कर्ष था कि अंतरिम राहत का विषय

उक्त अधिनियम की धारा *5 (1)* के अर्थ के भीतर जल विवाद से जुड़ा या प्रासंगिक मामला था।

यह *382* सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट *[2012] 9* एस. सी. आर. आयोजित किया गया था।

कि केंद्र सरकार इस मामले को मंजूरी के लिए भेज सकती है

न्यायनिर्णयन के लिए न्यायाधिकरण को अंतरिम राहत।

40. अदालत के आने का परिणाम

निष्कर्ष, तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए यह था कि न्यायाधिकरण के पास अंतरिम फैसला देने का अधिकार क्षेत्र नहीं था

या अंतरिम राहत प्रदान करने के परिणामस्वरूप न केवल न्यायालय दोनों के बीच अपने पहले के फैसले को खारिज कर देता पक्षकार अर्थात् दोनों राज्य, लेकिन तब भी इसकी आवश्यकता होती

न्यायालय न्यायाधिकरण के आदेश को बिना होने के रूप में घोषित करेगाअधिकार क्षेत्र। इसलिए अदालत ने कहाः

"83 ...... हालाँकि इस न्यायालय ने उक्त निर्णय द्वारा रखा है

प्रश्न खोलें। , क्या न्यायाधिकरण आनुषंगिक है,

अंतरिम राहत देने के लिए सहायक, अंतर्निहित या निहित शक्ति जब ऐसी राहत देने के लिए कोई संदर्भ नहीं दिया जाता है अगर, यह शब्दों में प्रश्न के दूसरे भाग को समाप्त कर दिया है।

इसलिए, हम ऐसी स्थिति को स्वीकार नहीं कर सकते हैं जिसके तहत

प्रश्न *3* और उस मामले के लिए प्रश्न *1* और *2* हो सकते हैं

ताकि उक्त निर्णय पर हमारी राय आमंत्रित की जा सके

इस न्यायालय से। यह स्पष्ट रूप से हमारे समान होगा

उक्त निर्णय पर अपील में बैठे जो यह है

न्यायनिर्णायक अधिकारिता में भी ऐसा करना हमारे लिए अनुज्ञेय नहीं है।

न ही राष्ट्रपति के लिए यह सक्षम है कि वह हमें एक के साथ निवेश करेएक के माध्यम से उक्त निर्णय पर अपीलीय क्षेत्राधिकार

संविधान के अनुच्छेद *143* के तहत संदर्भ "।

न्यायनिर्णायक प्रक्रिया में नहीं किया जाना समान रूप से नहीं होगा एक संदर्भ की प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त किया गया।

41. अभिव्यक्ति, "अपील में बैठना" सटीक थी।

उपयोग किया जाता है। एक अपीलीय न्यायालय निचली अदालत की डिक्री *(*या रिट, आदेश या निर्देश*)* को खाली कर देता है जब वह एक अपील की अनुमति देता है-जो है -

इस न्यायालय को कावेरी *I* में क्या करने के लिए आमंत्रित किया गया था।

उस अपील का निर्णय पहले किया गया था, जिसमें कहा गया था कि न्यायाधिकरण के पास आरई थाः

2012 का विशेष संदर्भ संख्या *1*

383

[डी. के. जैन, जे.*]*

तमिल राज्य द्वारा मांगे गए अंतरिम आदेश को पारित करने का अधिकार क्षेत्र

नाडू। उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार न्यायाधिकरण द्वारा पारित अंतरिम आदेश को आधार पर रद्द करना।

कि यह अधिकारिता के बिना था, अनिवार्य रूप से न्यायाधिकरण को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश को खाली करने की आवश्यकता होगी

अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करें और अंतरिम मामले का फैसला करें। पैरा *85*

उस निर्णय ने मामले को किसी भी संदेह से परे कर दिया हैः

" 85 ...... सबसे पहले, के खंड *(1)* की भाषा

अनुच्छेद *143* श्री नरीमन के तर्क का समर्थन नहीं करता है।

वह इसका विरोध करता है। उक्त खंड राष्ट्रपति को अधिकार देता है

इस न्यायालय की राय के लिए कानून या तथ्य का प्रश्न संदर्भित करना।

जो उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है। जब इस न्यायालय में

एकर न्यायनिर्णायक क्षेत्राधिकार एकर आधिकारिक घोषणा करैत अछि।

कानून के प्रश्न पर राय, यह नहीं कहा जा सकता है कि वहाँ

कानून के सवाल पर सभी अदालतों और प्राधिकरणों के लिए बाध्यकारी है। अतः उक्त खंड के तहत राष्ट्रपति एक का उल्लेख कर सकते हैं

कानून का सवाल केवल तभी होता है जब इस न्यायालय ने इसका फैसला नहीं किया हो।

दूसरा, इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की समीक्षा की जा सकती है।

केवल अनुच्छेद *137* के तहत आदेश *40* के नियम *1* के साथ पढ़ा जाता है उच्चतम न्यायालय नियम, *1966* और शर्तों पर

उसमें उल्लेख किया गया है। जब, आगे, यह न्यायालय ओवररूल करता है

एक पूर्व मामले में उसके द्वारा व्यक्त कानून का दृष्टिकोण, यह नहीं है अपील में बैठकर और अपील का प्रयोग करते हुए ऐसा करें

पहले के निर्णय पर अधिकार क्षेत्र। यह व्यायाम में ऐसा करता है।

इसकी अंतर्निहित शक्ति और केवल असाधारण परिस्थितियों में

जैसे कि जब पहले का निर्णय आकस्मिकता के अनुसार होता है या है प्रासंगिक या भौतिक तथ्यों के अभाव में दिया गया या यदि

यह स्पष्ट रूप से गलत है और सार्वजनिक शरारत का उत्पादक है।

[देखिएः बंगाल इम्युनिटी कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य

(1955) 2 एससीआर *603]*। संविधान के तहत इस तरह की अपील

अधिकारिता इस न्यायालय में निहित नहीं है और न ही इसे निहित किया जा सकता है।

इसमें राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद *143* के तहत।

श्री *384* सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट *[2012] 9* एस. सी. आर. को स्वीकार करना।

नरीमन के तर्क का मतलब होगा कि सलाह

अनुच्छेद *143* के तहत अधिकार क्षेत्र भी एक अपीलीय है। के बीच अपने स्वयं के निर्णय पर इस न्यायालय की अधिकारिता

समान पक्षों और कार्यपालिका के पास इस न्यायालय से अपने निर्णय को संशोधित करने के लिए कहने की शक्ति है। यदि इस तरह की शक्ति को अनुच्छेद *143* में पढ़ा जाता है तो यह स्वतंत्रता में एक गंभीर प्रवेश होगा।

न्यायपालिका "।

42. आखिरकार, संदर्भ का जवाब दिया गया था

निम्नलिखित शब्दों में प्रश्न संख्या *3:*

"प्रश्न संख्या *3: (i)* अधिनियम के तहत गठित जल विवाद न्यायाधिकरण कोई भी अंतरिम मंजूरी देने के लिए सक्षम है।

विवाद के पक्षों को राहत जब इस तरह के लिए एक संदर्भ केंद्र सरकार द्वारा राहत दी जाती है*;*

((ii) क्या न्यायाधिकरण के पास अंतरिम मंजूरी देने की शक्ति है।

जब केंद्र द्वारा कोई संदर्भ नहीं दिया जाता है तो राहतइस तरह की राहत के लिए सरकार एक ऐसा सवाल है जो नहीं है

उन तथ्यों और परिस्थितियों में उत्पन्न होता है जिनके तहत

संदर्भ दिया जाता है। इसलिए हम इसे आवश्यक नहीं समझते हैं।

एक ही जवाब देने के लिए। *"43.* श्री सोली सोराबजी का मुख्य जोर इस पर था कि

पैराग्राफ *85* का दूसरा भाग, जो उनके अनुसार, इस न्यायालय को पहले व्यक्त किए गए विचार को रद्द करने से रोकता है।

अनुच्छेद *143 (1)* के तहत। हम सहमत होने के लिए राजी नहीं हैं विद्वान वरिष्ठ वकील। परिच्छेद को ध्यान से पढ़ना होगा।

जे. सावंत सबसे पहले इस न्यायालय के "निर्णय" के मामले पर विचार करते हैं।

जबकि बाद के वाक्य में वह एक दृष्टिकोण पर विचार करता है

न्यायालय द्वारा व्यक्त कानून, और इसकी व्याख्या करने का प्रयास

इन दोनों स्थितियों के दृष्टिकोण के बीच अंतर।

इन शब्दों का उपयोग कभी-कभी एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है लेकिन नहीं।यहाँ ऊपर। हमारा मानना है कि न्यायमूर्ति सावंत जानबूझकर न्याय करते हैं

मामले पर चर्चा करने के बाद "जब, आगे, यह न्यायालय कानून के दृष्टिकोण को खारिज कर देता है" शब्दों का उपयोग करके दोनों के बीच का अंतर।

एक "निर्णय"।

44. ब्लैक लॉ डिक्शनरी एक "निर्णय" को "ए" के रूप में परिभाषित करती है।

तथ्यों पर विचार करने के बाद निर्णय लिया गया, और

कानूनी संदर्भ, कानून "; एक" राय "के रूप में" एक न्यायाधीश द्वारा बयान "

या किसी कारण के संबंध में निर्णय की अदालत ने प्रयास किया या उनके समक्ष बहस करते हुए, मामले में लागू कानून की व्याख्या करते हुए,

और उन कारणों का विवरण देना जिन पर निर्णय आधारित है।

और "निर्णय" और "राय" के बीच के अंतर की व्याख्या करता है। इस प्रकार हैः

"निर्णय आवश्यक रूप से 'राय' का पर्याय नहीं है। ए.

न्यायालय का निर्णय उसका निर्णय है; राय है

उस निर्णय के लिए दिए गए कारण, या की अभिव्यक्ति

न्यायाधीश के विचार "। *45.* इसलिए, पैरा *85* में "निर्णय" के संदर्भ और

"कानून के दृष्टिकोण को एक दूसरे से अलग किया जाना चाहिए। विद्वान।

न्यायाधीश ने कहा कि किसी निर्णय के मामले में, अपीलीयसर्वोच्च द्वारा एक घोषणा के बाद संरचना समाप्त हो जाती है

अदालत। इसलिए, पक्षकारों के पास समीक्षा का ही एकमात्र विकल्प बचा है

या उपचारात्मक अधिकारिता *(*निर्णय में उकेरा गया एक उपाय*)*

रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा और अन्न। *15) .* उन सीमित विकल्पों के प्रयोग के बाद, संबंधित पक्षों के पास है विवाद के संबंध में बिल्कुल कोई राहत नहीं है; यह माना जाता है

कानून की नजर में अनंत काल के लिए बस गए। हालाँकि कानून की नज़र में जो शाश्वत और अभी भी लचीली नहीं है, वह है राय या

"निर्णय पर पहुँचने के क्रम में घोषित कानून का दृष्टिकोण। न्यायमूर्ति सावंत स्पष्ट करते हैं कि इस न्यायालय की अपीलीय शक्ति के विपरीत,

इसकी अंतर्निहित शक्ति जब वे कहते हैं, ". यह बैठे हुए ऐसा नहीं करता है। पहले के निर्णय पर अपील और अपीलीय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना। यह अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए और केवल असाधारण परिस्थितियों में ऐसा करता है।

रूपा अशोक हुर्रा *(ऊपर)* में दो अभिव्यक्तियों के बीच का अंतर, निम्नलिखित शब्दों मेंः

"24. इस बात का कोई खंडन नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय है

15. (2002) 4 एससीसी *388*।

[2012] 9 एस सी आर।

386 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस न्यायालय द्वारा देश का कानून है*;* यह अपने लिए पूर्ववर्ती है। और भारत में सभी न्यायालयों/न्यायाधिकरणों और प्राधिकरणों के लिए। ए में

वहाँ निर्णय कानून की घोषणा और उसके अनुप्रयोग होगा

विवाद पर निर्णय देने के लिए मामले के तथ्यों पर

पार्टियों के बीच एल. आई. एस. तक। इसे संभालना जरूरी है

ध्यान रखें कि उच्चतम न्यायालय के संबंध में सिद्धांत

इसके बाध्यकारी पूर्ववर्ती से प्रस्थान अलग हैं

जिन आधारों पर पक्षों के बीच अंतिम निर्णय हो सकता हैपुनर्विचार किया जाए। यहाँ, हम मुख्य रूप से चिंतित हैं

बाद वाला। हालांकि, जब इस फैसले पर पुनर्विचार किया जाता है

न्यायालय से घोषित कानून से जुड़ी अंतिमता मांगी जाती है

साथ ही मामले में किए गए निर्णय के लिए, सामान्य रूप से है

चुनौती के तहत लाया गया "।

इसलिए, दो सीमाएँ हैं-एक अधिकार क्षेत्र और दूसरी स्व-अधिरोपित।

46. पहली सीमा यह है कि इस न्यायालय का निर्णय कर सकता है

किसी और तरीके से नहीं। यह इस संदर्भ में था कि कावेरी के पैरा *85* में *II,* इस न्यायालय ने कहा था कि राष्ट्रपति एक प्रश्न का उल्लेख कर सकते हैं

जब इस न्यायालय ने इसका निर्णय नहीं किया है। श्री हरीश साल्वे,विद्वान वरिष्ठ वकील, सही है जब वह तर्क देता है कि एक बार

पार्टियों के बीच तय किया जाता है, ऑपरेटिव डिक्री केवल हो सकती है

समीक्षा में खोला गया। फैसले को उलटना-एक मिसाल के रूप में -डिक्री को फिर से नहीं खोलता है।

47. दूसरी सीमा, न्यायिक व्यवस्था का एक स्व-अधिरोपित नियम

अनुशासन, वह था जो एक कानूनी पर न्यायालय की राय को खत्म कर देता था

मुद्दा अपील में बैठने का गठन नहीं करता है, लेकिन केवल असाधारण परिस्थितियों में किया जाता है, जैसे कि जब पहले निर्णय लिया गया हो।

प्रासंगिक या भौतिक तथ्यों के अभाव में दिया जाता है या यदि यह स्पष्ट रूप से गलत है और सार्वजनिक शरारत पैदा करने में सक्षम है। इस प्रस्ताव के लिए, न्यायालय ने इस पर भरोसा किया कि

बंगाल प्रतिरक्षा मामले *(ऊपर)* में निर्णय जिसमें यह था

अभिनिर्धारित किया कि जब अनुच्छेद *141* यह निर्धारित करता है कि आरई द्वारा घोषित कानूनः

2012 का विशेष संदर्भ संख्या *1*

387

[डी. के. जैन, जे.*]*

यह न्यायालय भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होगा, यह स्पष्ट रूप से इस न्यायालय के अलावा अन्य न्यायालयों को संदर्भित करता है।

और यह कि न्यायालय आम तौर पर पिछले उदाहरणों का पालन करेगा, सिवाय इसके कि जहां इस पर पुनर्विचार करना आवश्यक था

उस निर्णय में निर्धारित कानून की शुद्धता। वास्तव में,कानून के किसी सिद्धांत का अतिनिर्णय अपीलीय का परिणाम नहीं है।

अधिकारिता लेकिन इसकी अंतर्निहित शक्ति का एक परिणाम। यह

अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग तब तक किया जा सकता है जब तक कि पिछली डिक्री

यह अंतर-पक्षीय रूप से प्रभावित नहीं होता है। यह पलटने की कोशिश है

पिछले मामले का निर्णय जो समस्याग्रस्त है, यही कारण है कि

न्यायालय ने कहा कि "संविधान के तहत ऐसी अपीलीय अधिकारिता इस न्यायालय में निहित नहीं है, और न ही इसे इसमें निहित किया जा सकता है।

राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद *143* के तहत।

48. इसलिए, कावेरी द्वितीय में विवाद को शामिल किया गया था

कावेरी *1* में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय द्वारापक्षकारों और निर्णय ने न्यायिक प्रक्रिया के रूप में काम किया और

इसलिए, यह राय दी गई कि अनुच्छेद *143 (1)* के तहत विवेकाधिकार हो सकता है

व्यायाम न करें। यह भी देखा गया है कि इस न्यायालय ने

अंतर-राज्यीय जल के प्रासंगिक प्रावधानों का विश्लेषण किया गया

विवाद अधिनियम, *1956* और उसके बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि

कि न्यायाधिकरण के पास अंतरिम राहत देने का अधिकार क्षेत्र था यदि अंतरिम राहत देने का प्रश्न संदर्भ का हिस्सा था। इस आधारशिला पर यह माना गया था कि निर्णय रेस के रूप में संचालित होता है

न्यायपालिका। अतः कावेरी द्वितीय से यह स्पष्ट है कि न्यायालय ने

स्पष्ट रूप से पिछले के अनुपात को स्पष्ट करने के खिलाफ नहीं था

कावेरी प्रथम में एक सलाहकार अधिकार क्षेत्र के दौरान निर्णय।

कावेरी द्वितीय का अपसारित पैरा *85*, इस न्यायालय के सलाहकार अधिकार क्षेत्र को निर्णय को पलटने के सीमित बिंदु पर प्रतिबंधित करता है।

एक 'विवाद' या एक दूसरे के बीच का मुद्दा।

49. अंत में इस न्यायालय की सात न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट रूप से

अभिनिर्धारित किया कि इस न्यायालय के पास अनुच्छेद *143 (1)* के तहत शक्ति है

इसके द्वारा दिए गए पिछले दृश्य को रद्द करने के लिए। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़, सी. जे. पुनः: विशेष न्यायालय विधेयक *(ऊपर)*

आयोजितः

[2012] 9 एस सी आर।

388

"101 ...... हम इस दृष्टिकोण की ओर झुकाव रखते हैं कि हालांकि यह हमेशा होता है

पहले से ही प्रश्न की पुनः जांच करने के लिए इस न्यायालय के लिए खुला है

इसके द्वारा निर्णय लिया गया और यदि आवश्यक हो, तो पहले के दृष्टिकोण को रद्द कर दिया गया

भारत के क्षेत्र में अन्य सभी न्यायालयों की तरह, इसके द्वारा लिया गया

वे चिंतित हैं कि उन्हें दृष्टिकोण से बंधा होना चाहिए

इस न्यायालय द्वारा अपनी सलाह के प्रयोग में भी व्यक्त किया गया

संविधान के अनुच्छेद *143 (1)* के तहत अधिकार क्षेत्र।

50. उच्चारणों का एक समूह है जिसमें यह

न्यायालय ने या तो पिछले निर्णयों के अनुपात को समझाया, स्पष्ट किया या पढ़ा है। सबसे पहले संदर्भ में, पुनः: दिल्ली

विधि अधिनियम, *1912 (ऊपर)*, संदर्भ के कारण किया गया था

जतिन्द्र नाथ गुप्ता बनाम में संघीय न्यायालय का निर्णय। बिहार प्रांत *& Ors.16*। इसकी पृष्ठभूमि

मुखर्जिया, जे. ने संदर्भ की व्याख्या इस प्रकार कीः

"इस न्यायालय की सलाहकार राय लेने की आवश्यकता

कहा जाता है कि यह इस तथ्य से उत्पन्न हुआ है कि क्योंकि

जतिन्द्र नाथ गुप्ता बनाम में संघीय न्यायालय का निर्णय।

बिहार प्रांत, जिसके पास उप-प्रावधान था

बिहार सार्वजनिक रखरखाव की धारा *1* की धारा *(3)*आदेश अधिनियम, *1947*, बिहार प्रांत के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

विधायिका, इसकी राशि के कारण एक प्रतिनिधिमंडल के लिए एक बाहरी प्राधिकरण के लिए इसकी विधायी शक्तियाँ, संदेह

दूसरा वास्तव में कुछ न्यायिक मामलों में विचाराधीन हैकुछ उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित कार्यवाही

भारत में न्यायालय "।

न्यायमूर्ति दास ने इसी राय में, यह देखते हुए कि निर्भरता थी जतिंद्र नाथ गुप्ता *(ऊपर)* में संघीय न्यायालय के फैसले पर हस्तक्षेप करने वालों के लिए विद्वान वकील द्वारा रखा गया, दर्ज किया गया

जिसे विद्वान महान्यायवादी ने कड़ी चुनौती दी थी उस मामले में संघीय न्यायालय के बहुमत के निर्णय की शुद्धता। अन्य बातों के साथ, यह देखते हुए कि संदर्भ था

16. [1949-50] एफ. सी. आर. *595.*

एक तरह से उस निर्णय के कारण, विद्वान न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया

इस प्रकार हैः

"मैं अत्यंत विनम्रता के साथ यह कहने के लिए बाध्य महसूस करता हूं कि

कारण पहले से ही दिए गए हैं, कि बहुमत की टिप्पणियाँ

उस मामले में संघीय न्यायालय बहुत दूर चला गया और

विद्वान महान्यायवादी के साथ समझौता, मैं असमर्थ हूँ

उन्हें सिद्धांतों की सही व्याख्या के रूप में स्वीकार करना।

विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन से संबंधित "।

51. इस संदर्भ में केशव का उल्लेख करना फायदेमंद होगा।

राष्ट्रपति जो मूल रूप से विशेषाधिकारों से संबंधित था विधान सभा और एक पीठ द्वारा अधिकार क्षेत्र का प्रयोग

उच्च न्यायालय से। उच्च न्यायालय ने एक रिट याचिका पर विचार किया

संविधान के अनुच्छेद *226* के तहत, निर्णय को चुनौती देते हुए

विधानसभा ने एक केशव सिंह को प्रतिबद्ध किया, जो नहीं था

इसके सदस्यों में से एक, इसकी अवमानना के लिए जेल में। मसला यह था कि

चाहे रिट याचिका पर विचार करके, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश

न्यायालय के उल्लंघन के लिए विधानमंडल की अवमानना की गई थी

इसके विशेषाधिकार और उन्मुक्ति। उसी के लिए, यह न्यायालय में निहित प्रासंगिक प्रावधानों का अर्थ लगाने के लिए आगे बढ़े

अनुच्छेद *194 (3)* और संविधान के अन्य अनुच्छेदों के साथ इसका सामंजस्य

संविधान, विशेष रूप से अनुच्छेद *19 (1) (ए), 21* और *22.* इस संदर्भ में,

*"*शर्मा*" (*ऊपर*)* में निर्णय विचार के लिए आया।शर्मा के मामले में जो सवाल उठे उनमें से एक था -

निहित प्रावधानों पर अनुच्छेद *19 (1) (ए)* और *21* का प्रभाव अनुच्छेद *194 (3)* के उत्तरार्ध में। अधिकांश लोगों का मानना था कि

विचाराधीन विशेषाधिकार प्रासंगिक समय पर मौजूद था और

इसलिए, के बाद के भाग के तहत शामिल माना जाना चाहिए

अनुच्छेद *194 (3)*। यह अभिनिर्धारित किया गया कि अनुच्छेद *19 (1) (ए)* लागू नहीं होता है

19 (1) (क*)* अनुच्छेद *194 (3)* के साथ सीधे टकराव में था। विशेष तौर पर बाद के अनुच्छेद में प्रावधान सामान्य पर प्रबल होगा

पूर्व में निहित प्रावधान। यह आगे कहा गया कि हालांकि

अनुच्छेद *21* लागू हुआ, इसका उल्लंघन नहीं किया गया था। अल्पसंख्यक

दूसरी ओर, विचार ने माना कि विचाराधीन विशेषाधिकार में *[2012] 9* एस. सी. आर. था।

390 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

स्थापित नहीं किया गया; यहां तक कि यह मानते हुए भी कि वही स्थापित किया गया था

और इसे अनुच्छेद *194 (3)* के उत्तरार्ध में शामिल किया जाना था, फिर भी इसे इस आधार पर अनुच्छेद *19 (1) (ए)* द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए कि

संविधान के भाग *III* द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकार

सर्वोच्च महत्व के थे और एक पर प्रबल होना चाहिए

गुणपति केशवरम रेड्डी बनाम नफीसुल में निर्णय पर हसन और *U.P.17* राज्य ने देखा कि उक्त

निर्णय पूरी तरह से एक रियायत पर आधारित था और नहीं कर सकता था,

इसलिए, इस न्यायालय का एक सुविचारित निर्णय माना जाए।

52. केशवरम रेड्डी *(ऊपर)* में निर्णय से निपटा गया

अनुच्छेद *22 (2)* के अधीन आने वाले मामले में अनुच्छेद *22 (2)* की प्रयोज्यता

अनुच्छेद *194 (3)* का भाग। यह ध्यान देने योग्य है कि शर्मा की अल्पमत राय ने केशवराम रेड्डी को एक अभिव्यक्ति के रूप में माना

राय मानी जाती है, जो न्यायालय के लिए बाध्यकारी थी। केशव में

सिंह की राय थी कि शर्मा के मामले में, बहुमत के फैसले में कहा गया था कि अनुच्छेद *21* के लिए लागू था

निष्कर्ष कि कथित उल्लंघन साबित नहीं हुआ था। अल्पमत के दृष्टिकोण पर टिप्पणी करते हुए यह राय दी गई कि यह था

यह विचार करना अनावश्यक है कि क्या अनुच्छेद *21* इस तरह से लागू होता है क्योंकि उक्त दृष्टिकोण सभी मौलिक अधिकारों को मानता है।

भाग *III* द्वारा सर्वोपरि रूप से गारंटी दी गई है, और इसलिए, उनमें से प्रत्येक अनुच्छेद *194 (3)* के प्रावधानों को नियंत्रित कर सकता है।

53. उस समय पीठ ने कहा कि

शर्मा, याचिकाकर्ता द्वारा आग्रह की गई दलीलों ने एक नहीं उठाया

सभी की प्रासंगिकता और प्रयोज्यता के रूप में सामान्य मुद्दा

भाग *III* द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकार। द.

केवल दो अनुच्छेदों के उल्लंघन का अनुरोध किया गया था और वे थे

अनुच्छेद *194 (3)* का हिस्सा सामान्य रूप से मौलिक अधिकारों के अधीन था, और वास्तव में, बहुमत के विचार पर भी यह नहीं हो सकता था*17.* आकाशवाणी *1954* एससी *636*।

391

आरईः *2012* का विशेष संदर्भ संख्या *1*

[डी. के. जैन, जे.*]*

कहा कि उक्त दृष्टिकोण ने सभी के आवेदन को बाहर कर दियामौलिक अधिकार, स्पष्ट और सरल कारण के लिए कि

अनुच्छेद *21* को लागू माना गया था और उसके कथित उल्लंघन के बारे में याचिकाकर्ता की दलीलों के गुण-दोष

मामले की जांच की गई और खारिज कर दिया गया। इसलिए, यह सही नहीं था

बहुमत के निर्णय को सामान्य निर्णय के रूप में पढ़ने के लिए

अनुच्छेद *194 (3)* के उत्तरार्द्ध भाग के प्रावधान और इनमें से कोई भी भाग *III* द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के प्रावधान,

उत्तरार्द्ध को हमेशा पूर्व के आगे झुकना चाहिए। यह आगे देखा गया था

कि बहुमत के निर्णय ने संयोग से टिप्पणी की थी

केशवराम रेड्डी के मामले में निर्णय *(ऊपर)*। इसके अलावा

अनुच्छेद *22* के लागू होने के बारे में कोई विवाद नहीं था

उस मामले में, और इसलिए, बहुमत द्वारा की गई टिप्पणी

पहले के निर्णय पर निर्णय आंशिक रूप से सटीक नहीं था। उनके

वकील की रियायत और एक के रूप में नहीं माना जा सकता हैइस विषय पर राय पर विचार किया। ऐसा कहने के बाद, पीठ ने

इस प्रकार राय दीः

"...... इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस टिप्पणी का पहला भाग है

सटीक नहीं। वकील द्वारा रियायत दी गई थी

टिप्पणी को सख्ती से उचित नहीं कहा जा सकता है। यह है,हालाँकि, यह सच है कि गुणों के बारे में कोई चर्चा नहीं है

श्री मिस्त्री की ओर से उठाए गए विवाद और उस पर

इस हद तक, बहुमत के निर्णय के लिए यह कहना अनुज्ञेय हो सकता है कि यह एक सुविचारित राय नहीं थी

न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में कोई मुद्दा नहीं उठापंडित शर्मा का मामला। इसलिए हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं।

कि *392* सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट *[2012] 9* एस. सी. आर. के पूर्व निर्णय की वैधता या शुद्धता के बारे में बहुमत के निर्णय में की गई आज्ञाकारी टिप्पणियाँ।

गुणपति केशवरम रेड्डी के मामले में इस अदालत को ऐसा नहीं करना चाहिए

यह माना जाए कि उन्होंने प्रश्न का निर्णय ले लिया है। अन्य में

शब्दों में, यह सवाल कि क्या अनुच्छेद *22 (2)* लागू होगाऐसे मामले पर इस न्यायालय द्वारा विचार किया जा सकता है यदि

ए. आर. घ "जब ऐसा करना आवश्यक हो जाए।

54. उपरोक्त निर्णय से यह स्पष्ट है कि जबकि

संविधान के अनुच्छेद *143 (1)* के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना

यह न्यायालय इस उद्देश्य के लिए पहले के निर्णय पर विचार कर सकता है -

क्या पिछले निर्णय में आग्रह किए गए विवाद ने उठाया था

एक सामान्य मुद्दा या नहीं; क्या बड़े मुद्दे पर विचार करना आवश्यक था जो उत्पन्न नहीं हुआ था; और क्या एक सामान्य मुद्दा

प्रस्ताव रखा गया था। यह भी कहा गया है कि

जहाँ एक की प्रयोज्यता के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न नहीं हुआ

संवैधानिक कानून का विशेष पहलू, एक में की गई टिप्पणियां

निर्णय को सटीक नहीं माना जा सकता है; और आगे यह हो सकता है यह राय दी जानी चाहिए कि पहले के निर्णय में कुछ आज्ञाकारी हैं

अवलोकन।

55. इस प्रकार, केशव सिंह में, एक सात-न्यायाधीश पीठ, जबकि

अनुच्छेद *143 (1)* के तहत एक संदर्भ का मनोरंजन करना, एक

इसकी व्याख्या के संबंध में पिछला निर्णय जिसमें एक कुछ अनुच्छेदों के संबंध में संवैधानिक सिद्धांत, और

उन्होंने यह मत व्यक्त किया कि शर्मा के मामले में व्यक्त विचार,केशवराम रेड्डी के मामले में दिए गए एक प्रस्ताव के संबंध में, यह गलत था।

56. इस स्तर पर, सर्वोच्च न्यायालय को संदर्भित करना योग्य है

अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन और अन्य। बनाम यूनियन ऑफ

भारत *1 8.* जे. एस. वर्मा, जे. *(*उस समय उनके प्रभु के रूप में*)* के लिए बोल रहे थे।

न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित अन्य निष्कर्षों के अलावा, बहुमत हस्तांतरण के साथ, इस प्रकार व्यक्त किया गयाः

" (8) स्थानांतरित न्यायाधीश/मुख्य न्यायाधीश की सहमति नहीं है से पहले या किसी भी बाद के हस्तांतरण के लिए आवश्यक

एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय।

18. (1993) 4 एससीसी *441*।

393

आरईः *2012* का विशेष संदर्भ संख्या *1*

[डी. के. जैन, जे.*]*

(9) प्रमुख की सिफारिश पर किया गया कोई भी स्थानांतरणभारत के न्याय को दंडात्मक नहीं माना जाना चाहिए, और

इंगित का पालन किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है किसी को भी न्यायसंगत अधिकार प्रदान करें।

(11) केवल निर्दिष्ट आधारों पर सीमित न्यायिक समीक्षा

पहले नियुक्तियों के मामलों में उपलब्ध है और

स्थानांतरण "।

जहाँ तक सीमित न्यायिक समीक्षा के आधार का संबंध है

ओरिटी ने इस प्रकार राय दीः

" 481. मानदंडों के रूप में ये दिशा-निर्देश नहीं होने चाहिए

में किसी भी न्यायसंगत अधिकार को प्रदान करने के रूप में माना जाता है

न्यायाधीश का स्थानांतरण। संवैधानिक आवश्यकता के अलावा

स्थानांतरण केवल की सिफारिश पर किया जा रहा है

भारत के मुख्य न्यायाधीश, स्थानांतरण का मुद्दा नहीं है

कारणों सहित किसी भी अन्य आधार पर न्यायोचितस्थानांतरण या उनकी पर्याप्तता। मुखिया की राय

इंगित तरीके से गठित भारत का न्याय पर्याप्त है किसी भी मनमानेपन या पूर्वाग्रह के खिलाफ सुरक्षा और संरक्षण,

साथ ही स्वतंत्रता का कोई क्षरण

न्यायपालिका।

482. ...... के साथ परामर्श की इच्छा के आधार को छोड़कर

नामित संवैधानिक पदाधिकारी या किसी की कमी

की सिफारिश के बिना किया जा रहा स्थानांतरण भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये मामले न्यायसंगत नहीं हैं

पक्षपात सहित कोई अन्य आधार, जो किसी भी मामले में

की प्रक्रिया में बहुलता के तत्व द्वारा बहिष्कृत किया जाता है

निर्णय लेना "।

57. 1998 के विशेष संदर्भ संख्या *1* में, *(*सामान्यतः*)*

*"*दूसरे न्यायाधीशों के मामले*"* के रूप में गलती की गई*)*, प्रश्न संख्या *2* पढ़ता हैनिम्नलिखित हैः

" (2) क्या न्यायाधीशों का स्थानांतरण न्यायिक रूप से समीक्षा योग्य है उपरोक्त निर्णय में उच्चतम न्यायालय के अवलोकन के आलोक में कि 'इस तरह का स्थानांतरण न्यायसंगत नहीं है

कोई भी आधार 'और इसका आगे का अवलोकन जो सीमित न्यायिक है

हस्तांतरण के मामलों में समीक्षा उपलब्ध है, और सीमा और

न्यायिक समीक्षा का दायरा "।

उसी का जवाब देते हुए, पीठ ने इस प्रकार राय दीः

" 37. इसमें शामिल गंभीरता को देखते हुए यह हमारे दिमाग के लिए अनिवार्य है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण में, कि मुख्य न्यायाधीश

भारत के मुख्य न्यायाधीश के विचार प्राप्त करने चाहिए

उच्च न्यायालय जहाँ से प्रस्तावित स्थानांतरण किया जाना है

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी प्रभावित

जिसे हस्तांतरण किया जाना है। यह इस बात से सहमत है

दूसरे न्यायाधीशों के मामले में बहुमत का निर्णय जो

दूसरे के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श का प्रतिपादन करता है

उच्च न्यायालय। भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी इसमें शामिल होना चाहिए।

उच्चतम न्यायालय के एक या अधिक न्यायाधीशों के विचारों को ध्यान में रखें।

जो ऐसी सामग्री प्रदान करने की स्थिति में हैं जो

प्रस्तावित है या नहीं, यह तय करने की प्रक्रिया में सहायता करना।

स्थानांतरण होना चाहिए। ये विचार होने चाहिए

लिखित रूप में व्यक्त किया गया और इसके द्वारा विचार किया जाना चाहिए

भारत के मुख्य न्यायाधीश और चार वरिष्ठतम न्यायाधीश

चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों में से प्रत्येक को होना चाहिएके साथ भारत सरकार को प्रेषित किया गया

स्थानांतरण का प्रस्ताव। जब तक स्थानांतरण का निर्णय नहीं लिया गया है वनाच्छादित तरीके से लिया गया है, यह निर्णायक नहीं है

और भारत सरकार को बाध्य नहीं करता है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद *217 (1)* और *222 (1)* में भारत में न्यायाधीशों की बहुलता के साथ परामर्श की आवश्यकता है

भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय का गठन। द.

भारत के मुख्य न्यायाधीश की एकमात्र व्यक्तिगत राय *395* है।

आरईः *2012* का विशेष संदर्भ संख्या *1*

[डी. के. जैन, जे.]

उक्त के अर्थ के भीतर "परामर्श" का गठन नहीं करता है

2. कनिष्ठ न्यायाधीशों का स्थानांतरण न्यायिक रूप से समीक्षा योग्य है केवल इस हद तकः कि सिफारिश की गई है कि

भारत के मुख्य न्यायाधीश ने इस संबंध में ऐसा नहीं किया है

चार वरिष्ठतम बच्चों के परामर्श से बनाया गया था

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और/या उनके विचार

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिनका स्थानांतरण किया गया है

जिस पर हस्तांतरण किया जाना है, वह नहीं किया गया है। प्राप्त किया "।

58. उपरोक्त से, यह स्पष्ट है कि जबकि

अनुच्छेद *143 (1)* के तहत संदर्भ पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने

के माध्यम से समावेश के तरीके या विधि में से एक के रूप में कहा जाए अनुपात को बदले बिना संशोधन करें। इसके लिए

किसी संदर्भ की वैधता का उद्देश्य, यह कहने के लिए पर्याप्त है किपूर्व निर्णय की अनुमति है। इसके अलावा, कोई भी इस तथ्य से अनजान नहीं हो सकता है कि सीमित न्यायिक समीक्षा का दायरा,

दूसरा न्यायाधीश मामला, जो अन्यथा काफी प्रतिबंधित है,

राष्ट्रपति के लिए अदालत की राय में थोड़ा विस्तार किया गया था

संदर्भ।

59. यह ध्यान देने योग्य है कि लगभग हर

अनुच्छेद *143 (1)* के तहत दायर संदर्भ को चुनौती मिली है।

एक या दूसरे आधार पर इसकी रखरखाव के बारे में, लेकिन सभी

डॉ. एम. इस्माइल फारूकी और अन्य को छोड़कर, संदर्भों का जवाब दिया गया है। *(ऊपर),* जिसे बिना जवाब दिए वापस कर दिया गया था, मुख्य रूप से इस आधार पर कि संदर्भ एक संवैधानिक उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है।

60. उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि

न्यायालय सम्मानपूर्वक एक संदर्भ का उत्तर देने से इनकार कर देगा यदि वह है

अनुचित, अस्वीकार्य और अवांछनीय; या तैयार किए गए प्रश्नों के विशुद्ध रूप से सामाजिक-आर्थिक या राजनीतिक कारण हैं, *396* सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट *[2012] 9* एस. सी. आर.

जिनका किसी भी प्रावधान से कोई संबंध नहीं हैसंविधान के या अन्यथा कोई संवैधानिक नहीं हैं

महत्व; या जवाब देने में असमर्थ हैं; या नहीं करेंगे

किसी भी उद्देश्य को कम करता है; या आधिकारिक घोषणा होती है

इस न्यायालय ने पहले ही निर्दिष्ट प्रश्न का निर्णय ले लिया है।

61. हाथ में मामले में, यह जांच की जानी है कि क्या

2 जी केस एक ऐसा निर्णय है जिसने निपटा है और निर्णय लिया है

प्रश्न संख्या *1* में निहित विवाद या इनमें से किसी से भी मिलता हैऊपर उल्लिखित मानदंड। जैसा कि हम समझते हैं, इस प्रश्न में अनुच्छेद के तहत निहित संवैधानिक सिद्धांत की व्याख्या शामिल है।

14 संविधान और यह बहुत सार्वजनिक महत्व का है क्योंकि यह

प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन/अलगाव/निपटान/वितरण से संबंधित

संसाधन। इसके अलावा सवाल यह है कि क्या *2* जी मामला चल रहा है।

उस संबंध में आधिकारिक घोषणा पर विचार किया जाना चाहिए तभी एक राय व्यक्त की जा सकती है। उक्त व्यक्ति के लिए

उद्देश्य अन्य सभी बाधाएं दूर से काम में नहीं आती हैंवर्तमान संदर्भ में।

62. इसलिए हमारा विचार है कि जब तक

स्पेक्ट्रम लाइसेंसों के आवंटन के संबंध में निर्णय है

अछूत, यह न्यायालय मूल्यांकन करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में है और

2 जी मामले में निर्णय के अनुपात को स्पष्ट करें। इस उद्देश्य के लिए तर्क के इस चरण में, इस पर बहुत कम जोर देने की आवश्यकता है, कि हम

2 जी में निर्णय के अनुपात को स्पष्ट करने का अधिकार क्षेत्र है

मामला, चाहे हम वास्तव में ऐसा करने के लिए चुनते हैं या नहीं। इसलिए, यह तथ्य कि इस संदर्भ के लिए हमें आवश्यकता हो सकती है

2 जी में जो कहा गया है उससे कुछ अलग कहेंकानून के प्रस्ताव के रूप में मामला, मूल पर प्रहार नहीं कर सकता है

संदर्भ की रखरखाव क्षमता। नतीजतन, हम अस्वीकार करते हैं

2 जी के अनुपात पर इसके प्रभाव के बावजूद बनाए रखने योग्य मामला, जब तक उस मामले में निर्णय अंतर-पक्षीय है

अप्रभावित छोड़ दिया जाता है।

मैरिट्स परः

63. यह हमें *397* का खुलासा किए गए विवाद के गुणों की ओर ले जाता है।

आरईः *2012* का विशेष संदर्भ संख्या *1*

[डी. के. जैन, जे.*]*

हमारे परामर्श के लिए संदर्भ में तैयार किए गए प्रश्नों में

राय दें।

64. जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, *2* जी मामले में फैसला

इसके अलावा अन्य तरीकों की वैधता के बारे में संदेह पैदा किया' प्राकृतिक संसाधनों के निपटान के लिए 'नीलामी', जिसके परिणामस्वरूप अंततः

वर्तमान संदर्भ दाखिल करने के लिए। इसलिए इससे पहले कि हम

प्रश्न संख्या *1* का उत्तर देने के लिए आगे बढ़ें, यह समझना अनिवार्य है कि *2* जी मामले में सटीक रूप से क्या कहा गया है और व्याख्या करें

उस मामले में घोषित कानून।

65. सभी वकील इस बात से सहमत थे कि अनुच्छेद *94* से *96* में

उक्त निर्णय अनुपात बनाम निपटान का भंडार है।

2 जी मामले में प्राकृतिक संसाधनों का। एक तरफ यह था कि तर्क दिया कि ये पैराग्राफ कानून के प्रस्ताव के रूप में निर्धारित करते हैं,

कि सभी क्षेत्रों में सभी प्राकृतिक संसाधन, और सभी में

सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से परिस्थितियों का निपटारा किया जाना है, और दूसरी ओर, यह आग्रह किया गया था कि उसमें टिप्पणियाँ

प्रतिद्वंद्वी स्टैंड में से, हम उन सिद्धांतों को संक्षेप में दोहरा सकते हैं जो एक निर्णय द्वारा घोषित 'कानून' के निर्धारण को नियंत्रित करते हैं।और इसका वास्तविक अनुपात।

66. संविधान के अनुच्छेद *141* में कहा गया है कि 'कानून

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित 'सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी हैभारत के क्षेत्र के भीतर। 'घोषित कानून' होना चाहिए

कानून के एक सिद्धांत के रूप में माना जाता है जो एक निर्णय से निकलता है,

या उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी कानून या निर्णय की व्याख्या,

जिसके आधार पर मामले का फैसला किया जाता है। *[* देखिएः फिदा हुसैन और ओआरएस। बनाम मुरादाबाद विकास प्राधिकरण और अन्र। *1 9]*। इसलिए यह

ऊपर से प्रवाहित होता है कि 'घोषित कानून सिद्धांत है

उठाए गए प्रश्नों के आलोक में समग्र रूप से एक निर्णय को पढ़ने पर निकाला जाता है, जिस पर मामले का निर्णय लिया जाता है। *[* साथ ही

देखूः अम्बिका क्वारी वर्क्स बनाम गुजरात राज्य और आयकर आयुक्त बनाम सन इंजीनियरिंग वर्क्स *(*पी*)*

Ltd.2[1]*]*। दूसरे शब्दों में, एक निर्णय में 'घोषित कानून', जो

19. (2011) 12 एससीसी *615*।

20. (1987) 1 एस. सी. सी. *212. 21. (1992) 4* एससीसी *363*।

न्यायालयों पर बाध्यकारी है, निर्णय का अनुपात निर्णय है। यह एक निर्णय और उस सिद्धांत का सार है जिस पर,

मामला तय किया जाता है, जिसके संबंध में पता लगाया जाना है

विषय-निर्णय का विषय।

67. प्रत्येक मामले में तथ्यों का एक अलग समूह और एक निर्णय शामिल होता है।

अपने स्वयं के तथ्यों पर एक मिसाल है; एक न्यायाधीश द्वारा कहा गया सब कुछ नहीं

निर्णय देते समय पूर्ववर्ती मूल्य निर्धारित किया जा सकता है। द.

एक निर्णय का सार जो पक्षकारों को मामले से जोड़ता है वह है -

जिस सिद्धांत पर मामले का निर्णय लिया जाता है और इस कारण से,किसी निर्णय का विश्लेषण करना और उससे अनुपात निकालना महत्वपूर्ण है।

फैसला करें। पूर्ववर्तियों को लागू करने के मामले में, विद्वान

न्यायमूर्ति बेंजामिन कार्डोजो "एक न्यायिक की प्रकृति" में

प्रोसेस ", ने कहा था कि" यदि न्यायाधीश इसे बुद्धिमानी से सुनाना चाहते हैं,

चयन के कुछ सिद्धांत उनका मार्गदर्शन करने के लिए होने चाहिए।

मान्यता के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले सभी संभावित निर्णय "और" लगभग निश्चित रूप से उनका पहला कदम उनकी जांच और तुलना करना है; "यह खोज, तुलना और कुछ और की प्रक्रिया है" और ऐसा नहीं होना चाहिए।

के खिलाफ हाथ में मामले के रंगों का मिलान करने के समान होना

कई नमूना मामलों के रंग "क्योंकि उस मामले में"

जिस व्यक्ति के पास मामलों का सबसे अच्छा कार्ड सूचकांक था, वह भी होगा

सबसे बुद्धिमान न्यायाधीश "। पूर्ववर्ती के साथ तुलना करने के खिलाफ चेतावनी

एक मामले के साथ दूसरे मामले के रंगों का मिलान करते हुए, उन्होंने संक्षेप में कहाप्रक्रिया, यदि रंग मेल नहीं खाते हैं, तो निम्नलिखित क्रम में

शब्दः

"यह तब होता है जब रंग मेल नहीं खाते हैं, जब संदर्भ

सूचकांक में विफल, जब कोई निर्णायक मिसाल नहीं है, कि

न्यायाधीश का गंभीर कार्य शुरू हो जाता है। तब उसे ऐसा करना चाहिए।

उसके सामने वादियों के लिए फैशन कानून। उनके लिए इसे बनाने में, वह इसे दूसरों के लिए बनाएगा। क्लासिक

बेकन का बयान हैः "कई बार, चीजों का अनुमान लगाया जाता है

जब इसका कारण और परिणाम संपत्ति के बिंदु तक पहुँच सकता है, तो निर्णय बहुत कम हो सकता है। द.

आज का वाक्य सही और गलत बना देगा

कल "। आरईः

2012 का विशेष संदर्भ संख्या *1*

399

[डी. के. जैन, जे.*]*

68. निर्णयों के पूर्ववर्ती मूल्य के संदर्भ में,

उड़ीसा और अन्य राज्यों में। बनाम मो. इलियास *22* इस न्यायालय ने टिप्पणी कीः

"...... पूर्ववर्तियों के सुस्थापित सिद्धांत के अनुसार, प्रत्येक

निर्णय में तीन बुनियादी अभिधारणाएँ शामिल हैंः *((i)* के निष्कर्ष

भौतिक तथ्य, प्रत्यक्ष और अनुमानित। एक अनुमानित खोजतथ्यों का वह निष्कर्ष है जिससे न्यायाधीश निष्कर्ष निकालता है -

प्रत्यक्ष या बोधगम्य तथ्य; *(ii)* सिद्धांतों के कथन।

द्वारा प्रकट की गई कानूनी समस्याओं पर लागू कानून का

तथ्य; और *(iii)* के संयुक्त प्रभाव के आधार पर निर्णय

उपरोक्त। एक निर्णय एक प्राधिकरण है कि यह वास्तव में क्या है।

तय करते हैं। किसी निर्णय में जो सार होता है वह है उसका अनुपात।

और न हर अवलोकन जो उसमें पाया जाता है और न ही तार्किक रूप से

में की गई विभिन्न टिप्पणियों से बहती है

फैसला "।

69. हाल ही में, भारत संघ बनाम अमृत लाल मनचंदा

& Anr.23, इस न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की हैः

"...... अदालतों की टिप्पणियों को न तो इस रूप में पढ़ा जाना चाहिए

यूक्लिड के प्रमेय और न ही क़ानून के प्रावधानों के रूप में और कि

भी उनके संदर्भ से बाहर ले जाया गया। ये टिप्पणियां होनी चाहिए

उस संदर्भ में पढ़ें जिसमें वे प्रतीत होते हैं

क़ानून। शब्दों, वाक्यांशों और प्रावधानों की व्याख्या करनाकानून, न्यायाधीशों के लिए इसे शुरू करना आवश्यक हो सकता है

लंबी चर्चा में लेकिन चर्चा का उद्देश्य है

समझाएँ और परिभाषित न करें। न्यायाधीश विधियों की व्याख्या करते हैं, वे

निर्णयों की व्याख्या न करें। वे शब्दों की व्याख्या करते हैंकानून; उनके शब्दों को कानून के रूप में व्याख्या नहीं की जानी चाहिए।

70. एक फैसले को समग्र रूप से पढ़ना भी महत्वपूर्ण है।

यह ध्यान में रखते हुए कि यह एक अमूर्त अकादमिक प्रवचन नहीं है

सार्वभौमिक प्रयोज्यता के साथ, लेकिन मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में बहुत अधिक आधारित। फैसले का हर हिस्सा है

एक बड़े पूरे का गठन करने वाले अन्य लोगों के साथ जटिल रूप से जुड़ा हुआ है और इस प्रकार, तार्किक सूत्र को अक्षुण्ण रखते हुए पढ़ा जाना चाहिए। इस संबंध में,

22. (2006) 1 एससीसी *275*।

23. (2004) 3 एससीसी *75*।

400 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2012] 9 एस सी आर।

इस्लामिक एकेडमी ऑफ एजुकेशन एंड अन्न। बनाम राज्य

कर्नाटक और ओआरएस। *24* , न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:

" निर्णय के अनुपात निर्णय का केवल पता लगाना होता है।

पूरा फैसला पढ़ने पर। वास्तव में, निर्णय का अनुपात वही है जो निर्णय में ही निर्धारित किया गया है। द.

प्रश्न के उत्तर को अनिवार्य रूप से इस संदर्भ में पढ़ना होगा कि निर्णय में क्या निर्धारित किया गया है, न कि

अलगाव। किसी भी अवलोकन के संबंध में किसी भी संदेह के मामले में,

कारण और सिद्धांत, निर्णय के दूसरे भाग में है

देखने के लिए। फैसले की एक पंक्ति को इधर-उधर पढ़ने से पूरे अनुपात का पता नहीं चल सकता है।

फैसले का "। *71.* इसलिए, *2* जी मामले का अनुपात होना चाहिए

उपरोक्त मार्गदर्शन के आलोक में समझा और सराहा गया

-सिद्धांत।

72. 2 जी मामले में पीठ ने पांच प्रश्न तैयार किए।

प्रश्न संख्या *(ii)* और *(v)* तथ्यात्मक मैट्रिक्स से संबंधित हैं और हैं -

विवाद को निपटाने के लिए प्रासंगिक नहीं है। शेष

तीन प्रश्न नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैंः

" (i) क्या सरकार को अलग-थलग करने का अधिकार है,

प्राकृतिक संसाधनों/राष्ट्रीय परिसंपत्तियों का हस्तांतरण या वितरण

समानता खंड के मूल सिद्धांतों के अनुरूप संविधान में निहित?

(iii) क्या डी. ओ. टी. द्वारा की गई कवायद

यू. ए. एस. लाइसेंस प्रदान करने के लिए सितंबर *2007* से मार्च *2008* तक

निजी उत्तरदाताओं के संदर्भ में

मनमानी और दुर्भावनापूर्ण और जनता के विपरीत है ब्याज?

((iv) क्या पहले आओ पहले पाओ की नीति का पालन किया गया था।

डी. ओ. टी. द्वारा लाइसेंस प्रदान करने के लिए प्रावधानों के अधिकार से बाहर है

24. (2003) 6 एससीसी *697*।

आरईः *2012* का विशेष संदर्भ संख्या *1*

401

[डी. के. जैन, जे.*]*

संविधान का अनुच्छेद *14* और क्या उक्त नीति

संचार मंत्री द्वारा मनमाने ढंग से बदला गया था

और सूचना प्रौद्योगिकी (इसके बाद के रूप में संदर्भित)संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री "),

ट्राई से परामर्श किए बिना, कुछ का पक्ष लेने की दृष्टि से

आवेदक? "

73. न्यायालय ने प्रश्न संख्या (i) पर विचार करते हुए कहा कि

कि राज्य को प्राकृतिक संसाधनों को वितरित करने का अधिकार है

वे सार्वजनिक संपत्ति/राष्ट्रीय संपत्ति का गठन करते हैं। इसके बाद,

पीठ ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः

यह जनहित के लिए हानिकारक हो सकता है। किसी भी अन्य राज्य की तरहकार्रवाई, संविधानवाद हर स्तर पर परिलक्षित होना चाहिए

प्राकृतिक संसाधनों का वितरण। के अनुच्छेद 39 (बी) में

संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि स्वामित्व

और समुदाय के भौतिक संसाधनों का नियंत्रण इस तरह से वितरित किया जाना चाहिए ताकि सबसे अच्छा लाभ हो

आम भलाई, लेकिन कोई व्यापक कानून नहीं बनाया गया हैप्राकृतिक संसाधनों को आम तौर पर परिभाषित करने के लिए अधिनियमित और

उनकी सुरक्षा के लिए ढांचा "।

74. विद्वान न्यायाधीशों ने 'पब्लिक ट्रस्ट' को संबोधित किया

सिद्धांत ', जैसा कि द इलिनोइस सेंट्रल रेलरोड कंपनी में प्रतिपादित किया गया है। बनाम।

इलिनोइस राज्य के लोग 25; एम. सी. मेहता बनाम कमल

नाथ & Ors.26; जमशेद होर्मुसजी वाडिया बनाम बोर्ड ऑफ

न्यासी, पोर्ट ऑफ मुंबई & Anr.27; बौद्धिक मंच,

तिरुपति बनाम। ए. पी. और अन्य का राज्य। 28 ; फोमेंटो रिसॉर्ट्स और

होटल्स लिमिटेड और ए. एन. आर. बनाम मिंगुएल मार्टिन्स और Ors.29 और

25. 36 एलईडी 1018: 146 अमेरिका 387 (1892)।

26. (1997) 1 एससीसी 388। 27. (2004) 3 एससीसी 214।

28. (2006) 3 एससीसी *549*।*29. (2009) 3* एससीसी *571*।

रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड बनाम रिलायंस इंडस्ट्रीज

सीमित *3 0* और आयोजितः

" 85. चूँकि प्राकृतिक संसाधन सार्वजनिक वस्तुएँ हैं, सिद्धांत

समानता, जो न्याय की अवधारणाओं से निकलती है

और निष्पक्षता, वास्तविक निर्धारण में राज्य का मार्गदर्शन करना चाहिए प्राकृतिक संसाधनों के वितरण के लिए तंत्र। इसमें

समानता के सिद्धांत के दो पहलू हैंः सबसे पहले, यह राज्य के अधिकारों और दायित्वों को नियंत्रित करता है।

इसके लोग और मांग करते हैं कि लोगों को दिया जाए

प्राकृतिक संसाधनों और/या इसके उत्पादों तक न्यायसंगत पहुंच

और यह कि उन्हें हस्तांतरण के लिए पर्याप्त रूप से मुआवजा दिया जाता है

निजी क्षेत्र के लिए संसाधन का; और दूसरा, यह राज्य के अधिकारों और दायित्वों को विनियमित करता है

निजी पक्ष जो संसाधन का अधिग्रहण/उपयोग करना चाहते हैं औरयह माँग करता है कि वितरण के लिए अपनाई गई प्रक्रिया न्यायसंगत, गैर-मनमाना और पारदर्शी हो और यह नहीं है

समान रूप से रखे गए निजी पक्षों के बीच भेदभाव करें।

अखिल भारतीय उपभोक्ता कांग्रेस बनाम मध्य प्रदेश राज्य और *Ors.*[3]*1* मामले में इस न्यायालय के फैसलों का उल्लेख करते हुए

और सच्चिदानंद पांडे और अन्न। बनाम पश्चिम बंगाल राज्य

& Ors.[3]*2*, पीठ ने अंततः इस प्रकार निष्कर्ष निकालाः

वितरण की प्रक्रिया संवैधानिक द्वारा निर्देशित होनी चाहिए समानता के सिद्धांत और व्यापक सहित सिद्धांत

सार्वजनिक भलाई "।

एक पारदर्शी और निष्पक्ष पद्धति को अपनाना, अवसर प्रतिस्पर्धा; और दावे को विफल करने के लिए किसी भी अवसर से बचना

30. (2010) 7 एससीसी 1.

31. (2011) 5 एस. सी. सी 29.

32. (1987) 2 एससीसी 295।

समान रूप से स्थित आवेदकों पर जोर दिया गया। जबकि

स्पेक्ट्रम जैसे प्राकृतिक संसाधनों के अलगाव से निपटने के लिए, यह था

उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य है कि वितरण और अलगाव के लिए एक गैर-भेदभावपूर्ण तरीका अपनाया जाए

जिसके परिणामस्वरूप अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय/सार्वजनिक सुरक्षा होगी।ब्याज।

76. अनुच्छेद 85 और 89, अवधारणा का उल्लेख करते हुए

'सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत', के सिद्धांत पर जोर देता हैसमानता, जिसे दो भागों में विभाजित किया गया है-एक है

मूल भाग और दूसरा नियामक भाग है। विनियामक पहलू में, अनुच्छेद 85 में कहा गया है कि प्रक्रिया

वितरण के लिए अपनाया जाना न्यायसंगत और गैर-मनमाना होना चाहिए और

संवैधानिक सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए जिसमें शामिल हैं -

वितरण और अलगाव के लिए अपनाया गया जो आवश्यक रूप से जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय और लोक हित की रक्षा होती है।

77. पैराग्राफ में प्रश्न संख्या (iii) और (iv) से निपटना।

94 निर्णय के 96 में, न्यायालय ने इस प्रकार राय दी:

" 94. पहले आओ-पहले आओ में एक मूलभूत दोष है।

मौका या दुर्घटना। अनुबंध देने से जुड़े मामलों मेंया सार्वजनिक संपत्ति का उपयोग करने के लिए लाइसेंस या अनुमति प्रदान करना,

पहले आओ पहले पाओ की नीति का आह्वान किया गया है

स्वाभाविक रूप से खतरनाक निहितार्थ। कोई भी व्यक्ति जो

सबसे ऊपर या सबसे नीचे बिजली गलियारे तक पहुंच

स्तर से जानकारी प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है

सरकारी फाइल या एजेंसी/उपकरण की फाइल

राज्य की कि कोई विशेष सार्वजनिक संपत्ति या संपत्ति है

निपटारे की संभावना है या एक अनुबंध होने की संभावना है

लाइसेंस या अनुमति दिए जाने की संभावना है,

वह तुरंत एक आवेदन करेगा और *[2012] 9* एस. सी. आर.

404

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

की कीमत पर कतार में पहले खड़े होने के हकदार बनें

अन्य सभी जिनके पास बेहतर दावा हो सकता है।

95. इस न्यायालय ने बार-बार यह निर्णय दिया है कि जहां भी कोई अनुबंध दिया जाना है या लाइसेंस दिया जाना है, जनता प्राधिकरण को चयन करने के लिए एक पारदर्शी और निष्पक्ष तरीका अपनाना चाहिए ताकि सभी पात्र व्यक्तियों को एक निष्पक्ष विकल्प मिल सके।

प्रतिस्पर्धा का अवसर। इसे अलग तरह से रखने के लिए, राज्य

और इसकी एजेंसियों/उपकरणों को सार्वजनिक संपत्ति के निपटान के लिए हमेशा एक तर्कसंगत तरीका अपनाना चाहिए और योग्य के दावे को विफल करने का प्रयास किया जाना चाहिए

आवेदक। जब दुर्लभ प्राकृतिक के अलगाव की बात आती है

स्पेक्ट्रम आदि जैसे संसाधन राज्य का बोझ हैं।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि वितरण और अलगाव के लिए एक गैर-भेदभावपूर्ण तरीका अपनाया गया है, जिसका परिणाम अनिवार्य रूप से होगा

राष्ट्रीय/लोक हित की रक्षा में।

96. हमारे विचार में, एक विधिवत प्रचारित नीलामी निष्पक्ष रूप से आयोजित की गई

और निष्पक्ष रूप से शायद निर्वहन का सबसे अच्छा तरीका है

प्राकृतिक संसाधनों/जनता के अलगाव के लिए उपयोग किए जाने पर यह बोझ और पहले आओ-पहले पाओ जैसे तरीके काम आते हैं।

बेईमान लोगों द्वारा संपत्ति का दुरुपयोग होने की संभावना है

जो केवल अधिकतम वित्तीय लाभ प्राप्त करने में रुचि रखते हैं

लाभ और संवैधानिक लोकाचार और मूल्यों के लिए कोई सम्मान नहीं है। दूसरे शब्दों में, हस्तांतरण या अलगाव करते समय

प्राकृतिक संसाधनों को अपनाना राज्य का कर्तव्य है

व्यापक प्रचार देकर नीलामी की विधि ताकि सभी पात्र व्यक्ति इस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।

78. इन अनुच्छेदों को पढ़ने से पता चलता है कि

न्यायालय सामान्य रूप से नीलामी के मामले पर विचार नहीं कर रहा था, लेकिन विशेष रूप से उन तरीकों की वैधता का मूल्यांकन कर रहा था जो इसमें अपनाए गए थे।

सितंबर *2007* से मार्च तक स्पेक्ट्रम का वितरण

2008. यह भी ध्यान देने योग्य है कि नीलामी का संदर्भ बाद के पैराग्राफ *(96)* में सवार के साथ किया गया है।

*'*शायद *'*। यह देखा गया है कि *"*एक विधिवत प्रचारित नीलामी*"*

निष्पक्ष और निष्पक्ष रूप से आयोजित करना शायद सबसे अच्छा तरीका है

इस बोझ का निर्वहन करना *"*। हम इस बात से अवगत हैं कि एक निर्णय *405* है।

आरईः *2012* का विशेष संदर्भ संख्या *1*

[डी. के. जैन, जे.*]*

एक क़ानून के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए, लेकिन साथ ही, हम नहीं कर सकते

इस तथ्य से अनजान रहें कि जब इस पर जोरदार बहस की जाती है

कि निर्णय नीलामी को एक संवैधानिक सिद्धांत के रूप में निर्धारित करता है,

"शायद" शब्द का महत्व बढ़ जाता है। यह बताता है कि

प्राकृतिक संसाधनों के अलगाव के लिए नीलामी की सिफारिश

कभी भी एक पूर्ण या कंबल के रूप में लेने का इरादा नहीं था

सभी प्राकृतिक संसाधनों पर लागू कथन, लेकिन बस

एक के आकर्षण पर पहली बार में किया गया एक निष्कर्ष

प्राकृतिक संसाधनों के निपटान में नीलामी जैसी विधि। चयन

'शायद' शब्द से पता चलता है कि विद्वान न्यायाधीश

नीलामी के अलावा किसी अन्य विधि की आवश्यकता वाली स्थितियों पर विचार किया जाता है

कल्पना करने योग्य और वांछनीय।

79. इसके अलावा, अंतिम निष्कर्ष पैराग्राफ में संक्षेपित किए गए हैं।

102 निर्णय *(*एस. सी. सी.*)* में नीलामी का कोई उल्लेख नहीं है।

निपटान के लिए एकमात्र अनुमेय और अंतर अधिकार विधि होने के नाते

प्राकृतिक संसाधनों के; निष्कर्ष के मामले तक सीमित हैं स्पेक्ट्रम। यदि न्यायालय ने वास्तव में यह स्पष्ट किया था कि

कानून का प्रस्ताव, कि नीलामी एकमात्र अनुमेय विधि है

या प्राकृतिक संसाधनों के अलगाव/आवंटन का तरीका, वही

सारांश के अंत में एक उल्लेख मिला होगा

निर्णय।

80. इसके अलावा, यदि निर्णय को अभिग्रहण के रूप में पढ़ा जाना है

सभी प्राकृतिक वस्तुओं के निपटान के एकमात्र अनुमेय साधन के रूप में नीलामी

संसाधनों, यह एक बड़ी संख्या में रद्द करने के लिए नेतृत्व करेंगेनीलामी के अलावा अन्य विधियों को निर्धारित करने वाले कानून, उदाहरण के लिए, एम. एम. आर. डी.

एक्ट करें। संदर्भ के गुणों के बारे में बात करते हुए, बाद में

चरण, हम चर्चा करेंगे कि नीलामी एक हो सकती है या नहींसंविधान के अनुच्छेद *14* के तहत संवैधानिक जनादेश, लेकिन

वर्तमान में, यह कहना पर्याप्त होगा कि कोई भी अदालत कभी भी निहित रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, या निष्कर्ष द्वारा, कई कानूनों को असंवैधानिक नहीं मानती है।

प्रत्येक कानून को परखने की अनुमति दिए बिना, संविधान को अधिकार देता है

अपने गुणों पर। सबसे गहन सिद्धांतों में से एक

संवैधानिकता संवैधानिकता की धारणा है।

अधिनियमित प्रत्येक विधान को सौंपा गया। हम पाते हैं कि *2* जी मामला

यहाँ तक कि कई कानूनों और निर्णयों पर भी विचार नहीं करता है जो *406* सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट करते हैं

[2012] 9 एस सी आर।

प्राकृतिक संसाधन; कुछ ऐसा जो उसने किया होगा, मामले में, यह नीलामी लागू करने के रूप में एक व्यापक दावा करने का इरादा रखता है

सभी प्राकृतिक संसाधनों को। इसलिए, हम आश्वस्त हैं कि अनुच्छेद *94* से *96* में दिए गए अवलोकन इससे आगे लागू नहीं हो सकते हैं।

विधि। *81.* इस प्रकार, इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद कि *2* जी मामला प्राकृतिक संसाधनों के लिए आवंटन के तरीकों से संबंधित नहीं है,

स्पेक्ट्रम के अलावा, अब हम पहले का जवाब देने के लिए आगे बढ़ेंगे।

अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित संदर्भ का प्रश्न,

जैसा कि प्रश्न पूरे संदर्भ का सार है,विशेष रूप से पहले पाँच प्रश्नों का सेट।

82. राष्ट्रपति सीमित पर इस न्यायालय की राय मांगते हैं

स्पेक्ट्रम के अलावा प्राकृतिक संसाधनों के अलगाव के लिए नीलामी के अलावा अन्य तरीकों की अनुमति का बिंदु। द.

प्रश्न में कई अवधारणाएँ भी हैं, जिन पर तर्क दिया गया था

संदर्भ की सुनवाई के माध्यम से हमारे सामने, जिसका व्यापक उत्तर प्राप्त करने के लिए उत्तर देने की आवश्यकता है माता-पिता का प्रश्न। कुछ विधियाँ अल्ट्रा वायर्स हैं और अन्य इंट्रा वायर्स हैं।

भारत के संविधान, विशेष रूप से अनुच्छेद *14* का अधिकार है? नीलामी की विधि के माध्यम से निपटान को बढ़ाया जा सकता है

संवैधानिक सिद्धांत? क्या यह न्यायालय निर्देश देने का हकदार है

एक निश्चित विधि को अपनाने के लिए कार्यकारी क्योंकि यह 'सर्वश्रेष्ठ' है

विधि? यदि नहीं, तो कार्यपालिका किस हद तक विचलित हो सकती है?

ऐसी 'सबसे अच्छी' विधि? इन मुद्दों का जवाब बदले में मिलेगा। पहले प्रश्न का उत्तर जो, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, राष्ट्रपति के संदर्भ का उत्तर देगा।

83. इन प्रश्नों का उत्तर देने से पहले, हम

कुछ छोटी-मोटी आपत्तियों का निपटारा करना चाहूंगा। सबसे पहले

2 जी में बनाए गए संसाधनों के वर्गीकरण से संबंधित

मामला. सी. पी. आई. एल. की ओर से पेश विद्वान वकील ने तर्क दिया कि यह सब

2 जी मामले में निर्णय एक विशेष आरई बनाने के लिए किया गया है:

2012 का विशेष संदर्भ संख्या *1*

407

[डी. के. जैन, जे.]

ऐसे मामलों की श्रेणी जहां सार्वजनिक नीलामी केवल कानूनी रूप से होती है

अलगाव की स्थायी विधि। प्राकृतिक संसाधन जो दुर्लभ, मूल्यवान हैं और जिनके लिए निजी संस्थाओं को आवंटित किया जाता है

व्यावसायिक दोहन। विद्वान महान्यायवादी,

हालाँकि, इस दावे का विरोध किया और तर्क दिया कि ऐसा कोई नहीं है

2 जी निर्णय में प्रस्ताव रखा गया था। उन्होंने इशारा किया कि

कि "वाणिज्यिक शोषण" शब्दों का उपयोग निर्णय में कहीं भी नहीं किया गया था, सिवाय एक अन्य उद्धरण के।

एक अलग संदर्भ में निर्णय। हम इस बात से सहमत हैं कि निर्णय स्वयं

दुर्लभ प्राकृतिक के लिए कोई विशेष मामला नहीं बनाता है

संसाधन केवल वाणिज्यिक दोहन के लिए हैं। हालाँकि, हम महसूस करते हैं कि इसके बावजूद, इस संदर्भ में, सीपीआईएल को प्रतिबंधित नहीं किया गया है।

प्राकृतिक के बीच अंतर करते हुए प्रस्तुत करना वाणिज्यिक दोहन के लिए संसाधन और उनका उद्देश्य

अन्य उद्देश्यों के लिए। इस न्यायालय के पास वर्गीकृत करने का अधिकार क्षेत्र है

संदर्भ की विषय वस्तु, यदि इसके लिए कोई वास्तविक मामला मौजूद है।

84. श्री शांति भूषण, विद्वान वरिष्ठ वकील,

उनके इस रुख का समर्थन करते हुए कि संदर्भ का पहला प्रश्न अवश्य होना चाहिए

इस तरह से जवाब दिया जाए ताकि प्राकृतिक संसाधनों के निपटान के लिए नीलामी को एकमात्र साधन के रूप में अनुमति दी जा सके, प्रस्तुत किया कि एक संयुक्त

अनुच्छेद *14* को पढ़ना, जो राज्य में गैर-मनमानेपन को निर्देशित करता है

39 (ख) जो राज्य की नीति का एक निदेशक सिद्धांत है जो आम लोगों की भलाई के लिए प्राकृतिक संसाधनों के वितरण से संबंधित है। लोग; और प्रस्तावना में पाया जाने वाला "ट्रस्टीशिप" सिद्धांत

जो यह आदेश देता है कि राज्य लोगों की ओर से सभी प्राकृतिक संसाधनों को एक न्यासी के रूप में रखता है

इन सिद्धांतों पर किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले नीलामी पर संवैधानिक निर्णय।

85. 2 जी मामले में, दो अवधारणाएँ हैं, "सार्वजनिक विश्वास"।

"सिद्धांत" और "ट्रस्टीशिप" को बढ़ावा दिया गया है, जिन पर सीपीआईएल के विद्वान वकील द्वारा भी भरोसा किया गया था।यह तर्क कि राज्य प्राकृतिक संसाधनों को एक न्यास में रखता है

लोगों के साथ संबंध। जहाँ तक "ट्रस्टीशिप" की बात है *[2012] 9* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

408 संबंधित, ऐसा कोई कुआँ नहीं है जिसे राज्य में सभी प्राकृतिक रूप से रखा गया हो

जनता के न्यासी के रूप में संसाधन और उन्हें उनसे निपटना चाहिए

इस तरह से जो इस तरह के न्यास की प्रकृति के अनुरूप हो।

हालांकि, सीपीआईएल की ओर से जो दावा किया गया था वह यह था कि सभी

प्राकृतिक संसाधन सार्वजनिक न्यास के दायरे में आते हैं।

सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनका हस्तांतरण या अलगाव वाणिज्यिक दोहन निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होता है और

केवल सार्वजनिक भलाई के लिए। विद्वान महान्यायवादी ने

दूसरी ओर, उत्साह से आग्रह किया कि विषय वस्तु

सिद्धांत और प्रतिबंधों की प्रकृति, यह लागू करता है, सीमित दायरे के हैं; कि सिद्धांत की प्रयोज्यता सीमित है

पर्यावरण से संबंधित कुछ सामान्य गुण, जैसेनदियाँ, समुद्र तट, जंगल और हवा, जो स्वतंत्र और निर्बाध हैं

आम जनता का उपयोग और इसके द्वारा लगाए गए प्रतिबंध

निजी स्वामित्व के लिए ऐसे संसाधनों के किसी भी अलगाव पर पूर्ण प्रतिबंध की अवधि। उनके अनुसार,

सभी प्राकृतिक संसाधनों के लिए सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत का विस्तार इससे काफी भ्रम पैदा हुआ और इसे स्पष्ट करने की आवश्यकता है।

86. सार्वजनिक विश्वास के सिद्धांत का अधिक विस्तार से प्रतिपादन किया गया

इलिनोइस में संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा *(ऊपर)* था

इस न्यायालय द्वारा एम. सी. मेहता *(ऊपर)* में भारतीय पर्यावरण न्यायशास्त्र को प्रस्तुत किया गया। बहुमत के लिए बोलते हुए, कुलदिप सिंह,जे. ने निम्नलिखित रूप में देखाः

"25. सार्वजनिक न्यास सिद्धांत मुख्य रूप से इस पर आधारित है -

सिद्धांत कि कुछ संसाधन जैसे वायु, समुद्र, जल और

जंगलों का लोगों के लिए इतना बड़ा महत्व है कि

एक संपूर्ण कि उन्हें एक बनाना पूरी तरह से अनुचित होगा

निजी स्वामित्व का विषय। उक्त संसाधन प्रकृति का एक उपहार होने के कारण, उन्हें जीवन में किसी भी स्थिति के बावजूद सभी के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कराया जाना चाहिए। सिद्धांत

सरकार को संसाधनों की रक्षा करने का आदेश देता हैअनुमति देने के बजाय आम जनता का आनंद

निजी स्वामित्व या वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए उनका उपयोग। प्रोफेसर सैक्स के अनुसार सार्वजनिक न्यास सिद्धांत

सरकार पर निम्नलिखित प्रतिबंध लगाता हैप्राधिकारः

409

आरईः *2012* का विशेष संदर्भ संख्या *1*

[डी. के. जैन, जे.*]*

*'*सरकार पर तीन प्रकार के प्रतिबंधअक्सर माना जाता है कि अधिकार द्वारा थोपा जाता है

सार्वजनिक विश्वासः सबसे पहले, न्यास के अधीन संपत्ति

सामान्य द्वारा उपयोग के लिए उपलब्ध होना चाहिएसार्वजनिक*;* दूसरा, संपत्ति को बेचा नहीं जा सकता है, यहां तक कि

उचित नकद समतुल्य के लिए और तीसरी संपत्ति के लिए

विशेष प्रकार के उपयोगों के लिए बनाए रखा जाना चाहिए।

विद्वान न्यायाधीश ने आगे कहाः

"34. हमारी कानूनी प्रणाली-अंग्रेजी सामान्य कानून पर आधारित

—

इसके हिस्से के रूप में सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत शामिल है

न्यायशास्त्र। राज्य सभी प्राकृतिक वस्तुओं का न्यासी है।

ऐसे संसाधन जो स्वाभाविक रूप से सार्वजनिक उपयोग के लिए हैं और

आनंद लेते हैं। बड़े पैमाने पर जनता समुद्र की लाभार्थी है

तट, बहते पानी, हवा, जंगल और पारिस्थितिक रूप से नाजुक भूमि। न्यासी के रूप में राज्य एक कानूनी कर्तव्य के अधीन है -

प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करें। इन संसाधनों का उद्देश्य था -

सार्वजनिक उपयोग को निजी स्वामित्व में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। *87.* कमल नाथ के मामले में फैसला *(*ऊपर*)* था

बौद्धिक मंच *(*ऊपर*)* में शामिल। यह दोहराते हुए कि

ई उन सभी प्राकृतिक संसाधनों का न्यासी है जो स्वभाव से हैं।

सार्वजनिक उपयोग और आनंद के लिए, न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

"76. कैलिफोर्निया का सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय स्तर पर

ऑडुबोन सोसायटी बनाम अल्पाइन देश का सुपीरियर कोर्ट

मोनो लेक केस के रूप में भी जाना जाता है पदार्थ का सारांश

सिद्धांत का। अदालत ने कहाः

"इस प्रकार सार्वजनिक विश्वास एक पुष्टि से अधिक हैसार्वजनिक संपत्ति का उपयोग करने की राज्य की शक्ति

उद्देश्य। यह राज्य के कर्तव्य की पुष्टि है।

लोगों की साझा विरासत की रक्षा के लिएनदियाँ, झीलें, दलदली भूमि और ज्वारीय भूमि,

केवल उन दुर्लभ मामलों में अधिकार का समर्पण करना

जब अधिकार का परित्याग इसके अनुरूप होता है

न्यास के उद्देश्य। *"[2012] 9* एस. सी. आर.

410 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह के कोण से सिद्धांत की एक अभिव्यक्ति है

सार्वजनिक विश्वास के संबंध में राज्य के सकारात्मक कर्तव्य।

एक नकारात्मक कोण से तैयार किया गया, सिद्धांत नहीं है

एक के रूप में आयोजित संपत्ति के अलगाव को बिल्कुल प्रतिबंधित करें

सार्वजनिक विश्वास। हालाँकि, जब राज्य के पास कोई संसाधन होता है कि जनता के उपयोग के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है, यह प्रदान करता है

किसी भी कार्रवाई पर उच्च स्तर की न्यायिक जांच

सरकार, चाहे वह मौजूदा सरकार के साथ कितनी भी सुसंगत क्यों न हो

ऐसे कानून, जो इस तरह के मुफ्त उपयोग को प्रतिबंधित करने का प्रयास करते हैं। को।

सरकार की ऐसी कार्रवाइयों की उचित रूप से जांच करना,

अदालतों को सरकार के बीच अंतर करना चाहिए

सार्वजनिक लाभ के लिए कार्य करने का सामान्य दायित्व, और

कुछ सार्वजनिक संसाधनों का न्यासी। इस प्रकार यह अभिनिर्धारित किया गया कि जब सकारात्मक कर्तव्य निर्धारित किए जाते हैं

एक अस्पष्ट कोण से, सिद्धांत बिल्कुल निषेध नहीं करता है

एक सार्वजनिक न्यास के रूप में आयोजित संपत्ति का अलगाव, लेकिन आदेश

उच्च स्तर की न्यायिक जांच।

88. फोमेंटो *(ऊपर)* में, न्यायालय का संबंध था -

गोवा में एक समुद्र तट तक जनता की पहुंच। माना कि यह एक

सार्वजनिक समुद्र तट जिसका निजीकरण नहीं किया जा सकता था या इनकार करने से रोका नहीं जा सकता था

पारंपरिक पहुँच, इस न्यायालय ने सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत को दोहराया

इस प्रकार हैः

" 52. इस मामले पर दूसरे से विचार किया जाना चाहिए।

कोण। सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत जिसे लागू किया गया है

सुश्री इंदिरा जयसिंह द्वारा उनके तर्क के समर्थन में कि

विचाराधीन समुद्र तट एक सार्वजनिक समुद्र तट है और अपीलकर्ता

अवरुद्ध/बाधित करके इसका निजीकरण नहीं किया जा सकता है।

सर्वेक्षण संख्या *803 (नई)* के माध्यम से उपलब्ध पारंपरिक पहुंच

नं. *246/2)* राज्य सरकार द्वारा निहित रूप से संलग्न है।

समझौते के खंड *4 (ix)* में। यह सिद्धांत मुख्य रूप से इस सिद्धांत पर आधारित है कि वायु, समुद्र, जल और वन जैसे कुछ संसाधनों का इतना बड़ा महत्व है कि

लोगों को एक पूरे के रूप में कि यह पूरी तरह से अनुचित होगा

उन्हें निजी स्वामित्व का विषय बनाएं। ये *411*

आरईः *2012* का विशेष संदर्भ संख्या *1*

[डी. के. जैन, जे.*]*

संसाधन प्रकृति का उपहार हैं, इसलिए उन्हें स्वतंत्र रूप से होना चाहिए। जीवन में किसी भी स्थिति की परवाह किए बिना सभी के लिए उपलब्ध है।

89. रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज *(*ऊपर*)* में, यह किया गया है

इसका व्यापक अनुप्रयोग है "। कमल नाथ *(*ऊपर*)* का उल्लेख करते हुए, न्यायालय ने कहा कि यह सरकार का कर्तव्य है कि वह प्रदान करेन्यासी के रूप में प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण संरक्षण

बड़े पैमाने पर लोग।

90. सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत एक विशिष्ट सिद्धांत है जिसमें

विशेष क्षेत्र और इसे सावधानीपूर्वक लागू किया जाना चाहिए। यह हो चुका है

हमारे सामने गंभीरता से बहस की गई कि क्या सिद्धांत हो सकता है

पर्यावरण संरक्षण के दायरे से परे लागू किया गया। रिचर्ड जे. लाज़र ने अपने लेख में कहा, "संपत्ति की अवधारणाओं को बदलना।

और प्राकृतिक संसाधनों में संप्रभुताः जनता से की पूछताछविश्वास सिद्धांत ", पर संदेह व्यक्त करते हुए

'सिद्धांत की 'मुक्ति', निम्नलिखित टिप्पणियाँ करती हैः

"सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत की ताकत अनिवार्य रूप से निहित है

इसकी उत्पत्ति में; नौगम्य जल और जलमग्न भूमि हैं

सिद्धांत का केंद्र, और बुनियादी विश्वास हितों में

नौवहन, वाणिज्य और मछली पकड़ना इसकी सार्वजनिक पहुंच की गारंटी का उद्देश्य है। टिप्पणीकार और न्यायाधीश

आर

समान रूप से "मुक्त", "विस्तार" के प्रयास किए हैं, और " सिद्धांत के दायरे को संशोधित करें फिर भी इसका मूल ध्यान बना हुआ है।

अपेक्षाकृत अपरिवर्तित। अदालतें अभी भी बार-बार लौटती हैं

इसकी वर्तमान भूमिका निर्धारित करने के लिए सिद्धांत का ऐतिहासिक कार्य।

जब सिद्धांत का विस्तार किया जाता है, तो अक्सर नहीं

विस्तार के लिए सिद्धांत के अतीत को अस्वीकार करने के बजाय वर्तमान के यातनापूर्ण निर्माण की आवश्यकता होती है।

हालाँकि, हम महसूस करते हैं कि वर्तमान के उद्देश्य के लिए

राय, इस मुद्दे में गहराई से उतरना आवश्यक नहीं है जैसा कि

जोसेफ द्वारा समझाया गया सिद्धांत। एल. सैक्स अपने लेख "द पब्लिक" मेंप्राकृतिक संसाधन कानून में विश्वास सिद्धांतः

हस्तक्षेप "यह है कि सार्वजनिक विश्वास एक उच्च डिग्री को अनिवार्य करता है

न्यायिक जांच, एक ऐसा मुद्दा जिसे हम वैसे भी विस्तार से देखेंगे

अनुच्छेद *14* के अधिदेश का उच्चारण करते हुए चर्चा करें संविधान।

91. हम भी इसी तरह से तेजी से निपटना चाहेंगे।

श्री शांति भूषण द्वारा दिया गया तर्क। विद्वान वरिष्ठ

वकील ने प्रस्तुत किया कि हमारे में संप्रभुता का भंडार प्रारंभिक शब्दों से इस देश के लोग ढांचे हैं

संविधान में लिखा है, "हम भारत के लोग. इसके द्वारा करते हैं।

इस संविधान को अपनाना, अधिनियमित करना और खुद को देना ", और

इसलिए सरकार, संप्रभु के प्रतिनिधि के रूप में,

प्राकृतिक संसाधनों को अलग-थलग करते हुए लोगों को न्यायिक व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए

" संविधान इस देश में सर्वोच्च शब्द है "और" सभी अंग " राज्य अपने अधिकार, अधिकार क्षेत्र और शक्तियों को प्राप्त करता है

संविधान और उसके प्रति निष्ठा "। इसके अलावा, यह धारणा कि संसद लोगों की प्रतिनिधि है, स्पष्ट रूप से थी

इन रे में खंडन किया गयाः दिल्ली विधि अधिनियम, *1912 (*ऊपर*)*, जहाँ यह था

उन्होंने कहा कि "एक निकाय के रूप में विधायिका को समग्र रूप से मतदाताओं की एक एजेंसी के रूप में नहीं देखा जा सकता है" और "अपने दम पर कार्य करता है"

अधिकार या शक्ति जो इसे संविधान से प्राप्त होती है।

92. दिल्ली नगर निगम बनाम बिड़ला कॉटन में,

स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स, दिल्ली और ए. एन. आर. *3 4.* इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि "यह सिद्धांत कि यह *(*संसद*)* लोगों का प्रतिनिधि है

रंगीन कुछ अमेरिकी निर्णय यहाँ नहीं उठते हैं "और

कि वास्तव में "संसद जो सभी की एकाग्रता से

तीनों विधायी सूचियों से प्राप्त विधान की शक्तियाँ सबसे सक्षम और शक्तिशाली विधायिका बन जाती हैं।

श्री शांति भूषण की चिंता की सराहना करते हैं किलोगों के हाथों में ऐसी कोई भी शक्ति प्राकृतिक संसाधनों के निपटान के दौरान लापरवाही के लिए मंजूरी नहीं होनी चाहिए।

33. (2007) 3 एस. सी. सी. *184;* पैरा *21*।*34. [1968] 3* एससीआर *251*।

413

आरईः *2012* का विशेष संदर्भ संख्या *1*

[डी. के. जैन, जे.*]*

विधायिका और कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह हैं

संविधान और यह वहाँ है जहाँ न्यायपालिका, के संरक्षक

संविधान को प्राकृतिक संसाधनों के निपटान की शक्तियों की रूपरेखा खोजना चाहिए, विशेष रूप से अनुच्छेद *14* और अनुच्छेद

39 (बी*)*।अनुच्छेद *14* का अधिदेशः

" 14. कानून के समक्ष समानता। - राज्य किसी से इनकार नहीं करेगा।कानून के समक्ष व्यक्ति की समानता या समान संरक्षण

भारत के क्षेत्र के भीतर कानून "।

94. अनुच्छेद *14* का अंतर्निहित उद्देश्य सभी के लिए सुरक्षित करना है।

व्यक्ति, नागरिक या गैर-नागरिक, स्थिति की समानता और

हमारे संविधान की प्रस्तावना में संदर्भित अवसर। द.

अनुच्छेद *14* की भाषा को नकारात्मक शब्दों में जोड़ा गया है और इसमें

प्रपत्र, राज्य को संबोधित एक चेतावनी। यह सीधे नहीं है

भेदभाव क्योंकि अनुच्छेद *14* की भाषा शब्द का उपयोग करती है" राज्य "जिसमें अनुच्छेद *12* के अनुसार कार्यकारी अंग शामिल है।

[देखिए: बशेशर नाथ बनाम। आयकर आयुक्त, दिल्ली और राजस्थान *& Anr.35]*। इसके अलावा, अनुच्छेद *14* व्यक्त किया गया है।

पूर्ण रूप से और इसका प्रभाव प्रतिबंधों द्वारा कम नहीं किया जाता है

जैसा कि अनुच्छेद *19 (2)-(6)* द्वारा अनुच्छेद *19 (1)* पर लगाया गया है।

35. 1959 सपं. *(1)* एस. सी. आर. *528-*"फिर अनुच्छेद की भाषा पर आते हुए, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह अनुच्छेद, रूप में, राज्य को संबोधित एक चेतावनी है और किसी भी व्यक्ति को कोई अधिकार प्रदान करने का प्रत्यक्ष रूप से तात्पर्य नहीं है जैसा कि कुछ अन्य अनुच्छेद, उदाहरण के लिए, अनुच्छेद *19* करता है। इस प्रकार राज्य पर लगाया गया दायित्व, निस्संदेह, सभी व्यक्तियों के लाभ के लिए सुनिश्चित करता है, क्योंकि इस अनुच्छेद के संचालन के आवश्यक परिणाम के रूप में, वे सभी कानून के समक्ष समानता का आनंद लेते हैं। हालाँकि, यह अप्रत्यक्ष रूप से जनादेश का परिणाम है, हालांकि आवश्यक और अपरिहार्य है। अनुच्छेद का आदेश राज्य को निर्देशित किया जाता है और इस प्रकार राज्य पर लगाए गए दायित्व की वास्तविकता मौलिक अधिकार का पैमाना है जो क्षेत्र के भीतर प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है।

भारत का आनंद लेना है। .

414 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2012] 9 एस सी आर।

हालांकि, इस तरह के प्रतिबंधों के अभाव के बावजूद,

न्यायिक निर्णयों के माध्यम से कुछ परीक्षण तैयार किए गए हैं

जाँच करें कि अनुच्छेद *14* का उल्लंघन किया गया है या नहीं।

95. स्थापना के बाद के पहले कुछ दशकों के लिए

इस न्यायालय के 'वर्गीकरण' परीक्षण को अपनाया गया था जिसने अनुमति दी थी

संस्थाओं के बीच वर्गीकरण के लिए जब तक यह आधारित था

एक समझदार अंतर पर और इसके साथ एक तर्कसंगत संबंध प्रदर्शित किया

नीति का अंतिम उद्देश्य। बुधन चौधरी और अन्य।

बनाम बिहार राज्य *3 6* श्री राम कृष्ण डालमिया में संदर्भित

बनाम। श्री न्यायमूर्ति एस. आर. तेंदोलकर और *Ors.*[3]*7* ने निम्नलिखित शब्दों में इसकी व्याख्या कीः

"अब यह अच्छी तरह से स्थापित है कि जबकि अनुच्छेद *14* वर्ग विधान को मना करता है, यह उचित वर्गीकरण को मना नहीं करता है

अनुमेय वर्गीकरण का परीक्षण दो शर्तों का होना चाहिए पूरा किया गया, अर्थात्, *(i)* कि वर्गीकरण को स्थापित किया जाना चाहिए

एक बोधगम्य अंतर पर जो व्यक्तियों को अलग करता है या

जिन चीजों को दूसरों से अलग करके समूहीकृत किया जाता है

समूह और, *(ii)* कि उस अंतर का एक तर्कसंगत होना चाहिए

व्यवसाय या इस तरह के। आवश्यकता यह है कि वर्गीकरण के आधार के बीच एक संबंध होना चाहिए और

विचाराधीन अधिनियम का उद्देश्य। यह भी ठीक है।

इस न्यायालय के निर्णयों द्वारा स्थापित कि अनुच्छेद *14*

न केवल एक मूल कानून द्वारा बल्कि प्रक्रिया के कानून द्वारा भी भेदभाव की निंदा करता है।

96. हालाँकि, ई. पी. रोयप्पा बनाम में इस न्यायालय के फैसले के बाद। तमिलनाडु राज्य और ए. एन. आर. *3 8* 'मनमानेपन'

सिद्धांत पेश किया गया था जिसने एक पांडित्यपूर्ण दृष्टिकोण को छोड़ दिया था

36. ए. आई. आर. *1955* एससी *191*।

37. [1959] 1 एससीआर *279*।

38. (1974) 4 एस. सी. सी *3.*

415

[डी. के. जैन, जे.*]*

समानता की ओर और केवल मनमानेपन के अस्तित्व को बनाए रखा

उन्होंने कहा कि अवधारणा को "क्रिब्ड, केबिन और" नहीं होना चाहिए। सैद्धांतिक सीमाओं के भीतर सीमितः -

बराबरी का सिद्धांत? यह एक संस्थापक विश्वास है, शब्दों का उपयोग करनाबोस का। जे., "जीवन का एक तरीका", और इसे इसके अधीन नहीं किया जाना चाहिए

एक संकीर्ण पांडित्यपूर्ण या शब्दकोशात्मक दृष्टिकोण। हम नहीं कर सकते।

इसके सभी को काटने के किसी भी प्रयास को स्वीकार करें।

दायरा और अर्थ, क्योंकि ऐसा करना इसका उल्लंघन करना होगा

सक्रिय परिमाण। समानता एक गतिशील अवधारणा है जिसके साथ

कई पहलुओं और आयामों और यह नहीं किया जा सकता है

पारंपरिक और सिद्धांत के भीतर सीमित और सीमितसीमाएँ "।

उनकी प्रभुता ने इसकी लंबाई और चौड़ाई की व्याख्या की।

अनुच्छेद *14* निम्नलिखित स्पष्ट शब्दों में हैः

" 85 ...... सकारात्मक दृष्टिकोण से, समानता विरोधी है।

मनमानी करने के लिए। वास्तव में समानता और मनमानी की शपथ ली जाती है।

दुश्मन; एक गणराज्य में कानून के शासन से संबंधित है जबकि

दूसरा, एक पूर्ण सम्राट की सनक और सनक के लिए।

जहाँ कोई कार्य मनमाना है, वहाँ यह निहित है कि वह असमान है।

इसलिए अनुच्छेद *14* का उल्लंघन है, और यदि यह किसी को प्रभावित करता है सार्वजनिक रोजगार से संबंधित मामला, यह भी उल्लंघन है

अनुच्छेद *16.* अनुच्छेद *14* और *16* मनमानेपन पर प्रहार करते हैं

कार्रवाई का उल्लेख करें और निष्पक्षता और व्यवहार की समानता सुनिश्चित करें।

उनके लिए आवश्यक है कि राज्य की कार्रवाई वैध पर आधारित होनी चाहिए।

प्रासंगिक सिद्धांत सभी समान स्थितियों पर समान रूप से लागू होते हैं।

और यह किसी भी बाहरी या अप्रासंगिक द्वारा निर्देशित नहीं होना चाहिएविचार क्योंकि यह समानता से इनकार होगा।

जहां राज्य की कार्रवाई के लिए कार्यात्मक कारण, के रूप में

एंटीकैम्बर से प्रेरित करने वाले उद्देश्य से अलग

मन की, वैध और प्रासंगिक नहीं है, लेकिन बाहरी *416* सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट है

[2012] 9 एस सी आर।

और अनुमेय विचारों के क्षेत्र के बाहर, यह

शक्ति के दुर्भावनापूर्ण प्रयोग के बराबर होगा और वह है

अनुच्छेद *14* और *16* द्वारा प्रभावित। शक्ति का माला फिडे अभ्यास और

मनमानेपन से निकलने वाले विभिन्न घातक विकिरण हैं।

एक ही उपः वास्तव में बाद वाला पहले वाले को समझता है।

दोनों अनुच्छेद *14* और *16* द्वारा बाधित हैं।

97. रोयप्पा के मामले में दी गई उनकी राय के आधार पर

(ऊपर*)*, भगवती, जे., मेनका गांधी बनाम संघ में आयोजित।भारत *& Anr.3*[9]।

" तर्कसंगतता का सिद्धांत, जो कानूनी रूप से और साथ ही

दार्शनिक रूप से, समानता या गैर का एक आवश्यक तत्व है

21 न्यायसंगतता की परीक्षा का जवाब देना होगा ताकि अनुच्छेद *14* के अनुरूप। यह सही और न्यायपूर्ण होना चाहिए।

निष्पक्ष *"*और मनमाना, काल्पनिक या दमनकारी नहीं*"*।

98. अजय हसिया और ओआरएस में। बनाम खालिद मुजीब सहरावर्दी और

Ors.40, इस अदालत ने कहा कि *'*मनमानेपन*'* का परीक्षण झूठ बोल रहा था *" "*सरल लेकिन गर्भवती*"* रूप में अव्यक्त और डूबा हुआ

अनुच्छेद *14* और *'*वर्गीकरण*'* से बदलाव की व्याख्या की निम्नलिखित शब्दों में *'*मनमानेपन*'* सिद्धांत का सिद्धांतः

" 16 ...... वर्गीकरण का सिद्धांत जो द्वारा विकसित किया गया है

अदालतें अनुच्छेद *14* की व्याख्या नहीं करती हैं और न ही इसका उद्देश्य है। और उस लेख का अंत। यह केवल एक न्यायिक सूत्र है

यह निर्धारित करना कि क्या विधायी या कार्यकारी कार्रवाई में सवाल मनमाना है और इसलिए समानता से इनकार का गठन करता है। यदि वर्गीकरण उचित नहीं है और करता है

ऊपर उल्लिखित दो शर्तों को पूरा नहीं करने पर, विवादित विधायी या कार्यकारी कार्रवाई स्पष्ट रूप से होगी -

अनुच्छेद *14* के तहत मनमानी और समानता की गारंटी

उल्लंघन किया जाएगा। इसलिए जहाँ भी है

राज्य की कार्रवाई में मनमानी चाहे वह विधायिका की हो

39. (1978) 1 एससीसी *248*।

40. (1981) 1 एससीसी *722*।

या अनुच्छेद *12* के तहत कार्यपालिका या किसी *'*प्राधिकरण*'* का,

अनुच्छेद *14* तुरंत अमल में आता है और हड़ताल करता है।

ऐसी राज्य कार्रवाई को कम करें। वास्तव में, अवधारणा

तर्कसंगतता और गैर-मनमानेपन पूरे क्षेत्र में व्याप्त है।

संवैधानिक योजना और एक सुनहरा धागा है जो चलता है

संविधान के पूरे ताने-बाने के माध्यम से *"*।

99. रमण दयराम शेट्टी बनाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा

भारतीय प्राधिकरण और *Ors.4*[1] ने अनुच्छेद की सीमाओं की व्याख्या की

14 सरकार के कामकाज के बारे में निम्नानुसारः -

" 12 ...... इसलिए, यह कानून माना जाना चाहिए कि कहाँ

सरकार जनता के साथ व्यवहार कर रही है, चाहे किसी भी तरह से

या लाइसेंस या अन्य प्रकार की उदारता प्रदान करना, सरकार अपनी मीठी इच्छा पर मनमाने ढंग से कार्य नहीं कर सकती और जैसे

एक निजी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति के साथ व्यवहार करें जिसे वह पसंद करता है, लेकिन

इसकी कार्रवाई मानक या मानदंडों के अनुरूप होनी चाहिए।

जो मनमाना, तर्कहीन या अप्रासंगिक नहीं है। शक्ति या

अनुदान के मामले में सरकार का विवेकाधिकार

नौकरियों का पुरस्कार, अनुबंध, कोटा,

अनुज्ञप्ति आदि तर्कसंगत रूप से सीमित और संरचित होने चाहिए। प्रासंगिक और गैर-भेदभावपूर्ण मानक या मानक और यदि

सरकार किसी भी मामले में ऐसे मानक या मानक से अलग हो जाती है।

विशेष मामले या मामले, सरकार की कार्रवाई

गिराए जाने के लिए उत्तरदायी होगा, जब तक कि इसे दिखाया नहीं जा सकता है

सरकार द्वारा कि प्रस्थान मनमाना नहीं था, लेकिन

कुछ वैध सिद्धांत पर आधारित था जो अपने आप में नहीं था

अतार्किक, अनुचित या भेदभावपूर्ण "।

100. इस प्रकार समानता और मनमानेपन को *"*शपथ*"* घोषित किया गया।

दुश्मनों "और यह माना गया था कि एक मनमाना कार्य गलत होगासमानता का अधिकार। गैर-मनमानेपन को कानून के शासन के साथ जोड़ा गया था जिसके बारे में जेफरी जोवेल ने अपने मौलिक लेख "द

आज कानून का शासन "ने कहाः -

41. (1979) 3 एससीसी *489:* ए. आई. आर. *1979* एस. सी. *1628*

418 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट *[2012] 9* एस. सी. आर.

*"*कानून का शासन सिद्धांत मुख्य रूप से की शक्ति पर लागू होता है

कार्यान्वयन। यह मुख्य रूप से प्रक्रियात्मक निष्पक्षता की स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। जब किसी अधिकारी द्वारा कानून के शासन की अनदेखी की जाती है तो यह

कभी-कभी अदालतों द्वारा लागू किया जा सकता है।

101. जैसा कि उपरोक्त अभिव्यक्तियों से स्पष्ट है।

' मनमानेपन 'और' अनुचितता 'का उपयोग किया गया है विनिमेय रूप से और वास्तव में, एक के संदर्भ में परिभाषित किया गया है

दूसरा। हाल ही में, शर्मा ट्रांसपोर्ट बनाम सरकार में

ए. पी. और *Ors.42* के इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की हैः

" *25* ...... मनमाना के रूप में वर्णित होने के लिए, यह दिखाया जाना चाहिए कि यह उचित और स्पष्ट रूप से मनमाना नहीं था।

"मनमाने ढंग से" अभिव्यक्ति का अर्थ हैः एक अनुचित में

तरीके से, जैसा कि निश्चित या मनमौजी या खुशी से किया जाता है,

पर्याप्त निर्धारण सिद्धांत के बिना, में स्थापित नहीं

चीजों की प्रकृति, गैर-तर्कसंगत, नहीं किया गया या उसके अनुसार कार्य करना

तर्क या निर्णय के लिए, केवल इच्छा पर निर्भर करता है।

102. इसके अलावा, भले ही 'वर्गीकरण' सिद्धांत था

कभी खारिज नहीं किया गया, इसे इस न्यायालय के साथ कम पक्ष मिला है क्योंकि

'मनमानेपन' सिद्धांत की तुलना में। ओम कुमार और ओआरएस में।

बनाम भारत संघ, इस न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित कियाः

" *59.* लेकिन, ई. पी. रोयप्पा बनाम. टी. एन. भगवती राज्य, जे. अनुच्छेद *14* के प्रयोजनों के लिए एक और परीक्षण। यह कहा गया था

कि यदि प्रशासनिक कार्रवाई "मनमाना" थी, तो यह हो सकता है

प्रशासक को ऐसे के रूप में वर्णित किया गया है जो तर्कहीन है और ठोस कारण पर आधारित नहीं है। यह भी वर्णित है किअनुचित है "।

103. हालाँकि, इस न्यायालय ने इसके खिलाफ भी चेतावनी दी है

'मनमानेपन' सिद्धांत का मनमाना उपयोग। आम तौर पर, कानून हैं

42. (2002) 2 एससीसी *188*।

43. (2001) 2 एससीसी *386*।

आरईः *2012* का विशेष संदर्भ संख्या *1*

419

[डी. के. जैन, जे.*]*

भारत के संविधान के भाग *III,* विधायी अक्षमता या अत्यधिक प्रत्यायोजन का उल्लंघन करने के लिए खारिज कर दिया गया। हालांकि, रोयप्पा के मामले *(*ऊपर*)* के बाद से, सिद्धांत शिथिल रहा है।

आवेदन किया। ए. पी. और अन्य राज्यों में यह न्यायालय। बनाम मैकडॉवेल एंड कंपनी।*& Ors.44* ने एक उद्देश्यपूर्ण और वैज्ञानिक की आवश्यकता पर जोर दिया

मनमानेपन का विश्लेषण, विशेष रूप से हड़ताल करते समय

कानून। न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी ने टिप्पणी कीः

" 43 ...... संसद या उस मामले के लिए राज्य की शक्ति

विधायिकाएँ दो तरह से प्रतिबंधित हैं। द्वारा बनाया गया एक कानून

केवल दो आधारों और दो आधारों पर। *, (1)* की कमी विधायी क्षमता और *(2)* में से किसी का उल्लंघन

संविधान के भाग *III* में गारंटीकृत मौलिक अधिकार

या किसी अन्य संवैधानिक प्रावधान का। कोई तीसरा नहीं है

जमीन। हम चर्चा में नहीं पड़ना चाहते हैं।

प्रक्रियात्मक अनुचितता और मूल की अवधारणाएँ अनुचितता-निर्णयों से प्रेरित अवधारणाएँ

संयुक्त राज्य सर्वोच्च न्यायालय। अमेरिका में भी, ये

अवधारणाएँ और विशेष रूप से मूल देय की अवधारणा प्रक्रिया अंतहीन विवाद की साबित हुई है,

इसे गंभीर रूप से कम करने की दिशा में नवीनतम सोच

जमीन *(*मूल देय प्रक्रिया*)*। मुख्य आलोचनाएँमूल नियत प्रक्रिया के आधार के विरुद्ध यह है कि

यह न्यायालयों को विवेक के मध्यस्थों के रूप में स्थापित करना चाहता है

विधान के विशेष टुकड़े को अधिनियमित करने में विधायिका।

हमारे लिए यह कहना ही काफी है कि यह किसी भी नाम से हो।

विशेषता, अमान्यीकरण का आधार इसके भीतर आना चाहिए

ऊपर वर्णित दो मैदानों के चार कोने। अन्य में

समानता खंड/समान संरक्षण खंड का उल्लंघनउसमें स्थापित। इसी तरह, यदि किसी अधिनियम को चुनौती दी जाती है

द्वारा गारंटीकृत किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के रूप में

अनुच्छेद *19 (1)* के खंड *(ए)* से *(जी)* तक, इसे निरस्त किया जा सकता है

44. (1996) 3 एससीसी *709*।

केवल तभी जब यह किसी भी खंड *(*खंडों*)* से *(6)* तक सहेजा नहीं गया हो

अनुच्छेद *19* आदि। किसी भी अधिनियम को केवल यह कहकर निरस्त नहीं किया जा सकता है कि यह मनमाना या अनुचित है। कुछया किसी अधिनियम को अमान्य करने से पहले अन्य संवैधानिक दुर्बलता का पता लगाना होगा। किसी अधिनियम को निरस्त नहीं किया जा सकता है।

इस आधार पर कि अदालत इसे अनुचित समझती है। संसद और

विधायिकाएँ, जैसा कि वे हैं

जन-प्रतिनिधियों को पता होना चाहिए और लोगों की जरूरतों और उनके लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है, इसके बारे में जागरूक रहें। अदालत उनके बारे में निर्णय नहीं दे सकती है

बुद्धिमत्ता। इस संबंध में यह याद रखना चाहिए किप्रशासनिक कार्रवाई के मामले में भी,

न्यायिक समीक्षा तीन आधारों तक सीमित है, अर्थात्। , *((i)*

अनुचितता, जो अधिक उचित रूप से हो सकती है

इसे अतार्किकता कहा जाता है, *(ii)* अवैधता और *(iii)* प्रक्रियात्मक अनुचितता *(*सिविल सेवा संघों की परिषद *v* देखें। मंत्री

सिविल सेवा के लिए जो निर्णय इसके द्वारा स्वीकार किया गया है

अदालत भी*)*।

*** व्यापक रूप से और बल्कि अंधाधुंध रूप से उपयोग की जाने वाली एक अभिव्यक्ति -स्वाभाविक रूप से अस्पष्ट आयात की एक अभिव्यक्ति। द.

भारत में इस अभिव्यक्ति का व्यापक उपयोग एक की याद दिलाता है

फ्रैंकफर्टर, जे ने हैटी माई टिलर बनाम में क्या कहा। अटलांटिक

कोस्ट लाइन रेलरोड कं., *87* एल ईडी *610: 318* यूएस *54(1943) . "* वाक्यांश जीवन की शुरुआत एक साहित्यिक अभिव्यक्ति के रूप में करता है;

इसका आनंद जल्द ही इसकी आलसी पुनरावृत्ति और पुनरावृत्ति की ओर ले जाता है।

इसे एक कानूनी सूत्र के रूप में स्थापित करता है, जिसका बिना किसी भेदभाव के उपयोग किया जाता है

विभिन्न और कभी-कभी विरोधाभासी विचारों को व्यक्त करने के लिए ",

विद्वान न्यायाधीश ने कहा।

104. इसलिए, रोयप्पा युग के बाद से,

'मनमानेपन' की अवधारणा कोई महत्वपूर्ण नहीं रही है।

परिवर्तन करें। कुछ निर्णयों ने सिद्धांत पर टिप्पणी की है

मनमानेपन परीक्षण की शिथिलता और इसकी परतों को अनुमेय सीमाओं के भीतर रखने की कोशिश की। उदाहरण के लिए, जहाँ

कानून या नियमों को मनमाना होने के कारण निरस्त कर दिया गया है। अनुचित होने के अर्थ में *[*देखें*]:* एयर इंडिया बनाम नरगेश आरईः

2012 का विशेष संदर्भ संख्या *1*

421

[डी. के. जैन, जे.*]*

मिर्जा *1 5 (*पीपी पर एससीसी। *372-373)]* केवल इसके आधार पर

" जैसा कि ऊपर बताया गया है, मैकडॉवेल के मामले *(*ऊपर*)* में मनमानेपन पर संदेह किया गया है। लेकिन अन्यथा, विषय वस्तु,

अनुच्छेद *14* के उल्लंघन की जाँच के लिए सामग्री और परीक्षण कमोबेश अपरिवर्तित रहे हैं।

105. निर्णयों की प्रवृत्ति की जांच से यह स्पष्ट है

यह समझ में आता है कि राज्य की कार्रवाई, चाहे वह संबंधित हो अनुदान का वितरण, अनुबंधों का अनुदान या भूमि का आवंटन,

अनुच्छेद *14* की कसौटी पर परीक्षण किया जाना है

संविधान। किसी कानून को मनमाना होने के कारण निरस्त नहीं किया जा सकता है।

संवैधानिक दुर्बलता की ओर इशारा किए बिना

मैकडॉवेल के मामले *(ऊपर)* ने कहा है। इसलिए, एक राज्य कार्रवाई

संविधान के अनुच्छेद *14* के तहत संवैधानिक दुर्बलताओं के लिए परीक्षण किया जाना चाहिए। कार्रवाई निष्पक्ष, उचित, गैर-उचित होनी चाहिए।

भेदभावपूर्ण, पारदर्शी, गैर-मनमौजी, निष्पक्ष, पक्षपात या भाई-भतीजावाद के बिना, स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देने के लिए

प्रतिस्पर्धा और न्यायसंगत व्यवहार। इसके अनुरूप होना चाहिए

ऐसे मानदंड जो तर्कसंगत हों, कारणों से सूचित हों और जिनके द्वारा निर्देशित हों

जनहित आदि। इन सभी सिद्धांतों में निहित हैं

अनुच्छेद *14* की मौलिक अवधारणा। यह आदेश है कि

भारत के संविधान का अनुच्छेद *14*।

*'*नीलामी*'* एक संवैधानिक आदेशः

106. इस तरह के संवैधानिक इरादे और प्रभाव

अनुच्छेद *14,* सवाल उठता है-क्या प्राकृतिक संसाधनों के निपटान की एक विधि के रूप में नीलामी को संवैधानिक घोषित किया जा सकता है*?*

भारत के संविधान के अनुच्छेद *14* के तहत जनादेश*?* हम.

बिना किसी हिचकिचाहट के इसका जवाब नकारात्मक में देंगे क्योंकि कोई अन्य

जवाब पूरी तरह से अनुच्छेद की योजना के विपरीत होगा

14. सबसे पहले, अनुच्छेद *14* सकारात्मक और नकारात्मक अधिकारों का संकेत दे सकता है

एक व्यक्ति, लेकिन राज्य के संबंध में, यह केवल नकारात्मक शब्दों में है*;* राज्य के खिलाफ एक चेतावनी की तरह जोराज्य को मनमाना, अनुचित, मनमौजी या भेदभावपूर्ण कार्रवाई करने से रोकता है। अनुच्छेद *14,*

45. (1981) 4 एससीसी 335।

इसलिए, राज्य को विशेष कदम उठाने के लिए आदेश देने के बजाय कुछ प्रकार की कार्रवाई करने के खिलाफ एक निषेधाज्ञा है।

नीलामी के आदेश को इसकी योजना में पढ़ना इस प्रकार होगा

अनुच्छेद की स्पष्ट भाषा से स्पष्ट आशय के पूरी तरह से विपरीत।

107. दूसरा, एक संवैधानिक जनादेश एक निरपेक्ष है।

सिद्धांत जिसे सभी स्थितियों में लागू किया जाना है; यह नहीं हो सकता है

कुछ में लागू किया गया और दूसरों में परीक्षण नहीं किया गया। निरपेक्ष सिद्धांतफिर मामला दर मामला आधार पर यह देखने के लिए लागू किया जाता है कि कौन सी कार्रवाई की जाती है

संवैधानिक सिद्धांत की आवश्यकताओं को पूरा करना और जो

नहीं करते हैं।

108. न्यायमूर्ति के. सुब्बा राव ने अपने व्याख्यानों में

"कुछ संवैधानिक समस्याएं" शीर्षक वाली पुस्तक, आलोचनात्मक विश्लेषण

भारतीय संवैधानिक विकास के रुझानों को निम्नानुसार बताया गया हैः

मामलों, मुझे कोई संदेह नहीं है कि की मनमानीअधिकारियों को कम किया जाएगा। अगर इन अधिकारियों को सौंपा गया है

विवेकाधीन शक्तियों के साथ, महसूस करें कि उनके अवैध

लोगों के अधिकारों का उल्लंघन करने वाले आदेशों को रद्द कर दिया जाएगाउपयुक्त प्राधिकारी द्वारा, वे शायद ही कभी आदेश पारित करते थे

लेकिन आदेशों के सार की जांच की जाएगीखुला मैदान, वे अपनी सीमा के भीतर रखने की कोशिश करेंगे। द.

सार्वजनिक रूप से शिकायतों को दूर करने का डर हमेशा से रहा है

अदालतों को रिटों से भरा जाएगा जिसका कोई आधार नहीं है। *109.* न्यायमूर्ति के. के. ने भी इसी तरह की भावना व्यक्त की थी।

मैथ्यू एक पुस्तक के रूप में शामिल व्याख्यानों की श्रृंखला में

"लोकतंत्र, समानता और स्वतंत्रता" शीर्षक जिसमें यह कहा गया है कि न्यायिक समीक्षा की ताकत मामले-दर-मामले में निहित है

न्यायनिर्णयन "। यही कारण है कि यह न्यायालय अपनी पवित्रता मेंकेशवानंद भारती श्रीपदगलवरु बनाम केरल राज्य और आरईः

2012 का विशेष संदर्भ संख्या *1*

423

[डी. के. जैन, जे.*]*

एक अमेरिकी निर्णय से एक उद्धरण, निम्नानुसार देखा गयाः

" 1695 ...... "उचित प्रक्रिया" अभिव्यक्ति का कारण है

कभी परिभाषित नहीं किया गया है कि यह एक अवधारणा का प्रतीक है

निष्पक्षता जिसके संबंध में निर्णय लिया जाना है

प्रत्येक मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ और उसके अनुसार भी

समाज में कुछ समय के लिए प्रचलित आदतों के लिए

जिसे अवधारणा को लागू करना होगा। न्यायधीश के रूप में

फ्रैंकफर्टर ने कहा, "उचित प्रक्रिया" तकनीकी नहीं है।

समय, स्थान और उससे असंबंधित एक निश्चित सामग्री के साथ अवधारणापरिस्थितियाँ *[*संयुक्त फासीवाद विरोधी शरणार्थी देखें*]*

समिति *v.* मैकग्राथ *341* यू. एस. *123]* "।*110.* इसलिए, समानता को केवल अर्थ तक सीमित नहीं किया जा सकता है।

नीलामी, हर परिदृश्य में इसका परीक्षण किए बिना। पश्चिमी राज्य में

बंगाल बनाम अनवर अली सरकार *^ 7,* यह न्यायालय, कोटच से उद्धृत करते हुए

बनाम। पायलट कमांडर *4 3* ने माना था कि "संवैधानिक आदेश

किसी राज्य के लिए कानूनों का समान संरक्षण एक लक्ष्य निर्धारित करता है

एक सटीक के आविष्कार और अनुप्रयोग से प्राप्य नहीं है

आदर्श लोकतंत्र के आवश्यक तत्वों के संदर्भ में किसी भी कानून की वैधता का परीक्षण नहीं किया जा सकता है, जो वास्तव में शामिल हैं।संविधान में। *(* देखिएः इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज

नारायण *9)*। न्यायालयों को किसी क़ानून को अमान्य घोषित करने की स्वतंत्रता नहीं है।

क्योंकि उनकी राय में यह भावना के खिलाफ है

संविधान। अदालतें किसी सीमा या संवैधानिक घोषणा नहीं कर सकतीं।

कुछ आदर्श की खोज करने की धारणा के तहत आवश्यकता

मानक। इसके अलावा, एक संवैधानिक सिद्धांत इन तक सीमित नहीं होना चाहिएः

एक सटीक सूत्र लेकिन एक अमूर्त सिद्धांत लागू होना चाहिए

सटीक स्थितियों के लिए। एक संवैधानिक जनादेश के रूप में नीलामी आयोजित करने का परिणाम सामाजिक प्रयासों, कल्याणकारी योजनाओं सहित इससे भटकने वाली हर कार्रवाई को रद्द करना होगा।

46. (1973) 4 एससीसी *225*।

47. 1952 एस. सी. आर. *284* पीपी पर। *297 .*

48. 330 अमेरिका *552*।

49. 1975 (एस. सी. सी. *1*।

और प्रचार नीतियाँ, भले ही सी. पी. आई. एल. ने स्वयं तर्क दिया हो

उसी के खिलाफ, और नीलामी को अनिवार्य बनाने के लिए कहाकेवल दुर्लभ प्राकृतिक संसाधनों के अलगाव के लिए

निजी और वाणिज्यिक व्यावसायिक उद्यम। यह अजीब होगा कि केवल एक सीमित समूह के लिए एक संवैधानिक सिद्धांत के रूप में नीलामी प्राप्त करें

अनुच्छेद की व्यापक और सामान्य घोषणा से स्थितियों का

14. संवैधानिक निर्णय की ताकत मामले के निर्णय के मामले में निहित है और इसलिए नीलामी को बढ़ाया नहीं जा सकता है एक संवैधानिक जनादेश।

111. अंत में, नीलामी को एक संवैधानिक जनादेश के रूप में पढ़ना

यह अस्वीकार्य होगा क्योंकि इस तरह का दृष्टिकोण विकृत हो सकता है

अनुच्छेद *39 (बी)* में सन्निहित एक अन्य संवैधानिक सिद्धांत। द.नीति के कुछ सिद्धांतों की गणना करने वाला लेख कहा गया है,

राज्य के बाद, निम्नानुसार हैः

"राज्य, विशेष रूप से, अपनी नीति को इस दिशा में निर्देशित करेगा कि

सुरक्षित करना -

(ए)।

(ख) सामग्री का स्वामित्व और नियंत्रण

समुदाय के संसाधनों को इस प्रकार वितरित किया जाता है कि

आम भलाई के लिए सबसे अच्छा;

प्राकृतिक संसाधनों का निपटान उपयोग का एक पहलू है और

वितरित किया जाता है ताकि आम भलाई को सर्वोत्तम रूप से कम किया जा सके। लेख *37* यह प्रावधान करता है कि भाग *IV* के प्रावधान नहीं होंगे

किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय, लेकिन उसमें निर्धारित सिद्धांत फिर भी देश के शासन में मौलिक हैं।

और यह राज्य का कर्तव्य होगा कि वह इन सिद्धांतों को कानून बनाने में लागू करे।

112. इसलिए, यह अनुच्छेद, एक अर्थ में, एक प्रतिबंध है -

'संविधान में निर्मित 'वितरण'। लेकिन प्रतिबंध आरई हैः

2012 का विशेष संदर्भ संख्या *1*

425

[डी. के. जैन, जे.*]*

वस्तु पर थोपा जाता है न कि साधन पर। 'वितरण' को नियंत्रित करने वाला व्यापक और अंतर्निहित सिद्धांत आगे बढ़ना है

आम भलाई। लेकिन उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए,

संविधान सामान्य शब्द 'वितरण' का उपयोग करता है। वितरण की व्यापक रूपरेखा होती है और यह केवल एक अर्थ तक सीमित नहीं हो सकता है।

प्राकृतिक संसाधनों का वितरण/आवंटन जो अंततः "आम भलाई" को कम करें।

113. तमिलनाडु और अन्य राज्यों में। बनाम एल. अबू कावुर बाई

& Ors.5⁰, इस न्यायालय ने व्यापक-आधारित अवधारणा की व्याख्या की

'वितरण इस प्रकार हैः

"89. ...... अनुच्छेद *39 (*ख*)* में प्रयुक्त 'वितरण' शब्द होना चाहिए

व्यापक रूप से इस तरह से समझा जाता है कि एक अदालत पूरा और

में निहित वैधानिक इरादे के लिए व्यापक प्रभाव

अनुच्छेद *39 (*बी*)*। शब्द का एक संकीर्ण निर्माण

' 'वितरण' उसी उद्देश्य को पराजित या निराश कर सकता है जो

अनुच्छेद कम करने का प्रयास करता है "।

114. विभिन्न से 'वितरण' की परिभाषाओं पर ध्यान देने के बाद

शब्दकोश, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

"92. इसलिए, यह स्पष्ट है कि विशाल रेंज को देखते हुए

ऊपर उल्लिखित शब्दकोशों में उल्लिखित, यह नहीं होगाविशुद्ध रूप से 'वितरण' शब्द का अर्थ लगाने के लिए सही हो

शाब्दिक अर्थ ताकि इसका अर्थ केवल किसी विशेष का विभाजन हो।

दयालु या विशेष व्यक्तियों के लिए। शब्द, विभाजन,

आबंटन, आबंटन, वर्गीकरण, स्पष्ट रूप से इसके अंतर्गत आते हैं

'वितरण' शब्द का व्यापक विस्तार। तो समझा जाता है,

अनुच्छेद *39 (*बी*)* में उपयोग किए गए शब्द 'वितरण' में शामिल होंगेःएक के विभिन्न पहलू, पहलू, तरीके और शब्दावली

वितरण की व्यापक अवधारणा।

115. इस प्रकार, इसे पूर्व-उद्धृत से देखा जा सकता है।

अनुच्छेद जो निस्संदेह "वितरण" शब्द में व्यापक हैं *50. (1984) 1* एससीसी *515*।

[2012] 9 एस सी आर।

426 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आयाम और सभी शिष्टाचार और विधियों को शामिल करता है

वितरण, जिसमें वर्ग, उद्योग, क्षेत्र शामिल होंगे,

निजी और सार्वजनिक अनुभाग आदि। बुनियादी को ध्यान में रखते हुए

अनुच्छेद *39 (*बी*)* की प्रकृति, के तहत समानता की एक संकीर्ण अवधारणा

इसलिए, एक ऐसी गुहा नहीं हो सकती है जो "सामान्य भलाई" और "बड़ी" हो। जनहित को संवैधानिक वास्तविकता के रूप में देखा जाना चाहिए

यथार्थीकरण के योग्य।

116. सी. पी. आई. एल. के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि राजस्व

वाणिज्यिक दोहन के लिए किसी प्राकृतिक संसाधन की बिक्री या अलगाव के दौरान अधिकतमकरण ही जनता को प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है।

अच्छा है क्योंकि एकत्र किए गए राजस्व को कल्याण के लिए उपयोग किया जा सकता है

नीतियाँ बनाना और बढ़ते घाटे को नियंत्रित करना। इसके अनुसार

विद्वान वकील, चूंकि राजस्व को अधिकतम करने का सबसे अच्छा तरीका नीलामी के माध्यम से है, यह एक संवैधानिक बन जाता है

अनुच्छेद *39 (*बी*)* के तहत भी सिद्धांत। लेकिन हम नहीं हैं

ऐसा करने के लिए राजी किया। नीलामी सबसे अच्छा तरीका हो सकता है राजस्व को अधिकतम करना लेकिन राजस्व को अधिकतम करना हमेशा नहीं हो सकता है

सार्वजनिक भलाई के लिए सबसे अच्छा तरीका बनें। आम भलाई "है

के वितरण के लिए अनुच्छेद *39 (*बी*)* के तहत एकमात्र मार्गदर्शक कारक

प्राकृतिक संसाधन। यह परीक्षण की कसौटी है कि क्या कोई

नीति "आम भलाई" को कम करती है और यदि ऐसा किया जाता है, चाहे कोई भी साधन अपनाया गया हो, तो यह स्पष्ट रूप से इसके अनुसार हैअनुच्छेद *39 (*बी*)* में निहित सिद्धांत।

117. कर्नाटक राज्य और अन्न में। बनाम श्री

रंगनाथ रेड्डी और अन्न। *51* , न्यायमूर्ति कृष्ण लायर ने कहा

कि *39 (*ख*)* जैसे अनुच्छेद के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए,

उस अनुच्छेद के शब्दों को संकीर्ण अर्थ के बजाय व्यापक अर्थ दिया जाना चाहिए। उनकी अद्वितीय शैली में, उनके प्रभु ने राय दी इस प्रकारः

" *83.* दो निष्कर्ष हमें सर्वोत्कृष्ट समझते हैं। भाग *IV*, विशेष रूप से अनुच्छेद *39 (*बी*)* और *(*सी*)*, एक भविष्यवादी जनादेश है

51. (1977) 4 एससीसी *471*।

राज्य के परिवर्तन के संदेश के साथ

आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था। सबसे पहले, इस तरह के बदलाव की आवश्यकता है

मशीनरी। दूसरा और परिणामस्वरूप, उच्च के प्रति निष्ठासंविधान का उद्देश्य, अर्थात। , सामाजिक और आर्थिक

भौतिक अभाव और पूर्ण असमानताओं के संदर्भ में न्याय

बड़े पैमाने पर, अदालत को आरोप लगाने के लिए मजबूर करता हैके साथ उपयोग किए जाने वाले गर्भवती शब्दों के लिए विस्तृत अर्थ

आशावादी दूरदर्शिता, उनके अर्थ को सीमित करने के लिए नहीं

प्रावधान को प्रेरित करने वाले उद्देश्यों का विरोधाभास। को।

अनुष्ठान के माध्यम से संविधान के प्रति फरीसी बनें

निर्माण सामाजिक-आध्यात्मिक दबाव को कमजोर करने के लिए हैसंस्थापक पिताओं का गतिशील विश्वास।

118. बेनेट कोलमैन एंड कंपनी और ओआरएस के मामले में। बनाम।

समुदाय के भौतिक संसाधनों का लोचदार मानक है आम भलाई "। इस प्रकार "सामान्य भलाई" अनुच्छेद *39 (*बी*)* में एक मानक है।

जिसकी प्रयोज्यता पर इस न्यायालय द्वारा तथ्यों पर विचार किया गया था

मामले से। उस मामले में भी यह न्यायालय विकसित नहीं हुआ था "सामान्य" के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने स्वयं के आर्थिक मानदंड

अनुच्छेद *39 (*बी*)* में "अच्छा", जो निदेशक सिद्धांतों का हिस्सा है।

119. "आम भलाई" के मानदंड को समझना होगा।

और समग्र तरीके से सराहना की। यह स्पष्ट है कि

जिस तरह से आम भलाई को सबसे अच्छी तरह से कम किया जाता है, वह कोई ऐसा मामला नहीं है जिसे किसी भी संवैधानिक मानदंड से मापा जा सके-यह देश के आर्थिक और राजनीतिक दर्शन पर निर्भर करेगा।

सरकार ने। राजस्व को अधिकतम करना ही एकमात्र तरीका नहीं है।

जिसे आम भलाई के लिए कम किया जा सकता है। जहाँ राजस्व अधिकतमकरण एक नीति का उद्देश्य है, जिसे अनिवार्य माना जा रहा है।

उस समय उस संसाधन को आम भलाई को कम करने का सबसे अच्छा तरीका होने के लिए, नीलामी बेहतर होगी।

विधियाँ, हालांकि एकमात्र विधि नहीं है। राजस्व कहाँ है*?*

52. (1972) 2 एससीसी *788*।

[2012] 9 एस सी आर।

428 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अधिकतमकरण वितरण नीति का उद्देश्य नहीं है,

नीलामी का सवाल ही नहीं उठेगा। राजस्व संबंधी विचार विकास के लिए गौण विचार मान सकते हैं।विचार करें।

120. इसलिए, निष्कर्ष में, निवेदन है कि

अनुच्छेद *14* का अधिदेश यह है कि किसी प्राकृतिक संसाधन का कोई भी निपटान

वाणिज्यिक उपयोग के लिए राजस्व को अधिकतम करने के लिए होना चाहिए, और इस प्रकार

नीलामी द्वारा, न तो कानून पर आधारित है और न ही तर्क पर। वहाँ कोई नहीं है

आर्थिक नीतियों के मामले में संवैधानिक अनिवार्यता

अनुच्छेद *14* किसी भी आर्थिक नीति को संवैधानिक अधिदेश के रूप में परिभाषित नहीं करता है। यहां तक कि *39 (*बी*)* का जनादेश भी नहीं लगाता है

सार्वजनिक भलाई के लिए अपनाए गए साधनों पर प्रतिबंध और व्यापक शब्द *'*वितरण*'* का उपयोग करता है, यह सुझाव देते हुए कि वितरण की पद्धति निश्चित नहीं है। आर्थिक तर्क

यह स्थापित करता है कि प्राकृतिक संसाधनों का अलगाव/आवंटन

सबसे अधिक बोली लगाने वाला अनिवार्य रूप से कम करने का एकमात्र तरीका नहीं हो सकता है।

आम भलाई, और कभी-कभी, सार्वजनिक भलाई के विपरीत हो सकती है।

इसलिए, सभी प्राकृतिक पदार्थों के निपटान पर बहुत कम जोर देने की आवश्यकता है।

नीलामियों के माध्यम से संसाधन स्पष्ट रूप से संवैधानिक नहीं हैं आदेश।

नीलामी से विधायी प्रभाग

121. परिणामस्वरूप, इस न्यायालय ने कई अवसरों पर,

प्राकृतिक के निपटान के लिए निर्देशात्मक साधन दिए गए निर्णय

विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न संसाधनों के लिए नीलामी के अलावा अन्य संसाधन

परिस्थितियाँ। कुछ मामलों को संदर्भित करना लाभदायक होगा।

और इस न्यायालय द्वारा विचलन के लिए अपनाए गए कारणों की सराहना करते हैंनीलामी की विधि से।

122. मेसर्स कस्तुरी लाल लक्ष्मी रेड्डी बनाम स्टेट ऑफ

जम्मू और कश्मीर और अन्र. *53* , प्रभावकारिता की तुलना करते हुए

घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नीलामी, पी. एन. भगवती, जे.

देखा गयाः -

"22. ...... यदि राज्य टैपिंग अनुबंध सरलता दे रहा था

53. (1980) 4 एससीसी *1.*

इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि राज्य को उच्चतम मूल्य प्राप्त करने के लिए नीलामी करनी होगी या निविदाएं आमंत्रित करनी होंगी।

सार्वजनिक कल्याण या ब्याज, लेकिन इस तरह के मामले में जहांराज्य स्थापना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पानी, बिजली, कच्चा माल आदि जैसे संसाधनों का आवंटन कर रहा है।

राज्य के भीतर उद्योगों के बारे में, हमें नहीं लगता कि राज्य है

विज्ञापन देना और लोगों को बताना कि वह राज्य के भीतर एक विशेष उद्योग स्थापित करना चाहता है और आमंत्रित करना चाहता है

जो इस उद्देश्य के लिए प्रस्ताव लाने के इच्छुक हैं। राज्य ऐसा करने का विकल्प चुन सकता है, यदि वह उचित समझता है और

एक दी गई स्थिति में, यह भी हो सकता है ऐसा करना राज्य के लिए लाभप्रद है, लेकिन यदि कोई निजी पक्ष राज्य के सामने आता है और एक उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव देता है,

राज्य किसी का उल्लंघन नहीं करेगा

संवैधानिक या कानूनी दायित्व यदि वह ऐसे पक्ष के साथ बातचीत करता है और संसाधन और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए सहमत होता है

उद्योग स्थापित करने के उद्देश्य से। राज्य नहीं है

ऐसे पक्ष को बताने के लिए बाध्य: "कृपया प्रतीक्षा करें मैं पहले विज्ञापन दूंगा,

पता लगाएँ कि क्या कोई अन्य प्रस्ताव आने वाले हैं और फिर उसके बाद

सभी प्रस्तावों पर विचार करते हुए, तय करें कि क्या मुझे आपको सेट करने देना चाहिए

उद्योग को ऊपर उठाएँ "। राज्य को ऐसे मामले में किसी निजी उद्यमी के साथ बातचीत करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। उसे राज्य के भीतर एक उद्योग स्थापित करने के लिए प्रेरित करना और यदि

राज्य ऐसे उद्यमी के साथ अनुबंध करता है

स्थापना के लिए संसाधन और अन्य सुविधाएं प्रदान करना

क्योंकि राज्य ने ईमानदारी से, उचित रूप से और सार्वजनिक रूप से कार्य किया हैब्याज। यदि अनुबंध के नियम और शर्तें या आसपास की परिस्थितियाँ दर्शाती हैं कि राज्य ने कार्रवाई की है

दुर्भावनापूर्ण या अनुचित या भ्रष्ट उद्देश्य से या किसी के निजी हितों को बढ़ावा देने के लिएराज्य, अदालत निस्संदेह हस्तक्षेप करेगी और हड़ताल करेगी

राज्य की कार्रवाई को मनमाना, अनुचित या लोक हित के विपरीत माना जाए। लेकिन जब तक राज्य की कार्रवाई सही है

न्यायालय केवल *430* सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट *[2012] 9* एस. सी. आर. में हस्तक्षेप नहीं करेगा।

इस आधार पर कि कोई विज्ञापन या प्रचार नहीं किया गया था

की गई या निविदाएं आमंत्रित की गईं। *"123.* सच्चिदानंद पांडे *(ऊपर)* में कस्तूरी को देखने के बाद

लाल के मामले *(ऊपर)* का निष्कर्ष इस प्रकार निकाला गयाः

"40. में उद्धृत प्रासंगिक मामलों पर विचार करने पर

निम्नलिखित प्रस्तावों को भी लिया जा सकता हैः राज्य के स्वामित्व वाली या सार्वजनिक स्वामित्व वाली संपत्ति नहीं है

कार्यपालिका के पूर्ण विवेकाधिकार पर निपटा जाए।

कुछ उपदेशों और सिद्धांतों का पालन करना पड़ता है।जनहित सर्वोपरि विचार है। इनमें से एक

लोक हित को सुरक्षित करने के तरीके, जब किसी संपत्ति के निपटान के लिए आवश्यक माना जाता है, उसे बेचना है।

सार्वजनिक नीलामी द्वारा या निविदाएं आमंत्रित करके संपत्ति। हालांकि

यह सामान्य नियम है, यह एक अपरिवर्तनीय नियम नहीं है। वहाँ

ऐसी स्थितियाँ हो सकती हैं जहाँ मजबूर करने वाले कारण हों

नियम से प्रस्थान की आवश्यकता है लेकिन फिर कारण

क्योंकि प्रस्थान तर्कसंगत होना चाहिए और नहीं होना चाहिए

भेदभाव का संकेत। सार्वजनिक न्याय की उपस्थिति उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी न्याय करना। कुछ नहीं करना चाहिए।

जो पूर्वाग्रह, नौकरी या भाई-भतीजावाद का आभास देता है।

124. हाजी टी. एम. हसन रावथर बनाम। केरल वित्तीय

कॉर्प. *54* , सहित कानून की एक विस्तृत समीक्षा के बाद

कस्तूरी लाल *(ऊपर)* और सच्चिदानंद पांडे *(ऊपर)* में निर्णय, यह माना गया था कि राज्य के स्वामित्व का सार्वजनिक निपटान गुण एकमात्र नियम नहीं है। अन्य बातों के साथ-साथ यह भी देखा गया कि

" 14. राज्य या किसी के स्वामित्व वाली सार्वजनिक संपत्ति

राज्य के उपकरणों को आम तौर पर सार्वजनिक नीलामी या निविदाएं आमंत्रित करके बेचा जाना चाहिए। यह न्यायालय रहा है

उस नियम पर जोर देते हुए, न केवल संपत्ति के लिए उच्चतम मूल्य प्राप्त करने के लिए बल्कि की गतिविधियों में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए

राज्य और सार्वजनिक प्राधिकरण। उन्हें निस्संदेह ऐसा करना चाहिए।

निष्पक्षता से काम लें। उनके कार्य वैध होने चाहिए। उनके सौदे

54. (1988) 1 एससीसी *166*।

ऊपर होना चाहिए। उनका लेन-देन होना चाहिए

बिना किसी घृणा या स्नेह के। कुछ भी सुझाव देने वाला नहीं होना चाहिए

भेदभाव। उनके द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया जाना चाहिए जो पक्षपात, पक्षपात या भाई-भतीजावाद का आभास देता है।

आम तौर पर ये कारक अनुपस्थित होंगे यदि मामला है

सार्वजनिक नीलामी या निविदाओं द्वारा बिक्री के लिए लाया गया। यही कारण है कि

अदालत ने बार-बार कहा और दोहराया कि राज्य

स्वामित्व वाली संपत्तियों का सार्वजनिक रूप से निपटान किया जाना आवश्यक है।

लेकिन यह एकमात्र नियम नहीं है। ओ. चिन्नाप्पा रेड्डी, जे. यह देखा गया कि "हालांकि यह सामान्य नियम है, लेकिन यह एक नहीं है

अपरिवर्तनीय नियम "। ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं जो आवश्यक हों

नियम से प्रस्थान, लेकिन फिर ऐसे उदाहरण होने चाहिए

मजबूरियों द्वारा उचित ठहराया जाता है, न कि समझौते द्वारा। इसे होना ही चाहिए।

बाध्यकारी कारणों से उचित ठहराया जाए न कि केवल सुविधा "।

यहाँ, न्यायालय ने पिछले फैसलों को जोड़ा और कहा

संसाधनों के सार्वजनिक निपटान से विचलन

सहनीय होना चाहिए; इस तरह के विचलन को उचित ठहराया जाना चाहिए

कारण बताना और केवल सुविधा से नहीं।

125. एम. पी. तेल निष्कर्षण और ए. एन. आर. में। बनाम। एम. पी. और राज्य

55. इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

कार्रवाई, खुली निविदाएं आमंत्रित करके बड़ी रकम का वितरण या सार्वजनिक नीलामी द्वारा वांछनीय है, यह नहीं माना जा सकता है कि नहीं

बातचीत द्वारा इस तरह की उदारता का मामला वितरण है

अनुमति है। तत्काल मामले में, एक नीतिगत निर्णय के रूप में

के साथ समझौते में प्रवेश करके सुरक्षात्मक उपाय

साल के बीजों की सुनिश्चित आपूर्ति के लिए चयनित औद्योगिक इकाइयाँ

सरकार द्वारा रियायती दर पर लिया गया है। कुछ स्वीकृत लोगों पर रॉयल्टी की दर भी तय की गई है।

मूल्य निर्धारण सूत्र का सिद्धांत जैसा कि आगे बताया जाएगा।

अतः साल के बीजों का वितरण या आवंटन

उत्तरदाताओं और अन्य इकाइयों के लिए निर्धारित रॉयल्टी

(1997) 7 एससीसी *592*।

समझौतों द्वारा कवर किए जाने पर हमला नहीं किया जा सकता है। होना ही है।

सराहना की कि इस मामले में, सार्वजनिक नीलामी द्वारा वितरण या खुली निविदा द्वारा उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है

साल के बीज की आपूर्ति के माध्यम से सुरक्षात्मक उपाय की नीति

औद्योगिक इकाइयों को रॉयल्टी की रियायती दर पर

वैध और वस्तुनिष्ठ विचारों पर चुने जाने पर समझौतों द्वारा कवर किया जाता है।

126. नेताजी बैग और ओआरएस में। बनाम। डब्ल्यू. बी. और *Ors.56* की स्थिति, यह

न्यायालय ने कहा कि निविदाएं जारी नहीं की गईं या आयोजित नहीं की गईं

सार्वजनिक नीलामी, सभी मामलों में, मनमाने ढंग से कार्यकारी शक्ति के प्रयोग का परिणाम नहीं माना जाएगा।

तरीके से। यह कहा गया थाः

" 19. ...... प्रस्ताव पर कोई विवाद नहीं हो सकता है।

कि आम तौर पर जब किसी भी राज्य की भूमि का इरादा है

हस्तांतरित या राज्य की उदारता प्रदान करने का निर्णय लिया गया,

रिसॉर्ट को सार्वजनिक नीलामी या हस्तांतरण के लिए रखा जाना चाहिए

लोगों से निविदाएं आमंत्रित करना। यह निश्चित होगा। आदेश के अनुपालन की गारंटी देने की विधि

संविधान का अनुच्छेद *14*। निविदा जारी नहीं की गई या नहीं सार्वजनिक नीलामी का आयोजन सभी मामलों में नहीं माना जाएगा।

में कार्यकारी शक्ति के प्रयोग का परिणाम होना

एक मनमाना तरीका। यदि चुनौती दी जाती है तो सामान्य नियम को अपवाद बनाना राज्य कार्यपालिका द्वारा उचित ठहराया जा सकता है।

उचित कार्यवाहियों में। संवैधानिक अदालतें

कथित अनियमितताओं का अनुमान लगाने की उम्मीद नहीं की जा सकती है,

अवैधता या असंवैधानिकता और न ही अदालतें कर सकती हैं

उनकी राय को प्रामाणिक राय के लिए प्रतिस्थापित करें

राज्य कार्यकारी। अदालतों को इससे कोई सरोकार नहीं है

अंतिम निर्णय लेकिन केवल निर्णय की निष्पक्षता के साथ

बनाने की प्रक्रिया। इस न्यायालय ने एक बार फिर बताया कि हो सकता है

नीलामी से अपवाद; अंतिम परीक्षा केवल निष्पक्षता की हैनिर्णय लेने की प्रक्रिया और अनुच्छेद *14* का अनुपालन

संविधान से। *56. (2000) 8* एससीसी *262*।

आरईः *2012* का विशेष संदर्भ संख्या *1*

433

[डी. के. जैन, जे.*]*

127. एम एंड टी कंसल्टेंट्स में, सिकंदराबाद बनाम एस. वाई.

नवाब *57*, इस न्यायालय ने फिर से दोहराया कि निविदाएं जारी नहीं की गईंहमेशा इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँचता है कि अभ्यास

शक्ति मनमाना हैः

" 17. एक सावधानीपूर्वक और निष्पक्ष मूल्यांकन और

अभिलेख पर रखी गई सामग्री पर विचार नहीं किया जाता है

विशिष्ट तथ्यों पर कोई उचित प्रभाव छोड़ें औरइस मामले की परिस्थितियाँ, कि कुछ भी अप्रिय जो

अदालतों द्वारा सार्वजनिक आलोचना या निंदा की आवश्यकता होती है

कानून बन गया था। यह अब अच्छी तरह से तय किया गया है कि गैर

निविदा जारी करना या सार्वजनिक नीलामी या निमंत्रण की अनुपस्थिति

अकेले कदम को दोष देने के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं है या एक

सार्वजनिक प्राधिकरण की कार्रवाई या तो मनमाना या

अनुचित या दुर्भावनापूर्ण या अनुचित

चिंतित हैं। अदालतें हमेशा इसके पक्ष में रही हैं -इसे अपनाने के लिए अधिकारियों के पास पर्याप्त अक्षांश बचा है

उनके साथ परियोजनाओं के प्रबंधन की अपनी तकनीकें

के आधार पर सहवर्ती आर्थिक संभावनाएँ

उपयुक्त वित्तीय द्वारा निर्देशित स्थिति की आवश्यकताएँ

द्वारा प्रेरित प्राधिकारी के सर्वोत्तम हित में नीति

जनहित के साथ-साथ इस तरह के उद्यमों को शुरू करने में भी।

128. विलियनूर लियार्काई पडुकप्पु मैयम बनाम संघ में।

भारत और ओआरएस। *58*, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ थी

पांडिचेरी बंदरगाह के विकास से संबंधित

जहाँ एक ठेकेदार को निविदा जारी किए बिना चुना गया था

या सार्वजनिक नीलामी आयोजित करना। यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः

अपीलकर्ता कि पांडिचेरी सरकार थी पूरी जनता को बदलने में मनमाना और अनुचित

व्यक्तिगत चयन की एक प्रणाली में निविदा प्रक्रिया और,

इसलिए, अपीलों को स्वीकार किया जाना चाहिए, इससे रहित है

57. (2003) 8 एससीसी *100*।

58. (2009) 7 एससीसी *561*।

गुण। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि निविदाएं जारी न करना या सार्वजनिक नीलामी न करना सभी मामलों में नहीं माना जाएगा।

में कार्यकारी शक्ति के प्रयोग का परिणाम होना

एक मनमाना तरीका।

171. इस तरह के मामले में जहां राज्य आवंटित कर रहा है

बंदरगाह के विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जल, बिजली, कच्चा माल आदि जैसे संसाधन,

न्यायालय को नहीं लगता कि राज्य विज्ञापन देने के लिए बाध्य है

और लोगों को बताएँ कि वे अपने हिस्से का विकास चाहते हैं।

एक विशेष तरीके से और इस उद्देश्य के लिए प्रस्तावों के साथ आने के लिए इच्छुक लोगों को आमंत्रित करें। राज्य चुन सकता है कि

ऐसा करें यदि यह उचित लगता है और किसी दी गई स्थिति में यह हो सकता है

ऐसा करने के लिए राज्य के लिए लाभप्रद होना, लेकिन यदि कोई निजी

पार्टी राज्य के सामने आती है और विकास करने की पेशकश करती है

बंदरगाह, राज्य किसी का उल्लंघन नहीं करेगा

संवैधानिक दायित्व यदि यह ऐसे पक्ष के साथ बातचीत करता है और इसके लिए संसाधन और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए सहमत होता है बंदरगाह के विकास का उद्देश्य "।

129. इसलिए, यह स्पष्ट है कि कोई संवैधानिक नहीं है

अनुच्छेद *14* के तहत नीलामी के पक्ष में जनादेश। सरकार ने

बार-बार नीलामी के क्रम से विचलित हुआ है और यह अदालत ने बार-बार ऐसी कार्रवाइयों को बरकरार रखा है। न्यायपालिका परीक्षण करती है

मनमानेपन के सीमित दायरे पर ऐसे विचलन और

अनुच्छेद *14* के तहत निष्पक्षता और इसकी भूमिका उस हद तक सीमित है।

अनिवार्य रूप से जब भी नीति का उद्देश्य राजस्व के अलावा कुछ भी होअधिकतमकरण, कार्यकारी को अन्य तरीकों को अपनाने के लिए देखा जाता है

नीलामी से अधिक।

130. कानूनी तर्क के अलावा, अनिवार्य नीलामी हो सकती है।

आर्थिक तर्क के विपरीत भी हो। विभिन्न संसाधन हो सकते हैं

अलग उपचार की आवश्यकता होती है। बहुत बार, अन्वेषण और

शोषण अनुबंधों को एक साथ बंडल किया जाता है क्योंकि

प्राकृतिक संसाधनों की खोज में भारी पूंजी की आवश्यकता। एक चिंता इस तरह के अन्वेषण को शुरू करने का जोखिम उठाएगी

और भारी लागत केवल तभी आती है जब इसका उपयोग सुनिश्चित किया जाता हैसंसाधन की खोज की गई; एक विवेकपूर्ण व्यावसायिक उद्यम, आरई पसंद नहीं करेगाः

2012 का विशेष संदर्भ संख्या *1*

435

[डी. के. जैन, जे.*]*

अन्वेषण गतिविधियों में शामिल उच्च लागतों को वहन करना और फिर

एक खुली नीलामी में उस संसाधन के लिए प्रतिस्पर्धा करें। तर्क यह है कि पेटेंट में लागू होने के समान। फर्मों को प्रोत्साहन दिया जाता है

के वादे के साथ अनुसंधान और विकास में निवेश करें

उस आविष्कार की बिक्री के लिए बाजार तक अनन्य पहुंच।

इस तरह का दृष्टिकोण आर्थिक और कानूनी रूप से सही है और कभी-कभी अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक होता है।

इसी तरह, अन्वेषण और दोहन अनुबंधों को जोड़ना हो सकता है।

एक विशिष्ट उद्योग में विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है।

131. नीलामी से इसी तरह के विचलन से इनकार नहीं किया जा सकता है।

जब राज्य की नीति का उद्देश्य किसी उद्योग के घरेलू विकास को बढ़ावा देना है, जैसे कस्तूरी लाल के मामले में,

ऊपर चर्चा की गई। हालाँकि, ये उदाहरण विशुद्ध रूप से हैं यह प्रदर्शित करने के लिए कि नीलामी नहीं हो सकती है

सभी प्राकृतिक संसाधनों के अलगाव के लिए एकमात्र मानदंड।

दुर्व्यवहार की संभावना

132. यह भी तर्क दिया गया कि भले ही नीलामी की विधि

अनुच्छेद *14* के तहत जनादेश नहीं है, यह एकमात्र होना चाहिएअनुमेय विधि, अन्य विधियों की संवेदनशीलता के कारण

दुरुपयोग करने के लिए। यह तर्क, हमारे विचार में, एक के विपरीत है

निर्णयों का संग्रह।*133.* आर. के. गर्ग बनाम भारत संघ और अन्य। *59,* न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती, पाँच विद्वानों की संविधान पीठ की ओर से बोलते हुए

न्यायाधीशों ने अभिनिर्धारित कियाः

" 8 ...... न्यायालय को हमेशा याद रखना चाहिए कि "कानून है

व्यावहारिक समस्याओं के लिए निर्देशित, कि आर्थिक

तंत्र अत्यधिक संवेदनशील और जटिल है, कि कई समस्याएं एकवचन और आकस्मिक हैं, कि कानून नहीं हैं

अमूर्त प्रस्ताव और अमूर्त इकाइयों से संबंधित नहीं हैं

और अमूर्त समरूपता द्वारा मापा नहीं जाता है *";"* कि सटीक ज्ञान और उपचार का अच्छा अनुकूलन हमेशा नहीं होता है।

59. (1981) 4 एससीसी *675*।

[2012] 9 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एस.

संभव "और वह" निर्णय काफी हद तक एक भविष्यवाणी आधारित है

अल्प और अव्यक्त अनुभव पर "। प्रत्येक

विशेष रूप से आर्थिक मामलों में कानून अनिवार्य रूप से है

अनुभवजन्य और यह प्रयोग पर आधारित है या जिसे कोई परीक्षण और त्रुटि विधि कह सकता है और इसलिए यह नहीं कर सकता है।

सभी संभावित स्थितियों के लिए प्रदान करें या सभी संभव पूर्वानुमान करें

दुर्व्यवहार करते हैं। इसमें खामियां और असमानताएं हो सकती हैं।

जटिल प्रयोगात्मक आर्थिक कानून लेकिन उस पर अकेले खाते में इसे अमान्य नहीं माना जा सकता है। अदालतें ऐसा नहीं कर सकतीं, जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने बताया है।

कृषि सचिव बनाम में उच्चतम न्यायालय। सेंट्रल रीग रिफाइनिंग कंपनी को राहत के लिए न्यायाधिकरणों में परिवर्तित किया जाएगा

ऐसी क्रूरताओं और असमानताओं से। वहाँ भी हो सकता है

दुरुपयोग की संभावनाएँ, लेकिन वह भी अपने आप में एक नहीं हो सकती हैं

कानून को अमान्य करने के लिए आधार, क्योंकि यह नहीं है किसी भी विधानमंडल के लिए ऐसा अनुमान लगाना संभव है जैसे कि कुछ लोगों द्वारा

ईश्वरीय विवेक, विकृतियाँ और इसके विधान का दुरुपयोग जो इसके प्रावधानों के अधीन लोगों द्वारा किया जा सकता है और इस तरह के विकृतियों और दुरुपयोग के खिलाफ प्रावधान किया जा सकता है। वास्तव में,

इसके निर्माण पर कितना भी ध्यान दिया जाए, ऐसे कानून की कल्पना करना मुश्किल है जो ऐसा नहीं है।

विकृत मानव सरलता द्वारा दुरुपयोग किए जाने में सक्षम। इसलिए न्यायालय को इसकी संवैधानिकता पर निर्णय लेना चाहिए -

इसकी क्रूरताओं या असमानताओं या दुरुपयोग की संभावनाओं द्वारा इसके किसी भी प्रावधान से। यदि कोई क्रूरता, असमानताएँ या

दुरुपयोग की संभावनाएं सामने आती हैं, विधायिका कर सकती है

हमेशा कदम बढ़ाते हैं और उपयुक्त संशोधनकारी कानून बनाते हैं।

यही व्यावहारिक दृष्टिकोण का सार है जो आवश्यक है।

जटिल से निपटने में विधायिका का मार्गदर्शन करें और उन्हें प्रेरित करें आर्थिक मुद्दे "।

134. फिर डी. के. त्रिवेदी एंड संस एंड ओआरएस में। बनाम राज्य गुजरात और *Ors.5*[1], संवैधानिक वैधता को बनाए रखते हुए

94 एल एड *381 338* यूएस *604 (1950)*।

(1986) मान लीजिए एससीसी *20*।

आरईः *2012* का विशेष संदर्भ संख्या *1*

437

[डी. के. जैन, जे.*]*

एम. एम. आर. डी. अधिनियम की धारा *15 (1)* के इस न्यायालय ने निम्नलिखित शब्दों में इस सिद्धांत की व्याख्या कीः

" 50. जहाँ कोई क़ानून विवेकाधीन शक्तियाँ प्रदान करता है

कार्यपालक या प्रशासनिक प्राधिकारी, वैधता या

ऐसी शक्ति की संवैधानिकता का आंकलन इस आधार पर नहीं किया जा सकता है कियह धारणा कि कार्यपालक या ऐसा प्राधिकारी कार्य करेगा

विवेकाधिकार के प्रयोग में एक मनमाना तरीका

उसे प्रदान किया गया। यदि कार्यपालक या प्रशासनिक

प्राधिकरण मनमाने तरीके से कार्य करता है, इसकी कार्रवाई होगी कानून में खराब और अदालतों द्वारा रद्द किए जाने के लिए उत्तरदायी है लेकिन

शक्ति के दुरुपयोग या मनमाने ढंग से प्रयोग की संभावना

शक्ति प्रदान करने वाले कानून को शक्ति अमान्य नहीं कर सकती है। या वह शक्ति जो उसके द्वारा प्रदान की गई है।

135. इसलिए, दुरुपयोग की संभावना आधार नहीं हो सकती है

एक विधि को निरस्त करने के लिए क्योंकि यह संविधान के अधिकार से बाहर है। यह है। वास्तविक दुरुपयोग जिसे न्यायालय के समक्ष लाया जाना चाहिए

संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर परीक्षण किए जाने के लिए। वास्तव में,

यह कहा जा सकता है कि नीलामी में भी आवंटन के किसी भी अन्य तरीके की तरह दुरुपयोग की संभावना है, लेकिन यह आधार नहीं हो सकता है इसे असंवैधानिक पद्धति भी घोषित करना। ये

कमियों में कार्टेलाइजेशन, "विनर्स कर्स" शामिल हैं।घटना जिसके द्वारा एक बोलीदाता एक उच्च, अवास्तविक और

बोलीदाता, कई नीलामियों के मामले में, सभी संसाधनों के लिए बोली लगाता है और अधिक संसाधनों के दोहन के लिए लाइसेंस जीतता है

जो वह व्यावहारिक रूप से निष्पादित कर सकता है), आदि। लेकिन फिर भी,

उक्त कारणों से नीलामी को अधिकार से बाहर नहीं कहा जा सकता है और यह निपटान का एक आकर्षक और पसंदीदा साधन बना हुआ है।

प्राकृतिक संसाधनों का विशेष रूप से जब राजस्व अधिकतम होप्राथमिकता। इसलिए, न तो नीलामी, और न ही निपटान के किसी अन्य तरीके को संविधान के अधिकार से परे माना जा सकता है।

संभावित दुरुपयोग के कारण।

नीति निर्णयों की न्यायिक समीक्षा

136. विद्वान महान्यायवादी ने यह भी तर्क दिया कि *438* सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

[2012] 9 एस सी आर।

प्राकृतिक संसाधनों के लिए वितरण की एक विधि निर्धारित करना उल्लंघन करता है

नीतिगत मामलों में न्यायपालिका द्वारा हस्तक्षेप न करने का सदियों पुराना स्थापित सिद्धांत। भले ही इसकी आकृतियाँ

विषय, जैसा कि न्यायालयों ने बार-बार राय दी है हम कुछ सिद्धांतों को संक्षेप में दोहराना चाहते हैं, विशेष रूप से

आर्थिक नीति विकल्पों और मूल्य निर्धारण के संबंध में।

137. इस विषय पर सबसे शुरुआती घोषणाओं में से एक

रुस्तम कावासजी कूपर बनाम यूनियन में इस अदालत से आया था।

भारत *62 (*आमतौर पर "बैंक राष्ट्रीयकरण मामले" के रूप में जाना जाता है*)*

जिसमें इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यह ऐसा मंच नहीं है जहाँ परस्पर विरोधी हों।

नीतिगत दावों पर बहस की जा सकती है*;* केवल उस उपाय की वैधता पर निर्णय लेने की आवश्यकता होती है जिसका संबंधियों से बहुत कम संबंध है।

विभिन्न राजनीतिक और आर्थिक सिद्धांतों के गुण। अदालत ने देखा गयाः

" 63. यह न्यायालय वह मंच नहीं है जिसमें ये परस्पर विरोधी हैं।

दावों पर बहस हो सकती है। क्या कोई वास्तविक आवश्यकता है

ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग सुविधा के लिए, क्या निश्चित है

समुदाय के वर्ग बैंकिंग उद्योग के संसाधनों के लाभ से वंचित हैं, चाहे प्रशासन हो।

वाणिज्यिक बैंकिंग क्षेत्र की सरकार द्वारा

समुदाय के लिए फायदेमंद साबित नहीं होगा और इसके लिए नेतृत्व करेंगे

प्रशासन में कठोरता, चाहे सरकार

प्रशासन लाभ-उद्देश्य को छोड़ देगा, और भले ही वह छोड़ दिया जाए, जनता को पर्याप्त लाभ होगा, चाहे एक साधन के रूप में बैंकिंग पर अनुचित जोर दिया जाए

सामाजिक पुनर्जनन, विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों में,प्राथमिकताओं के एक तर्कसंगत क्रम के लिए एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण है

हमारे राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए

ऐसे मामले हैं जिनकी निर्धारण में बहुत कम प्रासंगिकता हैउपाय की वैधता। यह फिर से इस न्यायालय के लिए नहीं है कि

62. (1970) 1 एससीसी *248*।

439

आरईः *2012* का विशेष संदर्भ संख्या *1*

[डी. के. जैन, जे.*]*

विभिन्न राजनीतिक सिद्धांतों के सापेक्ष गुणों पर विचार करें।

या आर्थिक नीतियाँ। संसद में प्रविष्टि *45* के तहत है,

सूची *I* बैंकिंग और अन्य के संबंध में कानून बनाने की शक्ति

नामित बैंकों की वाणिज्यिक गतिविधियाँ अनिवार्य रूप से

आनुषंगिकः इसके पास अधिग्रहण के लिए कानून बनाने की शक्ति है

प्रविष्टि *42*, सूची के तहत नामित बैंकों का उपक्रम

III. में निहित शक्ति के प्रयोग से या नहीं

रिजर्व बैंक पूर्व-मौजूदा कानूनों के तहत, परिणाम हो सकते हैं

जिसे प्राप्त करना अधिनियम का उद्देश्य है, वह है

हमारा निर्णय, इस बात पर विचार करने में प्रासंगिक नहीं है कि क्या अधिनियम

प्राधिकरण, लेकिन न्यायालय नीति पर अपील में नहीं बैठेगासंसद द्वारा एक कानून बनाने में। अदालत नहीं ढूँढ सकती

अधिनियम में केवल इस आधार पर दोष है कि यह अस्वीकार्य है

बैंकों के उपक्रम को संभालने के लिए, जिसके बारे में कहा जाता है

याचिकाकर्ता ने मितव्ययिता और कुशल प्रबंधन द्वारा निर्धारित किया था

एक प्रभावशाली और कुशल व्यावसायिक संगठन बनाना

उद्योग के बड़े क्षेत्रों की सेवा करना।

138. आर. के. गर्ग *(ऊपर)* में, इस न्यायालय ने यह भी कहा कि

संबंधित कानून के प्रति अधिक न्यायिक सम्मान दिखाया जाना चाहिए।

आर्थिक जटिलता के कारण आर्थिक गतिविधियाँ

परीक्षण की एक पद्धति के माध्यम से समस्याएं और उनकी पूर्ति औरत्रुटि। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, यह भी स्पष्ट किया गया है कि एक

आर्थिक कानून कठोरता, असमानताओं से परेशान हो सकते हैं, अनिश्चितता या दुरुपयोग की संभावना आधार नहीं हो सकती है

इसे नीचे फेंक दें। निम्नलिखित अवलोकन जो एक का उल्लेख करते हैं अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले इस विषय पर एक अस्पष्ट व्याख्या हैंः

"8. समान महत्व का एक अन्य नियम यह है कि संबंधित कानून

आर्थिक गतिविधियों पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

स्वतंत्रता जैसे नागरिक अधिकारों को छूने वाले कानूनों की तुलना में अक्षांश

भाषण, धर्म आदि। यह किसी से कम नहीं कहा गया है।

होम्स, जे. की तुलना में, कि विधायिका को अनुमति दी जानी चाहिए

कुछ जोड़ों में खेलते हैं, क्योंकि इसे *[2012] 9* एस. सी. आर. से निपटना पड़ता है।

जटिल समस्याएं जो समाधान को स्वीकार नहीं करती हैं

कोई भी सिद्धांत या स्ट्रैट-जैकेट सूत्र और यह हैविशेष रूप से आर्थिक मामलों से संबंधित कानून के मामले में यह सच है।

जहाँ, समस्याओं की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए

इससे निपटने की आवश्यकता है, जोड़ों में अधिक खेलना पड़ता है

विधायिका को अनुमति दी जाए। अदालत को और अधिक महसूस करना चाहिए

विधायी निर्णय को न्यायिक सम्मान देने के लिए इच्छुक

अन्य क्षेत्रों की तुलना में आर्थिक विनियमन के क्षेत्र में

जहाँ मौलिक मानवाधिकार शामिल हैं। कहीं नहीं।

क्या इस चेतावनी को अधिक सम्मानपूर्वक व्यक्त किया गया है मोरे वी। डाउड *3* जहाँ फ्रैंकफर्टर, जे. ने अपनी पुस्तक में कहा है

बेजोड़ शैलीः

'उपयोगिताओं, कर और आर्थिक विनियमन मामलों में,

न्यायिक आत्मसंयम के लिए अच्छे कारण हैं यदि

विधायी निर्णय के प्रति न्यायिक सम्मान नहीं। द.

आखिरकार विधायिका की सकारात्मक जिम्मेदारी है।

अदालतों के पास केवल नष्ट करने की शक्ति है, न कि

पुनर्निर्माण करें। जब इन्हें जोड़ा जाता है

आर्थिक विनियमन की जटिलता, अनिश्चितता, त्रुटि के लिए दायित्व, के विस्मयकारी संघर्ष

विशेषज्ञ, और न्यायाधीशों ने कितनी बार

घटनाओं द्वारा खारिज कर दिया गया-आत्म-सीमा को न्यायिक ज्ञान का मार्ग माना जा सकता है औरसंस्थागत प्रतिष्ठा और स्थिरता "।

139. प्रीमियम ग्रेनाइट और ए. एन. आर. में। बनाम। टी. एन. और अन्य का राज्य। *64*

इस न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह एक कानून की वैधता है न कि इसकी

प्रभावकारिता जिसे चुनौती दी जा सकती हैः

"*54.* यह शुरू करने के लिए अदालत का अधिकार क्षेत्र नहीं है

एक अभ्यास में सार्वजनिक नीति का अपरिवर्तित महासागर

इस बात पर विचार करें कि क्या कोई विशेष सार्वजनिक नीति बुद्धिमान है

या एक बेहतर सार्वजनिक नीति विकसित की जा सकती है। इस तरह के व्यायाम

कार्यपालिका के विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए और

63. 354 यूएस *457*।

64. (1994) 2 एससीसी *691*।

आरईः *2012* का विशेष संदर्भ संख्या *1*

441

[डी. के. जैन, जे.*]*

जैसा भी मामला हो, विधायी प्राधिकरण। अदालत ने कहा कि

केवल एक सार्वजनिक नीति की वैधता पर विचार करने के लिए कहा गया

जब कोई चुनौती दी जाती है कि ऐसा नीतिगत निर्णय

संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हैभारत का या कोई अन्य वैधानिक अधिकार।

140. दिल्ली विज्ञान मंच और अन्य में। बनाम भारत संघ और

एन *5*। इस न्यायालय के तीन विद्वान न्यायाधीशों की एक पीठ, जबकि

दूरसंचार क्षेत्र को खोलने के खिलाफ दावे को खारिज करना

दोहराया कि बहस और प्रवचन के लिए मंच किसी नीति के गुण और दोष संसद होती है। यह दोहराया गया

कि इस न्यायालय की सेवाओं की मांग तब तक नहीं की जाती है जब तक किनीति विवादित है, और आगे, कि कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता है

नीतियों में से किसी का उल्लंघन या उल्लंघन है संवैधानिक या वैधानिक प्रावधान। यह इस प्रकार थाः

" 7. विधानों के संबंध में क्या कहा गया है

उन नीतियों के संबंध में भी लागू होती हैं जोसंसद द्वारा स्वीकृत। उनका न्यायालय में परीक्षण नहीं किया जा सकता है।

देश में प्रचलित ऐसी कोई भी राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए अपनाया गया है या नहीं। विचार और विचार हो सकते हैं,

राय और विचार जो साझा किए जा सकते हैं और जिन पर विश्वास किया जा सकता हैप्रतिनिधियों सहित देश के नागरिकों द्वारा

संसद में जनता। लेकिन इसे ठीक करना होगा।

संसद जिसे ऐसी नीतियों को मंजूरी देनी होती है।

141. बाल्को कर्मचारी संघ में *(*विनियमित*)* बनाम यूनियन ऑफ

भारत और *Ors.56*, इस न्यायालय ने आगे बताया कि न्यायालय को

नीतिगत मामलों की प्रभावशीलता की न्यायिक समीक्षा से दूर रहना,

न केवल इसलिए कि यह इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, बल्कि इसलिए भी कि इसमें इस तरह के कार्य के लिए आवश्यक विशेषज्ञता का अभाव है। इस न्यायालय के पिछले विचारों की पुष्टि करते हुए, न्यायालय ने*65. (1996) 2* एससीसी *405*।

66. (2002) 2 एससीसी *333*।

[2012] 9 एस सी आर।

442 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह पाया गया कि आर्थिक कानूनों से निपटने के दौरान,

न्यायालय, मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र को समाप्त नहीं करते हुए

कार्रवाई या असंवैधानिक कानून, केवल में हस्तक्षेप करना चाहिए

वे मामले जहां कानून में परिलक्षित दृष्टिकोण नहीं है

बिलकुल भी लिया जा सकता है। अदालत ने जोर दिया

कि जब तक आर्थिक निर्णय, आर्थिक आधार पर नहीं

समीचीनता, इतना उल्लंघनकारी होने के लिए प्रदर्शित किया जाता है

शक्ति पर संवैधानिक या कानूनी सीमाएँ या इसलिए तर्क के लिए घृणित,

कि अदालतें हस्तक्षेप करने से इनकार कर देंगी।

142. बाल्को *(*ऊपर*)* में, न्यायालय ने पीयरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड के फैसले का संज्ञान लिया।

& एन. आर. बनाम भारतीय रिजर्व बैंक *67* और कहा कि कुछ

मूल्य निर्धारण जैसे मामले ऐसी अनिश्चितताओं पर आधारित हैं और गतिशीलता जिसे विशेषज्ञों को भी सही करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है

अनुमान, इस न्यायालय के लिए इसे और अधिक आवश्यक बनाते हुए

गैर-हस्तक्षेप का अभ्यासः

"31. न्यायालय का कार्य यह देखना है कि वह वैध प्राधिकारी है।

दुरुपयोग नहीं किया जाता है लेकिन अपने लिए कार्य को उपयुक्त नहीं बनाता है

उस प्राधिकरण को सौंपा गया। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि एक सार्वजनिक

वैधानिक शक्तियों के साथ निवेशित निकाय को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि

अपनी शक्ति से अधिक या दुरुपयोग करें। इसे सीमाओं के भीतर रखना चाहिए। इसके लिए प्रतिबद्ध प्राधिकारी। इसे सद्भावना से कार्य करना चाहिए और

इसे उचित रूप से कार्य करना चाहिए। अदालतों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए

आर्थिक नीति जो विशेषज्ञों का कार्य है। यह नहीं है।

के मामलों पर निर्णय में बैठने के लिए न्यायालयों का कार्य

आर्थिक नीति और इसे अनिवार्य रूप से इस पर छोड़ दिया जाना चाहिए

विशेषज्ञ निकाय। ऐसे मामलों में विशेषज्ञ भी गंभीरता से ले सकते हैं।

और निश्चित रूप से अलग है। अदालतों से यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि

विशेषज्ञों की सहायता के बिना भी उन्हें तय करें।

143. मेसर्स प्राग आइस एंड ऑयल मिल्स एंड ए. एन. आर. में पहले के मामले में।

बनाम भारत संघ, इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की थीः *(* एससीसी

पी। *478* , पैरा *24)*

67. (1992) 2 एससीसी *343*।

68. [1978] 3 एससीसी *459*।

443

आरईः विशेष संदर्भ। *2012* की संख्या *1*

[डी. के. जैन, जे.*]*

"हम यह नहीं सोचते कि यह इस न्यायालय का कार्य है या

आर्थिक मामलों पर निर्णय देने वाला कोई भी न्यायालय

निर्णय लेने का दिन। उनमें से कई, मूल्य निर्धारण के एक उपाय के रूप में अनिवार्य रूप से होना चाहिए, अंतिम की भविष्यवाणी के मामले हैं

परिणाम जिन पर विशेषज्ञ भी गंभीर रूप से गलती कर सकते हैं और

निश्चित रूप से भिन्न। अदालतों से निश्चित रूप से उम्मीद नहीं की जा सकती है।

विशेषज्ञों की सहायता के बिना भी उन्हें तय करना।

144. मध्य प्रदेश राज्य बनाम नर्मदा बचाओ

आंदोलन *& Anr.69*, इस अदालत ने कहा कि न्यायपालिका नहीं कर सकती

तुलनात्मक विश्लेषण के अभ्यास में संलग्न हों

निष्पक्षता, तार्किक या वैज्ञानिक आधार, या किसी नीति का विवेक। यह आयोजित किया गया

कि न्यायालय द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय को निरस्त नहीं कर सकता है

सरकार केवल इसलिए कि उसे लगता है कि एक और निर्णय निष्पक्ष, या अधिक वैज्ञानिक या तार्किक, या बुद्धिमान होता।

नीतियों की समझदारी और सलाह आमतौर पर नहीं होती है।

न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी जब तक कि नीतियां इसके विपरीत न हों

वैधानिक या संवैधानिक प्रावधान या मनमाना या तर्कहीन या शक्ति का दुरुपयोग।

145. श्री सुब्रमण्यम स्वामी ने भी हमारे ध्यान में लाया।

प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन पर एक रिपोर्ट, एक द्वारा तैयार

श्री अशोक चावला की अध्यक्षता में समिति *(*इसके बाद संदर्भित*)*

"चावला समिति की रिपोर्ट" के रूप में*)*, जिसने एक

दुर्लभ प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन और मूल्य निर्धारण पर भारत सरकार के लिए प्रचुर वैचारिक ढांचा। कोयला,

खनिज, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, स्पेक्ट्रम, वन, भूमि और

पानी। उन्होंने निपटान के साधन के रूप में नीलामी के पक्ष में रिपोर्ट की टिप्पणियों का खंडन किया। हालांकि, राय के बाद से

चावला समिति की रिपोर्ट लंबित है।

सरकार द्वारा स्वीकृति, इसके लिए अनुचित होगा हम इस पर न्यायिक निर्भरता रखें। इसके अलावा, रिपोर्ट निपटान के साधनों का एक आर्थिक विश्लेषण करती है, न कि कानूनी।

प्राकृतिक संसाधन। इस संदर्भ का उद्देश्य होगा -

69. (2011) 7 एस. सी. सी. *239*।

अगर यह न्यायालय इसके बजाय एक संवैधानिक जवाब देता है तो सबसे अच्छी सेवा होगी।

आर्थिक से अधिक।

146. वर्तमान के संदर्भ में संक्षेप में

संदर्भ में, इस बात पर जोर देने की आवश्यकता है कि यह न्यायालय ऐसा नहीं कर सकता है

विभिन्न विधियों का तुलनात्मक अध्ययन करना प्राकृतिक संसाधनों का वितरण और सबसे अधिक सुझाव

प्रभावी विधि, यदि एक सार्वभौमिक प्रभावी विधि है

सबसे पहले। यह ऐसे मामलों के लिए कार्यपालिका के जनादेश और विवेक का सम्मान करता है। संबंधित कार्यप्रणाली

प्राकृतिक संसाधनों का निपटान स्पष्ट रूप से एक आर्थिक नीति है। यह.

जटिल आर्थिक विकल्प शामिल हैं और न्यायालय में इसका अभाव है

उन्हें बनाने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता। जैसा कि बार-बार हुआ है।

कहा, यह इस न्यायालय का प्रयास नहीं हो सकता और न ही होगा

अन्य विधियों की तुलना में नीलामी की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करें प्राकृतिक संसाधनों का निपटान। न्यायालय एक आदेश नहीं दे सकता है।

सभी तथ्यों और परिस्थितियों में अपनाई जाने वाली विधि। इसलिए, नीलामी, प्राकृतिक संसाधनों के निपटान का एक आर्थिक विकल्प, यह संवैधानिक जनादेश नहीं है। हालाँकि, हम जल्दबाजी में यह जोड़ सकते हैं कि न्यायालय इसकी वैधता और संवैधानिकता का परीक्षण कर सकता है।

इन तरीकों से। जब पूछताछ की जाती है, तो न्यायालयों को अधिकार होता है -

वितरण के विभिन्न साधनों की कानूनी वैधता का विश्लेषण करना और

संवैधानिक जवाब दें कि कौन से तरीके अधिकार से बाहर हैंऔर संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत आता है। फिर भी,

यह तुलना नहीं कर सकता है और न ही करेगा कि कौन सी नीति बेहतर है।

अन्य, लेकिन, यदि कोई नीति या कानून स्पष्ट रूप से इस हद तक अनुचित है कि

अनुच्छेद *14* की निष्पक्षता की आवश्यकता का उल्लंघन करता है

संविधान, न्यायालय इसे निरस्त करने में संकोच नहीं करेगा।

147. अंत में, बाजार मूल्य, अर्थशास्त्र में, का एक सूचकांक है

मूल्य जो एक बाजार किसी वस्तु के लिए निर्धारित करता है। हालांकि, यह मूल्यांकन कई गतिशील चर का एक कार्य है; यह एक है

विज्ञान और कानून नहीं। नीलामी कई कीमतों में से एक है।

खोज तंत्र। चूँकि कई चर शामिल हैं

इस तरह के मूल्यांकन, नीलामी या किसी अन्य प्रकार की प्रतिस्पर्धा में

बोली लगाना, एक आर्थिक जनादेश भी नहीं हो सकता है, बहुत

कम संवैधानिक जनादेश।

148. हमारी राय में, नीलामी अधिक होने के बावजूद

प्राकृतिक संसाधनों के अलगाव/आवंटन की बेहतर विधि,

सभी प्राकृतिक संसाधनों के अलगाव के लिए एक संवैधानिक आवश्यकता या सीमा नहीं मानी जा सकती है और इसलिए, प्रत्येक

नीलामी के अलावा अन्य तरीके को रद्द नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह संवैधानिक जनादेश से परे है।

149. उपरोक्त उपदेशों को ध्यान में रखते हुए, हमारे पास है

राय दी कि नीलामी को एक माध्यम के रूप में दर्जा नहीं दिया जा सकता है

एक संवैधानिक सिद्धांत। प्राकृतिक संसाधनों का अलगाव हैएक नीतिगत निर्णय, और उसी के लिए अपनाए गए साधन हैं

इस प्रकार, कार्यकारी विशेषाधिकार। तथापि, जब ऐसा नीतिगत निर्णय किसी सामाजिक या कल्याणकारी उद्देश्य द्वारा समर्थित नहीं है, और

बहुमूल्य और दुर्लभ प्राकृतिक संसाधनों को निजी उद्यमियों को अधिकतम लाभ के व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए अलग किया जाता है।

प्रतिस्पर्धी साधनों के अलावा अन्य साधनों को अपनाना और

अधिकतम राजस्व मनमाना हो सकता है और संविधान के अनुच्छेद *14* के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए, निर्धारित करने के बजाय या

हम मानते हैं कि एक विधि को प्रतिबंधित करना, विधियों की न्यायिक जांच है

प्राकृतिक संसाधनों का निपटान सिद्धांतों के अनुरूप प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर होना चाहिए।

जिसे हमने ऊपर निकाला है। जिसमें विफल, न्यायालय,

न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग, कार्यपालिका को कार्यकाल देगा

कारण के रूप में मनमाना, अनुचित, अनुचित और मज़बूत कार्रवाई

संविधान के अनुच्छेद *14* के साथ इसका विरोध।

150. अंत में, पाँच के पहले समूह के लिए हमारा जवाब

सवाल यह है कि नीलामी ही एकमात्र अनुमेय तरीका नहीं है

सभी क्षेत्रों में सभी प्राकृतिक संसाधनों के निपटान के लिए और

सभी परिस्थितियाँ।

151. शेष प्रश्नों के संबंध में, हम महसूस करते हैं कि

इन प्रश्नों के उत्तर का सीधा असर होगास्पेक्ट्रम के अलगाव का तरीका और इसलिए, के प्रकाश में

विद्वान महान्यायवादी का बयान कि सरकार

2 जी मामले में फैसले की शुद्धता पर सवाल नहीं उठा रहा है, *446* सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2012] 9 एस सी आर।

हम सम्मानपूर्वक इन प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार करते हैं। द.

राष्ट्रपति के संदर्भ का जवाब उसी के अनुसार दिया जाता है।

152. यह राय राष्ट्रपति को प्रेषित की जाएगी।

उच्चतम न्यायालय नियम, *1966* के भाग *5* में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार।

जगदीश सिंह खेहर, जे. *1.* मुझे विशेषाधिकार मिला है

मेरे सम्मानित भाई डी. के. द्वारा दी गई राय पर विचार करने के लिए।

जैन, जे. राय का हर बिट *(*जो इसके बाद होगा*)*

मेरे द्वारा संदर्भित, *"*मुख्य राय*"* के रूप में*)* तय पर आधारित है

इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून के प्रस्ताव। इसलिए, इसके साथ किसी भी असहमति का कोई सवाल नहीं हो सकता है। मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूँ

उसमें व्यक्त राय।

2. राष्ट्रपति के संदर्भ में पहला सवाल,

वास्तव में कारण है, मेरे रिकॉर्ड करने के लिए, कुछ अन्य

उस विषय पर बारीकियां जिसके बारे में सलाह मांगी गई है। द. राष्ट्रपति के संदर्भ में पहले प्रश्न की आवश्यकता होती है

उच्चतम न्यायालय इस पर सलाह देगा, *"*क्या केवल

सभी प्राकृतिक संसाधनों के निपटान के लिए अनुमेय विधि

सभी क्षेत्रों और सभी परिस्थितियों में, के आचरण से है

नीलामी*? "*. यह समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है, भाव

राष्ट्रपति के संदर्भ में पहला प्रश्न। के लिए ले लो

एक काल्पनिक स्थिति का उदाहरण जहाँ, *100* की वैधता

विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों के निपटान के उदाहरण हैं -

विचार के लिए लिया गया। अगर पहला सवाल लिया जाए तो

शाब्दिक अर्थ, कि क्या सभी प्राकृतिक पदार्थों के निपटान की विधि

सभी परिस्थितियों में संसाधन केवल नीलामी द्वारा होते हैं, तो फिर, यहाँ तक कि

यदि उपरोक्त *100* विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों में से *99* ऐसे हैं, जिनका केवल नीलामी के माध्यम से निपटान किया जा सकता है, तो पहले प्रश्न का उत्तर अभी भी नकारात्मक होगा। यह

नकारात्मक में उत्तर गलत प्रभाव देगा,

कि नीलामी के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का निपटान करना आवश्यक नहीं है। निश्चित रूप से, राष्ट्रपति का संदर्भ नहीं दिया गया है

इस तरह की निर्दोष सलाह लेने के लिए बनाया गया। तत्काल संदर्भ

केंद्र सरकार के *447* तक जीवित रहने के बावजूद बनाया गया है

आरई: *2012* का विशेष संदर्भ संख्या *1*

[जगदीश सिंह खेहर, जे।*]*

तथ्य यह है कि ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं जिनका केवल नीलामी के माध्यम से निपटान किया जा सकता है। कोयले के लिए एक खनन पट्टा

खानों और खनिजों की धारा *11* ए *(*विकास और विनियमन*)* अधिनियम, *1957* केवल चयन के माध्यम से दिया जा सकता है।

प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा नीलामी के माध्यम से। इसके अलावा,

केंद्र द्वारा लिया गया सचेत निर्णयसरकार अब से केवल इसके माध्यम से स्पेक्ट्रम आवंटित करेगी

नीलामी के माध्यम से प्रतिस्पर्धी बोली। ऐसे हो सकते हैं मामले गुणा किया। इसलिए यह स्पष्ट है कि सरकार जीवित है

तथ्य यह है कि कुछ प्राकृतिक संसाधनों का निपटान होना चाहिए

केवल नीलामी द्वारा किया गया। यदि ऐसा है, तो संदर्भ में पहला प्रश्न शाब्दिक उत्तर नहीं चाहता है। पहला सवाल

इस न्यायालय की राय लेने के लिए समझा जाना चाहिए कि क्या

ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिनमें प्राकृतिक संसाधनों को होना चाहिए

केवल नीलामी द्वारा निपटाया गया। मामले के इस पहलू पर प्रतिक्रिया के बिना राय देने से साधक नहीं बन पाएगा।

सलाह, कोई भी बुद्धिमान। यह केवल यह पहलू है, जो होगा

मेरी तत्काल राय का मुख्य विषय।

3. विचार के क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले

पूर्वगामी अनुच्छेद में व्यक्त किया गया है कि यह दर्ज करना आवश्यक है कि सुनवाई के दौरान व्यापक बहस हुई थी,

क्या, राजस्व का अधिकतमकरण एकमात्र होना चाहिएसभी प्राकृतिक संसाधनों के निपटान के लिए अनुमेय विचार,

सभी क्षेत्रों में और सभी परिस्थितियों में। कोर्स के दौरान

इस बहस के बारे में भारत के विद्वान महान्यायवादी ने

यह स्वीकार किया गया कि प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से नीलामी निश्चित रूप से एक निर्विवाद साधन था, जिसके द्वारा

राजस्व वापसी सुनिश्चित है। ऐसा नहीं है कि कोई विद्वान महान्यायवादी को स्वीकृत प्रस्ताव से बांधना चाहेगा।

विद्वतापूर्ण बहस के दिनों और हफ्तों के दौरान,

विद्वान वकील ने इस बात पर जोर दिया कि परिसंपत्तियों का निपटान

निविदा, निविदा-सह-नीलामी और नीलामी की प्रक्रियाएँ

राजस्व लाभ का अधिकतमकरण सुनिश्चित करना। बेशक, वहाँ हैं

निविदा और नीलामी प्रक्रियाओं की एक बड़ी विविधता, प्रत्येक के साथ

अपनी बारीकियाँ। और हमें सूचित किया गया कि एक सही विकल्प, *448* सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

[2012] 9 एस सी आर।

यह राजस्व लाभ को अधिकतम करने का आश्वासन देगा। यह शब्द

"नीलामी "मेरी तत्काल राय में व्यक्त, इसलिए हो सकता है

राजस्व रिटर्न को अधिकतम करने के साधन के रूप में पढ़ें, भले ही अपनाया गया साधन तकनीकी और सही होना चाहिए।

निविदा, निविदा-सह-नीलामी, या नीलामी के रूप में वर्णित।

4. कानून और समानता के समक्ष समानता की अवधारणा

कानूनों का संरक्षण, मौलिक अधिकार से निकलता है

भारत के संविधान के अनुच्छेद *14* में व्यक्त किया गया। समानता है

एक निश्चित अवधारणा। इसकी समझ में भिन्नता सबसे अच्छा हो सकता है।

राष्ट्र की परिपक्वता और विकास का संदर्भ है

सोचा। शुरुआत में, समानता का उल्लंघन एक याचिका थी जिसे आगे बढ़ाया गया था

निष्पक्ष व्यवहार का दावा करने वाले व्यक्तियों द्वारा। चुनौतिएँ उठाईं गईं

भेदभावपूर्ण व्यवहार के कारण भी। समानता की मांग की गई थी उन लोगों द्वारा जो अधिक योग्य थे, जब लाभ दिए गए थे

जिनके पास कम क्षमता है। धीरे-धीरे न्यायिक हस्तक्षेप आया

न्यायसंगत उपचार की मांग की जानी चाहिए, यहां तक कि एक वर्ग के लिए भी

समाज एकजुट हो जाता है। एक अधिकार क्षेत्र, जो नियत समय पर आया

जनहित याचिका के रूप में वर्णित किया जाना। यह सब एक साथ शुरू हुआ

सम्मानजनक मानव अस्तित्व के लिए बुनियादी अधिकारों की मांग।

वर्षों से, सामाजिक अधिकारों के निर्धारण की अवधारणा, विभिन्न दिशाओं और मार्गों में पार हो गया है। इतना ही।

ताकि, अब इक्विटी में अधिकार, कभी-कभी वर्तमान स्थितियाँ भी

वर्तमान निर्णय को इस तरह का विवाद कहा जा सकता है प्रकृति। एक परिपक्व समाज में, व्यक्तिगत अधिकार और बहुवचन अधिकार

संतुलित होना चाहिए, ताकि अधिकारों का दोलनशील पेंडुलम,

निष्पक्ष और समान रूप से, उनके संबंधित मापदंडों को पहचानते हैं। भारत जैसे देश के लिए पेंडुलम को समझना चाहिए

एक तरफ एक नागरिक के अधिकारों को संतुलित करना, और

124,14,91,960 (भारत की वर्तमान अनुमानित जनसंख्या*)*

दूसरी ओर देश के नागरिक। लेख का वास्तविक प्रभाव

व्यक्तिगत अधिकार, लेकिन यह भी सुनिश्चित करके कि इसके नागरिकसंतुलन का दूसरा पक्ष भी इसी तरह अपने अधिकार से वंचित नहीं है।

कानून के समक्ष समानता, और आरई के समान संरक्षण के उनके अधिकार के लिए:

कानून हैं। एक व्यक्तिगत नागरिक लाभार्थी नहीं हो सकता है,

देश की लागत *(*शेष *124,14,91,960* नागरिक*)* अर्थात,

बहुलता। अन्य सभी की कीमत पर एक को समृद्ध करना बराबर होगा।

बहुलता अर्थात स्वयं राष्ट्र को वंचित करना। इसका सार

राष्ट्रपति के संदर्भ में पहला सवाल, इस मुद्दे को उठाता है

क्या राष्ट्र के प्राकृतिक संसाधनों पर स्वामित्व का अधिकार है,

देश के नागरिकों में निहित। तत्काल मुद्दे का जवाब

बदले में यह निर्धारित करेगा कि यह अनिवार्य है या नहीं प्राकृतिक संसाधनों के निपटान के लिए नीति तैयार करते समय कार्यपालक

संसाधन, यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह सार्वजनिक भलाई और सार्वजनिक लाभ को कम करता है

ब्याज।

5. जनहित का परिचय और स्वीकृति

न्यायशास्त्र की अवधारणा के रूप में मुकदमा एक व्यापक विषय है।

व्यक्ति का अधिकार*)* विशेष रूप से जब बहुलता है, एक या के लिए अन्य कारण, इसका निवारण करने की स्थिति में नहीं

शिकायतें। यह अपर्याप्तता हमेशा उत्पन्न नहीं हो सकती है

वित्तीय बाधाएँ। यह कभी-कभी इसकी कमी से उत्पन्न हो सकता है

जागरूकता। अन्य समयों में केवल जबरदस्त ताकत से

कार्यकारी प्राधिकरण। इस देश में न्यायशास्त्र संबंधी विचार,

जनहित याचिका के उद्भव के बाद, मांग कर रहा है

व्यक्तिगत अधिकारों और लोगों के अधिकारों के बीच संतुलन बनाएँ

बहुलता। आखिरकार, सभी प्राकृतिक संसाधन राष्ट्र की सामूहिक संपत्ति हैं। इस न्यायालय को पिछले कुछ समय से यह अवसर मिला है दशकों से, प्राकृतिक के संदर्भ में नागरिकों के अधिकारों को निर्धारित करने के लिए

संसाधन। उन परिसंपत्तियों के लिए एक व्यक्तिगत नागरिक का अधिकार, जैसे -

इसके अलावा, देश के शेष नागरिकों के अधिकार हैं,

अब एक आम मुकदमे में विपरीत पक्षों पर उभरा। व्यक्त की गई कानूनी स्थिति को चित्रित करने का प्रयास किया जाएगा

राज्य द्वारा संसाधनों का, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या तत्काल इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून द्वारा इस मुद्दे का निपटारा किया गया है।

6 (क) सबसे पहले इस निर्णय का संदर्भ दिया गया था।

एस. जी. जयसिंघानी बनाम भारत संघ और अन्य में न्यायालय।

, एयर *1967 450* सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

[2012] 9 एस सी आर।

एस. सी. *1427,* जिसमें इस न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में टिप्पणी कीः

" 14. इस संदर्भ में इस बात पर जोर देना महत्वपूर्ण है कि

मनमानी शक्ति की अनुपस्थिति नियम की पहली आवश्यकता है।

कानून जिस पर हमारी पूरी संवैधानिक प्रणाली है

आधारित है। कानून के शासन द्वारा शासित प्रणाली में, विवेकाधिकार,जब कार्यकारी अधिकारियों को प्रदान किया जाता है, तो होना चाहिए

स्पष्ट रूप से परिभाषित सीमाओं के भीतर सीमित। से कानून का शासनइस दृष्टिकोण का अर्थ है कि निर्णय लिए जाने चाहिए

ज्ञात सिद्धांतों और नियमों के अनुप्रयोग द्वारा और

सामान्य तौर पर, ऐसे निर्णय पूर्वानुमेय होने चाहिए और

नागरिक को पता होना चाहिए कि वह कहाँ है। अगर कोई निर्णय लिया जाता है

बिना किसी सिद्धांत या बिना किसी नियम के यह अप्रत्याशित है।

और ऐसा निर्णय लिए गए निर्णय के विपरीत है।

कानून के शासन के अनुसार। *(* डाइस-लॉ ऑफ देखें।

संविधान-*10* वीं संस्करण। , परिचय *cx) "*। कानून ने

यूनाइटेड में जे. डगलस ने कहा, *"*यह अपने सबसे अच्छे क्षणों तक पहुँच गया।*"*

राज्य बनाम। वंडरलिच, *(1951) 342* यू. एस. *98 "*, जब यह मुक्त हो गया है।

किसी शासक के असीमित विवेक से आदमी। जहाँ

विवेक, निरपेक्ष है, मनुष्य ने हमेशा पीड़ा झेली है। इसमें है।

इस अर्थ में कि कानून के शासन को सनक का कट्टर दुश्मन कहा जा सकता है। विवेक, जैसा कि लॉर्ड मैन्सफील्ड ने निर्धारित किया था

जॉन विल्क्स के मामले में क्लासिक शब्दों में, *(1770) 4* बर

2528 पी पर। *2539 "* इसका अर्थ है कानून द्वारा निर्देशित ठोस विवेकाधिकार।

इसे नियम द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए, न कि हास्य द्वाराः यह मनमाना, अस्पष्ट और काल्पनिक नहीं होना चाहिए।

(जोर मेरा है*)*

उपरोक्त मामले में इस बात पर जोर दिया गया कि

जानते हैं कि निर्णय किसी विशेष के पक्ष में क्यों लिया गया है पार्टी। इससे जो बात प्रभावित हुई वह यह थी कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी इसे प्रभावित करेगी।

मनमाना।

(ख*)* हमारे विचार के लिए *451* में निर्णय का भी उल्लेख किया गया था।

आरईः *2012* का विशेष संदर्भ संख्या *1*

[जगदीश सिंह खेहर, जे।*]*

रासबिहारी पांडा आदि। बनाम उड़ीसा राज्य *(1969) 1* एस. सी. सी. *414*।

इस मामले में अपीलकर्ताओं की ओर से यह प्रचार किया गया था कि केंदु की बिक्री के लिए सरकार द्वारा तैयार की गई मशीनरी

संविधान के अनुच्छेद *14* और *19 (1) (*जी*)* के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन। यह इंगित किया गया था कि घटनाओं की योजना में खरीदार केवल नामित थे एजेंट। यह भी तर्क दिया जाता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा उस नीति को निरस्त करने के बाद जिसके तहत एजेंटों को आगे बढ़ना था

केंदु में व्यवसाय अपने दम पर छोड़ देता है और लाभ कमाने के लिए

स्वयं, सरकार अपनी पार्टी की मदद करने के लिए-लोगों ने उन व्यक्तियों का एक निकाय स्थापित किया जो खरीदार होने वाले थे जिनके लिए

एकाधिकार बिक्री रियायती दरों पर की जानी थी और

कि वह लाभ जो अन्यथा अर्जित किया जाता

अब राज्य को उन खरीदारों की ओर मोड़ दिया जाएगा। यह आयोजित किया गया थाः

" 15. अधिनियम की धारा *10* धारा *3* सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट *[2012] 9* एस. सी. आर. की समकक्ष है।

और सरकार को बेचने या अन्यथा करने के लिए अधिकृत करता है

केंदु के पत्तों का निपटान इस तरह से करें किसरकार निर्देश दे सकती है। अगर खरीद का एकाधिकार

धारा *3* द्वारा केंदु का त्याग वैध है, जहाँ तक इसका इरादा है।

केवल राज्य के लाभ के लिए प्रशासित होने के लिए, सरकार द्वारा केंदु पत्तों की बिक्री या निपटान भी किया जाना चाहिए।

लोक हित में होना चाहिए और किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग के निजी हित की सेवा नहीं करना चाहिए। यह सच है कि इसके लिए

सरकार, सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए,

एक विवेकपूर्ण व्यापारी के रूप में कार्य करना, और बेचना याअन्यथा धारा *3* के तहत अधिग्रहित एकाधिकार के तहत खरीदे गए केंदु पत्तों का निपटान करें, लेकिन लाभ

बिक्री का परिणाम सार्वजनिक लाभ के लिए होना चाहिए न कि निजी लाभ के लिए। धारा *11* में यह प्रावधान है कि सरकार द्वारा व्यापार से प्राप्त शुद्ध लाभ में से

केंदु में समितियों को कम से कम आधी राशि का भुगतान किया जाना है और ग्राम पंचायतें इस बात पर जोर देती हैं कि

अवधारणा है कि केंदु की बिक्री या निपटान की मशीनरी

जनहित की सेवा के लिए छुट्टियों को भी रद्द किया जाना चाहिए। यदि निपटान की योजना बिचौलियों का एक वर्ग बनाती है

प्रदान की गई सेवा की प्रकृति के अनुपात में नहीं या उनके द्वारा किया गया कर्तव्य, यह अनुच्छेद *19 (6) (ii)* के संरक्षण का दावा नहीं कर सकता है।

16. धारा *10* बिक्री या निपटान की विधि को छोड़ देती है।

केंदु सरकार को छोड़ देता है जैसा वे उचित समझते हैं। द.

सरकार की कार्रवाई यदि आम जनता के हित में परिकल्पित और निष्पादित की जाती है तो यह न्यायिक नहीं है।

जांच पड़ताल करें। लेकिन यह सरकार को नहीं दिया जाता है

अपने स्वयं के तृतीय पक्षों के पक्ष में एकाधिकार बनाएँ

एकाधिकार।

17. केंदु पत्तियों की बिक्री के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा अपनाई गई योजनाओं की वैधता का निर्णय इस प्रकार किया जाना चाहिए -

अनुच्छेद *19 (1) (*जी*)* और अनुच्छेद *14* का प्रकाश। आमंत्रित करने के बजाय

सरकार द्वारा कुछ पुराने ठेकेदारों को दी गई निविदाएँ

वर्ष *1968* के लिए उसमें उल्लिखित शर्तों पर केंदु पत्तियों को खरीदने का विकल्प। द्वारा सुझाए गए कारण

सरकार ने कहा कि ये प्रस्ताव इसलिए दिए गए क्योंकि

खरीदारों ने पूर्व में अपने दायित्वों का पालन किया था।

सरकार की संतुष्टि के लिए वर्ष का कोई महत्व नहीं है। राज्य द्वारा दायर हलफनामे से

सरकार ऐसा प्रतीत करती है कि कीमत सार्वजनिक रूप से ली गई है जनवरी *1968* से पहले और बाद में नीलामी बहुत अधिक थी।

उन कीमतों से अधिक जिन पर केंदु के पत्ते थे

पुराने ठेकेदारों को दिया। सरकार ने महसूस किया

कि पुराने लाइसेंसधारियों के साथ अनुबंध करने और उनकी शर्तों को नवीनीकृत करने की पेशकश करने की योजना गंभीर थी

आपत्ति, क्योंकि इसने मनमाने ढंग से व्यापार में रुचि रखने वाले कई व्यक्तियों को बाहर करने की मांग की थी। तब सरकार ने

केंदु की अग्रिम खरीद के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करने का निर्णय लिया

लेकिन उन व्यक्तियों के लिए निमंत्रण को सीमित कर दिया जिन्होंने पिछले वर्ष बिना अनुबंध के अनुबंध किए थे

चूक और सरकार की संतुष्टि के लिए। के द्वारा

सरकार द्वारा प्रस्ताव देने के बजाय नई योजना, आरईः

2012 का विशेष संदर्भ संख्या *1*

453

[जगदीश सिंह खेहर, जे।*]*

मौजूदा ठेकेदारों को विशेष अधिकार दिया गया था

केंदु के पत्ते खरीदने का प्रस्ताव दें। लेकिन जहाँ तककेंदु पत्तियों की खरीद के लिए निविदाएं देने का अधिकार

उन व्यक्तियों तक सीमित था जिन्होंने प्राप्त किया था

एक ही आपत्ति। प्रस्ताव देने का अधिकार खुला है व्यक्तियों का एक सीमित वर्ग यह प्रभावी रूप से अन्य सभी को बंद कर देता है

केंदु पत्तियों का व्यापार करने वाले व्यक्ति और नए भी

उस व्यवसाय में प्रवेश करने वाले। यह प्रत्यक्ष रूप से भेदभावपूर्ण था,और अधिकार पर अनुचित प्रतिबंध लगाए

चालू रखने के लिए मौजूदा ठेकेदारों के अलावा अन्य व्यक्ति

व्यवसाय। हमारे विचार में, दोनों योजनाओं द्वारा विकसित

सरकार मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रही थी

अनुच्छेद *19 (1) (*जी*)* और अनुच्छेद *14* के तहत याचिकाकर्ता क्योंकि

केंदु कुछ व्यापारियों को छोड़ देता है, और अन्य को अलग कर देता है भेदभावपूर्ण व्यवहार के लिए व्यापारी।

18. इस परिस्थिति के आधार पर वर्गीकरण कि

कुछ मौजूदा ठेकेदारों ने उन्हें पूरा किया था

सरकार की संतुष्टि किसी भी वास्तविकता पर आधारित नहीं है। और एक न्यायपूर्ण और उचित अंतर रखने वाला महत्वपूर्ण अंतर

प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य से संबंध अर्थात प्रभावी

लोक हित में एकाधिकार का निष्पादन। बहिष्करण

व्यापार में रुचि रखने वाले सभी व्यक्तियों में से, जो व्यापार में नहीं थे

पिछले वर्ष के लाइसेंसधारी प्रत्यक्ष रूप से मनमाने हैं, इसका तोड़ने वालों के शोषण को रोकने के उद्देश्य से कोई सीधा संबंध नहीं था

और केंदु के पत्तों के उत्पादक, और न ही उनके पास कोई न्याय था या

से पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए उचित संबंध

राज्य को व्यापार।

19. उस कानून की वैधता जिसके द्वारा राज्य ने ग्रहण किया था

किसी दी गई वस्तु में व्यापार के लिए एकाधिकार का न्याय किया जाना चाहिए।

परीक्षण द्वारा कि क्या उससे होने वाला पूरा लाभ है

राज्य को आश्वस्त करने के लिए, और एकाधिकार का उपयोग एक सीमित वर्ग *[2012] 9* एस. सी. आर. को निजी लाभ प्रदान करने के लिए एक वस्त्र के रूप में नहीं किया जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

व्यक्तियों से। सरकार द्वारा पहले अपनाई गई योजना

कुछ नामित लोगों के साथ अनुबंध करने की पेशकशलाइसेंसधारक, और बाद में लाइसेंसधारियों से निविदाएं आमंत्रित करते हैं जो

पिछले वर्ष अपने अनुबंधों को पूरा किया था संतोषजनक रूप से जमीन पर शून्य घोषित होने के लिए उत्तरदायी है

कि यह अनुचित रूप से केंदु पत्तों में व्यापारियों को बाहर करता है

अपने व्यवसाय को जारी रखें। केंदु बेचने की योजना

चयनित खरीदारों को या केवल निविदाओं को स्वीकार करने के लिए

खरीदारों के एक निर्दिष्ट वर्ग से "एकीकृत रूप से" नहीं था

और अनिवार्य रूप से "के निर्माण के साथ जुड़ा हुआ है

एकाधिकार और इस न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण पर नहीं था

अकादासी पधान मामला, *(1963)* सप. *2* एससीसी *691,*

अनुच्छेद *19 (6) (ii)* द्वारा संरक्षितः इसलिए उसे संतुष्ट करना था

के पहले भाग के तहत तर्कसंगतता की आवश्यकता

अनुच्छेद *19 (6)*। योजना का समर्थन करने का कोई प्रयास नहीं किया गया

इस आधार पर कि उसने उचित प्रतिबंध लगाए

व्यापार करने के लिए व्यापारियों के मौलिक अधिकार

केंदु के पत्तों में। उच्च न्यायालय ने इस बात पर भी विचार नहीं किया कि क्या व्यक्तियों पर लगाए गए प्रतिबंधों को बाहर रखा गया है।

व्यापार के लाभ से परीक्षण संतुष्ट हुआ

अनुच्छेद *19 (6)* के पहले भाग के तहत तर्कसंगतता। द. उच्च न्यायालय ने इस दृष्टिकोण से समस्या की जांच की कि क्या

राज्य सरकार की कार्रवाई को इस वजह से दूषित किया गया था

किसी भी तिरछे उद्देश्य का, और क्या यह ऐसा था

व्यापार करने वाला विवेकपूर्ण व्यक्ति गोद ले सकता है।

20. की ओर से कोई स्पष्टीकरण देने का प्रयास नहीं किया गया है

बताएँ कि किसी प्रसिद्ध व्यक्ति द्वारा क्यों प्रस्ताव दिया गया है।

खरीद के लिए व्यापार में रुचि रखने वाले बीड़ियों के निर्माता वर्ष *1968* के लिए तीन करोड़ रुपये में केंदु पत्तों की पूरी फसल को अस्वीकार कर दिया गया था। यदि हितों के लिए

अकेले राज्य को ध्यान में रखा जाना था,

राज्य को एक करोड़ रुपये से अधिक का लाभ हुआ

उस प्रस्ताव को स्वीकार करें। हम यह सुझाव नहीं दे रहे हैं कि केवल इसलिए कि वह प्रस्ताव दिया गया था, सरकार बाध्य थी

इसे स्वीकार करने के लिए। सरकार को विवेकपूर्ण तरीके से विचार करना पड़ा

व्यवसायी, चाहे, आरई को ध्यान में रखते हुएः

2012 का विशेष संदर्भ संख्या *1*

455

[जगदीश सिंह खेहर, जे।*]*

परिस्थितियों में, इसे प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिए, विशेष रूप से

प्रस्तावक की वित्तीय स्थिति के आलोक में, प्रतिभूति

जिसे वह देने को तैयार था और जिसका प्रभाव

प्रस्ताव की स्वीकृति अन्य व्यापारियों पर पड़ सकती है और

आम जनता का हित।

21. उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों ने कहा है कि कि उनके विचार में विवेकाधिकार का प्रयोग नहीं था

मनमाना दिखाया गया, और न ही कार्रवाई को दिखाया गयाईमानदारी की कमी। लेकिन यह निष्कर्ष खुला है

आलोचना कि सरकार को नहीं दिखाया गया है

केंदु पत्तियों की प्रचलित कीमतों पर विचार करें

उस समय जब प्रस्ताव दिए गए थे, की अनुमानित फसल

केंदु छोड़ता है, बाजार की स्थिति और अधिक कीमतों पर प्रस्तावक द्वारा अपना कार्य पूरा करने की संभावना

दायित्व, और क्या यह राज्य के हित में था

सभी व्यक्तियों से खुले बाजार में निविदाएं आमंत्रित करना।

चाहे उन्होंने पहले अनुबंध किए थे या नहीं

वर्ष। यदि सरकार देय राशि सुनिश्चित करने के लिए चिंतित थी

खरीद के लिए निविदाएं जमा करने वालों का प्रदर्शन

केंदु पत्तियों में से, यह सरकार के लिए तैयार करने के लिए खुला था

उस संबंध में पर्याप्त सुरक्षा उपाय। हमारे निर्णय में,

निवेदन है कि सरकार की कार्रवाई ईमानदारी से की गई थी

याचिकाकर्ताओं को इस दलील पर पराजित किया जाए कि सरकार आक्षेपित योजना को अपनाने में एक त्रुटि हुई

निर्णय।

22. उस याचिका से सरकार को मदद मिलती अगर

कार्रवाई कानून में वैध थी और आपत्ति यह थी कि

सरकार ने अपने विवेक का प्रयोग करते हुए गलती की। परिस्थितियों में यह विचार करना अनावश्यक है कि क्या

सरकार ने अपनी पार्टी के हित में काम किया-पुरुष और

बिक्री के लिए योजनाओं को तैयार करने में पार्टी फंड बढ़ाएँ

केंदु *1968* में चला जाता है।

456 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट *[2012] 9* एस. सी. आर.

23. इन कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान,

जिस वर्ष के लिए अनुबंध दिए गए थे, उसकी अवधि समाप्त हो गई है। द.

जिन व्यक्तियों को अनुबंध दिए गए थे, वे पहले नहीं थे।

हमें, और हम उन अनुबंधों की घोषणा नहीं कर सकते जो किए गए थे

केंदु की बिक्री के लिए सरकार द्वारा प्रवेश

वर्ष *1968* के लिए इन कार्यवाहियों में गैरकानूनी छोड़ देता है।अपीलार्थियों के वकील इस बात से सहमत हैं कि यह होगा

पर्याप्त है यदि यह निर्देश दिया जाए कि खरीद के लिए निविदाएं

सरकार द्वारा अगले महीने केंदु छुट्टी आमंत्रित की जाएगी

व्यापार में रुचि रखने वाले सभी व्यक्तियों से मौसम। हम विश्वास करते हैं।

कि निविदा स्वीकार करते समय राज्य सरकार कार्रवाई करेगी।

आम जनता के हित में न कि किसी वर्ग के हित में

व्यापारियों को ताकि अगले मौसम में राज्य को मिल सके

केंदु में व्यापार में एकाधिकार का पूरा लाभ

पत्तियां और उनका कोई अनुपातहीन हिस्सा नहीं हो सकता है

किसी भी निजी एजेंसी को भेज दिया गया। इन बातों के अधीन

टिप्पणियाँ हम याचिकाओं में आगे कोई आदेश नहीं देते हैंजिनसे ये अपीलें उठती हैं।

(जोर मेरा है)

इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों के अवलोकन से पता चलता है,

कि सरकार को एक विवेकपूर्ण व्यवसायी के रूप में कार्य करना चाहिए, और

कि अर्जित लाभ सार्वजनिक लाभ के लिए होना चाहिए न कि इसके लिए

निजी लाभ। उचित प्रतिबंध की याचिका के तहत उठाया गया

भारत के संविधान का अनुच्छेद *19 (6)*

सरकारी कार्रवाई को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि

इस योजना ने बिचौलियों का निर्माण किया जो बड़े अनुपातहीन लाभ अर्जित करेंगे। इस न्यायालय ने भी कार्रवाई करने का फैसला किया

भेदभावपूर्ण क्योंकि इसने याचिकाकर्ताओं जैसे अन्य लोगों को बाहर रखा

विचार के क्षेत्र से। अंत में, एक दिशा आई

इस न्यायालय द्वारा जारी किया गया जिसमें सरकार को कार्य करने की आवश्यकता हैआम जनता का हित और निविदाएं आमंत्रित करना ताकि राज्य इस तरह से पूरा लाभ अर्जित कर सके कि

असमान लाभ किसी भी निजी एजेंसी को दिया जाता है।

(ग) रिलायंस को रमण दयराम शेट्टी आरई पर भी रखा गया था:

[जगदीश सिंह खेहर, जे।*]*

भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण और अन्य। , *(1979) 3*

सी *489*, जिसमें इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 21. यह नियम भी सीधे सिद्धांत से प्रवाहित होता है

अनुच्छेद *14* में सन्निहित समानता। यह अब एक के रूप में अच्छी तरह से स्थापित है

ई. पी. रोयप्पा बनाम में इस न्यायालय के निर्णयों का परिणाम।

तमिलनाडु राज्य, *(1974) 4* एस. सी. सी. *3* और मेनका

गांधी बनाम. भारत संघ, *(1978) 1* एस. सी. सी. *248*, कि अनुच्छेद

14 राज्य की कार्रवाई में मनमानेपन पर हमला करता है और सुनिश्चित करता है

निष्पक्षता और व्यवहार की समानता। यह आवश्यक है कि राज्य

कार्रवाई मनमाना नहीं होनी चाहिए बल्कि कुछ बातों पर आधारित होनी चाहिए।

तर्कसंगत और प्रासंगिक सिद्धांत जो गैर है

भेदभावपूर्णः इसे किसी बाहरी द्वारा निर्देशित नहीं किया जाना चाहिए।

या अप्रासंगिक विचार, क्योंकि वह होगा

समानता से इनकार। तर्कसंगतता का सिद्धांत और

तर्कसंगतता जो कानूनी रूप से और साथ ही दार्शनिक रूप से एक

समानता या गैर-मनमानी का आवश्यक तत्व है अनुच्छेद *14* द्वारा प्रस्तावित और इसे प्रत्येक राज्य की विशेषता होनी चाहिए।

कार्रवाई, चाहे वह कानून के अधिकार के तहत हो या अभ्यास में होकानून बनाए बिना कार्यकारी शक्ति। राज्य ने

इसलिए, प्रवेश करने में मनमाने ढंग से कार्य नहीं कर सकते हैं किसी तीसरे पक्ष के साथ संविदात्मक या अन्यथा संबंध, लेकिन

इसकी कार्रवाई किसी मानक या मानक के अनुरूप होनी चाहिए जो

तर्कसंगत और गैर-भेदभावपूर्ण है। यह सिद्धांत थाइस न्यायालय की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा मान्यता प्राप्त और लागू किया गया

रे, सी. जे., एरसियन उपकरण और रसायनों में लिमिटेड वी. पश्चिम बंगाल राज्य *(ऊपर)* जहाँ विद्वान

मुख्य न्यायाधीश ने बताया कि

"राज्य द्वारा कार्यकारी कार्य किया जा सकता है

कानून बनाना या कानून बनाए बिना। द.

व्यापार में ऐसी शक्तियों और कार्यों का प्रयोग

राज्य संविधान के भाग *III* के अधीन है।

अनुच्छेद *14* कानून के समक्ष समानता की बात करता है और

कानूनों का समान संरक्षण। अवसर की समानतासार्वजनिक अनुबंधों के मामलों पर लागू होना चाहिए। द.

राज्य को व्यापार करने का अधिकार है। राज्य में *9* एस. सी. आर. *(2012)* हैं।

समानता का पालन करने का कर्तव्य। एक साधारण व्यक्ति।

किसी भी व्यक्ति के साथ व्यवहार न करने का विकल्प चुन सकते हैं। द.

सरकार व्यक्तियों को बाहर करने का विकल्प नहीं चुन सकती

भेदभाव से। ब्लैकलिस्टिंग का क्रम हैकिसी व्यक्ति को अवसर की समानता से वंचित करने का प्रभाव

सार्वजनिक अनुबंध के मामले में। एक व्यक्ति जो

अनुमोदित सूची में प्रवेश करने में असमर्थ है

काली सूची में डालने के आदेश के कारण। एक नागरिक के पास हैएक में प्रवेश करने के लिए समान व्यवहार का दावा करने का अधिकार

अनुबंध जो उचित, आवश्यक और

उसके वैध आह्वान के लिए आवश्यक। यह सच है कि न तो

याचिकाकर्ता और न ही प्रतिवादी को कोई अधिकार है

एक अनुबंध में प्रवेश करें लेकिन वे बराबर के हकदार हैं

अन्य लोगों के साथ व्यवहार जो निविदा या उद्धरण प्रदान करते हैंमाल की खरीद के लिए "।

इसलिए इसे एक आवश्यक परिणाम के रूप में पालन करना चाहिएअनुच्छेद *14* में निहित समानता का सिद्धांत कि हालांकि

राज्य के साथ संबंध बनाने से इनकार करने का अधिकार है

किसी को भी, फिर भी अगर यह ऐसा करता है, तो यह मनमाने ढंग से किसी को भी नहीं चुन सकता है

वह व्यक्ति जो इस तरह के रिश्ते में प्रवेश करना पसंद करता है और

समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों के बीच भेदभाव करना,

लेकिन इसे कुछ मानकों के अनुरूप कार्य करना चाहिए या

सिद्धांत जो तर्कसंगतता की कसौटी पर खरा उतरता है और

गैर-भेदभाव और ऐसे मानक से कोई विचलन

या सिद्धांत अमान्य होगा जब तक कि इसका समर्थन नहीं किया जा सकता है

या कुछ तर्कसंगत और गैर भेदभावपूर्ण पर उचित ठहराया गया

जमीन।

22. यह जानना दिलचस्प है कि इस नियम को मान्यता दी गई थी और

बिक्री के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा आवेदन किया गया

रासबिहारी में उड़ीसा सरकार द्वारा केंदु पत्तियों का पांडा वी। उड़ीसा राज्य *(1969) 1* एस. सी. सी. *414*। यह निर्णय

राज्य की कार्रवाई में मनमानेपन के खिलाफ नियम की प्रयोज्यता के संबंध में हम जो विचार ले रहे हैं, उसका पूरी तरह से समर्थन करते हैं।

*(*जोर मेरा है*)*

इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्धारण का विश्लेषण

इससे यह निष्कर्ष निकलेगा कि राज्य को व्यापार करने का अधिकार है।

अपनी व्यापारिक गतिविधि में सार्वजनिक अनुबंधों को निष्पादित करने में राज्य को

प्रासंगिक सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाए, न कि बाहरी या

अप्रासंगिक विचार। उसी पर आधारित होना चाहिए

तर्कसंगतता और तर्कसंगतता के साथ-साथ गैर-मनमानेपन। यह.

यह निष्कर्ष निकाला गया कि राज्य एक में प्रवेश करते हुएअनुबंध संबंध, मानकों को बनाए रखने के लिए बाध्य था

ऊपर उल्लिखित। और उक्त मानकों से कोई भी विचलन अमान्य होगा जब तक कि वह अच्छे कारणों से समर्थित न हो।

(घ*)* दिए गए निर्णय की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया गया था।

कस्तुरी लाल लक्ष्मी रेड्डी बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य

& एन*.* आर*. , (1980) 4* एस*.* सी*.* सी*. 1,* जिसमें तथ्यात्मक पृष्ठभूमि भी हैजैसा कि, कानूनी स्थिति पैराग्राफ *19* में व्यक्त की गई थी

उस निर्णय का जो नीचे दिया जा रहा हैः

"19. तथ्यों की पृष्ठभूमि से यह स्पष्ट है और

जिन परिस्थितियों में विवादित आदेश आया था

बनाए गए और विवादित में निर्धारित नियम और शर्तें

आदेश दें कि यह एक टैपिंग अनुबंध सरलीकरण नहीं था जो

दूसरे उत्तरदाताओं को देने का इरादा था। द.

दूसरे उत्तरदाता नियमित रूप से आश्वस्त होना चाहते थेउनसे पहले राल के आकार में कच्चे माल की आपूर्ति

राज्य के भीतर एक कारखाना स्थापित करने का निर्णय ले सकता था और यह था

ऐसे कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि

विवादित आदेश को दोहन अनुबंध देने के लिए बनाया गया थादूसरे उत्तरदाता। यह वास्तव में आवंटन के माध्यम से था

राज्य के भीतर एक कारखाना स्थापित करने का दायित्व और वह *3500* मीट्रिक टन राल जिसे बनाए रखने की अनुमति दी गई थी

द्वारा निकाले गए राल से दूसरे उत्तरदाताओं द्वारा

उन्हें स्थापित करने के लिए कारखाने में उपयोग करने की आवश्यकता थी

उनके द्वारा ऊपर और यह प्रदान किया गया था कि राल का कोई हिस्सा नहीं

निकाले गए को बाहर निकालने की अनुमति दी जानी चाहिएराज्य। विवादित आदेश का पूरा उद्देश्य *[2012] 9* एस. सी. आर. था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दूसरे को *3500* मीट्रिक टन राल उपलब्ध कराएँ

कारखाने को चलाने के उद्देश्य से उत्तरदाताओं कोउनके द्वारा स्थापित। राज्य के लिए लाभ यह था कि एक नया

रोसिन, तारपीन तेल और अन्य के निर्माण के लिए कारखाना

व्युत्पन्न अपने क्षेत्रों के भीतर राज्य के लोगों को नौकरी के अधिक अवसर प्रदान करेंगे।

उनकी समृद्धि को बढ़ाना और राज्य को बढ़ाना। राजस्व और इसके अलावा राज्य को एक

कम से कम *1500* मीट्रिक टन राल की निश्चित आपूर्ति

बिना किसी वित्तीय भागीदारी या जोखिम के और इसके साथ इसके लिए उपलब्ध राल की अतिरिक्त मात्रा, यह सक्षम होगा

अधिक रोजगार पैदा करने के लिए एक और कारखाना स्थापित करना।

अवसर और, वास्तव में, जवाबी-शपथ पत्र के रूप में

गुलाम रसूल, सरकार के अवर सचिव ने दायर किया

राज्य की ओर से यह दर्शाता है कि सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के राल आसवन संयंत्र की स्थापना के लिए कदम उठाने में कोई समय नहीं गंवाया

राजौरी जिले में सुंदरबनी नाम के राज्य के एक दूरदराज के क्षेत्र में। इसके अलावा, राज्य सक्षम होगा

........इन दुर्गम क्षेत्रों से राल का सुरक्षित निष्कर्षण

उन्हें अनुमति देने के बजाय सर्वोत्तम संभव शर्तों पर

अप्रयुक्त रहें या हास्यास्पद रूप से कम रॉयल्टी पर दिए जाएं। हम याचिकाकर्ताओं के इस तर्क को स्वीकार नहीं कर सकते कि विवादित आदेश के तहत एक बड़ा लाभ प्रदान किया गया था

राज्य की कीमत पर दूसरे उत्तरदाता पर। यह है। विवादित आदेश की शर्तों से स्पष्ट करें कि दूसरे उत्तरदाताओं को कम से कम *5000* निकालना होगा

3500 मीट्रिक टन रखने का अधिकार होना। द. काउंटर-पहले प्रतिवादी की ओर से गुलाम रसूल और दूसरे की ओर से गुरन देवाया का हलफनामा

देवया यह *Rs.200* प्रति क्विंटाल के पड़ोस में होगा, लेकिन अगर हम प्रति क्विंटाल *Rs.175* के न्यूनतम आंकड़े पर लागत लेते हैं, तो निष्कर्षण की कुल लागत और संग्रह *Rs.87,50,000* और इस *461* पर आएगा।

आरईः *2012* का विशेष संदर्भ संख्या *1*

[जगदीश सिंह खेहर, जे।*]*

Rs.87 का निवेश, *50,000* द्वारा किया जाना आवश्यक है

दूसरा उत्तरदाता प्रचलित ब्याज की राशि

बैंक दर लगभग *Rs.13,00,000* तक होगी। अब, के रूप में रुपये *87,50,000* प्लस के इस खर्च के खिलाफ

Rs.13,00,000 दूसरे उत्तरदाता हकदार होंगे

1500 मीट्रिक टन के संबंध में राज्य से दावा करना

द्वारा स्वीकृत दर पर ही उस तक पहुँचाया जाने वाला राल

निकटवर्ती सुलभ वनों के लिए वन विभाग

जिनका काम मजदूरी-अनुबंध के आधार पर किया जा रहा था। यह है।पलटवार में कहा गया-गुलाम रसूल और गुरन के हलफनामे

देवया और इस कथन को गंभीरता से चुनौती नहीं दी गई है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से, कि निष्कर्षण की लागत और

वन विभाग द्वारा स्वीकृत संग्रह

मजदूरी-अनुबंध के आधार पर आसपास के सुलभ वन दिए गए वर्ष में *1978-79 Rs.114* प्रति क्विंटाल था और

इस प्रकार, दूसरे उत्तरदाता से दावा करने का अधिकार होगा

राज्य के संबंध में *Rs.114* प्रति क्विंटाल से अधिक नहीं

1500 मीट्रिक टन इसे दिया जाना है और इसके अलावा निष्कर्षण की वास्तविक लागत के बीच का अंतर वहन करना

और संग्रह और राज्य से प्राप्त राशि

1500 मीट्रिक के संबंध में *Rs.114* प्रति क्विंटाल की दर टन, दूसरे उत्तरदाताओं को भुगतान करना होगा

शेष *3500* मीट्रिक टन की कीमत उनके द्वारा *Rs.350* प्रति क्विंटाल की दर से रखी जाएगी। इस पर

गणना, *3500* मीट्रिक टन की लागत को बनाए रखा जाना है

दूसरे उत्तरदाताओं द्वारा *Rs.474* प्रति क्विंटाल पर काम किया जाएगा। परिणाम यह होगा कि विवादित आदेश के तहत

राज्य को इस दर से *1500* मीट्रिक टन राल मिलेगा।

Rs.114 प्रति क्विंटाल जबकि दूसरे उत्तरदाता

उनके द्वारा रखे गए *3500* मीट्रिक टन के शेष के लिए *Rs.474* प्रति क्विंटाल की दर से भुगतान करना होगा। जाहिर है, एक बड़ी

विवादित के तहत राज्य को लाभ प्राप्त होगा

आदेश दें। यदि राज्य को मजदूरी अनुबंध के माध्यम से इन दुर्गम क्षेत्रों में आग लगनी थी, तो बिना लिए न्यूनतम लागत *Rs.175* प्रति क्विंटाल होगी।

के कारण होने वाले अतिरिक्त व्यय को ध्यान में रखते हुए

ब्याज, लेकिन विवादित आदेश के तहत राज्य को क्या मिलेगा?

[2012] 9 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1500 बहुत कम दर पर मीट्रिक टन राल *Rs.114* प्रति क्विंटाल बिना किसी जोखिम या खतरे के। राज्य ने

रखे गए *3500* मीट्रिक टन राल के लिए भी प्राप्त होगा दूसरे उत्तरदाता द्वारा मूल्य या रॉयल्टी की दर से

Rs.260 प्रति कुंतल की दर जिस पर राज्य आबंटित कर रहा थारेसिन से लेकर मध्यम पैमाने की औद्योगिक इकाइयाँ और दर

Rs.320 प्रति क्विंटाल जिस पर यह छोटे को राल आवंटित कर रहा था

राज्य के भीतर स्केल इकाइयाँ। यह देखना मुश्किल है कि कैसे

इन तथ्यों को विवादित आदेश कहा जा सकता है

राज्य के लिए नुकसानदेह या किसी भी तरह से पक्ष में

राज्य की कीमत पर दूसरा उत्तरदाता। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि आयोजित नीलामी में

दिसंबर *1978,* जनवरी *1979* और अप्रैल *1979,* कीमत

प्राप्त राल का *Rs.484, Rs.520* जितना था और *Rs.700* प्रति क्विंटाल क्रमशः और जब बाजार मूल्य

इतना ऊँचा था, यह अनुचित और जनहित के विपरीत था

राज्य की ओर से दूसरे को राल बेचने के लिए

Rs.320 प्रति क्विंटाल की दर से उत्तरदाता

आक्षेपित आदेश। यह तर्क, हालांकि यह प्रशंसनीय लग सकता है, गलत है क्योंकि यह ध्यान में नहीं रखता है।

बाहर राल के निर्यात की अनुमति नहीं देने की राज्य की नीति

इसके क्षेत्र लेकिन इसे केवल स्थापित कारखानों में उपयोग के लिए आवंटित करना

राज्य के भीतर। यह स्पष्ट है कि इस नीति को देखते हुए, नहीं

राज्य द्वारा राल की नीलामी की जाएगी और वहाँ होगा

खुले बाजार में और इसमें राल की बिक्री का कोई सवाल ही नहीं है।

स्थिति, यह अवधारणा आयात करने के लिए पूरी तरह से अप्रासंगिक होगा बाजार मूल्य की जिसके संदर्भ में पर्याप्तता

राज्य द्वारा दूसरे उत्तरदाताओं से ली गई कीमत का आकलन किया जा सकता है। अगर राज्य केवल राल बेच रहा था, तो वहाँ

इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि राज्य को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए

उच्चतम मूल्य विषय, निश्चित रूप से, किसी भी अन्य ओवरराइडिंग के लिए

लोकहित पर विचार करना और उस स्थिति में,किसी निजी व्यक्ति को कम कीमत पर राल देने की कार्रवाई

यह मनमाना और जनहित के विपरीत होगा। लेकिन, जहाँ राज्य ने नीति के रूप में बिक्री बंद कर दी है।

बाहरी लोगों को राल और इसे केवल उद्योगों को आवंटित करने का निर्णय आरईः

2012 का विशेष संदर्भ संख्या *1*

463

[जगदीश सिंह खेहर, जे। *]*

प्रोत्साहन के उद्देश्य से राज्य के भीतर स्थापित औद्योगीकरण, शिकायत की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती है कि

राज्य उससे कम कीमत पर राल दे रहा है जो

इसे खुले बाजार में प्राप्त किया जा सकता है। का पैमाना खुले बाजार में कीमत पूरी तरह से अयोग्य होगी, क्योंकि

राज्य की नीति को देखते हुए, इसका कोई सवाल ही नहीं होगा

ऐसे मामले में राज्य को राल की बिक्री से राजस्व अर्जित नहीं करना है, बल्कि इसके भीतर उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देना है। राज्य। इसके अलावा, आयोजित नीलामी में प्राप्त कीमतें

दिसंबर *1978*, जनवरी *1979* और अप्रैल *1979* में ऐसा नहीं हुआ।

राल की सही और वास्तविक कीमत को दर्शाता है, क्योंकि

जब इन नीलामियों का आयोजन किया गया था, यह बन गया था

ज्ञात था कि राज्य ने प्रतिबंध लगाने का नीतिगत निर्णय लिया था

1979-80 से अपने क्षेत्रों से राल का निर्यात

और इसलिए नीलामी में प्राप्त कीमतें थीं

कीमतों की कमी। वास्तव में, अप्रैल *1979* में आयोजित नीलामी थी

राज्य में अंतिम नीलामी और चूंकि यह ज्ञात था कि

भविष्य में कोई राल नीलामी द्वारा बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं होगा

बाहरी लोगों के लिए खुला बाजार, *Rs.700* की अत्यधिक उच्च कीमतकारखाने के मालिकों द्वारा प्रति क्विंटाल की पेशकश की गई थी

राज्य के बाहर कारखाने, ताकि उन्हें उतना ही मिले

अपनी औद्योगिक इकाइयों को खिलाने के उद्देश्य से राल

कुछ समय के लिए। प्रति-शपथपत्रों से पता चलता है कि, वास्तव में,

वर्ष *1978* के दौरान प्राप्त राल का औसत बिक्री मूल्य

79 केवल *Rs.433* प्रति क्विंटाल था और इस कीमत की तुलना में, दूसरे उत्तरदाताओं को कीमत का भुगतान करना आवश्यक था या

3500 के लिए *Rs.474* प्रति क्विंटाल की उच्च दर पर रॉयल्टी

विवादित आदेश के तहत उनके द्वारा मीट्रिक टन राल रखा जाएगा। परिस्थितियों में यह असंभव है कि

देखें कि यह कैसे कहा जा सकता है कि राज्य की कीमत पर दूसरे उत्तरदाता को कोई लाभ प्रदान किया गया था। द.विवादित आदेश के खिलाफ चुनौती का पहला प्रमुख होना चाहिए,

इसलिए अस्वीकार कर दिया जाए। "

(जोर मेरा है*)*

464 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2012] 9 एस सी आर।

विवाद की तथ्यात्मक स्थिति की जाँच

ऊपर निकाले गए निर्णय से पता चलता है कि राज्य सरकार ने अपने भीतर एक कारखाना स्थापित करने के लिए एक नीति तैयार की थी।

राज्य, जिसके परिणामस्वरूप अधिक रोजगार का सृजन होगा

कहा गया कि कारखाना राज्य को कम से कम *1500* मीट्रिक टन का आश्वासन देगाबिना किसी वित्तीय भागीदारी के राल। यह बदले में होगा

राज्य को एक और कारखाना स्थापित करने में सक्षम बनाना

राज्य के लोगों के लिए रोजगार के अवसर। यह है।

इसलिए, कि इस न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि आक्षेपित आदेश दूसरे प्रत्यर्थी के पक्ष में राज्य द्वारा पारित किया जा सकता है

राज्य के लिए नुकसानदेह और पक्षपाती नहीं कहा जाएगा

दूसरा उत्तरदाता। एक तरह से समझते हुए, यह

न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश में कोई कमजोरी नहीं पाई गई राज्य सरकार ने क्योंकि राज्य सरकार ने दिया था

एक ऐसी नीति का प्रभाव जो आम लोगों के लिए सबसे अच्छा होगाराज्य के निवासियों की भलाई *(*भारत के संविधान के अनुच्छेद *39 (*बी*)* के अनुसार*)* एक भौतिक संसाधन आवंटित करते समय,

हालांकि अनुच्छेद *39 (*बी*)* का कोई संदर्भ नहीं दिया गया था

निर्णय में भारत का संविधान। क्या भी महत्वपूर्ण है यह है कि इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से ध्यान दिया है कि यदि राज्य सरकार

केवल राल बेच रहा था, यह उच्चतम प्राप्त करने के लिए बाध्य था

संभावित कीमत।

(ई*)* तब द्वारकादास मरफतिया का संदर्भ दिया गया था और

सन्स बनाम बॉम्बे बंदरगाह का न्यासी मंडल, *(1989) 3*

एस. सी. सी. *293*, जिसमें प्रत्यर्थी का मामला था, कि उसके मामले में सबूत यह कटारा द्वारा उल्लेख किया गया था कि साजिश थी

धनजी मावजी को आवंटित किया गया क्योंकि यह नीति थी

कि क्रॉस में इस साक्ष्य को कोई चुनौती नहीं थी जाँच। यह भी दावा किया गया कि कोई सबूत नहीं था

सभी अधिभोगियों को संयुक्त किरायेदारी पर भूखंड देने की पोर्ट ट्रस्ट की कथित नीति पर। विद्वान वकील के अनुसार

पोर्ट ट्रस्ट द्वारा संबोधित पत्रों में प्रत्यर्थी और

अपीलार्थी और/या उनके आरई द्वारा और उनकी ओर से पत्रों मेंः

2012 का विशेष संदर्भ संख्या *1*

465

[जगदीश सिंह खेहर, जे।*]*

कथित सहयोगी चिंताओं को उन्होंने विशेष रूप से स्वीकार किया था, कि

पोर्ट ट्रस्ट की रहने वालों को भूखंड आवंटित करने की नीति थी

इसके प्रमुख भागों की और वास्तव में एक शिकायत की गई थी

उनके द्वारा, कि बॉम्बे की उक्त नीति के अनुसार

पोर्ट ट्रस्ट, के सहयोगियों को एक भूखंड आवंटित नहीं किया जा रहा था

अपीलार्थी। मामले के उस दृष्टिकोण में यह तर्क दिया गया था कि क्या भूखंड संयुक्त रूप से दिया जाना चाहिए था

किरायेदारी या नहीं, में अदालत द्वारा नहीं लिया जा सकता था

न्यायिक समीक्षा के अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग। रिलायंस था

परिषद में लॉर्ड जस्टिस डिप्लॉक की टिप्पणियों पर रखा गया

सिविल सेवा संघों का *v.* सिविल सेवा मंत्री, *(1984)*

3 सभी ई. आर. *935,950,* जहाँ विद्वान लॉर्ड जस्टिस ने *3* को वर्गीकृत किया

न्यायिक समीक्षा के नियंत्रण के अधीन आधार, अर्थात्, अवैधता, तर्कहीनता और प्रक्रियात्मक अनुचितता। उपरोक्त तथ्यात्मक में

पृष्ठभूमि में इस न्यायालय ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकालाः

"21. हम प्रस्तुतियों को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। होने के नाते

सार्वजनिक निकाय अपने किरायेदार के साथ अपने व्यवहार के संबंध में भी, यह

लोक हित में कार्य करना चाहिए, और उस कर्तव्य का उल्लंघन हैदीवानी मुक़दमे या रिट में परीक्षा के लिए उत्तरदायी

अधिकार क्षेत्र।

प्रत्यर्थी की ओर से कि दुर्भावना का कोई सवाल नहीं थाइन कार्यवाहियों में आरोप लगाया गया या साबित किया गया। वास्तव में,

वह सही है। लेकिन यह ध्यान में रखना होगा कि

सरकारी नीति अमान्य होगी क्योंकि इसमें सार्वजनिक रूप से कमी होगी। ब्याज, अनुचित या कथित के विपरीत

एक सरकारी कार्रवाई उचित और सार्वजनिक हित में है। इसकी वैधता को चुनौती देने वाली पार्टी के लिए यह दिखाना है कि कार्रवाई अनुचित, मनमाना या घोषित मानदंडों के विपरीत है या सार्वजनिक हित द्वारा सूचित नहीं है, और

बोझ भारी है।

[2012] 9 एस सी आर।

466 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

37. जैसा कि हम इस मामले के तथ्यों को देखते हैं, वहाँ एक थाकिरायेदारों के साथ लेनदेन के संबंध में निहित दायित्व /

सार्वजनिक रूप से कार्य करने के लिए पोर्ट ट्रस्ट प्राधिकरण के अधिभोगियों

ब्याज/उद्देश्य। उस आवश्यकता को पूरा किया जाता है यदि वह

प्रदर्शित किया कि पोर्ट ट्रस्ट के अधिकारियों ने कार्रवाई की है

ऐसी नीति का अनुसरण जो सार्वजनिक उद्देश्य के लिए संदर्भित हो।एक बार जब वह मानक स्थापित हो जाता है कि क्या वह नीति है

पोर्ट ट्रस्ट प्राधिकरणों का अनुपालन में कार्य करने का दायित्व सार्वजनिक प्रयोजन का एक सार्वजनिक कानून उद्देश्य या एक निजी उद्देश्य था

कानून का उद्देश्य। इस संवैधानिक योजना के तहत

संबंधित द्वारा पोर्ट ट्रस्ट प्राधिकरणों की आवश्यकता थी

सार्वजनिक उद्देश्य के अनुसरण में कार्य करने के लिए कानून। हम संतुष्ट हैं।

कि वे ऐसा करने के लिए आगे बढ़े हैं।

(जोर मेरा है)

तत्काल मामले में, भले ही विवाद संबंधित था

एक किरायेदारी के मुद्दे पर, इस न्यायालय ने निर्णय दिया कि एक सार्वजनिक निकाय था

जनहित में कार्य करने के लिए बाध्य।

(च) कालानुक्रमिक अनुक्रम में, विद्वान परामर्श तब उद्धृत किया गया

महाबीर ऑटो स्टोर और अन्य। बनाम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और अन्य।*(1990) 3* एससीसी *752*। उसमें की गई प्रासंगिक टिप्पणियाँ,

वर्तमान विवाद का संदर्भ नीचे दिया जा रहा हैः

" 12. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि राज्य की प्रत्येक कार्रवाई या

कारण से अनजान कार्यों पर सवाल उठाया जा सकता है अनुच्छेद *226* या अनुच्छेद *32* के तहत कार्यवाही में मनमाना

संविधान। इस संबंध में रिलायंस रखी जा सकती है।

राधा कृष्ण में इस न्यायालय की टिप्पणियों पर

अग्रवाल बनाम। बिहार राज्य *(1977) 3* एस. सी. सी. *457*। यह आरई प्रतीत होता हैः

2012 का विशेष संदर्भ संख्या *1*

467

[जगदीश सिंह खेहर, जे।*]*

हमारे लिए, शुरुआत में, कि तथ्यों और परिस्थितियों में

मामला, प्रतिवादी कंपनी आई. ओ. सी. का एक अंग है

राज्य या राज्य का एक साधन जैसा कि विचार किया गया है संविधान के अनुच्छेद *12* के तहत। राज्य अपने में कार्य करता है

संविधान के अनुच्छेद *298* के तहत कार्यकारी शक्ति

व्यक्ति के साथ अनुबंध में प्रवेश करना या न करना

पार्टियाँ। संविधान का अनुच्छेद *14* लागू होगा।

शक्ति के उन अभ्यासों के लिए। इसलिए, अनुच्छेद *14* के तहत राज्य निकाय की कार्रवाई की जांच की जा सकती है। राधा को देखें।

कृष्ण अग्रवाल बनाम। बिहार राज्य पी। *462* , लेकिन अनुच्छेद *14*

संविधान का अर्थ इस प्रकार नहीं लगाया जा सकता है और न ही किया गया है

अनुबंध के बाद राज्य की कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा के लिए एक चार्टर राज्य को जवाबदेह ठहराने के लिए प्रवेश किया गया है

कारण बताकर अपनी कई गतिविधियों में अपने कार्यों के लिए

इस तरह के कार्यों के लिए। इस प्रकृति की स्थिति में निश्चित

प्रत्यर्थी कंपनी की गतिविधियाँ जिनका गठन किया गया था

संविधान के अनुच्छेद *12* के तहत राज्य निश्चित रूप से हो सकता है

संविधान के अनुच्छेद *14* के अधीन परिस्थितियाँ

अनुबंधों में प्रवेश करना या न करना और होना चाहिए

उचित और केवल वैध और प्रासंगिक पर लिया गया

विचार; यह किसी विशेष लेन-देन के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि क्या सुनवाई आवश्यक है।

और कारण बताए जाने चाहिए। यदि कोई अधिकार प्रदान किया जाता है

नागरिकों पर जिसमें हस्तक्षेप करने की मांग की जाती है, ऐसी कार्रवाई

संविधान के अनुच्छेद *14* के अधीन है, और होना चाहिए

उचित और केवल लोक हित के वैध और प्रासंगिक आधारों पर लिया जा सकता है। जहाँ मनमानेपन है

इस प्रकार के प्रवेश या प्रवेश न करने की कार्रवाई का उल्लेख करें

संविधान। यदि मामलों में भी सरकारी कार्रवाई की जाएअनुबंधों में प्रवेश करना या नहीं करना, संतुष्ट करने में विफल रहता है

तर्कसंगतता का परीक्षण, वही अनुचित होगा।

[2012] 9 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

3

इस संबंध में ई. पी. को निर्देश दिया जा सकता है।

रोयप्पा बनाम। तमिलनाडु राज्य *(1974) 4* एस. सी. सी. *3,*

मेनका गांधी बनाम. भारत संघ *(1978) 1* एस. सी. सी. *248,*

अजय हसिया बनाम। खालिद मुजीब सहरावर्दी *(1981) 1* एस. सी. सी. *722* , आर. डी. शेट्टी बनाम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण, *(1979) 3* एस. सी. सी. *489*, और द्वारकादास मरफतिया और

सन्स वी। बॉम्बे बंदरगाह के न्यासी मंडल, *(1989)*

3 एससीसी *293*। यह हमें लगता है कि तर्क और शासन का नियम

इससे निपटने में राज्य साधन द्वारा स्थिति या कार्रवाईवर्तमान जैसी स्थिति में नागरिक। भले ही

नागरिकों के अधिकार संविदात्मक प्रकृति के हैं।

अधिकार, निर्णय लेने का तरीका, तरीका और उद्देश्य

किसी अनुबंध में प्रवेश करना या नहीं करना, प्रासंगिकता की कसौटी पर न्यायिक समीक्षा के अधीन है और

लेन-देन के प्रकार में गैर-भेदभाव और वर्तमान मामले में व्यवहार की प्रकृति।

17. हमारी राय है कि ऐसे सभी मामलों में

सार्वजनिक कानून या निजी कानून अधिकार शामिल हैं, इस पर निर्भर करता है

मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ। द्वैधीकरण

अधिकारों और उपचारों के बीच किसी के द्वारा मिटाया नहीं जा सकता है

स्ट्रेट-जैकेट सूत्र। प्रत्येक में इसकी जांच की जानी चाहिए।

विशेष मामला। श्री साल्वे ने आग्रह किया कि

इस तरह के मनमाने प्रयोग के अनुच्छेद *14* के तहत कुछ मामले "शक्ति "और न कि उत्पन्न होने वाले"अधिकार "के प्रयोग के मामले

किसी अनुबंध के तहत या किसी कानून के तहत। हमारा मानना है कि

कि वह तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर निर्भर करेगा।

18. तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद

मामला और विवाद और व्यवहार की प्रकृतिपक्षकारों के बीच और कानून की वर्तमान स्थिति को देखते हुए,

हमारी राय है कि राज्य/जनता का निर्णय *469*

आरईः *2012* का विशेष संदर्भ संख्या *1*

[जगदीश सिंह खेहर, जे।*]*

संविधान के अनुच्छेद *298* के तहत अधिकार, एक प्रशासनिक निर्णय है और इस पर महाभियोग चलाया जा सकता है

यह आधार कि निर्णय किसी भी आधार पर भारत के संविधान के अनुच्छेद *14* का मनमाना या उल्लंघन है

सार्वजनिक कानून के क्षेत्र में उपलब्ध। हमें ऐसा लगता है कि इस संबंध में

आई. ओ. सी. जैसे निगम का पक्षकारों को सूचित किए बिनासंबंधित, जैसा कि अपीलार्थी-फर्म के मामले में नीति के कथित परिवर्तन पर और उस आधार पर कार्रवाई की मांग करने के लिए

18 वर्षों से अधिक के लेन-देन को समाप्त करना जिसमें बड़ी मात्रा में धन शामिल है, उचित कार्रवाई नहीं है।

विशेष रूप से सत्ता की एकाधिकारवादी प्रकृति को देखते हुए

इस क्षेत्र में उत्तरदाता का। इसलिए यह आवश्यक है कि

यह दोहराना कि सार्वजनिक कानून के क्षेत्र में भी संबंधित या प्रभावित होने वाले संबंधित व्यक्तियों को शामिल किया जाना चाहिए

आत्मविश्वास। क्या और किन परिस्थितियों मेंविश्वास को ध्यान में रखा जाना चाहिए

किसी भी जलडमरूमध्य-जैकेट के आधार पर रखा गया। यह शामिल अधिकार की प्रकृति और शक्ति की प्रकृति पर निर्भर करता है।

एक विशेष स्थिति में अभ्यास करने की मांग की। यह सच है कि सत्ता और अधिकार के बीच भेदभाव है लेकिनचाहे राज्य के पास हो या किसी राज्य का साधन

सार्वजनिक क्षेत्र या निजी क्षेत्र में कार्य करने का अधिकार एक मामला है।

जो, हमारी राय में, तथ्यों पर निर्भर करता है और

स्थिति की परिस्थितियाँ, लेकिन शक्ति का ऐसा प्रयोग राज्य या साधन द्वारा निपटा नहीं जा सकता है

राज्य को सूचित किए बिना और विश्वास में लिए बिना,

पार्टी जिसके अधिकार और शक्तियाँ प्रभावित होती हैं या मांगी जाती हैं

प्रभावित होने के लिए, आत्मविश्वास में। ऐसी स्थितियों में सबसे अधिक

अक्सर लोग ज्ञान के बहिष्करण से व्यथित महसूस करते हैं यदि विश्वास में नहीं लिया गया।

19. इस तरह का लेन-देन प्रशासनिक रूप से जारी रहना चाहिए।

राज्य के अंग के साथ निर्णय। यह संविदात्मक या वैधानिक हो सकता है लेकिन लगभग दो दशकों से पक्षों के बीच लेन-देन की स्थिति में, ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए

जिसका पालन किया जाएगा वह उचित, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होगा, यानी वह प्रक्रिया जिसे आम तौर पर स्वीकार किया जाता है *(एस. आई. सी. अपेक्षित है) 470* सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्टों के लिए

[2012] 9 एस सी आर।

राज्य का एक अंग और उस प्रक्रिया का पालन किया जाए

जागरूक होना चाहिए और सभी प्रभावित लोगों को होना चाहिए

विश्वास में लिया।

इस राय का कि यह कहना उचित होगा कि ऐसे मामले जहां राज्य की साधनता प्रवेश करती है

संविदात्मक क्षेत्र, यह घटना द्वारा शासित होना चाहिए

अनुबंध से। यह सच है कि यह आवश्यक नहीं हो सकता है

कारण दें लेकिन, हमारी राय में, इस प्रकृति के क्षेत्र में

संबंधित पक्षों के लिए निष्पक्षता होनी चाहिए, और

बड़ी संख्या या लंबी अवधि को ध्यान में रखते हुए और

पक्षों के बीच लेन-देन की प्रकृति,

अपीलार्थी को विश्वास में लिया जाना चाहिए था। समानता और निष्पक्षता कम से कम राज्य के अधिकार से निपटने वाले राज्य के एक साधन से इतनी मांग करती है।

अनुबंध को अस्तित्व में न रखने के लिए। लेकिन हमें करना होगा,

ऐसी प्रक्रिया विकसित करें जो काम करे।

23. यह हमारा निर्णय नहीं है जो महत्वपूर्ण है बल्कि एक निर्णय है

उपरोक्त आधार पर किस पर पहुंचना चाहिए

सरकार-जो निष्पक्ष रूप से तय की जाएगी और होनी चाहिएसंबंधित व्यक्तियों को विश्वास में लेने के बाद लिया जाता है जिनके अधिकार/दायित्व प्रभावित होते हैं। में निष्पक्षता

इस तरह की कार्रवाई पारदर्शी नहीं तो बोधगम्य होनी चाहिए। *(* जोर मेरा है*)*

ऊपर निकाले गए निर्णय में जो निष्कर्ष निकला, उसे लागू होने के विस्तार के रूप में वर्णित किया जा सकता है

विषय पर भारत के संविधान का अनुच्छेद *14*

संविदात्मक समझौते। इससे पहले, अनुबंध देने का एक कार्य निष्पक्षता की कसौटी पर तय किया गया था। इसके लिए

पहली बार, यहाँ तक कि अनुबंध में प्रवेश नहीं करने का निर्णय भी

व्यवस्था को न्यायिक *471* के दायरे में लाया गया है।

आरईः *2012* का विशेष संदर्भ संख्या *1*

[जगदीश सिंह खेहर, जे।*]*

समीक्षा करें। निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित होने की आवश्यकता, अर्थात,

सुशासन में लागू होने वाले सिद्धांतों को माना गया है

संविदात्मक व्यवस्था में प्रवेश न करने के लिए समान रूप से लागू होगा। उपरोक्त निर्णय का एक अन्य पहलू यह था कि

इस न्यायालय ने व्यक्त किया कि अनुबंध करने वाले पक्ष को अधिकार था

सूचित किया जाए *(*जानने का अधिकार*)* कि संविदात्मक व्यवस्था क्यों

जो लंबे समय तक *(1965* से *1983* तक) जारी रहा था

समाप्त किया जा रहा है।

(छ) दिए गए निर्णय पर बहुत जोर दिया गया था।

इस न्यायालय द्वारा कुमारी श्रीलेखा विद्यार्थी और अन्य में। बनाम राज्य यू. पी. और अन्य। *(1991) 1* एससीसी *212*। अवलोकन जो निर्भर थे

सुनवाई के दौरान निर्धारित किया जा रहा है

इसके नीचेः

21. भारत के संविधान की प्रस्तावना अपने सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का संकल्प लेती है।

राजनीतिक; और स्थिति और अवसर की समानता। प्रत्येक राज्य इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए। भाग *IV*

संविधान में 'राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत' शामिल हैं।

जो देश के शासन में मौलिक हैं और जिनका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता को सुरक्षित करना है

भाग *III* में गारंटीकृत व्यक्तिगत मौलिक अधिकार राज्य कार्रवाई की ज्यादतियों के खिलाफ संरक्षण, का एहसास करने के लिए

प्रस्तावना में दृष्टि। यह दर्शन है

संविधान, क्या यह कहा जा सकता है कि यह बहिष्करण पर विचार करता है

अनुच्छेद *14*-गैर-मनमानी जो शासन के लिए बुनियादी है

कानून-संविदात्मक क्षेत्र में राज्य की कार्रवाई से जब सभी

राज्य के कार्य सार्वजनिक भलाई के लिए होते हैं और उनसे निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होने की अपेक्षा की जाती है*?* हमें कोई संदेह नहीं है कि

संविधान अन्याय की परिकल्पना या अनुमति नहीं देता है या

प्रस्तावना में प्रतिपादित आदर्शों के विपरीत अपनी गतिविधि के किसी भी क्षेत्र में राज्य के कार्यों में अनुचितता।

हमारी राय में, यह संवैधानिक के लिए अलग होगा

अनुच्छेद *14* के अपवर्जन के तर्क को स्वीकार करने की योजना

अनुबंध संबंधी मामलों में।

दायरा और अनुमेय सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट *[2012] 9* एस. सी. आर.

ऐसे मामलों में न्यायिक समीक्षा के आधार और राहत

जो उपलब्ध हो सकते हैं वे अलग-अलग मामले हैं लेकिन वे हैं

इसके पूर्ण बहिष्कार के दृष्टिकोण को उचित नहीं ठहराते हैं। यह अधिक है

जब आधुनिक प्रवृत्ति भी जांच करने के लिए है

ऐसे अनुबंधों में एक शब्द की अनुचितता जहां सौदेबाजी की शक्ति असमान है ताकि ये नहीं हैं

बातचीत किए गए अनुबंध लेकिन मानक रूप अनुबंध असमान।

22. अनुबंधों में स्पष्ट अंतर है।

निजी पक्षों और अनुबंधों के बीच जिनके लिए राज्य

एक पार्टी है। निजी पक्ष केवल उनके बारे में चिंतित हैं

जबकि राज्य अपने व्यक्तिगत हित का प्रयोग करते हुए शक्तियाँ और अपने कार्यों का निर्वहन, निर्विवाद रूप से कार्य करता है, जैसे

सार्वजनिक भलाई और सार्वजनिक हित में इससे अपेक्षा की जाती है।

प्रत्येक राज्य की कार्रवाई का प्रभाव जनहित पर भी पड़ता है।

अकेले यह कारक कम से कम आयात करने के लिए पर्याप्त है

सार्वजनिक कानून दायित्वों की न्यूनतम आवश्यकताएँ और

इस चरित्र से राज्य द्वारा किए गए अनुबंधों या इसकी साधनता को प्रभावित करें। यह अलग बात है कि

संविदात्मक दायित्वों के दायरे में आने वाले विवादों के संबंध में न्यायिक समीक्षा का दायरा अधिक सीमित हो सकता है।

और संदिग्ध मामलों में पक्षों को हटा दिया जा सकता है

प्रदान किए गए उपचारों का सहारा लेकर उनके अधिकारों का निर्णय

विशुद्ध रूप से संविदात्मक विवादों के निर्णय के लिए। हालांकि,

इस हद तक, अनुच्छेद *14* के उल्लंघन के आधार पर यह आरोप लगाते हुए चुनौती दी जाती है कि विवादित कार्य

मनमाना, अनुचित या अनुचित है, तथ्य यह है कि विवाद भी संविदात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आता है।

दायित्व राज्य को उसके दायित्व से मुक्त नहीं करेंगे

हद तक, दायित्व हमेशा एक सार्वजनिक चरित्र का होता है प्रत्येक मामले में चाहे कोई अन्य अधिकार हो या

इसके अलावा दायित्व। एक अतिरिक्त संविदात्मक दायित्व दावेदार को गारंटी से वंचित नहीं कर सकता है।के हाथों गैर-मनमानेपन के अनुच्छेद *14* के तहत

अपने किसी भी कार्य में बताएँ।

23. इस प्रकार, वर्तमान जैसे मामले में, यदि यह दिखाया जाता है कि

राज्य की विवादित कार्रवाई मनमाना है और इसलिए संविधान के अनुच्छेद *14* का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है।

आक्षेपित अधिनियम को निरस्त करने में बाधा

इस सवाल के बावजूद कि क्या कोई अतिरिक्त अधिकार है,

संविदात्मक या वैधानिक, यदि कोई हो, भी उपलब्ध है पीड़ित व्यक्ति।

24. राज्य के विभाजित व्यक्तित्व को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है

डॉ. जेकिल और मिस्टर हाइड अनुबंध के क्षेत्र में ताकि

उस पर राज्य की सभी विशेषताओं को प्रभावित करें

एक अनुबंध करते समय सीमा को पूरा करने की आवश्यकता होती है

संविधान के अनुच्छेद *14* का दायित्व और उसके बाद

इसे नए को सजाने के लिए राज्य के अपने लिबास को छोड़ने की अनुमति देना

केवल के अधीन मनमाने ढंग से कार्य करने के लिए इसे सक्षम करने वाला अनुबंधसंविदात्मक दायित्व और उससे निकलने वाले उपाय। यह है।

वास्तव में राज्य के रूप में इसके व्यक्तित्व की प्रकृति जो है महत्वपूर्ण है और इसके सभी कार्यों की विशेषता होनी चाहिए, जो भी हो

कार्य की प्रकृति नहीं, संविदात्मक या अन्यथा, जो अनुमति प्राप्त जांच की प्रकृति के लिए निर्णायक है

इसके अधिनियम की वैधता की जांच करना। अनुच्छेद की आवश्यकता

14 निष्पक्ष, न्यायसंगत और यथोचित रूप से कार्य करने का कर्तव्य होने के नाते, वहाँ

कुछ भी नहीं है जो आवश्यकता की अवधारणा के खिलाफ है

संविदात्मक मामलों में भी राज्य हमेशा ऐसा कार्य करेगा।

राज्य के अधिनियमों के बीच एक बुनियादी अंतर है

जो हमेशा सार्वजनिक हित में होना चाहिए और जो एक

मुख्य रूप से व्यक्तिगत लाभ के लिए, जो बढ़ावा दे सकता है या नहीं भी। जनहित। इस तरह से देखा गया, जिसमें हम नहीं पाते हैं

वैचारिक कठिनाई या कालातीतता, हम कोई कारण नहीं पाते हैं कि क्यों

अनुच्छेद *14* की आवश्यकता में भी विस्तार नहीं होना चाहिए

राज्य गतिविधि के संचालन को विनियमित करने के लिए संविदात्मक मामलों का क्षेत्र।

25. वेड मेंः इंगित करने के बाद प्रशासनिक कानून *(*छठा संस्करण*)*

कि 'सार्वजनिक प्राधिकरणों की शक्तियाँ अनिवार्य रूप से सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट *[2012] 9* एस. सी. आर. हैं।

निजी व्यक्तियों से अलग, यह किया गया है

पीपी में संक्षेप में कहा गया है। *400-01* निम्नानुसारः

"...... निरंकुश विवेक की पूरी अवधारणा है

एक सार्वजनिक प्राधिकरण के लिए अनुपयुक्त, जिसके पास केवल इसलिए शक्तियां हैं ताकि वह उनका उपयोग कर सकेसार्वजनिक भलाई।

इस तरह के कानूनी अधिरोपण में कुछ भी विरोधाभासी नहीं है।

सीमाएँ। यह वास्तव में विरोधाभासी होगा यदि वे नहीं थे थोपा गया। न ही यह सिद्धांत अंग्रेजों की विचित्रता है और न ही

अमेरिकी कानूनः यह फ्रांसीसी कानून में समान रूप से प्रमुख है। न ही

क्या यह एक विशेष प्रतिबंध है जो केवल स्थानीय अधिकारियों को रोकता हैः यह क्राउन के मंत्रियों पर कम लागू नहीं होता है। ऐसा भी नहीं है।

प्रशासन के क्षेत्र तक सीमितः यह वहाँ संचालित होता है जहाँ कुछ सार्वजनिक उद्देश्य के लिए विवेकाधिकार दिया जाता है, क्योंकि

उदाहरण जहाँ एक न्यायाधीश को जूरी परीक्षण का आदेश देने का विवेकाधिकार है।

यह केवल वहाँ है जहाँ व्यक्तिगत लाभ के लिए शक्तियाँ दी जाती हैं।

अधिकार प्राप्त व्यक्ति का कि विवेकाधिकार निरपेक्ष है।

स्पष्ट रूप से यह सार्वजनिक कानून में लागू नहीं हो सकता है। इन्हीं कारणों से सिद्धांत रूप में ऐसा नहीं होना चाहिए।

गैर-समीक्षा योग्य प्रशासनिक विवेकाधिकार के रूप में, जो

यह उतना ही विरोधाभास होना चाहिए जितना कि

अनियंत्रित विवेक। वह प्रश्न जो पूछा जाना चाहिए

न्यायिक समीक्षा का दायरा क्या है, और कुछ विशेष मामलों में

मामलों में विवेकाधीन निर्णयों की समीक्षा की गुंजाइश न्यूनतम हो सकता है। यह स्वयंसिद्ध है कि सभी विवेकाधिकार दुरुपयोग करने में सक्षम हैं, और हर शक्ति के लिए कानूनी सीमाएं हैं

कहीं मिल जाए। इसलिए हम जो दृष्टिकोण ले रहे हैं, वह इसके अनुरूप है।

इस क्षेत्र में वर्तमान विचार। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायिक समीक्षा का दायरा प्रकार के संदर्भ में भिन्न हो सकता है।

शामिल मामले का, लेकिन यह तथ्य कि कार्रवाई की समीक्षा की जा सकती है,

चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

संदेह हो।

26. विषय का एक उपयोगी उपचार एक में पाया जाना है

लेख "न्यायिक समीक्षा और सार्वजनिक प्राधिकरणों की संविदात्मक शक्तियाँ", *(1990) 106 LQR 277-92*। निष्कर्ष

हाल के अंग्रेजी निर्णयों के आधार पर लेख में तैयार किया गया

यह है कि "सार्वजनिक कानून के सिद्धांतों की रक्षा के लिए डिज़ाइन किया गया है

नागरिकों को सार्वजनिक प्रकृति के कारण आवेदन करना चाहिए निकाय, और जनता की रक्षा करने में उनकी कुछ भूमिका हो सकती है

ब्याज "। अब न्यायिक समीक्षा की ओर रुझान है

संविदात्मक शक्तियाँ और अन्य गतिविधियाँ सरकार। हाल के निर्णय का भी उल्लेख किया गया है।

जोन्स बनाम में अपील न्यायालय का। स्वानसी नगर परिषद,

(1990) 1 डब्ल्यू. एल. आर. *54,* जहाँ अदालत का स्पष्ट झुकाव है

विचार है कि संविदात्मक शक्तियाँ आम तौर पर होनी चाहिए

पुनर्विलोकन योग्य संकेत दिया गया है, भले ही अपील न्यायालय

अंतिम चरण में लड़खड़ाया और ऐसा कहने से परहेज किया। यह है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अब समीक्षा पर जोर दिया जा रहा है

प्रत्येक राज्य की कार्रवाई क्योंकि यह इससे उत्पन्न नहीं होती है

कार्य की प्रकृति, लेकिन उस कार्य का प्रयोग करने वाले शरीर की सार्वजनिक प्रकृति से; और एक के पास सभी शक्तियाँ

सार्वजनिक प्राधिकरण, चाहे जो भी प्रदान किया गया हो, उसके पास है

'केवल इसलिए कि वह उनका उपयोग सार्वजनिक भलाई के लिए कर सके। उसी को सीमित करने वाला एकमात्र अपवाद पाया जाना है

विशिष्ट मामले जहां इस तरह का बहिष्कार वांछनीय हो सकता है

सार्वजनिक नीति के मजबूत कारणों के लिए। लेकिन यह करता है

संविदात्मक क्षेत्र में समीक्षा योग्यता के बहिष्कार को उचित नहीं ठहराते हैं।

राज्य को शामिल करना क्योंकि यह अब केवल निजी नहीं है

सार्वजनिक दृष्टि या जांच से बाहर रखी जाने वाली गतिविधि।

27. एक निजी पक्ष के विपरीत जिसका कार्य अज्ञात है

कारण और व्यक्तिगत प्रवृत्तियों से प्रभावित संविदात्मक मामलों के प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं

लोक हित को प्रभावित किए बिना अकेले ऐसा कोई भी कार्य

इस क्षेत्र में भी राज्य या किसी सार्वजनिक निकाय का

जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। एक सार्वजनिक के प्रत्येक धारक जिस पद के आधार पर वह राज्य या सार्वजनिक निकाय की ओर से कार्य करता है, वह अंततः लोगों के प्रति जवाबदेह होता है।

जिसे संप्रभुता निहित करती है। इस प्रकार, सभी शक्तियाँ *6* सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्टों में निहित हैं

[2012] 9 एस सी आर।

अनुबंध के क्षेत्र में भी कार्रवाई। इस प्रकार, प्रत्येक धारक एक सार्वजनिक पद एक न्यासी होता है जिसका सर्वोच्च कर्तव्य

देश के लोग और इसलिए, धारक का प्रत्येक कार्य

एक सार्वजनिक कार्यालय का, चाहे वह वर्गीकृत करने वाले लेबल का हो अधिनियम, सार्वजनिक कर्तव्य के निर्वहन में है जिसका उद्देश्य अंततः

सार्वजनिक भलाई। राज्य की गतिविधियों के विविधीकरण के साथ

कल्याणकारी राज्य को अपने कई कार्यों के माध्यम से भी अपने व्यापक कार्यों का निर्वहन करने की आवश्यकता होती है।

उपकरण, जिनके लिए अनुबंधों में प्रवेश करने की आवश्यकता होती है

इसके अलावा, यह अवास्तविक और व्यावहारिक नहीं होगा, इसके अलावा संविदात्मक मामलों को बाहर करना अनुचित होगा

राज्य के कार्यों का क्षेत्र अनुच्छेद *14* की कसौटी पर गैर-मनमाना और उचित होना आवश्यक है।

28. यह मानते हुए भी कि आयात करना आवश्यक है

किसी राज्य में कुछ सार्वजनिक तत्व की उपस्थिति की अवधारणा अनुच्छेद *14* को आकर्षित करने और न्यायिक समीक्षा की अनुमति देने के लिए कार्रवाई, हम

यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि राज्य या किसी सार्वजनिक निकाय के सभी कार्यों का अंतिम प्रभाव निस्संदेह हैलोक हित में, इस उद्देश्य के लिए आवश्यक सार्वजनिक तत्व संविदात्मक मामलों में भी मौजूद है। हम,

इसलिए, राज्य को बाहर करना मुश्किल और अवास्तविक लगता है

अनुबंध के बाद संविदात्मक मामलों में कार्रवाईन्यायिक समीक्षा के दायरे से इसकी वैधता का परीक्षण करने के लिए

अनुच्छेद *14* की अवज्ञा पर।

29. इस समय इस पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता है कि

भारत के संविधान का अनुच्छेद *14* सरकारी नीति के मामलों पर भी लागू होता है और यदि नीति या कोई अन्य

सरकार की कार्रवाई, यहां तक कि संविदात्मक मामलों में भी, तर्कसंगतता की कसौटी को पूरा करने में विफल रहती है,

असंवैधानिक है। *[* रमण दयराम शेट्टी बनाम देखें। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण, *(1979) 3* एस. सी. सी. *489,*

और कस्तुरी लाल लक्ष्मी रेड्डी बनाम। जम्मू राज्य और

कश्मीर, *(1980) 4* एससीसी *1]*। कर्नल ए. एस. सांगवान बनाम यूनियन आरईः

भारत का, *(1980)* सप. एस. सी. सी. *559,* जबकि विवेक कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में नीति को बदलें, जब

कानून या नियम द्वारा कुचला नहीं गया था, व्यापक माना जाता था,

निष्पक्ष रूप से और यह धारणा नहीं देनी चाहिए कि यह ऐसा था मनमाने ढंग से या किसी भी पूर्ववर्ती मानदंड द्वारा किया जाता है। चौड़ी स्वीप

अनुच्छेद *14* और प्रत्येक राज्य की कार्रवाई की आवश्यकता

इस टचस्टोन पर इसकी वैधता के लिए अर्हता प्राप्त करना, चाहे जो भी हो

राज्य की गतिविधि का क्षेत्र लंबे समय से स्थापित है। बाद में

इस न्यायालय के निर्णयों ने नींव को मजबूत किया है यह सिद्धांत और यह इस उद्देश्य के लिए इस न्यायालय के केवल दो हाल के फैसलों को संदर्भित करने के लिए पर्याप्त होगा।

33. इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह सच है, जैसा कि हमने पहले संकेत दिया है, कि राज्य की कार्रवाई की वैधता का अनुमान है और

भार उस व्यक्ति पर है जो अनुच्छेद *14* के उल्लंघन का आरोप लगाता है

दावे को साबित करने के लिए। हालांकि, जहां कोई प्रशंसनीय कारण या सिद्धांत इंगित नहीं किया गया है और न ही यह स्पष्ट है और इसलिए, विवादित राज्य की कार्रवाई पूर्व प्रतीत होती है

प्रत्यक्षतः मनमाना, मनमानेपन को साबित करने के लिए प्रारंभिक बोझ

अपनी कार्रवाई को उचित और उचित ठहराने के लिए राज्य पर जिम्मेदारी स्थानांतरित करने का निर्वहन किया जाता है। यदि राज्य उत्पादन करने में असमर्थ हैअपनी कार्रवाई को उचित और उचित ठहराने के लिए सामग्री,

मनमानेपन का आरोप लगाने वाले व्यक्ति पर बोझ को निर्वहन के लिए रखा जाना चाहिए। न्यायिक समीक्षा का दायरा सीमित है।

जैसा कि द्वारकादास मरफतिया मामले *(ऊपर)* में संकेत दिया गया है

इसे संतुष्ट करने के उद्देश्य से राज्य की कार्रवाई की देखरेख करना

ऐसे मामलों में न्यायिक समीक्षा। यह अदालतों के लिए नहीं है कि वे नीति को फिर से तैयार करें या इसे किसी अन्य के साथ प्रतिस्थापित करें जो हैअधिक उपयुक्त माना जाता है, एक बार मनमानेपन के आधार पर हमले को *[2012] 9* एस. सी. आर. दिखाकर सफलतापूर्वक खदेड़ दिया जाता है।

कि जो कार्य किया गया था, वह उचित और उचित था

मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ। जैसा कि संकेत दिया गया है

डिप्लॉक, एल. जे., सिविल सेवा संघ परिषद बनाम। मंत्री

सिविल सेवा के लिए, *(1984) 3* सभी ई. आर. *935,* की शक्ति

न्यायिक समीक्षा अवैधता के आधार तक सीमित है,

अतार्किकता और प्रक्रियात्मक अनुचितता। के मामले में

मनमानेपन, अतार्किकता का दोष स्पष्ट है।

......

36. मनमानेपन का अर्थ और वास्तविक महत्व अधिक है।

सटीक रूप से बताए गए या परिभाषित की तुलना में आसानी से देखा जा सकता है। द.

सवाल यह है कि क्या कोई आक्षेपित कार्य मनमाना है या नहीं,

अंततः तथ्यों पर जवाब दिया जाना है और

किसी दिए गए मामले की परिस्थितियाँ। आवेदन करने के लिए एक स्पष्ट परीक्षा

यह देखना है कि क्या कोई स्पष्ट सिद्धांत है

आक्षेपित अधिनियम से उभरना और यदि ऐसा है, तो क्या यह संतुष्ट करता है

तर्कसंगतता की परीक्षा। जहाँ एक विधि निर्धारित की गई है एक कार्य करने के लिए और अनुसरण करने में कोई बाधा नहीं है

उस प्रक्रिया, अधिनियम का निष्पादन अन्यथा और एक में

तरीका जो किसी भी स्पष्ट सिद्धांत को प्रकट नहीं करता है

जो उचित है, अपने आप में बुराई को आकर्षित कर सकता है

मनमानी। प्रत्येक राज्य की कार्रवाई को इसके द्वारा सूचित किया जाना चाहिएकारण और यह इस प्रकार है कि एक कार्य जो कारण से अज्ञात है, है

मनमाना। कानून का शासन कानूनों द्वारा शासन पर विचार करता है।और न कि उन लोगों के हास्य, सनक या सनक से जिनके लिए

कि 'चाहे आप कभी भी इतने ऊँचे हों, कानून आपके ऊपर हैं'। यह है।जिसे सत्ता में बैठे लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए।

(जोर मेरा है*)*

तत्काल निर्णय में निर्धारित कानूनी प्रस्ताव हो सकता है

संक्षेप में निम्नानुसार लिखा जाए। सबसे पहले, राज्य में कार्रवाई संविदात्मक क्षेत्र सार्वजनिक भलाई और सार्वजनिक हित के लिए होते हैं

और उनसे निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होने की अपेक्षा की जाती है। दूसरा, यह विदेशी होगा

संविदात्मक मामलों में भारत के संविधान के अनुच्छेद *14* के अपवर्जन के तर्क को स्वीकार करने के लिए संवैधानिक योजना।

दायित्व, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक चुनौती के लिए उठाया गया भारत के संविधान के अनुच्छेद *14* के तहत इस आधार पर कि

प्रत्येक राज्य की कार्रवाई को कारण के बारे में सूचित किया जाना चाहिए और यह निम्नलिखित हैकि कारण से अनजान कार्य मनमाना है। पाँचवाँ, जहाँ नहीं

प्रशंसनीय कारण या सिद्धांत इंगित किया गया है *(*या स्पष्ट है*)*, और जहां आक्षेपित कार्रवाई एकतरफा प्रतीत होती है,

राज्य पर अपनी कार्रवाई को निष्पक्ष और न्यायसंगत ठहराने की जिम्मेदारी आ जाती है।उचित है। छठा, सार्वजनिक पद का प्रत्येक धारक उन लोगों के प्रति जवाबदेह होता है जिनमें संप्रभुता निहित होती है। सभी शक्तियाँ निहित हैं

एक सार्वजनिक कार्यालय में, अनुबंध के क्षेत्र में भी, होने के लिए अभिप्रेत हैं इसका उपयोग सार्वजनिक भलाई और सार्वजनिक हित को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। और

सातवां, भारत के संविधान का अनुच्छेद *14* भी लागू होता है।

संविदात्मक मामलों में भी सरकारी नीति के मामलों में,

और यदि सरकार की नीति या कोई कार्रवाई संतुष्ट करने में विफल रहती है

तर्कसंगतता की परीक्षा, वही असंवैधानिक होगी।

(ज*)* इसके बाद निर्णय की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया।

लखनऊ विकास प्राधिकरण बनाम में प्रस्तुत। एम. के. गुप्ता

(1994) 1 एससीसी *243*। गंभीरता से, तत्काल निर्णय में कोई नहीं है

हाथ में मुद्दे के लिए सीधा असर। फैसला तय करता है

क्या पीड़ित को मुआवजा दिया जा सकता है

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, *1986* के तहत उपभोक्ता। यह भी तय करता है कि भुगतान करने की जिम्मेदारी किसे लेनी चाहिए।

मुआवजा दिया गया। लेकिन सब कुछ एक जैसा है

दिलचस्प अवलोकन जो संदर्भ में देखे जा सकते हैं विचाराधीन विषय। जिन टिप्पणियों पर जोर दिया गया है, उनके कुछ हिस्सों को नीचे देखा जा रहा हैः

"8. .... हमारे संविधान के तहत संप्रभुता निहित है

लोग उन्मुख होने के लिए बाध्य। व्यायाम में कोई पदाधिकारी नहींवैधानिक शक्ति की सीमा को छोड़कर, प्रतिरक्षा का दावा कर सकते हैं

कानून द्वारा ही संरक्षित। में कार्य कर रहे सार्वजनिक अधिकारी

संवैधानिक या वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन

ओ सर्वोच्च न्यायालयक रिपोर्टक समक्ष उत्पीड़क अपन व्यवहारक लेल उत्तरदायी छथि।

[2012] 9 एस सी आर।

आयोग जैसे कानून के तहत बनाए गए अधिकारी

के मूल्य के लिए उपभोक्ता की शिकायत पर विचार करें वस्तु या सेवाएँ और क्षतिपूर्ति। 'क्षतिपूर्ति' शब्द का फिर से बहुत व्यापक अर्थ है। अधिनियम में इसे परिभाषित नहीं किया गया है। शब्दकोश के अनुसार इसका अर्थ है,

'क्षतिपूर्ति या क्षतिपूर्ति की जा रही है; के रूप में दी गई चीज़

प्रतिफल; '। कानूनी अर्थों में यह वास्तविक नुकसान हो सकता है।

या अपेक्षित हानि और शारीरिक, मानसिक या विस्तारित हो सकती है।

यहां तक कि भावनात्मक पीड़ा, अपमान या चोट या हानि भी। इसलिए,

जब आयोग को अधिकार क्षेत्र में निहित किया गया हो

वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य प्रदान करना और उसे मुआवजा देना।

इसका व्यापक रूप से आयोग को सक्षम बनाने के लिए अर्थ लगाया जाना चाहिए

क्षतिपूर्ति का अर्थ। हमारी राय में प्रावधान एक उपभोक्ता को दावा करने में सक्षम बनाता है और अधिकार देता है उसके साथ किए गए किसी भी अन्याय के निवारण के लिए आयोग। कोई और।

निर्माण अधिनियम के उद्देश्य को विफल कर देगा। द.

न केवल वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य प्रदान करना बल्कि उपभोक्ता को उसके साथ हुए अन्याय की भरपाई भी करना। *10.* द्वारा निर्धारित राशि का भुगतान किसे करना चाहिए

अधिकार या इसे उन लोगों से प्राप्त किया जाना चाहिए जो थे इसके लिए जिम्मेदार*?* जैसा कि समझाया गया है*,* मुआवजे में शामिल हैं

वस्तुओं या सेवाओं के नुकसान के लिए और अन्याय की पीड़ा के लिए भी न्यायसंगत समतुल्य। उदाहरण के लिए सिविल अपील में

1991 के एस. एल. पी. *(*सिविल*)* संख्या *659* से उत्पन्न *1993* के सं. आयोग ने बैंगलोर विकास को निर्देश दिया।पट्टा-सह-बिक्री समझौता प्राप्त करने में उपभोक्ता द्वारा किए गए खर्च के लिए उसे *2446* रुपये का भुगतान करने का अधिकार

पंजीकृत क्योंकि यह वैकल्पिक के लिए अतिरिक्त खर्च था

उसे आवंटित स्थल। कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई। द *481*

आरईः *2012* का विशेष संदर्भ संख्या *1*

[जगदीश सिंह खेहर*,* जे।*]*

जिस क्षण प्राधिकरण को गलती का पता चला

इसके द्वारा प्रतिबद्ध*,* इसने प्रतिवादी को वैकल्पिक स्थल आवंटित करके तत्काल कार्रवाई की। यह क्षतिपूर्ति थी

प्रत्यर्थी को सटीक नुकसान हुआ। यह कर्तव्यों के उचित निर्वहन में उत्पन्न हुआ। इस तरह के कार्यों या चूक के लिए नुकसान

पीड़ितों को प्राधिकरण द्वारा ही ठीक किया जाना चाहिए। लेकिन जब पीड़ा दुर्भावनापूर्ण या दमनकारी के कारण होती है या

लोक सेवक के मनमौजी कार्य आदि*,* फिर उसकी प्रकृति

दायित्व में परिवर्तन। अधिनियम के तहत आयोग कर सकता है ऐसी राशि निर्धारित करें यदि उसकी राय में उपभोक्ता

जिसे गलत व्यवहार कहा जाता है, उसके कारण चोट लगी

अंग्रेजी न्यायालयों द्वारा अधिकारी। इंग्लैंड में भी जहाँ

अपमान आदि के लिए अनुकरणीय या गंभीर क्षति का पुरस्कार।

एक व्यक्ति को अब दंडात्मक, अपवाद माना गया है

कर्मचारियों द्वारा मनमाना या असंवैधानिक कार्रवाई सरकार '(टॉर्ट्स के कानून पर सैल्मंड और ह्यूस्टन)।

सार्वजनिक पद में दुर्भावना की व्याख्या वेड ने अपनी पुस्तक में की है।

प्रशासनिक कानून पर इस प्रकार की पुस्तकः

"जहाँ ऊपर जैसा कोई मंत्री कर्तव्य नहीं है, वहाँ भी

और यहां तक कि जहां कोई मान्यता प्राप्त यातना नहीं है जैसे कि

अतिक्रमण, उपद्रव या लापरवाही की जाती है,

सार्वजनिक प्राधिकरण या अधिकारी उत्तरदायी हो सकते हैं दुर्भावनापूर्ण, जानबूझकर या हानिकारक के लिए नुकसान

गलत-करना। इस प्रकार एक अत्याचार है जो किया गया है

सार्वजनिक कार्यालय में कदाचार कहा जाता है, और जोजानबूझकर सत्ता का दुर्भावनापूर्ण दुरुपयोग शामिल है

कुप्रशासन, और शायद अन्य गैरकानूनी भी

चोट पहुँचाने वाले कार्य "। (पी। 777)

जनता द्वारा शक्ति के दुरुपयोग के कारण हुई चोट के लिए एक नागरिक को क्षतिपूर्ति करने के लिए अदालतों का अधिकार क्षेत्र और शक्तिअधिकारियों की स्थापना लॉर्ड हेलशम द्वारा की गई है।

कैसेल एंड कंपनी लिमिटेड बनाम ब्रूम, 1972 एसी 1027, पर सिद्धांत है कि, 'अनुकरणीय क्षति का पुरस्कार कानून की ताकत को सही साबित करने में एक उपयोगी उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है'।

एक सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2012] 9 एस. सी. आर.

सरकार के सेवक भी हैं लोगों और उनकी शक्ति का उपयोग हमेशा होना चाहिए

सेवा के अपने कर्तव्य के अधीन '। एक सार्वजनिक पदाधिकारी यदि

वह दुर्भावनापूर्ण या दमनकारी कार्य करता है और

सत्ता के परिणामस्वरूप उत्पीड़न और पीड़ा होती है तो यह एक नहीं है

शक्ति का प्रयोग लेकिन इसका दुरुपयोग। कोई कानून नहीं देता है इसके खिलाफ सुरक्षा। जो इसके लिए जिम्मेदार है, उसे करना चाहिए।

इसका कष्ट उठाएँ। क्षतिपूर्ति या क्षति जैसा कि पहले बताया गया है

अधिकारी के अपने कर्तव्य का निर्वहन करने पर भी उत्पन्न हो सकता है ईमानदारी और ईमानदारी से। लेकिन जब यह मनमाने या मनमौजी व्यवहार के कारण उत्पन्न होता है तो यह अपना व्यक्तिगत चरित्र खो देता है।

और सामाजिक महत्व रखता है। ए का उत्पीड़न

सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा आम आदमी सामाजिक रूप से घृणित और कानूनी रूप से अस्वीकार्य है। यह उसे व्यक्तिगत रूप से नुकसान पहुँचा सकता है लेकिन

समाज को नुकसान कहीं अधिक गंभीर है। अपराध और भ्रष्टाचार

जनता की कमी के कारण समाज में उन्नति और समृद्धि होती है

प्रतिरोध। भावना से अधिक हानिकारक कुछ भी नहीं हैअसहायता। शिकायत करने के बजाय एक आम नागरिक

और लड़ाई अवांछनीय दबाव के आगे झुक जाती है

इसके खिलाफ खड़े होने के बजाय कार्यालयों में काम करना।इसलिए उत्पीड़न के लिए मुआवजे का पुरस्कार

उसे व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट करता है लेकिन सामाजिक बुराई को ठीक करने में मदद करता है। इसके परिणामस्वरूप कार्य संस्कृति में सुधार हो सकता है और इसमें मदद मिल सकती है दृष्टिकोण बदलें। वेड ने अपनी पुस्तक प्रशासनिक कानून में

यह देखा गया है कि यह सार्वजनिक अधिकारियों के श्रेय के लिए है कि इस पर केवल कुछ अंग्रेजी निर्णयों की सूचना दी गई है कदाचार का रूप, अर्थात् सार्वजनिक कार्यालयों में कदाचार

जिसमें जानबूझकर शक्ति का दुर्भावनापूर्ण उपयोग शामिल है

कुप्रशासन और शायद अन्य गैरकानूनी कार्य भी

चोट पहुँचाना। इसका एक कारण आरई प्रतीत होता है:

483

[जगदीश सिंह खेहर, जे।]

कानून का विकास जो अन्य कारकों के अलावा

कार्यप्रणाली पर एक स्वास्थ्यवर्धक जाँच रखने में सफल रहा

सरकारी या अर्ध-सरकारी कार्यालयों में धारण करके

अधिकारी जो व्यक्तिगत रूप से अपने मनमौजीपन के लिए जिम्मेदार हैं या

यहां तक कि अधिकार से बाहर की कार्रवाई के परिणामस्वरूप किसी नागरिक को उनके खिलाफ हर्जाना देकर चोट या नुकसान होता है। विभिन्न निर्णय।

समय-समय पर प्रस्तुत किए जाने को वेड द्वारा संदर्भित किया गया है सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा दुर्व्यवहार पर। हम उल्लेख करेंगे

उनमें से कुछ यह प्रदर्शित करने के लिए कि यह हमारे लिए कितना आवश्यक है

समाज। एशबी वी। सफेद, *(1703) 2* एल. डी. रेम *938,* द

हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने एक ऐसे निर्वाचक के पक्ष में यूबी जस इबी रेमेडियम के सिद्धांत का आह्वान किया जो गलत तरीके से चुनाव लड़ रहा था।

मतदान से रोक दिया और नुकसान के दावे का फैसला किया। इस निर्णय के अनुपात को अंग्रेजी न्यायालयों द्वारा विभिन्न स्थितियों में लागू और विस्तारित किया गया है।

11. आज इस प्रकार मुद्दा केवल पुरस्कार का नहीं है

क्षतिपूर्ति लेकिन इसका खामियाजा किसे भुगतना चाहिए। सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले अधिकार और शक्ति की अवधारणा

इसके कई आयाम हैं। यह जबरदस्त तरीके से हुआ है

समय के साथ परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन आर्थिक दृष्टिकोण। कार्य करने के लिए सशक्त प्राधिकारी

एक कानून के तहत शक्ति का प्रयोग करते समय सार्वजनिक निर्वहन

कर्तव्य। इसे सामान्य कल्याण और आम भलाई के लिए कार्य करना होगा। ईमानदारी और ईमानदारी से इस कर्तव्य का निर्वहन करने में, नुकसान

यह किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। और वह दावा कर सकता है

क्षतिपूर्ति जो परिस्थितियों में देय हो सकती है।

लेकिन जहां कर्तव्य मनमाने ढंग से किया जाता है या

सत्ता के प्रयोग के परिणामस्वरूप उत्पीड़न और पीड़ा होती है तो नुकसान का भुगतान करने की जिम्मेदारी निर्धारित की जानी चाहिए

किसके? एक आधुनिक समाज में कोई भी प्राधिकरण घमंड नहीं कर सकता है

स्वयं उस तरीके से कार्य करने की शक्ति जो मनमाना हो। यह है।

दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे मामले जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता हैरुक जाता है और सड़क पर आदमी को एक से भागने के लिए बनाया जाता है

बिना किसी परिणाम के दूसरे को समाप्त करें। विंडो क्लीयरेंस की संस्कृति पूरी तरह से मृत प्रतीत होती है। सामान्य मामलों में भी ए आम आदमी जिसके पास न तो राजनीतिक समर्थन है और न ही *[2012] 9 एस. सी. आर.*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

लोक उन्मुख में निष्क्रियता की बराबरी करने के लिए वित्तीय शक्ति

विभाग निराश हो जाते हैं और यह विश्वसनीयता को नष्ट कर देता है

सिस्टम। लोक प्रशासन, इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक विशाल

प्रशासनिक विवेकाधिकार की मात्रा जो रक्षा करती है

प्रशासनिक प्राधिकरण की कार्रवाई। लेकिन यह कहाँ पाया जाता है कि

विवेक का प्रयोग दुर्भावनापूर्ण था और शिकायतकर्ता

सुरक्षात्मक आवरण। जब कोई नागरिक ठीक होने की कोशिश करता है चोटों के संबंध में सार्वजनिक प्राधिकरण से मुआवजा

शक्ति के मनमौजी अभ्यास के लिए उसे पीड़ित किया और

राष्ट्रीय आयोग ने पाया कि यह विधिवत साबित हुआ है

उसी को प्रदान करने के लिए वैधानिक दायित्व। यह आज की तुलना में कभी अधिक आवश्यक नहीं था जब सामाजिक दायित्व भी थे।

वैधानिक शक्तियों के अनुदान द्वारा विनियमित। का परीक्षण

अनुदान का अनुमेय रूप समाप्त हो गया है। यह अब अनिवार्य है और

शक्ति के प्रयोग में निहित है कि यह इसके लिए होना चाहिए

समाज के लिए। जब न्यायालय राज्य के खिलाफ हर्जाने या मुआवजे के भुगतान का निर्देश देता है तो अंतिम

पीड़ित आम आदमी है। यह करदाताओं का पैसा है।जिनका भुगतान उन लोगों की निष्क्रियता के लिए किया जाता है जिन्हें इसके तहत सौंपा गया है

कानून के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए अधिनियम। अतः यह आवश्यक है कि आयोग जब

इस बात से संतुष्ट कि शिकायतकर्ता मुआवजे का हकदार है

उत्पीड़न या मानसिक पीड़ा या उत्पीड़न, जो पता चलता है

निश्चित रूप से सामग्री पर सावधानीपूर्वक दर्ज किया जाना चाहिए और

आश्वस्त करने वाली परिस्थितियाँ और हल्के में नहीं, तो यह होना चाहिए

आगे संबंधित विभाग को राशि का भुगतान करने का निर्देश दें

सार्वजनिक कोष से शिकायतकर्ता को तुरंत लेकिन

जिम्मेदार पाए जाने वालों से उसी की वसूली करें

इसे विभाजित करके इस तरह के अक्षम्य व्यवहार के लिए

आनुपातिक रूप से जहाँ एक से अधिक हैं

कार्यकर्ता "।

(जोर मेरा है)

निर्णय आरई के मूलभूत सिद्धांत को सामने लाता है:

2012 का विशेष संदर्भ संख्या *1*

485

*[*जगदीश सिंह खेहर, जे।*]*

कार्यकारी शासन। उक्त आधारभूत सिद्धांत आधारित है।

इस अहसास पर कि संप्रभुता लोगों में निहित है। द.

इसलिए निर्णय में यह दर्ज किया गया है कि संविधान का प्रत्येक अंग

मशीनरी का जन-उन्मुख होना अनिवार्य है। मौलिक

निर्णय द्वारा सामने लाया गया सिद्धांत यह है कि एक सार्वजनिक प्राधिकरण

सार्वजनिक शक्ति का प्रयोग एक सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन करता है, और इसलिए, सामान्य कल्याण और आम भलाई को कम करना पड़ता है। सारी शक्ति। समाज की भलाई के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। वह मुद्दा जो

विचार का विषय था, और ध्यान दिया गया है

उद्धरण के साथ, यह निष्कर्ष निकालकर निर्णय लिया गया कि

क्षतिपूर्ति राज्य द्वारा देय होगी (या

साधनात्मकता) जहाँ अनुचित अभाव के कारण

विवेक के अनुचित प्रयोग के परिणामस्वरूप नुकसान हुआ है,

क्षतिपूर्ति राज्य (या उसके साधन) द्वारा देय है।

लेकिन जहाँ लोक पदाधिकारी अपने विवेक का प्रयोग करता है

कार्यपालक को स्वयं मुआवजे का भार उठाना चाहिए। देय के रूप में रखा गया। सार्वजनिक पदाधिकारी पर जिम्मेदारी स्थानांतरित करने का कारण ध्यान देने योग्य है। इस न्यायालय ने महसूस किया कि जब कोई न्यायालय नुकसान या मुआवजे के भुगतान का निर्देश देता है

बता दें, अंतिम पीड़ित आम आदमी है, क्योंकि यह करदाताओं का पैसा है जिसमें से नुकसान और लागत का भुगतान किया जाता है।

(i) हमारे विचार के लिए अगला उद्धृत निर्णय था

कॉमन कॉज, ए रजिस्टर्ड सोसाइटी बनाम भारत संघ और

ओआरएस। , *(1996) 6* एससीसी *530*। तत्काल मामला एक से निपटा गया

पेट्रोलियम उत्पादों के लिए खुदरा दुकानों के आवंटन को चुनौती*(* पेट्रोल पंप*)*। *15* व्यक्तियों के पक्ष में आवंटन किया गया था।

गरीबी या बेरोजगारी के आधार पर। बाकी प्रासंगिक

पुनः प्रस्तुत किए गए निर्णय के उद्धरणों से तथ्य सामने आते हैं

नीचे:

"24. ऊपर पुनः प्रस्तुत मंत्री के आदेशों में कहा गया है:

" आवेदक के पास अपना भरण-पोषण करने के लिए कोई नियमित आय नहीं है औरउसका परिवार *""*, आवेदक एक शिक्षित महिला है और संबंधित है

अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए *"*, आवेदक है

बेरोजगार और आय का कोई नियमित स्रोत नहीं है *"*, *6* सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2012] 9 एस सी आर।

आवेदक एक अशिक्षित, बेरोजगार अनुसूचित जनजाति है

आजीविका के नियमित स्रोत के बिना युवा *""*, आवेदक

परिस्थितियाँ आदि। सचमुच लाखों होंगे देश में इन परिस्थितियों वाले लोगों का या

बदतर। इन व्यक्तियों को लेने का कोई औचित्य नहीं है सिवाय इसके कि उन्होंने अनुग्रह प्राप्त किया है।

मंत्री के दुर्भावनापूर्ण विचारों पर। इनमें से कोई नहीं।

मामले इस न्यायालय के समक्ष रखी गई श्रेणियों में आते हैं।सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बनाम भारत संघ,

1995 सप. *(3)* एस. सी. सी. *382*, लेकिन भले ही हम मान लें तर्क के लिए कि ये मामले उनमें से कुछ में आते हैं या

इसी तरह के दिशानिर्देशों में विवेक का प्रयोग पूरी तरह से किया गया था

उद्देश्य को प्राप्त करने की मांग की जाती है, यह अनुमति नहीं देता है कई व्यक्तियों में से मनमाने ढंग से चुनने और चुनने की शक्ति

एक ही श्रेणी में आता है। पारदर्शी और उद्देश्यपूर्ण

मानदंड/प्रक्रिया को विकसित करना होगा ताकि चयन किया जा सके एक ही वर्ग के सदस्यों के बीच या

मनमानी। यह एक मामले के रूप में नीचे रखना आवश्यक हैइस बारे में नीति कि वरीयताओं को कैसे निर्धारित किया जाएगा

एक ही श्रेणी में आने वाले दो व्यक्ति। अगर दो प्रतिष्ठित खिलाड़ी संकट में हैं और केवल एक पेट्रोल पंप है

उपलब्ध है, स्पष्ट, पारदर्शी होना चाहिए और दोनों में से किसे प्राथमिकता दी जानी है, यह इंगित करने के लिए वस्तुनिष्ठ मानदंड/प्रक्रिया। व्यवस्था में पारदर्शिता का अभाव

आवेदनों को बुलाने के चरण से लेकर मंच तकआबंटन के आदेश पारित करना। इनके नाम

आबंटितों, आदेशों और आबंटन के कारणों को

सार्वजनिक ज्ञान और जांच के लिए उपलब्ध हो। श्री शांति भूषण ने सुझाव दिया है कि पेट्रोल पंप, एजेंसियां *487*

आरई: *2012* का विशेष संदर्भ संख्या *1*

[जगदीश सिंह खेहर, जे।*]*

आदि को सार्वजनिक नीलामी द्वारा आवंटित किया जा सकता है-श्रेणीवार

योग्य और वस्तुनिष्ठ रूप से चयनित आवेदकों के बीच। हम किसी भी प्रक्रिया को लागू नहीं करना चाहते हैं

सरकार। यह सरकार के लिए नीति का विषय है कि

लेट जाएँ। तथापि, हम निर्देश देते हैं कि कोई भी प्रक्रिया निर्धारित की जाए।

सरकार द्वारा पारदर्शी, न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और गैर-पारदर्शी होना चाहिए। मनमाना।

26. सामाजिक-आर्थिक दृष्टिकोण में बदलाव के साथ, जनता

सेवकों को अधिक से अधिक काम सौंपा जा रहा है

वितरण के क्षेत्र में भी विवेकाधीन शक्तियाँ

विभिन्न रूपों में सरकारी धन। हम इसे ऐसा मानते हैं

पूरी तरह से स्पष्ट है कि यदि कोई लोक सेवक अपने पद का दुरुपयोग करता हैया तो चूक या कमीशन के कार्य द्वारा, और

इसका परिणाम किसी व्यक्ति को चोट या हानि है

सार्वजनिक संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती हैलोक सेवक। कोई भी लोक सेवक यह नहीं कह सकता कि "आप तय कर सकते हैं"

दुर्भावनापूर्ण आधार पर एक आदेश को अलग करें लेकिन आप नहीं कर सकते

मुझे व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराएँ। "कोई भी लोक सेवक घमंड नहीं कर सकता।

स्वयं को इस तरह से कार्य करने की शक्ति जो मनमाना है।

(जोर मेरा है)

इस फैसले का विवाद पर सीधा असर पड़ता है

हाथ। यह स्पष्ट रूप से उस तरीके को चित्रित करता है जिसमें विवेकाधिकार होना चाहिए। प्रयोग किया जाए, विशेष रूप से जब विवेकाधिकार का उद्देश्य राज्य हो

उदारता। ऊपर पुनरुत्पादित टिप्पणियों का अवलोकन

पता चलता है कि संदर्भ के तहत राज्य की उदारता (पेट्रोल पंप)

गरीबी और बेरोजगारी के आधार पर आवंटित किया जाना था। इस तरह का आवंटन स्पष्ट रूप से "सर्वश्रेष्ठ" की नीति पर आधारित था।

संविधान के अनुच्छेद *39 (*बी*)* में निहित सामान्य भलाई को बढ़ावा देना।

भारत का संविधान। इस न्यायालय ने नीति में कोई दोष नहीं पाया।

गलती नीति को लागू करने के तरीके में थी। यह.

यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एक पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ मानदंड/प्रक्रिया

इसे विकसित किया जाना चाहिए, ताकि पात्र लोगों में से चुनाव निष्पक्ष रूप से और बिना किसी मनमानेपन के किया जा सके।

[2012] 9 एस. सी. आर.

488 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विवेक का प्रयोग जो सक्षम प्राधिकारी को सक्षम बनाता है

उपरोक्त निर्णय के अनुसार, एक ही श्रेणी में आने वाले कई व्यक्तियों को मनमाने ढंग से चुनना और चुनना होगा

मनमाना, और इस तरह संविधान के अनुच्छेद *14* का उल्लंघन

भारत से।

(जे) हाल के निर्णयों में से हमारा ध्यान था

मेरठ विकास प्राधिकरण बनाम एसोसिएशन ऑफ मेरठ में आमंत्रित

प्रबंधन अध्ययन और ए. एन. आर. आदि, *(2009) 6* एस. सी. सी. *171*। द.

इस मामले में न्यायनिर्णित विवाद से उभरता हैभूमि के *2* भूखंडों के आवंटन के लिए अपीलार्थी का निर्णय। उक्त उद्देश्य के लिए अपीलार्थी ने इच्छुक लोगों से निविदाएं आमंत्रित कीं।

लोग। जवाब में प्रत्यर्थी ने अपनी निविदा प्रस्तुत की। इसके बाद

प्रत्यर्थी को भूखंडों में से एक के आवंटन पर, प्रत्यर्थी ने आपत्ति जताई कि अपीलार्थी ने तय किया था

दूसरे भूखंड की आरक्षित कीमत उसके आस-पास के भूखंडों की तुलना में बहुत अधिक है। प्रत्यर्थी ने कार्रवाई पर हमला किया के आवंटन के लिए एक नया विज्ञापन जारी करने में अपीलार्थी

दूसरा प्लॉट। उपरोक्त के निर्धारण के क्रम में

विवाद इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

स्वीकृति को सूचित करने के लिए सूचित किया जाता है। व्यापक रूप से कहा गया है कि बिना शर्त होना चाहिए; उचित रूप में होना चाहिए, जिस व्यक्ति द्वारा निविदा दी जाती है वह सक्षम होना चाहिए और

अपने दायित्वों का पालन करने के लिए तैयार। निमंत्रण की शर्तें

निविदा को न्यायिक जांच के लिए खुला नहीं रखा जा सकता है क्योंकि

निविदा के लिए निमंत्रण अनुबंध के दायरे में है। हालांकि, ए.

सीमित न्यायिक समीक्षा उन मामलों में उपलब्ध हो सकती है जहाँ

यह स्थापित किया गया है कि निविदा के लिए निमंत्रण की शर्तें किसी विशेष की सुविधा के अनुरूप बनाई गई थीं।

बोली प्रक्रिया में भाग लेने से अन्य सभी लोगों को समाप्त करने की दृष्टि से व्यक्ति।

27. निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाले बोलीदाताओं ने

समानता और निष्पक्षता के अधिकार के अलावा कोई अन्य अधिकार नहीं

प्रतिस्पर्धी बोलियों के मूल्यांकन के मामले में उपचार

आरई नोटिस के जवाब में इच्छुक व्यक्तियों द्वारा दी गई पेशकश:

पारदर्शी तरीके से और स्वतंत्र रूप से निविदाएं आमंत्रित करना

छिपा हुआ एजेंडा। कोई शर्तों को चुनौती नहीं दे सकता है और

खाली जमीन को छोड़कर निविदा की शर्तें,

कारण निविदा के निमंत्रण की शर्तें हैं

अनुबंध के दायरे में। कोई बोलीदाता एक के रूप में हकदार नहीं है

प्रवेश के लिए निविदाएं आमंत्रित करने वाले प्राधिकरण पर जोर देने के अधिकार का मामला

नियम और शर्तों के बिना आगे की बातचीत में

ऐसी वार्ताओं के लिए इस प्रकार दी गई सूचना।

28. यह कानून में बहुत अच्छी तरह से स्थापित है और इसे फिर से कहने की आवश्यकता नहीं है।

हमारे हाथों में सार्वजनिक संपत्ति का निपटान

राज्य या उसके साधन एक न्यास के चरित्र में भाग लेते हैं। जनता के निपटान के लिए अपनाए जाने वाले तरीके

संपत्ति निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए

सभी इच्छुक व्यक्तियों को भाग लेने का अवसर

प्रक्रिया।

29. प्राधिकरण को सर्वोच्च को स्वीकार नहीं करने का अधिकार है बोली लगाने और यहां तक कि उच्चतम बोलीदाता के अलावा किसी अन्य निविदा को प्राथमिकता देने के लिए, यदि अच्छे और पर्याप्त कारण मौजूद हैं, जैसे -

उच्चतम बोली बाजार मूल्य का प्रतिनिधित्व नहीं करती है लेकिन वहाँ

इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि प्राधिकरण की कार्रवाई को स्वीकार करने मेंया बोली को अस्वीकार करना मनमानेपन से मुक्त होना चाहिए या

पक्षपात।

......

39. कानून को संक्षिप्त रूप से वेड ने अपनी पुस्तक में कहा है।

प्रबन्ध, प्रशासनिक कानूनः

" इसलिए सार्वजनिक प्राधिकरणों की शक्तियां अनिवार्य रूप से निजी व्यक्तियों की शक्तियों से अलग हैं। एक आदमी अपनाअपने आश्रितों के किसी भी अधिकार के अधीन रहते हुए वसीयत का निपटारा कर सकता है।

जिसे वह पसंद करता है उसका उपयोग करने की अनुमति देने की पूर्ण शक्ति है भूमि, एक देनदार को रिहा करने के लिए, या, जहां कानून अनुमति देता है, *0* सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट को बेदखल करने के लिए

[2012] 9 एस सी आर।

एक किरायेदार, उसके उद्देश्यों की परवाह किए बिना। यह निरंकुश है

विवेकपूर्ण। लेकिन एक सार्वजनिक प्राधिकरण इनमें से कोई भी काम तब तक नहीं कर सकता जब तक कि वह उचित रूप से और अच्छे विश्वास के साथ काम न करे।

लोक हित के वैध और प्रासंगिक आधार। तो एक शहर

परिषद ने गैरकानूनी तरीके से काम किया जब उसने अनुमति देने से अनुचित तरीके से इनकार कर दिया

एक स्थानीय रग्बी फुटबॉल क्लब शहर के खेल मैदान का उपयोग करता है,

हालांकि एक निजी मालिक निश्चित रूप से इनकार कर सकता था

दण्ड से मुक्ति। न ही कोई स्थानीय प्राधिकरण मनमाने ढंग से रिहा कर सकता है।

देनदार, और यदि यह किरायेदारों को बेदखल करता है, भले ही इसके अनुसार

एक अनुबंध के साथ, इसे उचित रूप से और सीमाओं के भीतर कार्य करना चाहिए।

निष्पक्ष लेन-देन का '। निरंकुश विवेक की पूरी अवधारणा एक सार्वजनिक प्राधिकरण के लिए अनुचित है, जो

उनके पास केवल इसलिए शक्तियाँ हैं ताकि वे उनका उपयोग कर सकें

जनता की भलाई "। , प्रशासनिक कानून, *9* वीं संस्करण। एच. डब्ल्यू. आर. वेड और सी. एफ. फोर्सिथ।

40. यह मानने में कोई कठिनाई नहीं है कि अधिकारियों का बकाया हैनिष्पक्ष रूप से कार्य करना कर्तव्य है लेकिन यह न्यायिक मामलों में समान रूप से अच्छी तरह से स्थापित है।

समीक्षा, न्यायालय गुण-दोष से संबंधित नहीं है या निर्णय की शुद्धता, लेकिन जिस तरीके से

निर्णय लिया जाता है या आदेश दिया जाता है। अदालत ने

राय के लिए अपनी राय को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है

मामले को तय करने वाला प्राधिकारी।

41. अपीलीय शक्ति और न्यायिक शक्ति के बीच का अंतर

समीक्षा सर्वविदित है लेकिन इसे दोहराने की आवश्यकता है। के माध्यम से

न्यायिक समीक्षा, न्यायालय के विवरण की जांच नहीं कर सकते द्वारा किए गए अनुबंध की शर्तें

सार्वजनिक निकाय या राज्य। अदालतें अंतर्निहित हैं

ऐसी किसी भी जांच के दायरे पर सीमाएँ। अगर अनुबंध

प्रक्रिया को नजरअंदाज किए बिना प्रवेश किया गया है जो

प्रकृति में और एक उद्देश्य के बाद बुनियादी कहा जा सकता है

उपलब्ध विभिन्न विकल्पों पर विचार करना

राज्य और जनता के हित को ध्यान में रखते हुए, फिर न्यायालय इसके स्थान पर अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य नहीं कर सकता है

ऐसे अनुबंध में प्रवेश करने के लिए किए गए चयन के संबंध में राय। लेकिन साथ ही अदालतें निश्चित रूप से *491* कर सकती हैं।

आरई: *2012* का विशेष संदर्भ संख्या *1*

[जगदीश सिंह खेहर, जे।*]*

जांच करें कि क्या *"*निर्णय लेने की प्रक्रिया*"* उचित, तर्कसंगत, मनमाना और अनुच्छेद *14* का उल्लंघन करने वाली नहीं थी। *(* स्टर्लिंग कंप्यूटर लिमिटेड देखें। बनाम एम एंड एन प्रकाशन

लिमिटेड, *(1993) 1* एस. सी. सी. *445)*।

50. हालाँकि, हमारी राय है कि प्रयास, यदि कोई हो,

एम. डी. ए. द्वारा अपने वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के लिए और

स्वयं राजस्व को अनुचित नहीं कहा जा सकता है।

निर्णय लें। यह अच्छी तरह से कहा जाता है कि राज्य के लिए संघर्ष

इसके संसाधनों का पूरा मूल्य विशेष रूप से स्पष्ट हैराज्य के स्वामित्व वाली प्राकृतिक परिसंपत्तियों को निजी क्षेत्र को बेचना।

जब भी सरकार या अधिकारियों को इससे कम मिलता है

जिस समय राज्य की संपत्ति व्यक्तियों के पास जाती हैबहुराष्ट्रीय निगमों के बजाय देश के भीतर;

फिर भी, जो धन राष्ट्र का होना चाहिए, वह खिसक जाता है

समग्र रूप से।

(जोर मेरा है)

तत्काल निर्णय में इस न्यायालय ने निर्धारित किया कि एक निविदा में

प्रक्रिया, एक निविदाकार को उचित व्यवहार और अधिकार का अधिकार है

समान व्यवहार किया जाए। निविदाओं का मूल्यांकन, यह किया गया है

आयोजित, पारदर्शी और किसी भी छिपे हुए एजेंडे से मुक्त होना चाहिए।

प्रशासनिक कानून पर वेड्स ट्रेटीज में व्यक्त विचार, कि सार्वजनिक अधिकारी इस तरह से कार्य नहीं कर सकते हैं जो उनके लिए खुला हो।

निजी व्यक्तियों को स्वीकार किया गया। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि सार्वजनिक अधिकारी न तो द्वेष से कार्य कर सकते हैं और न ही बदला लेने की भावना से। एक सार्वजनिकप्राधिकरण को उचित रूप से और अच्छे विश्वास में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है और

लोक हित के वैध और प्रासंगिक आधारों पर। सबसे अधिक

महत्वपूर्ण रूप से यह निष्कर्ष निकाला गया कि राज्य को "पूर्ण" प्राप्त करना चाहिए।

संसाधनों का मूल्य, विशेष रूप से जब राज्य के स्वामित्व वाली परिसंपत्तियाँ

निजी व्यक्तियों/संस्थाओं को पारित किया गया। वहाँ नहीं रुकते हुए अदालत ने आगे कहा कि जो कोई भी पूर्ण *[2012] 9* एस. सी. आर. से कम भुगतान करता है।

मूल्य, नागरिकों की संपत्ति को "छूट पर" प्राप्त करें, और इस तरह देश की संपत्ति गायब हो जाती है।

(के) हमारे विचार के लिए भी उद्धृत किया गया था जिसमें निर्णय था

रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड बनाम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड।

आदि, *(2010) 7* एस. सी. सी *1.* न्यायालय का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया कि

निम्नलिखितः

"*33.* श्री आर. एफ. नरीमन, उपस्थित वरिष्ठ वकील

आर. आई. एल. ने संदर्भ के साथ अपने तर्क को केंद्रित किया

उनके अनुसार, अधिनियम की धारा *392* का अंग्रेजी कानून या *1913* के कंपनी अधिनियम में कोई पूर्ववर्ती नहीं था। द. ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि विधायिका ने महसूस किया है

धारा *392* को अधिनियमित करने की आवश्यकता धारा *391* लाने की है।

धारा *394* के बराबर। धारा *394* केवल इन पर लागू होती हैऐसी कंपनियाँ जो पुनर्निर्माण और या समामेलन कर रही हैं,

परिसंपत्तियों और देनदारियों का दूसरे को हस्तांतरण

कंपनी। इस प्रकार, यह धारा *391* के तहत निर्दिष्ट कंपनी के वंश की एक प्रजाति पर लागू होता है। धारा *394,*

उप-धारा *1* विशेष रूप से कंपनी न्यायालय को बताती है कि

केवल समझौते को मंजूरी देने की शक्ति नहीं या

व्यवस्था लेकिन यह भी कंपनी अदालत को शक्ति देता है, एक बाद के आदेश द्वारा, के लिए प्रावधान करने के लिए "ऐसे

आनुषंगिक, परिणामी और पूरक मामले

यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि पुनर्निर्माण यासमामेलन पूरी तरह से और प्रभावी ढंग से किया जाएगा "

[धारा *394 (1) (vi)]*। यह शक्ति धारा *391* में अनुपस्थित है,

ताकि धारा *391* के अंतर्गत आने वाली कंपनियाँ, लेकिन इसके अंतर्गत न आएँ।

धारा *394,* कंपनी के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।

कंपनी को स्पष्ट रूप से दी गई शक्ति के समान गुणवत्ता अदालती पद-धारा *394* के तहत मंजूरी।

आरईः *2012* का विशेष संदर्भ संख्या *1*

493

[जगदीश सिंह खेहर, जे।*]*

122. उपरोक्त विश्लेषण से निम्नलिखित व्यापक हैं -स्थायी निष्कर्ष जो प्राप्त किए जा सकते हैं संघ की स्थितिः

(1) प्राकृतिक संसाधन निहित हैं

भारत के लोग। इस प्रकार, यह गंभीर कर्तव्य हैराष्ट्रहित की रक्षा के लिए राज्य।

भले ही अन्वेषण, निष्कर्षण और दोहन

(2)

कारण, पर संवैधानिक प्रतिबंधसरकार निजी क्षेत्र पर भी समान रूप से लागू होगी।

इस प्रक्रिया में खिलाड़ी। प्राकृतिक संसाधनों का होना जरूरी

हमेशा देश के हित में उपयोग किया जाए, औरनिजी हित नहीं।

व्यापक संवैधानिक सिद्धांत, वैधानिक

(3)

योजना के साथ-साथ इसकी उचित व्याख्या

पी. एस. सी. सरकार को यह निर्धारित करने का आदेश देता है कि

द्वारा आपूर्ति किए जाने से पहले गैस की कीमत

ठेकेदार।

गैस सहित सरकार की नीति

(4)

उपयोग नीति और ई. जी. ओ. एम. का निर्णयवर्तमान मामले में मूल्य निर्धारण पर लागू होगा।

(5)

आपूर्ति को विनियमित करने के लिए पर्यवेक्षी शक्तियाँ और गैस का वितरण।

128. हमारे जैसे संवैधानिक लोकतंत्र में, राष्ट्रीय

संपत्ति जनता की है। सरकार का मानना है किविश्वास में प्राकृतिक संसाधन। इसलिए, कानूनी रूप से, सरकार ऐसी परिसंपत्तियों का स्वामित्व सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट *[2012] 9* एस. सी. आर. के उद्देश्यों के लिए रखती है।

लोगों के हित में उनका विकास करना। में

वर्तमान मामले में, सरकार के पास गैस तब तक है जब तक यह नहीं पहुंच जातीइसका अंतिम उपभोक्ता। एक तंत्र के तहत प्रदान किया जाता है

सरकार और ठेकेदार *(*आर. आई. एल.*)* के बीच पी. एस. सी.

वर्तमान मामला*)*। पी. एस. सी. किसी अन्य को ओवरराइड करेगा।

ठेकेदार और किसी अन्य के बीच संविदात्मक दायित्व

पार्टी।

......

243. हमारे संविधान की संरचना ऐसी नहीं है कि

के प्रत्येक निर्देशक सिद्धांतों को पढ़ने की अनुमति देता है

राज्य नीति, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की शर्तों को प्राप्त करने के लिए बनाई गई है अलगाव। तर्क की संरचनात्मक रेखाएँ, नैतिक अनिवार्यताएँ

राज्य और इतिहास के सबक एक से दूसरे तक जाते हैं।

अन्य। राष्ट्रीय विकास और एकता की खोज में राष्ट्र, यह महसूस किया गया कि "स्वामित्व और नियंत्रण

समुदाय के भौतिक संसाधन "यदि एक में वितरित किए जाते हैंजिस तरह से आम भलाई नहीं होती है, यह नेतृत्व करेगा

राष्ट्रीय विकास की खोज से अवमूल्यन और

राष्ट्र की एकता। नतीजतन, अनुच्छेद *39 (*बी*)* संविधान की व्याख्या संविधान के अनुच्छेद *38* के आलोक में की जानी चाहिए और इसे संविधान को लागू करने के रूप में समझा जाना चाहिए।

यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य पर सकारात्मक दायित्व कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का वितरण

इसके परिणामस्वरूप लोगों और क्षेत्रों के बीच असमानता नहीं बढ़ती है। संवैधानिक तर्क के अनुरूप

मैट्रिक्स बस उच्चारण किया, और के लिए खोज के स्वीप में

राष्ट्रीय विकास और एकता एक अन्य प्रावधान है। लोगों और क्षेत्रों के बीच असमानताओं के कारण

राष्ट्र उन लक्ष्यों के प्रति शत्रुतापूर्ण है, अनुच्छेद *39 (सी)* कहता है

कि "आर्थिक प्रणाली का संचालन" जब बिना ध्यान दिए और अनियमित छोड़ दिया जाता है, तो "की एकाग्रता" की ओर ले जाता हैसामान्य नुकसान के लिए धन और उत्पादन के साधन "और राज्य को यह सुनिश्चित करने का आदेश देता है कि ऐसा ही हो

नहीं होता है।

495

आरईः *2012* का विशेष संदर्भ संख्या *1*

[जगदीश सिंह खेहर, जे।*]*

250 हम मानते हैं कि भौगोलिक क्षेत्रों से निकाले गए और दोहन किए गए प्राकृतिक संसाधनों के संबंध मेंअनुच्छेद *297* में निर्दिष्ट संघ निम्नलिखित नहीं कर सकता हैः

(1)

उन संसाधनों का हस्तांतरण शीर्षक उनके निष्कर्षण के बाद

जब तक कि संघ को न्यायपूर्ण और उचित प्राप्त न होउसी के लिए क्षतिपूर्ति*;*

(2)

एक ऐसी स्थिति विकसित करने दें जिसमें विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगकर्ता संभावित रूप से हो सकते हैं

ऐसे संसाधनों तक पहुंच से वंचित*;*

(3)

बिना किसी स्पष्ट प्रावधान के ऐसे संसाधनों के निष्कर्षण की अनुमति दें।संरक्षण का नीतिगत विवरण, जिसमें

कुल घरेलू उपलब्धता, अपेक्षित

पीढ़ियाँ, और भारत की सुरक्षा आवश्यकताएँ भी;आवधिक के बिना निष्कर्षण और वितरण की अनुमति दें

(4)

वर्तमान वितरण का मूल्यांकन और एक बनाना

अधिक इक्विटी कैसे प्राप्त की जा सकती है, इसका आकलन,क्षेत्रों के बीच और क्षेत्रों के बीच भी;

(5)

किसी ठेकेदार या किसी अन्य एजेंसी को निकालने की अनुमति दें और

बिना स्पष्ट के संसाधनों को वितरित करें

भारत संघ की अनुमति, जो अनुमति देता है

केवल तर्कसंगत रूप से बनाए गए प्रावधान के अनुसार ही प्रदान किया जा सकता है।

उपयोग नीति; और

(6)

किसी भी अंतिम उपयोगकर्ता को कोई गारंटी नहीं दी जा सकती है

एक अवधि से परे निरंतर पहुँच और उपयोग

सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाए।

पी. एस. सी. सहित कोई भी अनुबंध जो इसमें शामिल नहीं होता है

इसके घोषित सिद्धांत स्वयं ही कमजोर हो सकते हैं और संविधान के अनुच्छेद 14 के खिलाफ हो सकते हैं।

(जोर मेरा है)

दिलचस्प बात यह है कि इस मामले में संघ द्वारा अपनाई गई स्थिति

इसे उजागर करने की आवश्यकता है। इस न्यायालय को सूचित किया गया था कि स्वाभाविक

न्यास के रूप में संसाधन सरकार में निहित हैं,

भारत के लोगों के नाम पर। और वह, यह पवित्र था

राष्ट्रीय हित की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है। सबसे ज़्यादा

प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हमेशा लोगों के हित में किया जाना चाहिए। देश और निजी हित में नहीं। इसकी पृष्ठभूमि में

संघ द्वारा अपनाया गया रुख, कि इस न्यायालय ने ऊपर निकाले गए आवश्यक निर्देश जारी किए।

(1) अंतिम संदर्भ इस निर्णय के लिए दिया गया था

अखिल भारतीय उपभोक्ता कांग्रेस बनाम राज्य में न्यायालय

मध्य प्रदेश और अन्य। *, (2011) 5* एससीसी *29:*

या इसकी एजेंसियां/उपकरण किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा और सनक के अनुसार उदारता नहीं दे सकते हैं। राजनीतिक इकाइयाँ और/या राज्य के अधिकारी। प्रत्येक क्रिया /

राज्य और/या उसकी एजेंसियों/उपकरणों का निर्णय

उदारता देने या लाभ प्रदान करने के लिए एक पर आधारित होना चाहिए

ठोस, पारदर्शी, स्पष्ट और अच्छी तरह से परिभाषित नीति, जिसे प्रकाशन द्वारा जनता को सूचित किया जाएगा

आधिकारिक राजपत्र और अन्य मान्यता प्राप्त तरीके

प्रचार और ऐसी नीति को लागू/निष्पादित किया जाना चाहिए। एक गैर-भेदभावपूर्ण और गैर-मनमाना तरीका अपनाकर

नीति से लाभान्वित होने के लिए प्रस्तावित व्यक्तियों के वर्ग या श्रेणी की परवाह किए बिना। उदारता का वितरण

जैसे भूमि का आवंटन, कोटा का अनुदान, परमिट लाइसेंस आदि।

राज्य और उसकी एजेंसियों/उपकरणों द्वारा

हमेशा निष्पक्ष और न्यायसंगत तरीके से किया जाए और

पक्षपात या भाई-भतीजावाद का तत्व किसी विशेष व्यक्ति को दिए गए विवेक, यदि कोई हो, के प्रयोग को प्रभावित नहीं करेगा।

राज्य का पदाधिकारी या अधिकारी।

66. हम यह जोड़ सकते हैं कि कोई नीति नहीं हो सकती, बहुत कुछ।

कम, आरई के आधार पर भूमि आवंटित करने की एक तर्कसंगत नीतिः

2012 का विशेष संदर्भ संख्या *1*

497

[जगदीश सिंह खेहर, जे। *]*

व्यक्तियों, निकायों, संगठनों या संगठनों द्वारा किए गए आवेदन

संस्थान द्वारा किसी निमंत्रण या विज्ञापन का तिरस्कार किया जाता है

राज्य या उसकी एजेंसी/साधन। मनोरंजन द्वारा

व्यक्तियों, संगठनों या संगठनों द्वारा किए गए आवेदन भूमि के आवंटन या किसी अन्य अनुदान के लिए संस्थान

राज्य किस प्रकार की उदारता को अन्य पात्र लोगों से अलग नहीं कर सकता है

निजी उद्यम मनमाना माना जा सकता है, भेदभावपूर्ण और पक्षपात और/या भाई-भतीजावाद का कार्य

अनुच्छेद में सन्निहित समानता खंड की आत्मा का उल्लंघन करना

14 संविधान से।

67. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि राज्य कभी ऐसा नहीं कर सकता।

कार्य में लगे संस्थानों/संगठनों को भूमि का आवंटन करना।

शैक्षिक, सांस्कृतिक, सामाजिक या परोपकारी गतिविधियाँ या समाज की सेवा कर रहे हैं सिवाय इसके कि

नीलामी। फिर भी, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि एक बार

भूमि का एक टुकड़ा आबंटन के लिए निर्धारित या पहचाना जाता है ऐसी किसी भी गतिविधि में लगे संस्थान/संगठन,

आबंटन का वास्तविक अभ्यास इस तरह से किया जाना चाहिएसमानता के सिद्धांत के अनुरूप। योग्य व्यक्ति

प्राधिकरण को, निश्चित रूप से, एक जारी करना चाहिए

विज्ञापन में इन शर्तों को शामिल किया गया है

पात्रता ताकि सभी समान रूप से स्थित पात्रों को सक्षम बनाया जा सके

एक निश्चित मूल्य पर लेकिन उस मामले में भी आवंटन होना चाहिए लेख के अनुरूप एक स्वस्थ अभ्यास से पहले

14 संविधान "।

(जोर मेरा है*)*

निकाले गए निर्णय में इस न्यायालय की टिप्पणियां

न तो किसी सारांश की आवश्यकता है और न ही आगे

शुद्धिकरण।

498 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2012] 9 एस सी आर।

(एम*)* निश्चित रूप से, एक संदर्भ से कोई बचाव नहीं हो सकता है

सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और अन्य में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के लिए। भारत संघ और अन्य। *, (2012) 3*

एस. सी. सी. *1*, जो राष्ट्रपति की प्रस्तावना के अनुसार

संदर्भ, ऐसा लगता है कि संदर्भ क्यों आया बनाया जाए। व्यापक बहस की सुनवाई के दौरान,

प्रतिद्वंद्वी दलों के बीच, टिप्पणियों के प्रभाव पर आधारित

इस न्यायालय द्वारा निर्णय के पैराग्राफ *95* और *96* में अभिलिखित। उपरोक्त पैराग्राफ नीचे निकाले जा रहे हैं:

" 95. इस न्यायालय ने बार-बार यह अभिनिर्धारित किया है कि जहाँ भी

अनुबंध दिया जाना है या लाइसेंस दिया जाना है,

सार्वजनिक प्राधिकरण को एक पारदर्शी और निष्पक्ष तरीका अपनाना चाहिए

चयन करने के लिए ताकि सभी पात्र व्यक्तियों को निष्पक्ष चुनाव मिल सके।

प्रतिस्पर्धा का अवसर। इसे अलग तरह से रखने के लिए, राज्य

और इसकी एजेंसियों/उपकरणों को सार्वजनिक संपत्ति के निपटान के लिए हमेशा एक तर्कसंगत तरीका अपनाना चाहिए और

योग्य के दावे को विफल करने का प्रयास किया जाना चाहिए

आवेदक। जब स्पेक्ट्रम आदि जैसे दुर्लभ प्राकृतिक संसाधनों के अलगाव की बात आती है, तो यह राज्य का बोझ होता है

यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक गैर-भेदभावपूर्ण तरीका अपनाया जाए

वितरण और अलगाव, जिसका अनिवार्य रूप से परिणाम होगा

96. हमारे विचार में, एक विधिवत प्रचारित नीलामी निष्पक्ष रूप से आयोजित की गईऔर निष्पक्ष रूप से शायद निर्वहन का सबसे अच्छा तरीका है

प्राकृतिक संसाधनों/जनता के अलगाव के लिए उपयोग किए जाने पर यह बोझ और पहले आओ-पहले पाओ जैसे तरीके काम आते हैं।

बेईमान लोगों द्वारा संपत्ति का दुरुपयोग होने की संभावना है

जो केवल अधिकतम वित्तीय लाभ प्राप्त करने में रुचि रखते हैं

संवैधानिक लोकाचार के लिए कोई सम्मान नहीं है और

मूल्यों। दूसरे शब्दों में, हस्तांतरण या अलगाव करते समय

प्राकृतिक संसाधनों को अपनाना राज्य का कर्तव्य है

पात्र व्यक्ति इस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। जहाँ तक उपरोक्त मामले में विवाद है

संबंधित, यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि याचिकाकर्ता *499*

आरईः *2012* का विशेष संदर्भ संख्या *1*

[जगदीश सिंह खेहर, जे।*]*

असाधारण रिट का आह्वान करते हुए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया

भारत के संविधान के अनुच्छेद *32* के तहत इस माननीय न्यायालय की अधिकारिता। याचिका एक कारण के रूप में दायर की गई थी

जनहित में। कारण जिसने याचिकाकर्ता को पदोन्नत किया

इस न्यायालय का दृष्टिकोण यह था कि संघ ने नीति को अपनाया था

स्पेक्ट्रम के लाइसेंसों के आवंटन के लिए "पहले आओ पहले पाओ"। यह आरोप लगाया गया था कि उपरोक्त नीति में तत्व शामिल थाशुद्ध मौका या दुर्घटना। की ओर से यह दावा किया गया था कि

याचिकाकर्ताओं ने "पहले आओ पहले आओ" के सिद्धांतों का आह्वान किया

प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने की अनुमति के लिए स्वाभाविक रूप से खतरनाक प्रभाव। द्वारा व्यक्त किए गए प्रभाव

याचिकाकर्ताओं पर विधिवत विचार किया गया और याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाई गई याचिका को स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद,

निर्णय के पैराग्राफ *102* में निम्नलिखित निर्देश जारी किए गएः

"102. परिणामस्वरूप, रिट याचिकाओं की अनुमति दी जाती है

निम्नलिखित शर्तें -

निजी उत्तरदाताओं को दिए गए लाइसेंस

((i)

या दो प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार *10.1.2008* के बाद

लाइसेंसधारियों के लिए स्पेक्ट्रम को अवैध घोषित किया जाता है औरनिरस्त कर दिए जाते हैं।

((ii) उपरोक्त निर्देश इसके बाद लागू हो जाएगा।

चार महीने।

(iii) केंद्र द्वारा लिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए

2011 में सरकार, ट्राई नए सिरे से बनाएगीलाइसेंस देने और आवंटन के लिए सिफारिशें

22 सेवा क्षेत्रों में *2* जी बैंड में स्पेक्ट्रम नीलामी, जैसा कि स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए किया गया था

3 जी बैंड।

((iv) केंद्र सरकार इस पर विचार करेगी -

ट्राई की सिफारिशें और उचित *[2012] 9* एस. सी. आर.

पूर्ववर्ती न्यायालय की रिपोर्ट

अगले एक महीने के भीतर निर्णय और नए लाइसेंस

नीलामी द्वारा प्रदान किया जाएगा। उत्तरदाता सं। *2* , *3* और *9* जो थे

सार्वजनिक राजकोष की लागत पर लाभान्वित

द्वारा की गई पूरी तरह से मनमानी और असंवैधानिक कार्रवाई

यू. ए. एस. लाइसेंस देने और आवंटन के लिए डी. ओ. टी.

2 जी बैंड में स्पेक्ट्रम और जिन्होंने अपने स्पेक्ट्रम को बंद कर दिया के नाम पर कई हजार करोड़ की हिस्सेदारी

इक्विटी का नया निवेश या इक्विटी के हस्तांतरण से लाभ होगा।

7 और *10* रुपये की लागत का भुगतान करेगा। *50* एक-एक लाखक्योंकि उन्हें भी पूरी तरह से मनमाना और असंवैधानिक अभ्यास से लाभ हुआ था

डी. ओ. टी. द्वारा यू. ए. एस. लाइसेंस प्रदान करने के लिए और *2* जी बैंड में स्पेक्ट्रम का आवंटन। हमारे पास नहीं है

उत्तरदाताओं पर अधिरोपित लागत जिन्होंने

2004 और *2006* में अपने आवेदन जमा किए और

जिनके आवेदन *2007* तक लंबित रहे। चार महीने के भीतर, लागत का *50* प्रतिशत उच्चतम न्यायालय की कानूनी सेवाओं में जमा कर दिया जाएगा।

कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए उपयोग की जाने वाली समिति

गरीब और गरीब वादियों के लिए। शेष *50* प्रतिशत

लागत सृजित निधियों में जमा की जाएगी

मंत्रालय की पुनर्वास और कल्याण योजनाएं

रक्षा की।

हालाँकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस निर्णय में की गई टिप्पणियाँ किसी भी तरह से,

सी. बी. आई., प्रवर्तन निदेशालय और अन्य द्वारा लंबित जाँच को प्रभावित करता है। अभिकरण या

उन लोगों के प्रति पूर्वाग्रह पैदा करना जो सी. बी. आई. द्वारा दर्ज मामलों में अभियोजन का सामना कर रहे हैं या

जिनके आधार पर अभियोजन का सामना करना पड़ सकता है

आरोप-पत्र *(ओं)* जो सी. बी. आई. द्वारा दाखिल किए जा सकते हैं

भविष्य और विशेष न्यायाधीश, सी. बी. आई. फैसला करेगा

इस निर्णय से अप्रभावित मामला। हम भी *501*

आरईः *2012* का विशेष संदर्भ संख्या *1*

*[*जगदीश सिंह खेहर, जे।*]*

यह स्पष्ट करें कि यह निर्णय पूर्वाग्रहपूर्ण नहीं होगा

द्वारा की जा सकने वाली कार्रवाई में कोई भी व्यक्ति

आयकर अधिनियम के तहत अन्य जांच एजेंसियां,

1961 , धन शोधन निवारण अधिनियम, *2002*

और इसी तरह के अन्य कानून।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक समीक्षा। याचिका आई

तत्काल फैसले के खिलाफ संघ द्वारा दायर किया गया। वैसा ही,

हालाँकि, बिना किसी आरक्षण के वापस ले लिया गया।

तत्काल याचिका की सुनवाई के दौरान, भारत के लिए विद्वान अटॉर्नी जनरल ने इस न्यायालय को सूचित किया कि संघ ने

निर्णय को प्रभावी बनाने का निर्णय लिया, जहाँ तक स्पेक्ट्रम के आवंटन का संबंध है। मामले के उपरोक्त दृष्टिकोण में, केवल द्वारा दर्ज टिप्पणियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है

यह न्यायालय पैराग्राफ *95* और *96* में यहाँ ऊपर निकाला गया है। ए.

उपरोक्त अनुच्छेदों के अवलोकन से पता चलता है कि

के अनुच्छेद *14* की व्याख्या करते हुए इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय

भारत के संविधान में, इस न्यायालय ने एक बार फिर यह अभिनिर्धारित किया कि

एक संपर्क या लाइसेंस प्रदान करते हुए, कार्यपालक को एक को अपनाना होगा

पारदर्शी और निष्पक्ष तरीका। कार्यपालिका को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी पात्र व्यक्तियों को प्रतिस्पर्धा करने का उचित अवसर मिले। के लिए

अनुबंध या लाइसेंस प्रदान करते हुए, कार्यपालक को एक को अपनाना चाहिएतर्कसंगत विधि, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योग्य के दावे

आवेदकों को बख्शा नहीं जाता है। प्राकृतिक संसाधनों के बारे में

स्पेक्ट्रम आदि की तरह, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यह बाध्य कर्तव्य था

राज्य द्वारा एक गैर-भेदभावपूर्ण पद्धति को अपनाना सुनिश्चित करना जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय/सार्वजनिक सुरक्षा होगी।

ब्याज। इस न्यायालय ने यह भी विचार व्यक्त किया कि ऐसा करने का "शायद" सबसे अच्छा तरीका एक विधिवत प्रचारित विधि के माध्यम से होगा।

नीलामी निष्पक्ष और निष्पक्ष रूप से आयोजित की गई। इस प्रकार देखा गया, यह पुष्टि की गई कि राज्य विधि को अपनाने के लिए कर्तव्यबद्ध था प्राकृतिक को अलग करते हुए व्यापक प्रकाशन देकर नीलामी

संसाधन, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी पात्र व्यक्ति

प्रक्रिया में भाग लें।

7. के दायरे पर इस न्यायालय द्वारा निर्धारित मापदंड

मामलों में भारत के संविधान के अनुच्छेद *14* की प्रयोज्यता

3 502 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2012] 9 एस सी आर।

जहाँ राज्य, उसके साधन और उनके पदाधिकारी हैं,

संविदात्मक दायित्वों में लगे हुए *(*जैसे ही वे उभरते हैं*)*

ऊपर पैराग्राफ *6* में निकाले गए निर्णय*)* को संक्षेप में दिया जा रहा है।

व्याख्या की गई। भारत के संविधान के अनुच्छेद *14* की कसौटी का सामना करने में सक्षम होने के लिए, यह पहले से ही किया जा चुका है "मुख्य राय" में व्यक्त किया गया कि यह निष्पक्ष होना चाहिए,

निष्पक्ष, पक्षपात या भाई-भतीजावाद के बिना, की खोज मेंस्वस्थ प्रतिस्पर्धा और न्यायसंगत उपचार को बढ़ावा देना। द.

निर्दिष्ट निर्णय, उन सभी आवश्यकताओं का समर्थन करते हैं जहाँ

राज्य, इसके साधन और उनके पदाधिकारी हैं -

संविदात्मक लेन-देन में लगे हुए। इसलिए सभी

"संविदात्मक के संदर्भ में तैयार की गई सरकारी नीति

मामले, जो यह अभिनिर्धारित किए गए हैं, उपरोक्त के अनुरूप होने चाहिए

मापदंड। जबकि भारत के संविधान का अनुच्छेद *14* एक उचित वर्गीकरण की अनुमति देता है जिसका उद्देश्य के साथ एक तर्कसंगत संबंध है।

प्राप्त करने की मांग की गई, यह चुनने की शक्ति की अनुमति नहीं देता है और

एक ही में आने वाले कई व्यक्तियों में से मनमाने ढंग से चुनें श्रेणी। इसलिए, एक मानदंड या प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए।

ताकि एक ही श्रेणी में आने वालों के बीच विकल्प हो

तर्क, निष्पक्षता और गैर-मनमानेपन पर आधारित। भले ही वहाँ विचार के क्षेत्र में केवल दो दावेदार हैं, वहाँ

एक स्पष्ट, पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ मानदंड होना चाहिए या

यह इंगित करने की प्रक्रिया कि दोनों में से किसे प्राथमिकता दी जानी है। यही वह है जो पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा।

8. एक अन्य पहलू जो निर्णयों से उभरता है

(ऊपर पैराग्राफ *6* में निकाला गया*)* यह है कि, राज्य, इसका

वाद्ययंत्र और उनके कार्यकर्ता, उनका अभ्यास करते हुए

व्यापार या व्यवसाय आदि के मामलों में कार्यकारी शक्ति

अनुबंध करना, जनहित, सार्वजनिक उद्देश्य और सार्वजनिक भलाई के प्रति सचेत होना चाहिए। यह ऐसा है, क्योंकि प्रत्येक धारकसार्वजनिक पद जिसके आधार पर वह राज्य की ओर से कार्य करता है,

या इसके साधन, अंततः लोगों के प्रति जवाबदेह हैं

जिसमें संप्रभुता निहित है। इस प्रकार, सभी शक्तियाँ निहित हैंराज्य का उपयोग सार्वजनिक भलाई के लिए और सार्वजनिक रूप से किया जाना है।

ब्याज। इसलिए, एक आरई में निरंकुश विवेक का प्रश्नः

[जगदीश सिंह खेहर, जे।]

कार्यकारी प्राधिकरण, बस उत्पन्न नहीं होता है। विवेकाधिकार पर बंधन

एक स्पष्ट, पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ मानदंड या प्रक्रिया

जो जनहित, सार्वजनिक उद्देश्य और सार्वजनिक भलाई को बढ़ावा देता है।

एक सार्वजनिक प्राधिकरण को नियुक्त किया जाता है, इसलिए उचित रूप से कार्य करने के लिए और

सद्भावना से और जनता के वैध और प्रासंगिक आधारों पर

ब्याज।

9. के विषय पर इस न्यायालय द्वारा अभिलिखित टिप्पणियाँ

राज्यों की व्यस्तताओं के दौरान राजस्व रिटर्न

वाणिज्यिक उद्यमों में *(*निर्णयों से उभरना*)*

ऊपर पैराग्राफ *6* में निकाला गया*)*, संक्षेप में प्रस्तुत किया जा रहा है।

इसके नीचे। यह आयोजित किया गया है, जहां राज्य केवल एक उत्पाद बेच रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि राज्य को प्रयास करना चाहिए

उच्चतम मूल्य प्राप्त करने के लिए, निश्चित रूप से किसी अन्य के अधीन

सार्वजनिक विचार को ओवरराइड करना। एक व्यापार की वैधता सरकार द्वारा निष्पादित समझौते का निर्णय इसके द्वारा किया जाना है

परीक्षण, कि उससे उत्पन्न होने वाला पूरा लाभ

राज्य, और व्यक्तियों के एक सीमित वर्ग को निजी लाभ प्रदान करने के लिए एक लबादा के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। यदि कोई अनुबंध किया गया है

राज्य और जनता के हित को ध्यान में रखते हुए,

अपीलीय प्राधिकारी का पद ग्रहण करके किसी न्यायालय द्वारा इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। पाने का प्रयास

यह अभिनिर्धारित किया गया है कि इसके संसाधनों का "पूर्ण मूल्य" राज्य के स्वामित्व वाली प्राकृतिक वस्तुओं की बिक्री में विशेष रूप से स्पष्ट है।

निजी क्षेत्र के लिए संसाधन। जब भी राज्य को कम मिलता है

परिसंपत्तियों के पूर्ण मूल्य की तुलना में, यह अनुमान लगाया गया है कि

देश को धोखा दिया गया है, जितना, यह एक सरल राशि के बराबर है

धन का हस्तांतरण, समग्र रूप से नागरिकों से, जिसे भी मिलता है

छूट पर परिसंपत्तियाँ। और उस अर्थ में, यह निष्कर्ष निकाला गया है कि राष्ट्र की जो संपत्ति है, वह खो गई है। में।

भारत ने यह स्थिति अपनाई कि प्राकृतिक संसाधन निहित हैं राज्य में न्यास के रूप में, देश के नागरिकों के लिए और उनकी ओर से। यह भी स्वीकार किया गया था कि यह पवित्र था

उन प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह स्वीकार किया गया था कि प्राकृतिक संसाधनों को *504* सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट की आवश्यकता है

[2012] 9 एस सी आर।

हमेशा नागरिकों के सामान्य हित में उपयोग किया जाए

देश, और निजी हित के लिए नहीं।

10. कानूनी/संवैधानिक मापदंडों के आधार पर /

पूर्ववर्ती तीन अनुच्छेदों में उल्लिखित आवश्यकताएँ, *I*

इस पर एक राय देंगे कि क्या परिस्थितियाँ हैं

किन प्राकृतिक संसाधनों का केवल द्वारा निपटान किया जाना चाहिए

अधिकतम प्रतिफल सुनिश्चित करना। इसके लिए, मैं एक पर भरोसा रखूंगा

"मुख्य राय" में लिया गया निष्कर्ष, अर्थात्, "वितरण"

प्राकृतिक संसाधनों का एक नीतिगत निर्णय है, और साधन

इसके लिए अपनाए गए कार्यपालक विशेषाधिकार इस प्रकार हैं।

हालाँकि, जब इस तरह के नीतिगत निर्णय को सामाजिक संगठन द्वारा समर्थित नहीं किया जाता है।

या कल्याणकारी उद्देश्य, और बहुमूल्य और दुर्लभ प्राकृतिक संसाधनों को अधिकतम लाभ के वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए अलग किया जाता है।

निजी उद्यमी, उनके अलावा अन्य साधनों को अपनाना जो

प्रतिस्पर्धी हैं और राजस्व को अधिकतम करते हैं, मनमाना हो सकता है और संविधान के अनुच्छेद *14* के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। *(* को संदर्भित करें

उपरोक्त निष्कर्ष के साथ समझौता, और तदनुसार राय है कि जब प्राकृतिक संसाधनों को उपलब्ध कराया जाता है

विशेष रूप से वाणिज्यिक दोहन के लिए राज्य से निजी व्यक्ति

उनके व्यक्तिगत लाभों के लिए, राज्य का प्रयास होना चाहिए

राजस्व लाभ को अधिकतम करने की दिशा में। केवल यही होगा

यह सुनिश्चित करना कि संविधान के अनुच्छेद *14* में निहित मौलिक अधिकार

भारत का संविधान *(*कानून के समक्ष समानता और समानता का आश्वासन देना*)* कानूनों का संरक्षण*),* और इसमें निहित निर्देशक सिद्धांत

भारत के संविधान का अनुच्छेद *39 (*बी*) (*वह भौतिक संसाधन*)*

समुदाय के इस तरह से वितरित किए जाते हैं कि आम गुओड को कम करने के लिए सबसे अच्छा*),* के नागरिकों के लिए विस्तारित किया गया है

देश।

11. एक समान निष्कर्ष भी थोड़ा सा सामने आएगा।

अलग स्थिति। यह न्यायालय एक चुनौती से निपटने वाले मामले में

पेट्रोलियम उत्पादों के लिए खुदरा दुकानों के आवंटन के लिए*[* कॉमन कॉज, ए रजिस्टर्ड सोसाइटी बनाम भारत संघ और

ओआरएस। *, (1996) 6* एस. सी. सी. *530]* ने अभिनिर्धारित किया है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद *14,* विवेकाधीन शक्ति *505* को स्वीकार नहीं करता है।

जो मनमाने ढंग से प्रयोग करने में सक्षम है। स्वीकार करते समय

कि भारत के संविधान का अनुच्छेद *14* एक उचित अनुमति देता है

जिस उद्देश्य को प्राप्त करने की मांग की गई थी, उसके साथ एक तर्कसंगत संबंध रखने वाले वर्गीकरण में यह माना गया था कि भारत के संविधान का अनुच्छेद *14* राज्य को एक ही श्रेणी में आने वाले कई

व्यक्तियों में से मनमाने ढंग से चुनने की अनुमति नहीं देता है। एक पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ मानदंड/प्रक्रिया विकसित करनी होगी ताकि चुनाव किया जा सके।

एक ही वर्ग या श्रेणी से संबंधित लोगों में से है

तर्क, निष्पक्षता और गैर-मनमानेपन पर आधारित। ए की कल्पना करें

राज्य ने प्राकृतिक संसाधनों का निपटान करने का निर्णय लिया है। यहाँ पर फिर से, मेरी राय में, अगर निजी व्यक्तियों की भागीदारी है

विशेष रूप से अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए वाणिज्यिक दोहन के लिए,तब अकेले राजस्व को अधिकतम करने के राज्य के प्रयास से अनुच्छेद *14* में निहित संवैधानिक अधिदेश की पूर्ति होगी और

39 ((b) भारत के संविधान का।

12. "मुख्य राय" में, यह निष्कर्ष निकाला गया है कि

नीलामी एक संवैधानिक जनादेश नहीं है, एक की प्रकृति में निरपेक्ष सिद्धांत जिसे सभी स्थितियों में लागू किया जाना है। और इस तरह नीलामी को संविधान के अनुच्छेद *14* में नहीं पढ़ा जा सकता है।

भारत का संविधान, ताकि सभी स्थितियों में लागू किया जा सके (देखें

"मुख्य राय" के पैराग्राफ *107* पर)। नीलामी निश्चित रूप से

व्यक्त किए गए तरीके से संवैधानिक जनादेश नहीं है, लेकिन यह कर सकता है

निश्चित रूप से कुछ स्थितियों में राजस्व को अधिकतम करने के लिए लागू किया जाएगा।

कानूनी और संवैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वापसी। यह है,

इसलिए, कि मैंने निपटान के तरीके को व्यक्त करने के लिए चुना है

प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतमकरण शब्दों का उपयोग करके

पूर्वगामी दो अनुच्छेदों में "नीलामी" शब्द के स्थान पर "राजस्व"। लेकिन यह इंगित किया जा सकता है; के लिए अटॉर्नी जनरल

सुनवाई के दौरान भारत ने स्वीकार किया था कि

प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से नीलामी निश्चित रूप से एक निर्विवाद साधन था, जिसके द्वारा राजस्व लाभ को अधिकतम किया जाता था।

आश्वस्त है (इस संबंध में मेरे द्वारा दर्ज अन्य टिप्पणियाँ)

उपरोक्त अनुच्छेद *3* को भी ध्यान में रखा जा सकता है)।

506 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट में

[2012] 9 एस सी आर।

इस मामले के बारे में उपरोक्त दृष्टिकोण, जो कुछ भी कहा जाना चाहिए, वह यह है कि यदि राज्य किसी दी गई स्थिति में इस निष्कर्ष पर पहुंचता है, तो

प्राकृतिक वस्तुओं की नीलामी से अधिकतम राजस्व अर्जित किया जाएगा।

विचाराधीन संसाधन, तो केवल वही प्रक्रिया होगी जिसे उसे उन स्थितियों में अपनाना होगा जिन पर विचार किया गया है पूर्वगामी दो अनुच्छेद।

13. कोई इस तथ्य का न्यायिक संज्ञान लेने के लिए मजबूर है, कि

प्राकृतिक संसाधनों का आवंटन व्यापक बहस का विषय है।

देश में, इतना कि, इस तरह के आवंटन का मुद्दा

संसाधनों के परिणामस्वरूप हाल ही में दो सत्र रद्द हो गए थे

संसद से। सामग्री के आवंटन पर वर्तमान बहस

द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट द्वारा संसाधनों को प्रेरित किया गया है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, व्यापक नुकसान का दावा करते हुए

अनुचित आवंटन के आधार पर राजस्व। रिपोर्ट यह है कि

बोली स्वीकार नहीं की गई थी। देश ने ऐसा ही देखा *2* जी स्पेक्ट्रम के आवंटन के आधार पर कुछ समय पहले राजनीतिक विवाद हुआ था। उस अवसर पर विवाद लाया गया था

इस न्यायालय ने एक जनहित याचिका के माध्यम से, निर्णय

जिसकी रिपोर्ट सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बनाम भारत संघ, *(2012) 3* एस. सी. सी. *1* के रूप में की गई है। व्यापक राजस्व हानि, में

2 जी स्पेक्ट्रम के आवंटन की प्रक्रिया को विधिवत रूप से देखा गया। प्रत्येक अवसर पर जब प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन का मुद्दा, इसके परिणामस्वरूप राजस्व का कथित नुकसान होता है, इसे नुकसान के रूप में चित्रित किया जाता है

राष्ट्र के लिए। यह मुद्दा तब एक विषय बन जाता है

भारतीय राजनीति के सभी स्तरों पर व्यापक बहस। का नुकसान एक, अनिवार्य रूप से दूसरे को लाभ पहुँचाता है। इन सब पर

राष्ट्र के लिए अवसर हानि, की पहचान में अनुवाद

लाभार्थियों के रूप में निजी खिलाड़ी। यदि कोई मीडिया में दिखाई देने वाले आरोपों को स्वीकार करता है, तो दोषों के कारण

निपटान तंत्र, निजी पक्ष लाखों करोड़ भारतीय रुपये के लाभार्थी रहे हैं,

बस इसी वजह से। वर्तमान बहस में, प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दल

जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आरोप लगाए हैं, जिन्होंने जवाबी आरोपों के साथ अस्वीकार कर दिया गया। यह न्यायालय नहीं है, और आरईः

2012 का विशेष संदर्भ संख्या *1*

507

[जगदीश सिंह खेहर, जे। *]*

इसे कभी भी उस बहस का हिस्सा नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है।

ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति के संदर्भ का उद्देश्य इसे लागू करना है

दरारों को दूर करने के लिए न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार, ताकि

कानूनी और संवैधानिक मापदंडों को सही ढंग से समझा जाता है।

इससे भविष्य में इस तरह के विवादों से बचा जा सकेगा। अतः यह है कि

चौथे प्रश्न पर भी मेरे द्वारा एक राय दी जा रही है,

अर्थात्, "हस्तक्षेप के लिए अनुमेय गुंजाइश क्या है?

प्राकृतिक संसाधनों के निपटान के तरीकों सहित सरकार द्वारा नीति बनाने वाली अदालतें? इस पर दी गई सलाह

यह जोड़ने के लिए जल्दी करें कि न्यायालय वैधता का परीक्षण कर सकता है औरइन विधियों की संवैधानिकता। जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने

न्यायालयों को विभिन्न न्यायालयों की कानूनी वैधता का विश्लेषण करने का अधिकार है।

वितरण के साधन और इस बारे में संवैधानिक उत्तर देना

कौन सी विधियाँ अल्ट्रा वायर्स और इंट्रा वायर्स के प्रावधान हैं संविधान। फिर भी, इसकी तुलना नहीं की जा सकती और न ही होगी।

कौन सी नीति दूसरी की तुलना में बेहतर है, लेकिन, यदि कोई नीति या कानून है

स्पष्ट रूप से इस हद तक अनुचित है कि यह निष्पक्षता का उल्लंघन करता है

संविधान के अनुच्छेद *14* की आवश्यकता के अनुसार, न्यायालय

इसे गिराने में संकोच न करें। *", (* के अनुच्छेद *146* का उल्लेख करें

" मुख्य राय *")*। उपरोक्त निष्कर्ष का पूरी तरह से समर्थन करते हुए, मैं प्रस्ताव को और स्पष्ट करना चाहता हूं।

कुछ और करने से पहले, इसका उल्लेख करना आवश्यक है

भारत के संविधान का अनुच्छेद *39 (*बी*)*।

" 39. नीति के कुछ सिद्धांतों का पालन करना राज्य-राज्य विशेष रूप से अपनी नीति का निर्देशन करेगा।

सुरक्षा की दिशा में -

(ख*)* भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण

समुदाय का इस तरह से वितरण किया जाता है कि सबसे अच्छा निर्वाह किया जा सकेआम भलाई*;*

(जोर मेरा है*)*

ऊपर निकाले गए अनुच्छेद में निहित जनादेश

यह परिकल्पना की गई है कि सभी भौतिक संसाधनों को वितरित किया जाना चाहिए *508* सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट *[2012] 9* एस. सी. आर.

इस तरह से जो *"*आम भलाई के लिए सबसे अच्छा होगा*"*। यह.

इसलिए यह स्पष्ट है कि वितरण के लिए सरकारी नीति

ऐसे संसाधनों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाना चाहिए*"* समुदाय का सामान्य हित अर्थात इस समुदाय के नागरिक

देश। यह *"*मुख्य राय*"* में व्यक्त किया गया है कि नीति के मामले विधायिका के दायरे में आते हैं या कार्यकारी, और इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, जब तक कि नीति में नहीं है

वैधानिक कानून का उल्लंघन, या इसके प्रावधानों के अधिकार से बाहर है

भारत का संविधान। यह न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं है।

एक अदालत के लिए एक वैकल्पिक नीति का सुझाव देने के लिए, जो विवेक में

न्यायालय की परिस्थितियों में बेहतर उपयुक्त हो सकता है मामला। अब तक स्थिति स्पष्ट रूप से असंदिग्ध है।

नीति की वैधता और संवैधानिकता एक मामला है,

और इसके कार्यान्वयन का तरीका बिल्कुल अलग है। यहां तक कि

कार्यान्वयन चरण एक स्पष्ट और वैध नीति, हो सकता है

एक अवैध रणनीति का आकार लें (जो किया गया है

इसके बाद के मोड़ पर सचित्र)। राष्ट्रपति बनने के बाद से

संदर्भ किसी ठोस तथ्य स्थिति पर आधारित नहीं है, इसे काल्पनिक रूप से बनाना उचित होगा। यह सक्षम करेगा

निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार लोग, ताकि वे सराहना कर सकेंअतिक्रमण के डर के बिना उनके लिए उपलब्ध विकल्प

वैधता और संवैधानिकता की सीमाओं से परे। यह

यह भी सुनिश्चित करेगा कि वास्तव में एक सार्थक राय रही है

प्रस्तुत किया गया। जो चित्रण चुना गया है वह काल्पनिक है, और इसलिए, किसी भी समान के संदर्भ के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए

वास्तविक जीवन की स्थिति/परिस्थितियाँ। क्षण में फोकस

निजी वाणिज्यिक शोषण, अर्थात, जहाँ एक निजी खिलाड़ी करेगा इस तरह के आवंटन का लाभार्थी होना, और प्राकृतिक का दोहन करना

उनसे व्यक्तिगत लाभ कमाने के लिए संसाधन।

चुने गए चित्रण का उपयोग राय व्यक्त करने के लिए किया जाएगा।

उन मामलों पर जो वैधानिक प्रावधानों द्वारा शासित हैं, और साथ ही,

जो सरकारी नीतियों पर आधारित हैं। यह ऐसी बात है।

क्योंकि जहाँ तक वर्तमान विवाद का संबंध है,

प्राकृतिक संसाधनों के वितरण के लिए मानदंड *509* होने चाहिए।

आरईः *2012* का विशेष संदर्भ संख्या *1*

[जगदीश सिंह खेहर, जे। *]*

इन दोनों शीर्षों के तहत अलग-अलग जांच की गई।

कोयला एक प्राकृतिक संसाधन है। यह दृष्टांत का गठन करेगा।

वर्तमान विचार के लिए प्राकृतिक संसाधन। मान लीजिए।

निजी वाणिज्यिक दोहन के लिए कोयला लॉट आवंटित करने का सरकारी निर्णय। सबसे पहले, विधायी नीति का दृष्टिकोण।

खानों और खनिजों का उल्लेख किया जा सकता है। *(* विकास और विनियमन*)* अधिनियम, *1957 (*इसके बाद संदर्भित*)*

के रूप में, एमएएमडीआर अधिनियम*)*। अधिनियम विशेष रूप से संबंधित है

प्राकृतिक संसाधन। एम. एम. डी. आर. अधिनियम की धारा *11* ए सचित्र प्रावधान के रूप में चुना गया, यह प्रदर्शित करने के लिए कि कैसे एक

स्पष्ट रूप से वैध विधायी नीति, एक का आकार ले सकती है

अवैध रणनीति। उपरोक्त धारा *11* ए का चयन है -इस तथ्य के कारण कि इसे केवल एमएएमडीआर अधिनियम में जोड़ा गया था

13.2.2012 पर, और इस तरह, अब तक, उसके आधार पर कोयला लॉट का कोई वास्तविक आवंटन नहीं हुआ होगा। अनुभाग

11 एमएएमडीआर अधिनियम के ए को इसके तहत रखा जा रहा हैः

"11 ए. कोयला या लिग्नाइट के संबंध में प्रक्रिया-केंद्रीय

सरकार, अनुदान देने के उद्देश्य से

टोही परमिट, पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन

कोयला या लिग्नाइट वाले क्षेत्र के संबंध में पट्टा,

ऐसे पर प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा नीलामी के माध्यम से चयन करें

नियम और शर्तें जो निर्धारित की जा सकती हैं, एक कंपनी

में लगे हुए हैं,

(1) लोहा और इस्पात का उत्पादन*;*

((ख)

शक्ति का उत्पादन*;*

(iii)

खदान से प्राप्त कोयले की धुलाई*;* या

((iv) ऐसा अन्य अंतिम उपयोग जो केंद्र सरकार कर सकती है,

आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निर्दिष्ट करें, और

राज्य सरकार ऐसा अनुदान देगी

टोही परमिट, पूर्वेक्षण लाइसेंस या

कोयले या लिग्नाइट के संबंध में खनन पट्टा

नीलामी के माध्यम से चुनी गई कंपनी

इस खंड के तहत प्रतिस्पर्धी बोलीः

बशर्ते कि प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा नीलामी

कोयला या लिग्नाइट वाले क्षेत्र पर लागू नहीं होगा,

(क*)* जहाँ ऐसे क्षेत्र को आबंटन के लिए माना जाता है

खनन के लिए सरकारी कंपनी या निगम याइस तरह के अन्य निर्दिष्ट अंतिम उपयोग*;*

(ख*)*

जहाँ ऐसे क्षेत्र को आबंटन के लिए माना जाता है

कंपनी या निगम जिसे सम्मानित किया गया है प्रतिस्पर्धी बोलियों के आधार पर बिजली परियोजना

शुल्क *(*अल्ट्रा मेगा बिजली परियोजनाओं सहित*) "*।

स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजनों के लिए "कंपनी"

इसका अर्थ है धारा *3* में परिभाषित कंपनी

कंपनी अधिनियम, *1956* और इसमें एक विदेशी कंपनी शामिल है।

उस अधिनियम की धारा *591* के अर्थ के भीतर।

(जोर मेरा है*)*

किसी क्षेत्र के संबंध में खनन पट्टा देने के लिए

कोयले से युक्त, प्रावधान किसी भी संदेह के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता है, कि

चयन प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा नीलामी के माध्यम से किया जाएगा। इसलिए नीलामी के अलावा कोई अन्य प्रक्रिया नहीं हो सकती है।

कोयला खनन पट्टे के अनुदान के लिए अपनाया गया।

एमएमडीआर अधिनियम की धारा *11* ए भी क्षेत्र को परिभाषित करती है

ऐसी प्रतिस्पर्धी बोली में भाग लेने के लिए पात्रता। होना है।

पात्र, दावेदार को उत्पादन में लगा होना चाहिए

लोहा और इस्पात, या बिजली का उत्पादन, या कोयले की धुलाईएक खदान से प्राप्त, या केंद्र द्वारा अधिसूचित एक गतिविधि

सरकार। केवल वे जो विधायी रूप से निर्धारित को संतुष्ट करते हैं

पात्रता क्षेत्र, कोयला खनन के लिए प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति है

लीज पर दिया। निष्पक्षता के लिए, और मनमानी से बचने के लिए,प्रावधान में विचार किया गया है कि उनमें से सबसे अधिक बोली लगाने वाला

जो प्रतिस्पर्धी बोली की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, वे संबंधित कोयला खनन पट्टा प्राप्त करने में सफल होंगे। विचार के क्षेत्र को सीमित करने वाली विधायी नीति हो सकती है

न्यायिक समीक्षा का विषय। यह हमला किया जा सकता है, मामले मेंकिसी कानूनी या संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन। जैसा कि व्यक्त किया गया है

[जगदीश सिंह खेहर, जे।]

किसी कानूनी या संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन। जैसा कि व्यक्त किया गया है

"मुख्य राय" में प्रत्येक व्यक्तिगत मामले के तथ्य, इस तरह के निर्धारण के लिए निर्णायक कारक होंगे। की अनुपस्थिति में

ऐसी किसी भी चुनौती के लिए विधायी नीति बाध्यकारी होगी और

लागू करने योग्य। ऐसी स्थिति में, जो लोग इसमें नहीं आते हैं

विचार का क्षेत्र, प्रक्रिया से बाहर रखा जाएगा

एक क्षेत्र पर खनन पट्टे के लिए प्रतिस्पर्धी बोली की कोयले के भंडार। प्रतिस्पर्धी के माध्यम से नीलामी की प्रक्रिया में

बोली लगाना, यदि उद्देश्य आम भलाई का सर्वोत्तम उपयोग करना है(जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद *39* (बी) में) विधायी

नीति पूरी तरह से वैध होगी। तथापि, यदि व्यक्त किया गया

विधायी नीति का किसी वैध उद्देश्य से कोई संबंध नहीं है, या

भौतिक संसाधनों के वितरण के आदेश का उल्लंघन करता है

"आम भलाई के लिए सबसे अच्छा", यह अनुचित हो सकता है,

अनुचित या भेदभावपूर्ण।

एक प्रभावी विश्लेषण के लिए, एमएमडीआर अधिनियम की धारा *11* ए

अधिक गहन जाँच की आवश्यकता है। धारा *11* ए में कहा गया है कि

पूर्वगामी में निर्दिष्ट विधायी नीति का अपवाद पैराग्राफ में कोयले के लिए खनन पट्टे के अनुदान का भी प्रावधान है

नीलामी मार्ग का पालन किए बिना एक निजी खिलाड़ी को। द.

प्रावधान कोयले के लिए एक खनन पट्टे के अनुदान पर विचार करता है, बिना किसी पारस्परिक मौद्रिक या अन्य विचार के

पट्टेदार। एमएमडीआर अधिनियम की धारा *11* ए के प्रावधान में नीलामी मार्ग को शामिल नहीं किया गया है, जहां लाभार्थी सत्ता में है।

पीढ़ी। इस तरह के बहिष्कार पर केवल तभी विचार किया जाता है जबबिजली उत्पादन चिंता, बिजली परियोजना से सम्मानित किया गया था, पर

"शुल्क के लिए प्रतिस्पर्धी बोलियों" का आधार। यह महत्वपूर्ण है कि

इस बात पर जोर दें कि धारा *11* ए में कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं है

उपरोक्त, कि प्रत्येक उद्यमी जो एक बिजली परियोजना स्थापित करता है, प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर सफल होने के बाद,

कोयला खनन पट्टा आवंटित किया जाए। लेकिन अगर ऐसा कोई आवंटन है

वास्तव में बनाया गया, यह स्पष्ट है, कि ऐसे उद्यमी को नीलामी में भाग लिए बिना, कोयले का लॉट मुफ्त में मिलेगा।

लागत। एम. एम. डी. आर. अधिनियम की धारा *11* ए में शामिल विधायी नीति, यदि आम भलाई के लिए सबसे अच्छा है,यह वैध हो सकता है, ऐसी स्थिति में भी जब भौतिक संसाधन *[2012] 9* एस. सी. आर.

512 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एमएमडीआर अधिनियम की धारा *11* ए के प्रावधान में, वास्तविकता में है कम शुल्क पर बिजली उपलब्ध कराने पर विचार किया गया। उपरोक्त परंतुक को उचित के रूप में स्वीकार किया जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है।

संविधान के अनुच्छेद *14* में निहित जनादेश का उल्लंघन

भारत का, या यहाँ तक कि अनुच्छेद में निहित निर्देशक सिद्धांत

39 ((b) भारत के संविधान का।

काल्पनिक रूप से, एक प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया मान लें

बिजली उत्पादन में रुचि रखने वाले निजी खिलाड़ियों के बीच शुल्क

परियोजना। निजी पक्ष जो बिजली की आपूर्ति करने के लिए सहमत है

इस तरह की नीलामी में सबसे कम शुल्क सफल होगा। द.

महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या परियोजना के पुरस्कार में सफल होने वाले निजी पक्ष को खनन पट्टा दिया जाता है कोयले से युक्त एक क्षेत्र, निः शुल्क, इस तरह के अनुदान से संतुष्ट होगा

निष्पक्ष, उचित, न्यायसंगत और निष्पक्ष होने की परीक्षा। द.

व्यक्तिगत मामला। इसलिए, जवाब में हो सकता है सकारात्मक के साथ-साथ नकारात्मक भी। दोनों पहलू

बाद के पैराग्राफ में मामले को समझाया जा रहा है।

के आधार पर काल्पनिक चित्रण पर वापस जाना

एमएमडीआर अधिनियम की धारा *11* ए। एक कुछ और जोड़ देगा

तथ्य ताकि प्रभावी ढंग से कानूनी बिंदु को पेश करने में सक्षम हो

आयोजित किया गया है, और उक्त बोली प्रक्रिया हुई है बिना जानकारी के, कि एक कोयला खनन पट्टा होगा

सफल बोलीदाता को आवंटित किया जाता है, फिर भी सफल बोलीदाता है

कोयला खनन पट्टा प्रदान किया गया। क्या ऐसा अनुदान वैध होगा? उपरोक्त तथ्य स्थिति में, पूछे गए प्रश्न का उत्तर,

नकारात्मक में हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि, प्रतिस्पर्धी

शुल्क के लिए बोली लगाना लाभ के ज्ञान पर आधारित नहीं था, कि

एक कोयला खनन पट्टे के अनुदान के कारण, प्रतिद्वंद्वी दावेदारों के पास आएगा। कोयला खनन पट्टे का ऐसा अनुदान

इसलिए "शुल्क के लिए प्रतिस्पर्धी बोली" से कोई संबंध नहीं है। इसलिए इस स्थिति में कोयले के लिए खनन पट्टे का अनुदान एक होगा अप्रत्याशित गिरावट, वस्तु के साथ किसी भी संबंध के बिना प्राप्त करने की मांग की गई।

513

आरईः *2012* का विशेष संदर्भ संख्या *1*

[जगदीश सिंह खेहर, जे।*]*

बोली प्रक्रिया में संबंधित पक्षों के पास कोई अवसर नहीं था

संभावित लाभ के आधार पर बिजली की दरों को कम करना उन्हें कोयला खनन पट्टे से प्राप्त करने के लिए। इस मामले में ए.

भौतिक संसाधन को प्रदान किया गया माना जाएगा

पारस्परिक विचार के बिना अर्थात निःशुल्क। इस तरह की

आबंटन उचित नहीं हो सकता है और निश्चित रूप से मनमाना और संविधान के अनुच्छेद *14* का उल्लंघन करने वाला बताया जा सकता है।

भारत। इस तरह के आवंटन का आम भलाई को कम करने के उद्देश्य से कोई संबंध नहीं है, यहां तक कि गलत भी होगा

संविधान के अनुच्छेद *39 (*बी*)* में निहित निर्देशक सिद्धांत

भारत से। इसलिए, एक स्पष्ट और वैध नीति।

दोषपूर्ण कार्यान्वयन, कानून में अस्वीकार्य हो सकता है।

थोड़े बदले हुए तथ्यात्मक परिदृश्य में, निष्कर्ष हो सकता है

खैर अलग हो जाओ। यदि नीलामी की प्रक्रिया आयोजित करने से पहले,बिजली परियोजना के पुरस्कार के लिए *(*प्रतिस्पर्धी बोलियों के आधार पर*)*

शुल्क के लिए*)*, दावेदारों को यह बताया जाता है कि सफल बोलीदाता एक क्षेत्र पर खनन पट्टे का हकदार होगा। कोयले से युक्त, जो बिजली परियोजना के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे

आवश्यक रूप से उस लाभ को शामिल करें जिससे वे होने की संभावना थी

इस तरह के खनन पट्टे। शुल्क का अनुमान लगाते समय जिस पर वे

बिजली की आपूर्ति, वे इस तरह की भरपाई करने की स्थिति में होंगे

उनकी लागतों से लाभ। यह एक अवसर में परिणाम होगा

दावेदारों को शुल्क को उससे कम स्तर तक कम करने के लिए

उक्त पट्टे के बिना संभव हुआ है। ऐसी स्थिति में

कोयला खनन पट्टे से होने वाले लाभ को इसमें शामिल किया जाएगा

शुल्क के लिए प्रतिस्पर्धी बोली। इसलिए, यह सिर्फ नहीं होगा तथ्यों के तत्काल क्रम में यह मान लेना कि कोयला लॉट मुफ्त में दिया गया है। उक्त अनुदान को पढ़ना चाहिए,

कम शुल्क पर बिजली प्रदान करने के लिए एक पारस्परिक विचार। तत्काल तथ्यात्मक परिदृश्य में, खनन पट्टे का आवंटन

यह माना जाएगा कि इसका उद्देश्य भारत के संविधान के अनुच्छेद *39 (*बी*)* के संदर्भ में *"*आम भलाई को कम करना*"* है।

इसलिए इस तरह के खनन पट्टे का आवंटन, जिसके परिणामस्वरूप प्राकृतिक संसाधन का निःशुल्क आवंटन होता प्रतीत होता है, निष्पक्षता और तर्कसंगतता की कसौटी को पूरी तरह से संतुष्ट कर सकता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद *14* में विचार किया गया है।

मोरेसो, *514* सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट *[2012] 9* एस. सी. आर.

क्योंकि सभी के लिए एक निष्पक्ष खेल का मैदान उपलब्ध कराया गया है

जो बिजली परियोजना के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, उन्हें जागरूक करके

बोली लगाने से काफी पहले कोयला खनन पट्टे का अनुदानप्रक्रिया। इसलिए पक्षपात का सवाल ही नहीं उठेगा।

सवाल का जवाब, तत्काल तथ्य की स्थिति में, अच्छी तरह से हो सकता है सकारात्मक रहें।

सार्वजनिक भलाई के लिए प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन की नीति

विधायिका द्वारा परिभाषित किया जा सकता है, जैसा कि चर्चा की गई है

पूर्वगामी अनुच्छेद। इसी तरह, आवंटन के लिए नीति

प्राकृतिक संसाधनों का निर्धारण भी कार्यपालिका द्वारा किया जा सकता है।

वैधता और संवैधानिकता निर्धारित करने के लिए मापदंडदोनों बिल्कुल एक ही हैं। उपरोक्त दृष्टिकोण से

मामला, दर्ज किए गए निष्कर्ष के बारे में कोई संदेह नहीं हो सकता है

"मुख्य राय" में कि नीलामी जो कि कई मूल्य वसूली तंत्रों में से एक है, को एकमात्र नहीं माना जा सकता है।

प्राकृतिक संसाधनों के निपटान के लिए कभी भी एक वैध तरीका नहीं होना चाहिए (देखें मेरी तत्काल राय के पैराग्राफ *10* से *12* तक)।

इसलिए मैं यह कहते हुए निष्कर्ष निकालूंगा कि इसका कोई हिस्सा नहीं है

प्राकृतिक संसाधन को विशालता के रूप में नष्ट किया जा सकता है, दान, दान या दान, निजी शोषण के लिए। प्रत्येक

खर्च किए गए प्राकृतिक संसाधन का थोड़ा सा एक पारस्परिक वापस लाना चाहिए।

विचार करें। विचार की प्रकृति में हो सकता है

राजस्व अर्जित करना या हो सकता है "आम का सबसे अच्छा उपयोग करना"

अच्छा "। यह दोनों का मिश्रण हो सकता है। नहीं हो सकता है।

भौतिक संसाधनों का निः शुल्क या एक पर अपव्यय

उनके वास्तविक मूल्य से कम पर विचार करें। नागरिकों का एक समूह दूसरे समूह की कीमत पर समृद्ध नहीं हो सकता है, इसके लिए

यह उचित या उचित नहीं होगा।

संदर्भ ने आंशिक रूप से उत्तर दिया।